

भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास

कक्षा 11 के लिए पाठ्यपुस्तक

भाग - I



ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ
ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ।



ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ शिक्षा बोर्ड

साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर

© ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਪਹਲਾ ਸੰਸਕਰਣ 2025-26 235 ਪ੍ਰਤੀਯਾਂ

All rights, including those of translation, reproduction
and annotation etc., are reserved by
the Punjab Government.

ਸਯੋਜਕ : ਸੀਮਾ ਚਾਵਲਾ (ਵਿਸ਼ਯ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਾ ਬੋਰਡ, ਮੋਹਾਲੀ)

ਚੇਤਾਵਨੀ

1. ਕੋਈ ਭੀ ਏਜੇਨਸੀ-ਧਾਰਕ ਅਧਿਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਨੇ ਕੇ ਮਨੋਰਥ ਸੇ ਪਾਠ੍ਯ-ਪੁਸਤਕੋਂ ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਦਸਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ। (ਏਜੇਨਸੀ-ਧਾਰਕ ਕੇ ਸਾਥ ਹੁਏ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀ ਧਾਰਾ ਨੰ: 7 ਅਨੁਸਾਰ)
2. ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਾ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮੁਦ੍ਰਿਤ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪਾਠ੍ਯ-ਪੁਸਤਕੋਂ ਕੇ ਜਾਲੀ/ਨਕਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ (ਪਾਠ੍ਯ-ਪੁਸਤਕੋਂ) ਕੀ ਛਪਾਈ, ਸਟੌਕ ਕਰਨਾ, ਜਮਾਖੋਰੀ ਯਾ ਬਿਕ੍ਰੀ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀਯ ਦਫ਼ਤਰ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇ ਅਨ੍ਤਰਗਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਹੈ।
(ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਾ ਬੋਰਡ ਕੀ ਪੁਸਤਕੋਂ ਬੋਰਡ ਕੇ 'ਵਾਟਰ-ਮਾਰਕ' ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਰ ਹੀ ਛਪਵਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ।)

ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਟਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਚਿਵ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਾ ਬੋਰਡ, ਵਿਦ੍ਯਾ ਭਵਨ, ਫੇਜ਼-8, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਹ ਨਗਰ-160062 ਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਏਵ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼ (ਆਈ) ਚਨ੍ਡੀਗੜ੍ਹ।

आमुख

पंजाब राज्य के ग्यारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र विषय की हिन्दी माध्यम की पाठ्य-पुस्तक प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष व संतोष का अनुभव हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह पाठ्य-पुस्तक परंपरागत शिक्षण के स्थान पर गतिविधि केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत को मुख्य रखते हुए तैयार की गयी है, जो 'पुस्तक आधारित शिक्षा' की परंपरा से 'गतिविधि आधारित शिक्षा' की तरफ बढ़ने का एक अगामी कदम है। इस पुस्तक का पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक एन. सी. आर. टी. से अडैप्ट किया गया है।

हस्तिय पुस्तक के लिए किए गए प्रयासों की सफलता स्कूल प्रधानाचार्य व अध्यापकों पर भी अधिकतर निर्भर होगी जो विद्यार्थियों की स्व-अध्ययन और रचनात्मक रुचियों को उजागर करने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि उनके भीतर रचनात्मक का गुण उत्पन्न हो सके। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की यह पहलकदमी तभी उपयुक्त लक्ष्य तक पहुँच सकेगी अगर हम विद्यार्थियों को केवल निश्चित ज्ञान प्राप्त करने की जगह अध्ययन शिक्षण प्रक्रिया में पूरी तरह सहभागी बना सकेंगे।

इस पुस्तक की सार्थकता, अध्ययन के इलावा इस विषय की मुल्यांकन प्रक्रिया पर भी निर्भर होगी जो स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रक्रिया को मनोरंजक तथा व्यावहारिक बनायेगी। पाठ्य पुस्तक को मनोरंजक बनाने के लिए चित्रों तथा गतिविधियों को भी पाठ्य सामग्री में शामिल किया गया है।

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड इस पुस्तक के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक रचना समिति द्वारा किए गए कर्तव्यनिष्ठ प्रयासों की प्रशंसा करता है। हम प्रो. एम. वी. श्री निवासन, एन. सी. ई. आर. टी., तथा प्रो. जया सिंह, एन. सी. ई. आर. टी. के द्वारा पुस्तक समिति के कार्य में मार्गदर्शन व स्वीकृति के लिए दिए गए सहयोग के लिए विशेष रूप से आभारी हैं।

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड पाठ्य पुस्तक के प्रथम संस्करण के संशोधन व पुनर्विचार के लिए आने वाले सुझावों का स्वागत करता है।

चेयरमैन

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड

“ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ” ਪੰਜਾਬ।

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार

हरि वास्तुदेवन, प्रोफेसर, इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता

मुख्य सलाहकार

तापस मजूमदार, एमेरिटस प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

समिति

आर. श्रीनिवासन, प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग, अरिगनर अन्ना राजकीय कला महाविद्यालय, विल्लुपुरम तमिलनाडु।

गोपीनाथ, पेरुमुला, प्रवक्ता, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई

जया सिंह, प्रवक्ता, डी.ई.एस.एस., एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

निशित रंजन, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र), न्यू अलीपुर बहुद्देशीय विद्यालय, बेहला, कोलकाता

नीरजा रश्मि, प्रवाचक, डी.ई.एस.एस., एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

नौशाद अली आजाद, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

प्रतिमा कुमारी, प्रवक्ता, डी.ई.एस.एस., एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

पूनम बक्षसी, वरिष्ठ प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़

बी. सी. ठाकुर, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र), राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, दिल्ली

राम गोपाल, प्रवाचक, अर्थशास्त्र विभाग, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर, तमिलनाडु

सविता पटनायक, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र), डेमोस्ट्रेशन स्कूल, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सचिवालय मार्गष भुवनेश्वर

शर्मिष्ठा बनर्जी, प्रधानाध्यापिका, विद्या भारती बालिका उच्च विद्यालय, कोलकाता

हिन्दी अनुवाद

अनुवादक मंडल

एच. के. गुप्ता, दिल्ली

ओ. पी. अग्रवाल, नई दिल्ली

कांता जोशी, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र), राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, नई दिल्ली

बी. सी. ठाकुर पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र), राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, दिल्ली

भवानी शंकर बागला, प्रवाचक, अर्थशास्त्र विभाग, पी.जी.डी.ए.वी., नई दिल्ली

रश्मि शर्मा, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र), केंद्रीय विद्यालय, जे.एन.यू. कैंपस, नई दिल्ली

लीना सिंह, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र), केंद्रीय विद्यालय, ए.जी.सी.आर., दिल्ली

श्री प्रेम दास, नई दिल्ली

राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, नई दिल्ली

रमेश चन्द्र, नई दिल्ली

सदस्य समन्वयक

एम. वी. श्रीनिवासन, प्रवक्ता, डी.ई.एस.एस., एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

पाठ्य पुस्तक रचना एवं अनुवाद समिति (विषय समिति)

मुख्य सलाहकार

1. डा. मनजीत शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डी.ए.वी. कॉलेज सैक्टर-10, चंडीगढ़
2. डा. कुलविंदर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, युनिवर्सिटी स्कूल आफ बिजनैस, पंजाब, युनिवर्सिटी, चंडीगढ़

लेखक एवं अनुवादक सदस्य (पंजाबी अनुवाद एवं अभ्यास)

एस.सी.ई.आर.टी. कोऑर्डिनेटर

1. डा. अमित जुनेजा, लैक्चरर अर्थशास्त्र, शहीद बलविंदर सिंह सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल, साबूआना, फाजिलका
2. डा. रणजोध सिंह, लैक्चरर अर्थशास्त्र, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल, गोबिंदपुर बटिंडा
3. स. बलदेव सिंह, लैक्चरर अर्थशास्त्र, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल, होशियारपुर (स.अ.स. नगर)
4. श्रीमति सतिंदर कौर, लैक्चरर अर्थशास्त्र, शहीद-ए-आज़म सुखदेव थापर कन्या स्कूल ऑफ एमीनैस, भारत नगर चौक, लुधियाना
5. डा. सुशील कुमार, लैक्चरर अर्थशास्त्र, सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल, मानसा
6. श्री विक्रम कुमार भांगरा, लैक्चरर अर्थशास्त्र, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल, ज्वाहर नगर, लुधियाना
7. श्रीमति अमनदीप कौर, लैक्चरर अर्थशास्त्र, सारागढ़ी मैमोरियल स्कूल ऑफ एमीनैस, टाउन हाल, अमृतसर
8. श्रीमति सुनीता मिनहास, लैक्चरर अर्थशास्त्र, स.म.स.स., पी.ए.पी. कैपस, जालंधर

पंजाबी भाषा संशोधक समिति

1. श्रीमति जसविंदर कौर, असिस्टेंट (रिटन.) प्रोफेसर, एस.वी.एस. खालसा कालेज फॉर वूमैन, बडियाला
2. श्री बलविंदर सिंह, पंजाबी मास्टर, शहीद जगसीर सिंह, स.स.स. स्मार्ट स्कूल आफ एमीनैस बोहा, मानसा
3. श्रीमति सुष्मा रानी, साईंस मिस्ट्रेस, सरकारी हाई स्कूल, गेहले, मानसा

हिन्दी अनुवाद और संशोधन समिति

1. श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, आदर्श स.स. स्कूल, कोटभाई
2. श्रीमति रविन्द्र कौर, सेवानिवृत्त प्राचार्या, संत सुजान सिंह जी इन्टरनेशनल स्कूल, दिल्ली
3. श्रीमति अमनदीप कौर, लैक्चरर अर्थशास्त्र, सारागढ़ी मैमोरियल स्कूल ऑफ एमीनैस, टाउन हाल, अमृतसर

अंग्रेजी भाषा संशोधन समिति

1. श्रीमती चेतनप्रीत कौर नीलो, डी.ए.वी. कॉलेज, सैक्टर-50, चंडीगढ़
2. श्रीमती अनुबत्ता, अंग्रेजी मिस्ट्रेस, सरकारी उच्च विद्यालय, हसनपुर, मोहाली
3. श्रीमती अंजली शर्मा, (एम.ए., बी.एड.), आर.बी.डी.ए. बी. सी. सै. पब्लिक स्कूल, भटिंडा
4. श्रीमती नेहा अरोड़ा, अंग्रेजी मिस्ट्रेस, स.स.स. भांखरपुर, मोहाली

पुनर्विचार समिति सदस्य अंग्रेजी व पंजाबी माध्यम हस्तलिखित प्रतियों के मिलान व शोध

1. श्रीमती जसविंदर कौर, एसोसिएट प्रोफेसर, एस.वी.एस. खालसा कालेज फॉर वूमैन, बडियाला-4905, सैक्टर-68, मोहाली,
2. श्री रमन कुमार, लैक्चरर अर्थशास्त्र, स.स.स.स. मुस्तफाबाद, फतेहगढ़ साहिब, विषय कोऑर्डिनेटर, एस.सी.ई.आर.टी.
3. श्रीमती गुरशरण कौर, लैक्चरर अर्थशास्त्र, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल, दियालपुरा सोढीयां, साहिबजादी अजीत सिंह नगर
4. श्रीमती रविन्द्र कौर, सेवानिवृत्त प्राचार्या, संत सुजान सिंह जी इन्टरनेशनल स्कूल, दिल्ली
5. श्रीमती स्नेह लता, लैक्चरर अर्थशास्त्र, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल, बागड़ीया, मलेरकोटला
6. डा. आर. पी. सिंह, लैक्चरर कामर्स, स.स.स.स. घड़ऊआ, मोहाली
7. श्री पवन कुमार, लैक्चरर कामर्स स.स.स. जलालाबाद, फाजिलका
8. सदस्य समन्वयक सीमा चावला, विशेषज्ञ, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, मोहाली

विषा-सूची

क्र.सं.	पाठ का नाम	पेज नं.
1.	स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था	1-16
2.	भारतीय अर्थव्यवस्था 1950-1990	17-38
3.	उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण : एक समीक्षा	39-62
4.	भारत में मानव पूँजी का निर्माण	63-96
5.	ग्रामीण विकास	97-114
6.	रोज़गार : संवृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे	115-138
7.	पर्यावरण और धारणीय विकास	139-162
8.	पंजाब के भौतिक और मानव संसाधन	163-186
9.	पंजाब में कृषि और औद्योगिक विकास	187-208
10.	पंजाब की वित्तीय स्थिति	209-222
	पारिभाषिक शब्दावली	223-230

इकाई
एक

विकास नीतियाँ और अनुभव
(1947-90)

इस इकाई के दो अध्यायों के द्वारा हम स्वतंत्रता पूर्व से लेकर नियोजित विकास के चार दशकों तक के भारत द्वारा चुने गये पथ का समग्र रूप से अवलोकन करेंगे। तात्पर्य यह है कि भारत सरकार ने इसके लिए जो कठोर उपाय किये, जैसे-योजना आयोग का निर्माण तथा पंचवर्षीय योजनाओं की घोषणा, आदि का अध्ययन। पंचवर्षीय योजनाओं के समग्र अवलोकन तथा नियोजित विकास की विशेषताओं तथा परिसीमाओं के मूल्यांकन का अध्ययन इस इकाई में किया गया है।

1

स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप :

- स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की दशा के बारे में जानेंगे;
- भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकास तथा गत्यावरोध की स्थिति में पहुँचा देने वाले कारकों से परिचित होंगे।

अध्याय – 1

स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जायेगा।

विक्टर एलेक्जेंडर वूस, 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय

1.1 परिचय (Introduction)

इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास से अवगत कराना है। यद्यपि, देश की वर्तमान अवस्था तथा भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा इसलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं। इसी क्रम में हम उन सब बातों की भी स्पष्ट पहचान करेंगे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। इसके मूल सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हैं, विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व दो सौ वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना था। उस शासन की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पिछले सात दशकों में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं।

1.2 औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न-स्तरीय आर्थिक विकास (Low Level of Economic Development under the Colonial Rule)

अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि जनसामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियाँ हो रही थी। सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणि – रत्न, आदि से जुड़ी शिल्पकलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। भारत में बनी इन चीजों की विश्व के बाजारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मकता के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। (बॉक्स 1.1 देखें)

औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन था। इन नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को बदल डाला। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहाँ के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बन कर रह गया।

स्वाभाविक ही था कि राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया गया। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए पर उनके अनुमानों में बहुत विसंगतियाँ और आपसी मतभेद भी रहे हैं। इन आकलनकर्त्ताओं में दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, डॉ. वी. के. आर. वी. राव तथा

आर. सी. देसाई प्रमुख रहे हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉ. राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी सभी अध्ययनकर्त्ता एक बात पर सहमत रहे हैं कि 20 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक संवृद्धि दर 2 प्रतिशत से कम ही रही है तथा प्रतिव्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र आधा प्रतिशत ही रह गई थी।

बॉक्स 1.1 बंगाल का सूती उद्योग

मलमल एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है। इसका मूल निर्माण क्षेत्र बंगाल, विशेषकर ढाका के आस - पास का क्षेत्र रहा है (यह नगर अब बांग्लादेश की राजधानी है)। ढाका के मलमल ने उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में बहुत ख्याति अर्जित की थी। यह बहुत ही महीन कपड़ा होता था। विदेशी यात्री इसे शाही मलमल या मलमल खास भी कहते थे। इसका आशय यही था कि वह इस कपड़े को शाही परिवारों के उपयोग के योग्य मानते थे।

1.3 अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक (Sectors of Economy)

किसी भी अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रीय मॉडल में जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र, गौण क्षेत्र व तृतीय / क्षेत्र में संलग्न होती है।

प्राथमिक क्षेत्रक (Primary Sector) : इस क्षेत्रक में प्राकृतिक साधनों की सहायता से की जाने वाली गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। अधिकतर प्राकृतिक उत्पाद जो हम प्राप्त करते हैं वह कृषि क्षेत्रक से ही होते हैं। इसलिए इस क्षेत्रक को कृषि व संबंधित कार्य क्षेत्रक के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्रक गौण क्षेत्रक को कच्चा माल प्रदान करता है जिसकी अनुपलब्धि में उत्पादन नहीं हो सकता। प्राथमिक क्षेत्रक के प्रमुख उदाहरण कृषि, मछली पालन, पशु-पालन, खनन तथा वन संपत्ति, आदि हैं।

गौण क्षेत्रक (Secondary Sector) : इस क्षेत्रक को निर्माण क्षेत्रक अथवा औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर अंतिम उत्पाद पैदा करता है। यह प्राथमिक क्षेत्रक के उत्पादन के मूल्य में वृद्धि करता है। इस क्षेत्र के उत्पादन को किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। गौण क्षेत्रक का उदाहरण कपास उद्योग ले सकते हैं। यह प्राथमिक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित कपास को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर कपड़े का उत्पादन करता है।

तृतीय क्षेत्रक (Tertiary Sector) : तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्रक सबसे अधिक समूचे स्तर पर गतिविधियों के एक बड़े समूह को दर्शाता है। जिसमें व्यापार, आतिथ्य (होटल, रेस्टोरेंट),

परिवहन, संचार, मनोरंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, वैयक्तिक एवं सार्वजनिक सेवाएं, उधार, प्रबंधकी, रक्षा एवं सामाजिक सेवाएं, व्यावसायिक सेवाएं एवं अन्य सेवाएं शामिल हैं। सेवा क्षेत्र का कार्य अंतिम उत्पाद की अपेक्षा सेवाओं का उत्पादन है। सेवाएं अस्पृश्य वस्तुएं हैं। इनका प्रयोग उत्पादकता, प्रदर्शन, संभावना व स्थिरता की वृद्धि के लिए किया जाता है।

यह तर्क दिया जा सकता है कि कुल स्तर पर भी सेवा क्षेत्र दूसरे क्षेत्र (कृषि एवं उद्योग) से अधिक विभिन्नता वाला क्षेत्र है।

1.3.1 कृषि क्षेत्र (Agricultural Sector)

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश की लगभग 85 प्रतिशत जनसंख्या जो गाँवों में बसी थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी-रोटी कमा रही थी (बॉक्स 1.2 देखें)।

एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही। यही नहीं अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित हास या गिरावट भी अनुभव की गई। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हो, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू-व्यवस्था प्रणालियों को ही माना जा सकता है। आज के समस्त पूर्वी भारत में जो उस समय बंगाल प्रेसीडेंसी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ को जमींदार ही हड़प जाते थे, किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। यहीं नहीं, अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने

क्रिया करें

सत्रहवीं शताब्दी में अपने देश की कृषि समृद्धि के बारे में लिखिए। लगभग 200 वर्ष बाद जब ब्रिटिश भारत को छोड़कर गए, उस समय की कृषि की गतिहीनता के साथ इसकी तुलना कीजिए।

कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर, उनसे अधिक से अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रहती थी। इसी कारण कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनावों को झेलने को बाध्य होना पड़ा। **राजस्व व्यवस्था** की शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा है। राजस्व की निश्चित राशि

बॉक्स 1.2 पूर्व ब्रिटिश काल में कृषि

सत्रहवीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री बर्नीयर ने तत्कालीन बंगाल का इस प्रकार वर्णन किया है – “अपने दो बार के भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संगृहीत जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यह क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। यहाँ से सूती रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। यहाँ अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूँ, सब्जियाँ, अनाज, मुर्गे-मुर्गियाँ, बत्तख आदि का भरपूर उत्पादन होता है। यहाँ सूअरों के बड़े-बड़े झुंड तथा भेड़ बकरियों के विशाल झुंड भी विद्यमान हैं। इस क्षेत्र में हर प्रकार की मछलियाँ प्रचुरता में उपलब्ध हैं। अतीत में राजमहल से लेकर समुद्र तक परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी से (बहुत यत्न और श्रमपूर्वक) काट कर बनाई गई नहरों का जाल सा बिछा हुआ है।”

सरकार के कोष में जमा कराने की तिथियाँ पूर्व निर्धारित थीं। उनके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। साथ ही, प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान रहा है। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी-फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं किंतु उस उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे। क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था। जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल स्वरूप को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्य फसलें उगाना आरंभ किया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए ना ही संसाधन थे, ना तकनीक थी और ना ही कोई प्रेरणा।

सारणी 1.1 : 1946 में फसलों का क्विंटल प्रति हैक्टेयर उत्पादन

देश	चावल	गेहूँ	जौ	मक्का
इटली	41.7	13.3	9.7	15.1
स्पेन	42.2	9.6	12.9	14.8
अर्जन्टिना	33.9	10.0	11.9	22.3
जापान	36.9	9.7	10.7	12.5
भारत	12.3	6.0	7.9	6.2

स्वतंत्रता की पूर्वसंध्या पर भारत में कृषि उत्पादकता में कमी के तथ्य को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता को कई कारकों द्वारा समझाया जा सकता है। जिसमें प्रमुखतः हैं:-

- भूमि पर जनसंख्या का बढ़ रहा दबाव
- भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा कृषि सुधारों की अवहेलना



औपनिवेशिक शासन में कृषि की गतिहीनता

इन्हें कीजिए

- स्वतंत्र भारत के मानचित्र की अंग्रेजी शासन के भारत के मानचित्र से तुलना कर पता लगाइए कि देश का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बन गया ? यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण था ? (इस संदर्भ में डॉ. राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक 'इंडिया डिवाइडेड' का अध्ययन उपयोगी होगा)
- अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार की राजस्व व्यवस्था लागू की ? देश के किस क्षेत्र में कौन सी राजस्व व्यवस्थाएँ लागू की गई और वहाँ उसके क्या प्रभाव रहे ? आपको उन राजस्व व्यवस्थाओं की आज के भारत में कृषि परिदृश्य पर क्या छाप दिखाई देती है ? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए रमेशचंद्र दत्त की दो खंडों में प्रकाशित पुस्तक 'इकनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया' भी उपयोगी रहेगी। इस विषय को अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए आप ब्रिटिश भारत का एक कृषि - मानचित्र बनाने का प्रयास करें। अपने विद्यालय में लगे कंप्यूटर का आप इस कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। स्मरण रखिए कि किसी भी विषय को भली प्रकार समझने-समझाने में मानचित्र का अंकन बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है।

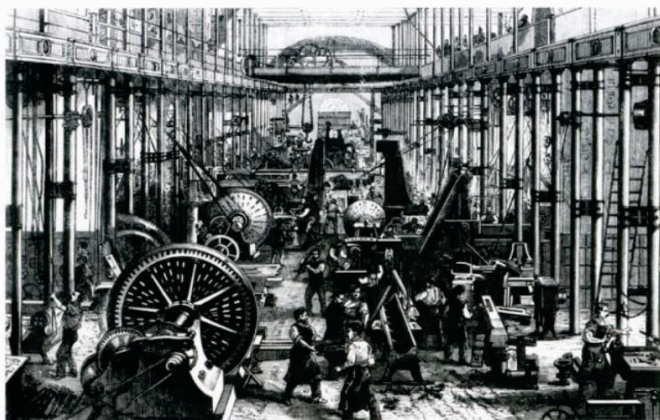
1.3.2 निर्माण/औद्योगिक क्षेत्रक (Industrial Sector)

कृषि की ही भाँति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्पकलाओं का पतन हो रहा था किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। भारत के इस वि-औद्योगीकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। दूसरे, वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश (ब्रिटेन) के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्पकलाओं के पतन से जहाँ एक ओर भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पादन से वंचित भारतीय बाजारों में माँग का भी प्रसार हो रहा था। इस माँग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया।

यद्यपि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी ही रही। प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती कपड़ा मिलें प्रायः भारतीय उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई थीं और ये देश के पश्चिमी क्षेत्रों (आज के महाराष्ट्र और गुजरात) में ही अवस्थित थीं। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। बीसवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लौह और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। टाटा आयरन स्टील कंपनी (TISCO) की स्थापना 1907 में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी, सीमेंट, कागज, आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए।

किंतु भारत में भावी औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूँजीगत उद्योगों का प्रायः अभाव ही बना रहा। पूँजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपूजों का निर्माण करते हैं। यत्र - तत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्प कला

आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्रक की सवृद्धि दर बहुत ही कम थी और सकल घरेलू (देशीय) उत्पाद या सकल वर्धित मूल्य में इसका योगदान भी बहुत कम रहा। इस नए उत्पादन क्षेत्रक की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्रक का कार्यक्षेत्र भी बहुत कम रहा। वास्तव में ये क्षेत्रक प्रायः रेल, बिजली, उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थे।



भारत में ब्रिटिश राज्य के अधीन सूती उद्योग

आजादी की पूर्व संध्या पर नव औद्योगिक क्षेत्रकों की वृद्धि दर अत्यन्त कम थी तथा सकल घरेलू उत्पादन (GDP) में इसका योगदान भी बहुत कम रहा। इस नव उत्पादन क्षेत्रक की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इनमें सार्वजनिक क्षेत्रक का कार्य भी बहुत कम रहा। वास्तव में इस क्षेत्रक से अभिप्राय— रेल, बिजली, उत्पादन, संचार, बंदरगाह व कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित था।

इन्हें कीजिए

- एक तालिका बना कर दर्शाएँ कि भारत में अन्य आधुनिक उद्योग सबसे पहले कहाँ और कब स्थापित हुए। क्या आप यह जानते हैं कि किसी आधुनिक उद्योग की स्थापना के लिए आधारभूत आवश्यकताएँ क्या होती हैं? उदाहरण के लिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में ही क्यों की गई? (यह अब झारखंड राज्य में है)
- आज भारत में कितने लौह और इस्पात कारखाने हैं? क्या ये लौह और इस्पात कारखाने विश्व के श्रेष्ठ संयंत्रों में गिने जाते हैं? क्या इन कारखानों की पुनर्रचना और तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो यह कार्य किस प्रकार हो सकेगा? आजकल यह तर्क दिया जा रहा है कि जो उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण नहीं हैं, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस विषय में आपके क्या विचार हैं?
- भारत के मानचित्र पर उन सूती कपड़ा और पटसन मिलों को अंकित करें जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विद्यमान थी।

1.3.3. सेवा क्षेत्रक (Tertiary Sector)

अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्रक की महत्वता यह है कि वह घरेलू एवं विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान डालते हैं। हालांकि सेवा क्षेत्रक में श्रम बल की संख्या में वृद्धि के साथ कृषि में श्रम बल की भागेदारी में वृद्धि हुई है। औपनिवेशिक काल के समय कृषि व औद्योगिक क्षेत्रकों के अतिरिक्त कुल श्रम बल का लगभग 17.2% ही अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्रक में कार्यरत था।



कृषि क्षेत्रक



औद्योगिक क्षेत्रक



सेवा क्षेत्रक

बॉक्स 1.3 स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार

स्वेज नहर उत्तर पूर्वी मिस्र में स्वेज स्थल संधि के आर - पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाला कृत्रिम जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर की मिस्र पत्तन पोर्ट साईट को लाल सागर की एक प्रशाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है। इस नहर से अमेरिका और यूरोप से आने वाले जलयानों को दक्षिण एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा प्रशांत महासागर तटवर्ती देशों के लिए एक छोटा और सीधा जलमार्ग सुलभ हो गया है। अब उन्हें अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। स्वेज नहर आज आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। वर्ष 1869 में इसके खुल जाने से परिवहन लागतें बहुत कम हो गईं और भारतीय बाजार तक पहुँचना सुगम हो गया।

1.4 व्यवसायिक संरचना (Occupational Structure)

औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रम की श्रमिकों के अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था जिसमें 70-75% जनसंख्या लगी हुई थी। उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रों में लगभग 15 प्रतिशत व 20 प्रतिशत जनसंख्या को रोजगार मिला हुआ था। क्षेत्रीय विभिन्नताओं में वृद्धि एक बड़ा पक्ष रहा है। उस समय मद्रास प्रेजीडेंसी (आज के तमिलनाडु, आंधरा, कर्नाटक व केरल प्रांतों के क्षेत्र), मुंबई तथा बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्य बल की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। निर्माण व सेवा क्षेत्रों के महत्व में धनात्मक रूप से वृद्धि हो रही थी। परन्तु उस समय में पंजाब, राजस्थान व उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में कार्यरत श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि देखी गई।

1.5 जनसांख्यिकीय संरचना (Demographic Structure)

ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएँ थीं फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या संवृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक दस वर्ष बाद जनगणना होती रही। वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जनसांख्यिकीय परिवर्तन के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है। किंतु उस समय तक ना तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और ना ही उसकी संवृद्धि दर बहुत अधिक थी।

सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर तो 16 प्रतिशत से भी कम ही थी। इसमें महिला साक्षरता दर नगण्य थी। यह केवल 7 प्रतिशत आँकी गई थी। जन-

स्वास्थ्य सेवाएँ तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थीं। जहाँ ये सुविधाएँ उपलब्ध थीं, वहाँ नितांत ही अपर्याप्त थी। परिणामस्वरूप, जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था, उनसे व्यापक जन – हानि होना एक आम बात थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊँची थी। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 33 प्रति हजार हो गई है, पर उस समय तो ये दर 218 प्रति हजार थी। जीवन प्रत्याशा दर भी आज के 69 वर्ष की तुलना में केवल 32 वर्ष ही थी। विश्वस्त आँकड़ों के अभाव में यह कह पाना कठिन है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी, परिणामस्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और बदतर हो गई।

1.6 निष्कर्ष (Conclusion)

स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। कृषि क्षेत्रक पहले से ही अत्यधिक श्रम – अधिशेष के भार से लदा था। उसकी उत्पादकता का स्तर भी बहुत कम था। औद्योगिक क्षेत्रक भी आधुनिकीकरण वैविध्य, क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की माँग कर रहा था। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारिक संरचनाओं में उन्नयन, प्रसार तथा जनोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापक गरीबी और बेरोज़गारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को जनकल्याणोन्मुखी बनाने का आग्रह कर रही थीं। संक्षेप में, देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ बहुत अधिक थीं।

गतिविधि

अब भी कई क्षेत्रों में यह धारणा मजबूत है कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए लाभकारी था। इस धारणा के संबंध में जानकारी एकत्र करें व कक्षा में चर्चा करें। आप का इस धारणा के प्रति क्या दृष्टिकोण होगा। अपनी कक्षा में ब्रिटिश शासन के भारत पर अच्छे और बुरे प्रभावों पर चर्चा करें।

पुनरावर्तन (Recap)

- स्वतंत्रता के बाद की आर्थिक विकास की उपलब्धियों को सही रूप में समझ पाने के लिए स्वतंत्रता पूर्व की अर्थव्यवस्था की सही जानकारी की आवश्यकता है।
- औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीतियाँ शासित देश और वहाँ के लोगों के आर्थिक विकास से प्रेरित नहीं थीं, उनका ध्येय तो इंग्लैंड के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन था।
- भले ही भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि से ही अपनी आजीविका पाता था, किंतु कृषि क्षेत्रक गतिहीन ही रहा – इसमें ह्रास के ही प्रमाण मिले हैं।
- भारत में अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण भारत के विश्व प्रसिद्ध हस्तकला उद्योगों का पतन होता रहा और उनके स्थान पर किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं हो पाई।

- पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, बार – बार प्राकृतिक आपदाओं और अकाल ने जनसामान्य को बहुत ही निर्धन बना डाला और इसके कारण भारत में उच्च मृत्युदर थी।
- अपने औपनिवेशिक हितों से प्रेरित होकर विदेशी शासकों ने आधारिक संरचना सुविधाओं को सुधारने के प्रयास किए थे परंतु इन प्रयासों में उनका निहित स्वार्थ था।

●●● अभ्यास ●●●

1. बहु-वैकल्पिक प्रश्न (Multiple Choice Questions)

- (i) भारत देश कब आजाद हुआ ?

क) 15 अगस्त 1947	ख) 26 जनवरी 1947
ग) 15 अगस्त 1948	घ) 26 जनवरी 1948
- (ii) ब्रिटिश – शासन के अधीन भारत की पूर्ति करने वाला था।

क) तैयार माल	ख) पूंजीगत – वस्तुएं
ग) कच्चा माल	घ) उपभोग वस्तुएं
- (iii) निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्रक का उदाहरण नहीं है ?

क) कृषि	ख) खानें
ग) बैंकिंग	घ) मच्छली पकड़ना
- (iv) निम्न में से कौन सा सेवा क्षेत्र का उदाहरण नहीं है ?

क) व्यापार	ख) जंगलात
ग) वित्त	घ) बालों की सजावट
- (v) बस्तीवाद के समय के दौरान जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि के कार्य में लगा हुआ था?

क) 10%	ख) 15-20%
ग) 70-75%	घ) 90%
- (vi) जागीरदारी प्रथा के अधीन सब से अधिक पीड़ित कौन था ?

क) ज़मींदार	ख) किसान
ग) सरकार	घ) इन में से कोई नहीं
- (vii) 1946 में भारत में गेहूं का उत्पादन (कुअंटलों में) कितना था ?

क) 12.3	ख) 6.0
ग) 7.9	घ) 6.2
- (viii) निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बर्तानिया से भारत बस्तीवादी शासन के अधीन आयात की जाती थी?

क) सूती कपड़े	ख) ऊनी कपड़े
ग) पूंजीगत वस्तुएं	घ) सभी वस्तुएं (क, ख, ग)

- (iv) भारत में बस्तीवादी सरकार द्वारा अपनायी गई आर्थिक नीतियों का क्या उद्देश्य था ?
- (v) बस्तीवाद दौरान भारत की कृषि में गत्यावरोध (Stagnation) के मुख्य कारण कौन से थे ?
- (vi) स्वतन्त्रता पूर्व भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रभावी व्यवस्थित औद्योगीकरण के पीछे दो पक्षीय उद्देश्य क्या थे ?
- (vii) 'परम्परावादी दस्तकारी उद्योग ब्रिटिश-शासन के अधीन बर्बाद हो गये थे।' क्या आप इस विचार से सहमत हो ? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताओ।
- (viii) ब्रिटिश भारत में बुनियादी ढांचे सम्बन्धित विकास नीतियों द्वारा कौन से उद्देश्य को प्राप्त करने का इरादा रखते थे ?
- (ix) ब्रिटिश बस्तीवादी शासन द्वारा अपनायी गई औद्योगिक नीति की कुछ कमियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करो।

5. दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न (Long Answer Questions)

- (i) भारत की स्वतंत्रता पूर्व व्यावसायिक संरचना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें।
- (ii) स्वतन्त्रता के समय भारत के समक्ष आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें।
- (iii) ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत भारत के कृषि क्षेत्र की दशा का वर्णन करें।
- (iv) भारत में अंग्रेजों की औद्योगिक नीति क्या थी व्याख्या करें।

प्रस्तावित अतिरिक्त गतिविधियां (Suggested Additional Activities)

उन वस्तुओं तथा सेवाओं की सूची तैयार करो जो स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध थी। इन की तुलना आज कल के लोगों द्वारा कुछ ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं की खपत के नमूने से करो। लोगों की जीवन स्तर में अनुभावित अन्तर को स्पष्ट करो।

स्वतन्त्रता पूर्व से सम्बन्धित आस पास के कसबों और गांवों के चित्र ढूंढें तथा उन की वर्तमान स्थिति से तुलना करो। आप कौन - कौन सी तबदीलियों को चिह्नित कर सकते हो ? क्या ऐसे परिवर्तन अच्छे या बुरे के लिए हैं ?

अपने अध्यापक के साथ अपने आस पास के सामाजिक तथा आर्थिक माहौल का अध्ययन करो तथा जानने का प्रयत्न करो कि क्या भारत में जागीरदारी - प्रथा सचमुच खत्म हो गई है ? इस के सम्बन्ध में एक समूह चर्चा का आयोजन करें। यदि इस सम्बन्धी विचार नकरात्मक प्राप्त होते हैं तो इसे खत्म करने के लिए कौन - 2 से उपाय सोचोगे तथा क्यों ?

आजादी से पूर्व देश के लोगों द्वारा अपनाये गये प्रमुख व्यवसाय कौन से थे ? सुधार सम्बन्धित नीतियों के परिपेक्ष्य में आप अब से 15 वर्ष पश्चात भारत में व्यवसायमुखी दृश्य की कल्पना कैसे करोगे ?

REFERENCES

- BADEN-POWELL, B.H. 1892. The Land Systems of British India, Vols I, II and III. Oxford Clarendon Press, Oxford
- BUCHANAN, D.H. 1966. Development of Capitalist Enterprise in India. Frank Cass and Co, London
- CHANDRA, BIPAN. 1993. "The Colonial Legacy" in BimalJalan (Ed.), The Indian Economy: Problems and Prospects. Penguin Books, New Delhi
- DUTT, R.C. 1963. Economic History of India, Vols I and II. Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, New Delhi
- KUMAR, D. AND MEGHNAD DESAI (Eds.). 1983. Cambridge Economic History of India. Cambridge University Press, Cambridge
- MILL, JAMES. 1972. History of British India. Associated Publishing House, New Delhi.
- PRASAD, RAJENDRA. 1946. India Divided. Hind Kitabs, Bombay
- SEN, AMARTYA, 1999. Poverty and Famines. Oxford University Press, New Delhi. Government Reports Economic Survey (for various years). Ministry of Finance, Government of India
- FIRST FIVE YEAR PLAN 1951-56 ,1952. Planning Commission, New Delhi



2

भारतीय अर्थव्यवस्था 1950–1990

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप

- योजनाबंदी के महत्त्व के बारे में जानेंगे ;
- योजनाबंदी के प्रभावशाली तरीकों को सिखोगे और योजनाबंदी को व्यवहारिकता में अपनायेंगे ;
- वर्ष 1950 से 1990 तक विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कृषि, उद्योग में अपनाई गई विकास की नीतियों को समझेंगे ;
- एक नियमित अर्थव्यवस्था के गुणों तथा सीमाओं की विवेचना कर सकेंगे।

अध्याय – 2

भारतीय अर्थव्यवस्था 1950-1990

भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन - सहन के स्तर को ऊँचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नये अवसर उपलब्ध करायेगी।

- प्रथम पंचवर्षीय योजना

2.1 परिचय (Introduction)

15 अगस्त, 1947 के दिन भारत ने स्वतंत्रता की नयी सुबह देखी। अंततः दो सौ वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भाग्य के विधाता बन गए। अब राष्ट्र के नव निर्माण का कार्य हमारे अपने हाथ में था। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ - साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी। विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियाँ हो सकती हैं (देखें बॉक्स 2.1) पर जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा। किंतु वे भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन (खेत और कारखाने) सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे, कोई निजी संपत्ति नहीं थी। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू-स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था।

नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूँजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादी संस्करणों के विकल्प की खोज की मांग की। यद्यपि उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त, किंतु कमियों से मुक्त थी। इसके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी देश होगा जिसके अंतर्गत

इन्हे कीजिए

विश्व में प्रचलित विभिन्न आर्थिक प्रणालियों का एक चार्ट बनाइए। पूँजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची बनाइए।

किसी कृषि फॉर्म पर अपनी कक्षा के साथ भ्रमण की योजना बनाए। कक्षा के सात समूह बनाएँ और प्रत्येक समूह को एक विशेष विषय में जानकारी एकत्र करने का काम सौंप दें। उदाहरण के लिए इस भ्रमण का उद्देश्य, इसमें खर्च होने वाला समय तथा संसाधन, साथ जाने वाले ऐसे व्यक्ति जिनसे संपर्क स्थापित करना है, भ्रमण के स्थानों के नाम, पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न, आदि। अपने शिक्षक की सहायता से इन विशिष्ट उद्देश्यों का संग्रह कीजिए तथा ऐसे कृषि फार्म के भ्रमण की सफलता के दीर्घकालिक उद्देश्यों से उनकी तुलना कीजिए।

निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनायेगी (देखें बॉक्स 2.2) निजी क्षेत्रक को भी योजना प्रयास का एक अंग बनने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। 1948 का उद्योगिक नीति प्रस्ताव और भारतीय संविधान के 'नीति निर्देशक सिद्धांत' इस दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई जिसके मुखी प्रधानमंत्री थे। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं का युग शुरू हुआ।

बॉक्स 2.1 आर्थिक प्रणालियों के प्रकार

प्रत्येक समाज को तीन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं:

- देश में किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए?
 - वस्तुएँ और सेवाएँ किस प्रकार उत्पादित की जाएँ? उत्पादक इस कार्य में मानव श्रम का अधिक प्रयोग करें अथवा पूँजी (मशीनों) का?
 - उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच किस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए?
1. इन सभी प्रश्नों का एक उत्तर तो माँग और पूर्ति की **बाज़ार शक्तियों** पर निर्भर करता है। बाज़ार अर्थव्यवस्था में, (जिसे पूँजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं) उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाज़ार में माँग है। यदि कारों की माँग है तो कारों का उत्पादन होगा और साइकिलों की माँग है तो साइकिलों का उत्पादन होगा। यदि श्रम, पूँजी की अपेक्षा सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा और यदि श्रम की अपेक्षा पूँजी सस्ती है, तो उत्पादन की अधिक पूँजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। **पूँजीवादी** अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होता। अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय - क्षमता कितनी है और वे किन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं। अभिप्राय यह है कि खरीदने के लिए जेब में रुपये होने चाहिए। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू को ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं थी, क्योंकि ऐसी व्यवस्था को अपनाने से हमारे देश के अधिकांश लोगों को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर ही नहीं मिल पाता।
 2. समाजवादी समाज इन तीनों प्रश्नों के उत्तर पूर्णतया भिन्न तरीके से देता है। समाजवादी समाज में सरकार ही यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यह माना जाता है कि सरकार यह जानती है कि देश के लोगों के हित में क्या है, इसीलिए लोगों की वैयक्तिक इच्छाओं को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता। सरकार ही यह निर्णय करती है कि वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण किस प्रकार किया जाए। सिद्धांततः यह माना जाता है कि समाजवाद में वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है, उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं। समाजवादी राष्ट्र अपने सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ सुलभ कराता है। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता क्योंकि प्रत्येक वस्तु राज्य की होती है।
 3. अधिकांश अर्थव्यवस्थाएँ मिश्रित अर्थव्यवस्थाएँ हैं अर्थात् सरकार तथा बाज़ार एक साथ इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं, कि क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन हो, तथा किस प्रकार वितरण किया जाए।

मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में बाज़ार उन्ही वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है जिसका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है तथा सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाज़ार सुलभ कराने में विफल रहता है।

बॉक्स 2.2 योजना क्या है ?

योजना इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। योजना के कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं, जिनको एक निश्चित समयावधि में प्राप्त करना होता है। भारत में योजनाएँ पाँच वर्ष की अवधि की होती थी और इसे पंचवर्षीय योजनाएँ कहा जाता था (यह शब्दावली राष्ट्रीय नियोजन में अग्रणी देश पूर्व सोवियत संघ से ही ली गई थी)। वर्ष 2017 तक के योजना प्रलेखों में केवल वर्ष की योजना अवधि में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का ही उल्लेख नहीं किया गया, अपितु उनमें आगामी बीस वर्षों में प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख होता था। इस दीर्घकालिक योजना को परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहते हैं। पंचवर्षीय योजना परिप्रेक्ष्यात्मक योजनाओं के लिए आधार प्रदान करती हैं।

यह तो संभव नहीं होगा कि सभी योजनाओं में परिप्रेक्ष्य योजना के सभी लक्ष्यों को एक समान महत्त्व दिया जाए। वस्तुतः विभिन्न लक्ष्यों में कुछ अंतर्द्वंद्व भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि प्रौद्योगिकी श्रम की आवश्यकता को कम करती है तो आधुनिक प्रौद्योगिकी के शुरू करने के लक्ष्य तथा रोजगार बढ़ाने के लक्ष्य में विरोध हो सकता है। आयोजकों को इस प्रकार के विरोधों का संतुलन करना पड़ता है— यह कार्य इतना सहज नहीं है भारत की विभिन्न योजनाओं में अलग – अलग लक्ष्यों पर बल दिया गया है।

भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ यह नहीं बताती थी कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का कितना उत्पादन किया जाएगा। यह ना तो संभव है और ना ही आवश्यक (पूर्व सोवियत संघ ने यह कार्य करने का प्रयास किया था और वह पूरी तरह विफल रहा)। अतः इतना ही पर्याप्त होता है कि योजनाएँ उन्हीं क्षेत्रों के विषय में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें जिनमें महत्वपूर्ण भूमिका हो, जैसे विद्युत् उत्पादन और सिंचाई आदि। शेष को बाज़ार पर छोड़ दिया जाना ही अधिक श्रेयस्कर रहता है।

2.2 पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य (The Goals of Five-Year Plans)

किसी योजना के स्पष्टतः निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे— संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्त्व दिया गया है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है, जिनको प्राथमिकता दी जानी है। हाँ, योजनाकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि जहाँ तक संभव हो चारों उद्देश्यों में कोई अंतर्विरोध न हो। आइए, योजना के इन लक्ष्यों के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करें।

संवृद्धि (Growth) : इसका अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। इसका अभिप्राय उत्पादक पूँजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार या उत्पादक,

बॉक्स 2.3 महालनोबिस: भारतीय योजनाओं के निर्माता

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में अनेक प्रसिद्ध विचारकों का योगदान रहा है। उनमें सांख्यिकीविद् प्रशांतचन्द्र महालनोबिस का नाम उल्लेखनीय है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सामान्यतः विकासात्मक योजना में एक अति महत्वपूर्ण योगदान है। योजना का काम सही मायने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ। इसमें भारतीय योजना के लक्ष्यों से संबंधित आधारीक विचार दिये गये हैं। यह योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। इसलिए उन्हें भारतीय योजना का निर्माता माना जा सकता है।



महालनोबिस का जन्म 1893 में कलकत्ता (कोलकाता) में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रेसीडेंसी कॉलेज कलकत्ता (कोलकाता) तथा सेंट्रल युनिवर्सिटी, इंग्लैंड में हुई। सांख्यिकी विषय में उनके योगदान के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। 1945 में उन्हें ब्रिटेन की एक सोसाइटी का फेलो (सदस्य) बनाया गया। यह वैज्ञानिकों का एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित संगठन है जिसका सदस्य केवल उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को ही बनाया जाता है।

महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आई.एस. आई) की स्थापना की तथा 'सांख्य' नामक एक जर्नल निकाला जो आज भी सांख्यिकीविदों के लिये परस्पर विचार विमर्श के लिये एक प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है। आज भी आई. एस. आई तथा सांख्य दोनों को ही समस्त विश्व में सांख्यिकीविदों और अर्थशास्त्रियों द्वारा अतिसम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान महालनोबिस ने भारत के आर्थिक विकास के लिए भारत तथा विदेशों से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किये जाने की सलाह दी। कालांतर में इनमें से कुछ अर्थशास्त्रियों को नोबल पुरस्कार मिला। यह इस बात को दर्शाता है कि उन्हें प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान थी। महालनोबिस द्वारा आमंत्रित किये गये अर्थशास्त्रियों में वे लोग भी थे जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाजवादी सिद्धांतों के कटु आलोचक थे। दूसरे शब्दों में वह अपने आलोचकों को सुनने के भी इच्छुक थे। यह उनकी महान विद्वता का द्योतक है।

आज अनेक अर्थशास्त्री महालनोबिस के योजना संबंधी दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं। परंतु भारत को आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिये उन्हें सदैव स्मरण किया जायेगा। सांख्यिकीविद् सांख्यिकीय सिद्धांत में उनके योगदान से लाभ उठाते रहेंगे।

स्रोत: सुखमय चक्रवर्ती, 'महालनोबिस, प्रशांतचन्द्र' इन जोन ईटवैल इट. एल., दी न्यू पालग्रेव डिक्शनरी, इकॉनामिक डेवलपमेंट, डब्ल्यू. डब्ल्यू नार्टन, न्यूयार्क एंड लंदन

बॉक्स 2.4 सेवा क्षेत्रक

देश के विकास के साथ- साथ इसमें एक संरचात्मक परिवर्तन आता है। भारत में तो यह परिवर्तन बहुत विचित्र रहा है। सामान्यतः विकास के साथ - साथ सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश कम होता है और उद्योगों का अंश प्रधान होता जाता है। विकास के उच्चतर स्तर पर पहुँच कर जी. डी. पी. में सेवाओं का अंशदान अन्य दोनों क्षेत्रों से अधिक हो जाता है। भारत में जैसा कि एक गरीब देश में अपेक्षा की जाती है, जी.डी.पी. में कृषि का अंश 50 प्रतिशत से अधिक था। किंतु 1990 में सेवा क्षेत्रक का अंश बढ़कर 40.59 प्रतिशत हो गया - यह कृषि तथा उद्योग दोनों से ही अधिक था। ऐसी स्थिति तो प्रायः विकसित देशों में ही पायी जाती है। 1991 के बाद की अवधि में तो सेवा क्षेत्रक के अंश की संवृद्धि की यह प्रवृत्ति और बढ़ गई। इससे देश में वैश्वीकरण का प्रारंभ हुआ। इसकी चर्चा अध्याय 3 में विस्तार से की जायेगी।

पूँजी तथा सेवाओं की दक्षता में वृद्धि से है। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक संवृद्धि से अभिप्राय विकास का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में निरंतर वृद्धि है। जी.डी.पी. एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। आपने यह अवधारणा दसवीं कक्षा में भी पढ़ी है। यदि जी. डी. पी को एक केक मान लिया जाए तो संवृद्धि का अर्थ इसके आकार में वृद्धि होगा। यह केक बड़ा होगा तो अधिक लोग उपभोग कर पाएँगे। यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है (प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार) तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है।

देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है। ये क्षेत्र हैं - कृषि क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक। इन क्षेत्रों के योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढाँचा तैयार होता है। कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि में कृषि का योगदान अधिक होता है तो कुछ में सेवा क्षेत्रक की वृद्धि इसमें अधिक योगदान करती है। (देखें बॉक्स 2.4)

आधुनिकीकरण (Modernization) : वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेतों की पैदावार बढ़ा सकता है। उसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकती है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण है।

आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है, जैसे यह स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। परंपरागत समाज में नारी का कार्यक्षेत्र घर की सीमाओं तक सीमित मान लिया जाता है। आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभाओं का घर से बाहर - बैंकों, कारखानों, विद्यालयों आदि स्थानों पर प्रयोग किया जाता है और ऐसा करने वाला समाज ही अधिकांशतः समृद्ध होता है।

आत्मनिर्भरता (Self-reliance) : कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक संवृद्धि, अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग के द्वारा कर सकता है। हमारी प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया, जिसका अर्थ है कि उन चीजों के आयात से बचा जाए, जिनका देश में ही उत्पादन संभव था। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। हाल

इन्हें कीजिए

- निम्नलिखित के लिए प्रौद्योगिकी में आए परिवर्तनों पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए।
 - (क) खाद्यान्न उत्पादन
 - (ख) उत्पादन की पैकेजिंग
 - (ग) जन संचार
 - 1990-91 तथा 2018-19 (इसके लिए पृष्ठ संख्या 192 भी देखें) के दौरान भारत द्वारा आयात एवं निर्यात की गई वस्तुओं की सुची बनाइए।
 - (क) इन में क्या अंतर आया है, बताइए।
 - (ख) क्या आपको आत्मनिर्भरता का प्रभाव दिखाई देता है ? चर्चा करें।
- उपर्युक्त विषयों में विस्तृत जानकारी के लिए आप नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण को देख सकते हैं।

ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों द्वारा आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना इस बात को समझाता है। इसके अतिरिक्त यह आशंका भी थी कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूँजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ कर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती थी।

समानता (Equity) : केवल संवृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जनसामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। किसी देश में उच्च संवृद्धि दर और विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हों, केवल धनी लोगों तक ही सीमित न रहें। अतः संवृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ-साथ समानता भी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए और धन संपत्ति के वितरण की असमानताएँ भी कम होनी चाहिए।

आइए, अब यह जानने का प्रयास करें कि 1950 से 1990 तक की अवधि में लागू की गई प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं ने किस प्रकार इन चार लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए तथा कृषि, उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ये प्रयास कहाँ तक सफल रहे। वर्ष 1991 के बाद अपनाई गई नीतियों और विकासात्मक मुद्दों के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे।

2.3 कृषि (Agriculture)

आपने पहले अध्याय में पढ़ा कि औपनिवेशिक शासन काल में कृषि क्षेत्र में न तो संवृद्धि हुई और न ही समता रह पाई। स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं को इन मुद्दों पर विचार करना पड़ा तथा उन्होंने भू-सुधारों तथा उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों के प्रयोग द्वारा भारतीय कृषि में एक क्रांति का संचार किया जिस को हरित क्रांति कहा जाता है।

भू-सुधार (Land Reforms) : स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भू-धारण पद्धति में जमींदार-जागीरदार आदि का वर्चस्व था। ये खेतों में कोई सुधार किये बिना मात्र लगान की वसूली किया करते थे। भारतीय कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता के कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका (यू. एस. ए.) से अनाज का आयात करना पड़ा। कृषि में समानता लाने के लिये भू-सुधारों की आवश्यकता हुई जिसका मुख्य ध्येय जोतों के स्वामित्व

बॉक्स 2.5 स्वामित्व तथा प्रेरणाएँ

‘किसान को भूमि’ की नीति इस विचारधारा पर आधारित है कि यदि किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया जाए तो वे उत्पादन बढ़ाने में अधिक रुचि (उन्हे अधिक प्रेरणा मिलेगी) लेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि भू-स्वामित्व से कृषक को अधिक उत्पादन का लाभ मिलता है। काशतकारों को भूमि में सुधारों की कोई प्रेरणा नहीं होती, क्योंकि अधिक उत्पादन से जमींदार को ही लाभ मिलता है। प्रेरणा प्रदान करने में स्वामित्व के महत्व को बताने के लिये पूर्व सोवियत संघ के किसानों के द्वारा बिक्री हेतु फलों की पैकिंग करने में लापरवाही का उदाहरण दिया जाता है। वे सड़े-गले फलों और ताजे फलों को एक साथ बंद कर देते थे। यह तो हरेक किसान जानता है कि गले फल ताजे फलों को भी खराब कर देते हैं, यदि उन्हें एक साथ पैक किया जाये। इससे किसान को ही हानि होगी, क्योंकि फल बिक नहीं पायेंगे।

अतः प्रश्न उठता है कि सोवियत संघ के किसान ऐसा काम क्यों करते थे जो उनको साफ तौर पर हानि पहुँचाये? इसका अर्थ किसानों के सम्मुख प्रेरणाओं से है, क्योंकि पूर्व सोवियत संघ में किसान भूमि के स्वामी नहीं थे। अतः न उन्हें लाभ होता था और न हानि। स्वामित्व न होने के कारण कृषकों को दक्ष होने की कोई प्रेरणा नहीं होती थी। इससे इस बात की भी जानकारी मिलती है कि अति उपजाऊ, विशाल कृषि क्षेत्र के उपलब्ध होने के बावजूद सोवियत संघ में कृषि क्षेत्र का उत्पादन कम क्यों था ?

स्रोत: थामस सोवेल, बेसिक इकॉनामिक्स: द सिटीजन्स गाइड टू दी इकॉनामी, न्यूयार्क: बेसिक बुक्स 2004 दूसरा संस्करण

में परिवर्तन करना था। स्वतंत्रता के एक वर्ष बाद ही देश में बिचौलियों के उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाये गये। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा (बॉक्स 2.5), बशर्ते उन्हें पर्याप्त पूँजी उपलब्ध कराई जाए। दरअसल समानता को बढ़ाने के लिये भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण एक दूसरी नीति थी। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। इस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों में भू - स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था।

बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा यह था कि लगभग 200 लाख काशतकारों का सरकार से सीधा संपर्क हो गया तथा वे जमींदारों के द्वारा किये जा रहे शोषण से मुक्त हो गए। भू-स्वामित्व से उन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। किंतु बिचौलियों के उन्मूलन तथा कर समानता के लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई। कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदारों ने कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़े-बड़े भूखंडों पर अपना स्वामित्व बनाए रखा। कुछ मामलों में काशतकारों को बेदखल कर दिया गया और भू-स्वामियों ने अपने आपको किसान भू-स्वामी (वास्तविक कृषक) होने का दावा किया। कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धनतम कृषि श्रमिकों (जैसे बटाईदार तथा भूमिहीन श्रमिक) को भूमि-सुधारों से कोई लाभ नहीं हुआ।

अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण कानून में भी बाधाएँ आईं। बड़े जमींदारों ने इस कानून को न्यायालयों में चुनौती दी, जिसके कारण इसे लागू करने में देर हुई। इस अवधि में वे अपनी भूमि निकट संबंधियों आदि के नाम कराकर कानून से बच गये। कानून में भी अनेक कमियाँ थीं, जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने भूमि पर अधिकार बनाए रखने के

लिए लाभ उठाया। केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारें वास्तविक किसान को भूमि देने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध थीं, इसी कारण इन प्रांतों में भू-सुधार कार्यक्रमों को विशेष सफलता मिली। दुर्भाग्यवश, अन्य प्रांतों की सरकारों में इस स्तर की प्रतिबद्धता नहीं थी इसलिए आज तक जोतों में भारी असमानता बनी हुई है।

हरित क्रांति (The Green Revolution) : स्वतंत्रता के समय देश की 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। इस क्षेत्रक में उत्पादकता बहुत ही कम थी, क्योंकि पुरानी औद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था और अधिसंख्य किसानों के पास आधारीक संरचना का भी नितांत अभाव था। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है। यदि मानसून स्तर कम होता था तो किसानों को कठिनाई होती थी, क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं। यह सुविधा कुछ ही किसानों के पास थी। औपनिवेशिक काल का कृषि गतिरोध हरित क्रांति से स्थायी रूप से समाप्त हो गया। हरित क्रांति का तात्पर्य उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों (HYV) के प्रयोग से है, विशेषकर गेहूँ तथा चावल उत्पादन में वृद्धि से। इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों, कीटनाशकों तथा निश्चित जल पूर्ति की भी आवश्यकता थी। इन आगतों का सही अनुपात में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण है। बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वसनीय सुविधाओं और उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि की खरीदारी के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी। अतः हरित क्रांति के पहले चरण में (लगभग 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक) HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। इसके अतिरिक्त, HYV बीजों का लाभ केवल गेहूँ पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया। हरित क्रांति के द्वितीय चरण (1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक) में HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुँचा और कई फसलों को लाभ हुआ। इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। अब भारत अपने खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका या किसी अन्य देश की कृपा पर निर्भर नहीं था।

यदि किसान बाज़ार में बेचने की जगह इस उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग करे तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर, यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाज़ार में बेच सकें, तो अधिक उत्पादन का निश्चय ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। किसानों द्वारा उत्पादन का बाज़ार में बेचा गया अंश ही 'विपणित अधिशेष' कहलाता है। हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूँ और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाज़ार में बेच रहे थे। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में, उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, कमी आई। अपनी कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का भोजन पर खर्च करने वाले निम्न आय वर्गों को कीमतों में इस सापेक्ष कमी से बहुत लाभ हुआ। हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित भण्डार बना सकी जिसे खाद्यान्नों की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता था।

यद्यपि हरित क्रांति से देश बहुत लाभांविता हुआ है पर यह प्रौद्योगिकी पूरी तरह निरापद नहीं है। एक जोखिम यह था कि इससे छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएँ बढ़ने की संभावनाएँ थी क्योंकि केवल बड़े किसान अपेक्षित आगतों को खरीदने में सक्षम थे, जिससे उन्हें हरित क्रांति का अधिकांश लाभ प्राप्त हो जाता था। इसके अतिरिक्त, इन फसलों में कीटनाशकों के आक्रमण की भी संभावनाएँ अधिक होती हैं। ऐसी दशा में इस प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले छोटे किसानों की फसल का सब कुछ नष्ट हो जाता। सौभाग्यवश, सरकार द्वारा किये गये कुछ उपायों के कारण ये आशंकाएँ सत्य साबित नहीं हुई। सरकार ने निम्न ब्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण दिये और



उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी ताकि छोटे किसानों को ये आवश्यक आगते उपलब्ध हो सकें। छोटे किसानों को इन आगतों की प्राप्ति से छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता भी समय के साथ बड़े खेतों की पैदावार के बराबर हो गई। इस प्रकार हरित क्रांति से छोटे-बड़े सभी किसानों को लाभ मिला। सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों की सेवाओं के कारण छोटे किसानों के जोखिम भी कम हो गए जो कीटनाशकों के आक्रमण से उनकी फसलों की बर्बादी का कारण थे। यदि सरकार ने इस प्रौद्योगिकी का लाभ छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास नहीं किये होते तो इस क्रांति का लाभ केवल धनी किसानों को ही मिलता।

1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि से भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया। यह निश्चय ही गौरवपूर्ण उपलब्धि रही है। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू यह रहा है कि 1990 तक भी देश की 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी थी। अर्थशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जैसे-जैसे देश संपन्न होता है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में और उस पर निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। भारत में 1950-90 की अवधि में यद्यपि जी. डी. पी. में कृषि के अंशदान में तो भारी कमी आई है पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं (जो 1950 में 67.50 प्रतिशत थी और 1990 तक घटकर 64.90 प्रतिशत ही हो पाई)। इस क्षेत्रक में इतनी उत्पादन वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा भी संभव थी फिर इस क्षेत्रक में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लगे रहने की क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर यही है कि उद्योग क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक कृषि क्षेत्रक में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए। अनेक अर्थशास्त्री इसे 1950-90 के दौरान अपनाई गई नीतियों की विफलता मानते हैं।

2.4 उद्योग और व्यापार (Industry and Trade)

अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया है कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब उनमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्रक होते हैं। उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं और यह कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। इनसे आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया था। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे। अधिकांश उद्योग सूती वस्त्र, पटसन आदि तक ही सीमित थे। जमशेदपुर और कोलकाता में लौह व

इस्पात की सुप्रबंदित फर्में थीं। यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना था तो हमें ऐसे औद्योगिक आधार का विस्तार करने की आवश्यकता थी जिसमें विविध प्रकार के उद्योग हों।

भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र (Public and Private Sector in Indian Industrial Development)

हमारे नीति-निर्माताओं के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूँजी नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इतना बड़ा बाज़ार भी नहीं था जिसमें से उद्योगपतियों को मुख्य परियोजनाएँ शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता। यद्यपि उनके पास ऐसा करने के लिए पूँजी भी थी। इन्हीं कारणों से सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी। इसका अर्थ यह था कि सरकार उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखेगी जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। निजी क्षेत्र की नीतियाँ सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों की अनुपूरक होंगी और सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभायेगा।

बॉक्स 2.6 कीमतें-संकेतकों के रूप में

आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि बाज़ार में कीमतों का निर्धारण किस प्रकार होता है? यह समझना आवश्यक है कि कीमतें वस्तुओं की उपलब्धता का संकेतक हैं। यदि कोई वस्तु दुर्लभ हो जाती है तो इसकी कीमत बढ़ जाती है और कीमतों के आधार पर उसके प्रयोग के संबंध में सही निर्णय लेने की इसके उपभोक्ताओं को प्रेरणा मिलती है। यदि निम्न पूर्ति के कारण पानी की कीमत बढ़ जाती है तो लोग इसका उपयोग सावधानीपूर्वक करेंगे। उदाहरण के लिए पानी संरक्षण के लिए वह बगीचे में पानी देना बंद कर सकते हैं। जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम शिकायत करते हैं और सरकार पर दोषारोपण करते हैं। परंतु पेट्रोल की कीमत में वृद्धि इसकी अधिक कमी को दर्शाती है और कीमत वृद्धि इस बात का संकेतक है कि पेट्रोल कम मात्रा में उपलब्ध है। यह पेट्रोल का कम उपयोग करने और वैकल्पिक ईंधनों की तलाश की प्रेरणा देता है।

कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सहायिकी कीमतों को वस्तु की पूर्ति का संकेतक नहीं होने देती है। जब बिजली और पानी को सहायिकीयुक्त दरों पर या निःशुल्क प्रदान किया जाता है तो उनकी कमी का ध्यान रखे बिना उनका फिजूल उपयोग किया जाएगा। यदि पानी निःशुल्क प्रदान किया जाएगा तो किसान पानी प्रधान फसलें उगाएँगे, भले ही उस क्षेत्र में जल संसाधनों की कमी हो और इन फसलों से दुर्लभ संसाधन भी कम हो जाएँगे। यदि पानी की कीमत दुर्लभता के अनुसार निर्धारित की जाए, तो किसान क्षेत्र के अनुकूल उपयुक्त फसलें उगाएँगे। उर्वरक कीटनाशकों पर सहायिकी संसाधनों का प्रयोग बढ़ाएगी जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। सहायिकी से फिजूल उपयोग को बढ़ावा मिलता है। प्रेरणा की दृष्टि से सहायिकी पर विचार करें और स्वयं से यह पूछें कि क्या किसानों को निःशुल्क बिजली प्रदान करना आर्थिक दृष्टि से उचित है?

औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956 (IPR 1956) : भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956 को अंगीकार किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। द्वितीय योजना में ही समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया। प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिन पर सरकार का अनन्य स्वामित्व था। दूसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्रक, सार्वजनिक क्षेत्रक के साथ मिल कर प्रयास कर सकते थे परंतु इनमें नई इकाइयों को शुरू करने की एकमात्र जिम्मेदारी राज्य की होती। तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्रक के अंतर्गत आते थे।

यद्यपि निजी क्षेत्रक में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था लेकिन इस क्षेत्रक को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया। नये उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक सरकार से लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लिया जाता था। इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। यदि उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। इसके अतिरिक्त, उन इकाइयों को कुछ रियायतें जैसे, कर लाभ तथा कम प्रशुल्क पर बिजली दी गई। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था।

इन्हें कीजिए

- एक छात्र समूह को किसी कृषि फार्म पर ले जाएँ और प्रयुक्त कृषि विधियों का अध्ययन करें, अर्थात् बीजों की किस्में, उर्वरक, मशीनें, सिंचाई के साधन, संबद्ध लागतें, विपणीय अधिशेष तथा अर्जित आय तैयार करें। यदि विधियों में परिवर्तन की जानकारी कृषक परिवार के किसी बुजुर्ग वृद्ध सदस्य से प्राप्त की जाएगी तो अधिक अच्छा रहेगा। उसके बाद:-
- (क) निष्कर्षों पर अपनी कक्षा में चर्चा करें।
- (ख) विभिन्न उप-समूहों का एक चार्ट बनाएँ जिनमें उत्पादन लागत में परिवर्तन, उत्पादकता, बीजों के प्रयोग, उर्वरकों, सिंचाई के साधनों, समय के प्रयोग, विपणीय अधिशेष और परिवार की आय में परिवर्तनों को दर्शाया गया हो।
- विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, (G-7, G-8 और G-10 देशों) की बैठकों के बारे में समाचार पत्रों की कतरनें एकत्र करें। कृषि सहायिकी पर विकसित और विकासशील देशों द्वारा व्यक्त विचारों पर चर्चा करें।
- इस तालिका में उपलब्ध जानकारी का प्रयोग कर भारत की अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक ढाँचे का एक पाई-चार्ट बनाएँ। दो पाई-चार्ट के आकार में परिवर्तन के संभावित कारणों पर चर्चा करें।

क्षेत्रक	1950-51	1990-91
कृषि	72.1	66.8
उद्योग	10.7	12.7
सेवाएँ	17.2	20.5

वर्तमान उद्योग को भी उत्पादन बढ़ाने या विविध प्रकार के उत्पादन (वस्तुओं की नई किस्मों का उत्पादन) करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक न हो। उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था जब सरकार इस बात से आश्वस्त होती थी कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता है।

लघु उद्योग (Small-Scale Industry) : 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति, जिसे कर्वे समिति भी कहा जाता है, ने ग्राम विकास की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों का प्रयोग किया जाए। लघु उद्योग की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए दिये जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। समय के साथ-साथ निवेश की सीमा भी बदलती रही है। 1950 में लघु औद्योगिक इकाई उसे कहा जाता था, जो पाँच लाख रु. का अधिकतम निवेश करती थी। इस समय फर्में में पाँच करोड़ रु का अधिकतम निवेश किया जा सकता है।

ऐसा माना जाता था कि लघु उद्योग अधिक श्रम-प्रधान होते हैं। अर्थात्, उनमें बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है। अतः वे अधिक रोजगारों का सृजन करते हैं। लेकिन ये बड़ी औद्योगिक फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। यह स्पष्ट है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए बड़ी फर्मों से उनकी रक्षा किये जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए अनेक उत्पादों को लघु उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया गया। ऐसे आरक्षण की कसौटी यह थी कि ये इकाइयाँ उन वस्तुओं के विनिर्माण के योग्य हैं। उन्हें अन्य छूट भी दी गई थीं जैसे, कम उत्पाद शुल्क तथा कम ब्याज दरों पर बैंक-ऋण।

2.5 व्यापार नीति : आयात प्रतिस्थापन (Trade Policy : Import Substitution)

भारत द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबंधित थी। प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता 'अंतर्मुखी व्यापार नीति' थी। तकनीकी रूप से इस नीति को 'आयात-प्रतिस्थापन नीति' कहा जाता है। इस नीति का उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना है। उदाहरण के लिए, विदेश में निर्मित वाहनों का आयात करने के स्थान पर उन्हें भारत में ही निर्मित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाये। इस नीति के अनुसार सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की। आयात संरक्षण के दो प्रकार थे : प्रशुल्क और कोटा। प्रशुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर है। प्रशुल्क लगाने पर आयातित वस्तुएँ अधिक महँगी हो जाती हैं जो वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित करती हैं। कोटे में उन वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट की होती है जिन्हें आयात किया जा सकता है। प्रशुल्क और कोटे का प्रभाव यह होता है कि उनसे आयात प्रतिबंधित हो जाते हैं और विदेशी प्रतिस्पर्धा से देशी फर्मों की रक्षा होती है।

संरक्षण की नीति इस धारणा पर आधारित थी कि विकासशील देशों के उद्योग अधिक विकसित देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं थे। यह माना जाता है कि यदि घरेलू उद्योगों का संरक्षण किया जाता तो समय के साथ वे प्रतिस्पर्धा करना भी सीख सकते थे। हमारे योजनाकारों को भी यह आशंका थी कि यदि आयातों पर प्रतिबंध ना लगाया जाता तो विलासिता की वस्तुओं के आयात पर विदेशी-मुद्रा खर्च होने की संभावना बढ़ जाती। 1980 के दशक के मध्य तक निर्यात-संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं किया गया था।

औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव (Effect of Policies on Industrial Development): प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियाँ वस्तुतः उल्लेखनीय रही हैं। औद्योगिक क्षेत्र की प्रगतियों का अनुपात 1950-51 में 13 प्रतिशत से बढ़कर 1990-91 में 24.6 प्रतिशत हो गया। जी. डी. पी. में उद्योगों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की 6 प्रतिशत वार्षिक संवृद्धि प्रशंसनीय है। भारतीय उद्योग सूची वस्त्र और पटसन तक

ही सीमित नहीं थे। वस्तुतः औद्योगिक क्षेत्रक प्रायः सार्वजनिक क्षेत्रक के कारण विविधतापूर्ण बन गया था। लघु उद्योगों के संवर्धन से उन लोगों को अवसर प्राप्त हुए जिनके पास व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए बड़े फर्मों को प्रारंभ करने हेतु पूँजी नहीं थी। विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति संरक्षण से उन इलेक्ट्रॉनिकी व ऑटोमोबाइल क्षेत्रकों में देशी उद्योगों का विकास हुआ, जिनका विकास अन्यथा संभव नहीं था।

भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्रक द्वारा किए गए योगदान के बावजूद कुछ अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्रक के अनेक उद्यमों के निष्पादन की कड़ी आलोचना की है। इस अध्याय के प्रारंभ में यह प्रस्तावित किया गया था कि शुरू में सार्वजनिक क्षेत्रक की आवश्यकता अधिक थी। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि सरकारी उद्यमों ने कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन (प्रायः उन पर एकाधिकार रखते हुए) जारी रखा, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। दूरसंचार सेवा का प्रावधान किया जाना एक और उदाहरण है। इस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्रक में आरक्षण प्रदान किया गया जबकि देखा गया है कि निजी क्षेत्रक के फर्म भी इस सुविधा को उपलब्ध करा सकते हैं। 1990 के दशक के अंत तक भी प्रतिस्पर्धा न होने के कारण व्यक्ति को टेलीफोन कनेक्शन लेने में लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इसका दूसरा उदाहरण मॉडर्न ब्रेड की स्थापना है जो ब्रेड विनिर्माण करने वाली एक फर्म है जैसे कि निजी क्षेत्रक ब्रेड का निर्माण ही नहीं कर सकता था। 2001 में यह फर्म निजी क्षेत्रक को बेच दी गई। मुख्य बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के योजनाबद्ध तरीके से विकास के चार दशक बाद भी इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया कि (क) केवल सार्वजनिक क्षेत्रक क्या कर सकता है और (ख) निजी क्षेत्रक भी क्या कर सकता है? यद्यपि निजी सार्वजनिक क्षेत्रक होटलों की भी व्यवस्था कर सकता है तथापि सरकार होटल चलाती है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने यह तर्क दिया है कि राज्य को उन क्षेत्रों से हट जाना चाहिए जिनमें निजी क्षेत्रक कार्य कर सकते हैं। सरकार ऐसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर संसाधनों का संकेंद्रण कर सकती है जिन्हें निजी क्षेत्रक उपलब्ध नहीं करा सकते।

अनेक सार्वजनिक क्षेत्रक की फर्मों ने भी भारी नुकसान उठाया था लेकिन उन्होंने काम जारी रखा क्योंकि किसी सरकारी उपक्रम का बंद किया जाना कठिन है। भले ही इसके कारण राष्ट्र के सीमित संसाधनों का निकास होता रहे। इसका अर्थ यह नहीं है कि निजी फर्मों को सदैव लाभ होता ही हो (वास्तव में कुछ सार्वजनिक क्षेत्रक की फर्में मूलतः निजी फर्में थीं जो हानि के कारण बंद होने की कगार पर थीं)। उसके बाद कामगारों की नौकरियों की सुरक्षा के लिए उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बहरहाल, नुकसान उठाने वाली निजी फर्में अपने आप को बनाए रखने के लिए संसाधनों का अपव्यय नहीं होने देंगी।

किसी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस का कुछ बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा दुरुपयोग किया गया। बड़े उद्योगपति नई फर्म शुरू करने के लिए नहीं बल्कि नई प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। परमिट लाइसेंस राज के अत्यधिक नियमन के कारण कुछ फर्में कार्यकुशल नहीं बन पाईं। उद्योगपति अपने उत्पादन के विषय में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में और संबंधित मंत्रालयों में लॉबी बनाने में समय व्यतीत करते थे।

विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण की आलोचना भी इस आधार पर की जा रही है कि यह उस स्थिति के बाद भी जारी रहा जब यह सिद्ध हो चुका था कि इसके लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक होगा। आयातों पर प्रतिबंधों के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता था, जिनका उत्पादन भारतीय उत्पादक करते थे। उत्पादक इस बात से अवगत थे कि उनके पास एक आबद्ध बाजार है, अतः उन्हें अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु कोई प्रेरणा नहीं थी। जब वे घटिया वस्तुओं को ऊँची कीमतों पर बेच सकते थे तब वे उनकी गुणवत्ता में सुधार करने की क्यों सोचते। आयातों की प्रतिस्पर्धा ने हमारे उत्पादकों को और अधिक दक्ष बनने को बाध्य

किया। कुछ अर्थशास्त्रियों का भी मत है कि सार्वजनिक क्षेत्रक का प्रयोजन लाभ कमाना नहीं है बल्कि राष्ट्र के कल्याण को बढ़ावा देना है। इस दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्रक की फर्मों का मूल्यांकन जनता के कल्याण के आधार पर किया जाना चाहिए। उनका मूल्यांकन उनके द्वारा कमाये गये लाभों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। संरक्षण के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि हमें विदेशी प्रतिस्पर्धा से उत्पादनों का संरक्षण तब तक करना चाहिए जब तक धनी राष्ट्र ऐसा करते रहें। इन सभी विरोधों के कारण अर्थशास्त्रियों ने हमारी नीति में परिवर्तन करने का आग्रह किया। अन्य समस्याओं सहित इस समस्या के कारण सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति प्रारंभ की।

भारत सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की जिनमें से कुछेक योजनाएं इस प्रकार हैं -

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. मेक इन इंडिया - 2014 | 2. श्रमेव जयते योजना - 2014 |
| 3. कौशल विकास योजना - 2015 | 4. एसपायर स्कीम - 2015 |
| 5. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना - 2015 | 6. अटल - इनोवेशन मिशन - 2016 |
| 7. स्टार्ट अप इंडिया - 2016 | 8. निर्यात ऋण विकास योजना - 2020 |

भारत में अब तक 12 पंच वर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं जिनका विवरण इस प्रकार है -

भारत में पंच वर्षीय योजनाएं (Five-Year Plans in India)

योजना	समय	सकल घरेलू उत्पादन का लक्ष्य (%)	प्राप्ति दर (%)
प्रथम पंच वर्षीय योजना	1951-1956	2.1	3.6
द्वितीय पंच वर्षीय योजना	1956-1961	4.5	4.3
तीसरी पंच वर्षीय योजना	1961-1966	5.6	2.7
तीन एक वर्षीय योजनाएं	1966-1969	-	-
चौथी पंच वर्षीय योजना	1969-1974	5.7	3.3
पांचवी पंच वर्षीय योजना	1974-1979	4.4	4.8
रोलिंग योजना	1978-1980	-	-
छठी पंच वर्षीय योजना	1980-1985	5.2	5.7
सातवीं पंच वर्षीय योजना	1985-1990	5	6
दो एक वर्षीय योजनाएं	1990-1992	-	-
आठवी पंच वर्षीय योजना	1992-1997	5.6	6.8
नौवीं पंच वर्षीय योजना	1997-2002	6.5	5.4
दसवी पंच वर्षीय योजना	2002-2007	8	7.6
ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना	2007-2012	9	8
बारहवीं पंच वर्षीय योजना	2012-2017	8	7

2.6 नीति आयोग (Niti Aayog) (National Institution for Transforming India)

योजना आयोग ने 1951 से 2017 तक 12 योजनाएं बनाई तथा राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन् 1991 के आर्थिक सुधारों के पश्चात निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होने लगी। विकास को उत्साहित करने के लिए योजनाओं के ढाँचे में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होने लगी। जनवरी – 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की स्थापना के साथ सामूहिक संघवाद के साथ निरंतर विकास को अपनाया गया। यह राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए प्रत्येक प्रांत की प्राथमिकताओं के अनुसार नीति निर्माण कर निरीक्षण व मूल्यांकन भी करता है। नीति आयोग को सरकार का **थिंक-टैंक** भी कहा जाता है।

क्या आप जानते हैं ?

थिंक टैंक किसी संस्था अथवा सरकार द्वारा किसी समस्या पर विचार करने तथा उसका समाधान ढूँढने के लिए एकत्रित विशेषज्ञों का समूह होता है।

नीति-आयोग की रचना (Structure of Niti Aayog)

1. **अध्यक्ष / चेयरपर्सन** : भारत का प्रधानमंत्री
2. **प्रबंधकीय काउंसिल** : सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा सभी केंद्र – शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री/लैफ्टीनेंट गवर्नर।
3. **प्रमुख / चेयर पर्सन** : भारत का प्रधानमंत्री
4. **क्षेत्रीय काउंसिल** : उस विशेष क्षेत्र में आने वाले राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री/लैफ्टीनेंट गवर्नर।
5. **विशेष रूप से आमंत्रित व्यक्ति** : इनमें विशेषज्ञ, अकादमिक विशेषज्ञ तथा विशेष रूप से अनुभवी व्यक्ति होते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

संगठनात्मक ढाँचा (Organizational Structure)

1. **चेयरपर्सन** : भारत का प्रधानमंत्री
2. **उप-चेयर पर्सन** : प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केबिनेट मंत्री स्थायी सदस्य-5 (केंद्रीय अथवा राज्यमंत्री) अस्थायी सदस्य – 2 (प्रमुख युनिवर्सिटियों अथवा अनुसंधान संस्थाओं के विद्वान)
3. **पद के आधार पर सदस्य** : केंद्रीय मंत्रियों से अधिकतम 4 मंत्री
4. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी** : प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सचिव स्तर का अधिकारी
5. **सचिव** : आवश्यकतानुसार

नीति आयोग के लक्ष्य (Objectives of NITI Aayog)

1. राज्यों की पूर्ण भागेदारी के साथ राष्ट्रीय विकास के लिए प्राथमिकताएं व रणनीति विकसित करना।
2. इस तथ्य को महत्व देते हुए कि शक्तिशाली राज्य शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करते हैं – सहयोगी संघवाद को उत्साहित करना।

3. योजनाओं के निर्माण गांव स्तर से आरंभ कर जिलास्तर, फिर राज्य स्तर तथा फिर राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं बनाते हुए नीचे से ऊपर की ओर का दृष्टिकोण अपनाना।
4. इस बात को विश्वसनीय बनाना कि आर्थिक रणनीति में राष्ट्रीय हितों को सम्मिलित किया जाता है।
5. समाज के उन वर्गों की ओर विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक योजनाबंदी निर्माण से अधिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
6. दीर्घकालिक नीति निर्माण करना तथा उनकी प्राप्तियों का निरीक्षण करना।
7. राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ मिलकर ज्ञान, अनुसंधान व उद्यम सहायक प्रणालियों का निर्माण करना।
8. अर्न्त क्षेत्रीय व अन्तर्विभागीय मुद्दों के हाल के लिए एक मंच तैयार करना ताकि योजनाओं को कुशलतापूर्वक लागू किया जा सके।
9. तकनीक का नवीनीकरण एवं साम्प्रथ्य निर्माण करना।
10. कार्यक्रमों को लागू करने की प्रक्रिया का निरंतर निरीक्षण करना व मूल्यांकन करना।

2.7 निष्कर्ष (Conclusion)

प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति उल्लेखनीय रही। हमारे उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की स्थिति की तुलना में विविधतापूर्ण हो गये। हरित क्रांति के परिणामस्वरूप भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। भूमि सुधारों का परिणाम यह हुआ कि घृणित जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया। औद्योगिक क्षेत्र में अनेक अर्थशास्त्री सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन से असंतुष्ट थे। अतिशय सरकारी नियमन के कारण उद्यमवृत्ति अवरुद्ध हो गई। आत्मनिर्भरता के नाम पर भारतीय उत्पादकों का संरक्षण विदेशी प्रतिस्पर्धा से किया गया और इससे उन्हें उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने की प्रेरणा नहीं मिली। भारतीय नीतियाँ अंतर्मुखी थीं जिस से हम एक सशक्त निर्यात क्षेत्रक विकसित करने में विफल रहे। बदलते हुए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के प्रसंग में यह सर्वत्र महसूस किया जा रहा था कि आर्थिक नीति में सुधार करने की आवश्यकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक सफल बनाने के लिए 1991 में एक नई आर्थिक नीति शुरू की गई। इस विषय पर अगले अध्याय में चर्चा की जायेगी।

पुनरावर्तन (Recap)

- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने एक आर्थिक पद्धति की कल्पना की जिसमें समाजवाद और पूँजीवाद की विशेषताएँ सम्मिलित थीं। इसकी परिणति मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल के रूप में हुई।
- सभी आर्थिक योजनाएँ पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही निर्मित की गई हैं।
- पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं—संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता।
- कृषि क्षेत्रक में मुख्य नीतिगत पहल के उपाय थे –भूमि सुधार तथा हरित क्रांति। इन पहलों से भारत को खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिली।
- कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों का अनुपात कम नहीं हुआ जैसी की आशा थी।

- औद्योगिक क्षेत्रक में नीतिगत, 'आयात स्थानापन्न' की नीति ने सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्रक के योगदान में वृद्धि की।
- औद्योगिक क्षेत्रक में एक बड़ी कमी यह थी कि सार्वजनिक क्षेत्रक की कार्य पद्धति कुशल नहीं थी क्योंकि यह घाटे की ओर उन्मुख थी जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्र के सीमित संसाधनों का बहिर्गमन और नुकसान हुआ।

●●● अभ्यास ●●●

1. बहु-वैकल्पिक प्रश्न (Multiple Choice Questions)

- (i) स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने किस किस्म की अर्थव्यवस्था को अपनाया?

(क) समाजवाद	(ख) पूंजीवाद
(ग) मिश्रित अर्थव्यवस्था	(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
- (ii) निम्नलिखित में से कौन सा पंच वर्षीय योजनाओं का सांझा उद्देश्य नहीं है?

(क) विकास	(ख) आत्म-निर्भरता
(ग) गरीबी हटाओ	(घ) समानता
- (iii) वर्तमान में भारत की योजनाओं को कौन बनाता है?

(क) वित्त मन्त्रालय	(ख) योजना आयोग
(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद	(घ) नीति आयोग
- (iv) जी. डी. पी का विस्तार रूप क्या है?

(क) Gross domestic Product	(ख) Gross deviatric Product
(ग) Great domestic Product	(घ) Gross devaluation Price
- (v) भारत की योजनाबन्दी के निर्माता कौन थे?

(क) जवाहर लाल नेहरू	(ख) महात्मा गांधी
(ग) पी. सी. महालोनोबिस	(घ) बी. आर. अंबेदकर
- (vi) आयात से सुरक्षा प्रमुख रूप में द्वारा की गई थी।

(क) टैरिफ तथा कोटा	(ख) आयात तथा निर्यात लायसैंस
(ग) कोटा तथा लायसैंस	(घ) ये सारे ही
- (vii) कौन से राज्यों में भूमि सुधार सफल रहे?

(क) महाराष्ट्र तथा तामिलनाडु	(ख) कर्नाटक तथा पश्चिमी बंगाल
(ग) उत्तर प्रदेश तथा बिहार	(घ) पश्चिमी बंगाल तथा केरल
- (viii) अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित प्रमुख समस्याएँ कौन सी हैं?

(क) क्या पैदा करना है?	(ख) कैसे पैदा करना है?
(ग) किस लिए पैदा करना है?	(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

- (ix) आधुनिकीकरण से अभिप्राय तकनीक तथा में परिवर्तन है।
 (क) भोजन सम्बन्धी आदतें (ख) जीवने जीने का ढंग
 (ग) सामाजिक दृष्टिकोण (घ) ये सभी ही
- (x) नीति-आयोग की स्थापना कब की गई?
 (क) 1950 (ख) 1951
 (ग) 2014 (घ) 2015

2. खाली स्थान भरो: (Fill in the blanks)

- (i) भारत में ऐसी योजनाबन्दी को अपनाया गया जिसमें क्षेत्र की मुख्य भूमिका थी।
 (ii) कृषि क्षेत्र में समानता को उत्साहित करने के लिए भूमि की तय की गई।
 (iii) आयात प्रतिस्थापन की नीति को विदेशी मुकाबले से सुरक्षित रखने के लिए थी।
 (vi) कृषि क्षेत्र में क्रांति के लिए बीजों का उपयोग किया गया।
 (v) आयात की जाने वाली वस्तुओं की अधिकतम मात्रा को दर्शाता है।
 (vi) हरित क्रांति से तथा फसलों का उत्पादन बढ़ गया।
 (vii) नीति आयोग का मुखिया होता है।

3. सही या गलत (True/False)

- (i) जी. डी. पी. में बढौत्तरी आर्थिक विकास को दर्शाती है।
 (ii) जो उद्देश्य कई योजनाओं में चलते रहते हैं वे दीर्घ कालीन उद्देश्य होते हैं।
 (iii) योजना आयोग की स्थापना 1951 में हुई।
 (iv) हरित क्रांति से कृषि उत्पादन की विक्रय योग्यता में बढौत्तरी हुई।
 (v) आयात वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर कोटा कहलाता है।
 (vi) कृषि क्षेत्रक के सुधारों को भूमि सुधार कहा जाता है।
 (vii) औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1955 में पास किया गया।

4. अति लघु प्रश्न:- (इन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दिया जाये) (Very Short Answer Questions)

- (i) अर्थव्यवस्था के भिन्न-भिन्न क्षेत्रको के नाम बताओ।
 (ii) आधुनिकीकरण से क्या अभिप्राय है?
 (iii) भारतीय योजनाओं के सांझे उद्देश्य कौन से हैं ?
 (iv) पहले पड़ाव में हरित-क्रांति किन राज्यों में आई?
 (v) लायसैंसिंग-प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य क्या था?
 (vi) लघु उद्योग कौन से होते हैं?

5. मिलान करो: (Match the following)

(i)	प्रधान मन्त्री	ज्यादा उत्पादन वाले बीज
	कुल घरेलु उत्पाद	वस्तुओं की आयात की जाने वाली मात्रा
	भूमि सुधार	नीति आयोग के चेयरमैन
	ऐच. वाई. जी. बीज	कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किये जाने वाले सुधार
	कोटा	अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में पैदा की जाने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक-मूल्य।

(ii)	भारतीय योजना बंदी का निर्माता	1967-68
	हरित क्रांति	1956
	पहली पंचवर्षीय योजना	1951
	औद्योगिक नीति की अवधारणा	पी. सी. महालोनोबिस

(iii)	पंचवर्षीय योजना	समयकाल
	दूसरी	2007-2012
	पहली	1956-1961
	ग्यारवहीं	2012-2012
	बारहवहीं	1951-1956

6. अति लघु उत्तरीय प्रश्न (Very Short Answer Questions)

- योजना की परिभाषा दो।
- आर्थिक योजनाबंदी से क्या अभिप्राय है?
- ज्यादा उपज देने वाली किस्में (HYV) वाले बीज क्या होते हैं?
- आत्म निर्भरता क्या होती है?
- विक्रय योग्य बढ़ौतरी क्या होती है?
- आयात प्रति स्थापना से क्या अभिप्राय है?
- भूमि सुधार क्या होते हैं?
- आर्थिक विकास का 'नीचे से ऊपर की ओर' दृष्टिकोण क्या होता है?

7. लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Questions)

- भारत ने योजनाबंदी को क्यों अपनाया?
- योजना के लक्ष्य क्या होने चाहियें?

- (iii) योजना के उद्देश्य के रूप में 'समानता के साथ विकास' की व्याख्या करो।
- (iv) भारत जैसे विकासशील, देश के लिए 'आत्म निर्भरता' को योजना के उद्देश्य के तौर पर रखना क्यों जरूरी था?
- (v) क्या योजना के उद्देश्य के रूप में 'आधुनिकीकरण' रोजगार पैदा करने में विरोधाभास पैदा करता है?
- (vi) अर्थव्यवस्था की क्षेत्रीय रचना क्या है? क्या यह जरूरी है कि सेवा क्षेत्रक किसी अर्थव्यवस्था में संवृद्धि करने में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे? तर्क-सहित विचार प्रकट करो।
- (vii) योजनाबंदी के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र को औद्योगिक विकास में अग्रणी भूमिका क्यों दी गई ?
- (viii) इस कथन की व्याख्या करो-“हरित क्रांति ने सरकार को अनाज का भण्डार करने के लिए जरूरत अनुसार अनाज की खरीद करने के योग्य बनाया जो कि घाटे के समय उपयोग में लाया जा सकता था।”
- (ix) हरित क्रांति के लागू होने के बावजूद 1990 तक भारत की 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र में क्यों लगी रही?

8. दीर्घ उत्तरीय वाले (Long Answer Questions)

- (i) आर्थिक योजनाबंदी क्या होती है? भारतीय योजनाबंदी के सांझे उद्देश्यों की चर्चा करें।
- (ii) कृषि क्षेत्र में लागू किये गये भूमि सुधारों की आवश्यकता तथा किस्मों की व्याख्या करो।
- (iii) हरित क्रांति क्या है? इसे क्यों लागू किया गया तथा इससे किसानों को क्या लाभ हुआ? संक्षेप में समझाइये।
- (iv) नीति-आयोग क्या है? इसकी संरचना तथा इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिये।

References

- BHAGWATI, J. 1993. *India in Transition: Freeing the Economy*. Oxford University Press, Delhi
- DANDEKAR, V.M. 2004. *Forty Years After Independence*, in Bimal Jalan, (Ed.). *The Indian Economy: Problems and Prospects*. Penguin, Delhi
- JOSHI, VIJAY. and I.M.D. LITTLE. 1996. *India's Economic Reforms 1991-2001*. Oxford University Press, Delhi
- MOHAN, RAKESH. 2004. *Industrial Policy and Controls*, in Bimal Jalan (Ed.). *The Indian Economy: Problems and Prospects*. Penguin, Delhi
- RAO, C.H. HANUMANATHA. 2004. *Agriculture: Policy and Performance*, in Bimal Jalan, (Ed.). *The Indian Economy: Problems and Prospects*. Penguin, Delhi



इकाई
दो

आर्थिक सुधार (1991) से

चालीस वर्षों के योजना बद्ध विकास के पश्चात् भारत एक दृढ़ औद्योगिक आधार प्राप्त करने के योग्य हो चुका है तथा अन्न उत्पादन में आत्म निर्भर बन गया है। फिर भी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहा करता है। 1991 में भुगतान संतुलन में एक संकट ने देश में आर्थिक सुधारों का आरंभ किया। इस इकाई में इन सुधारों की प्रक्रिया तथा भारत पर इनके प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है।

3

उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण : एक समीक्षा

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप

- 1991 में भारत में आरंभ की गई सुधार नीतियों की पृष्ठभूमि से परिचित होंगे;
- सुधार नीतियों को आरंभ किये जाने की प्रक्रिया को समझेंगे;
- वैश्वीकरण की प्रक्रिया और भारत के लिए इसके निहितार्थ से परिचित होंगे;
- विभिन्न क्षेत्रों पर सुधार प्रक्रिया के प्रभावों को जानेंगे।

अध्याय – 3

उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा

आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्राप्ति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है।

—के. आर. नारायणन (भारत के पूर्व-राष्ट्रपति)

3.1 परिचय (Introduction)

आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया। इसमें पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ एक साथ थी। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इन वर्षों में इस व्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए इतने अधिक नियम-कानून बनाए गए कि उनसे आर्थिक संवृद्धि और विकास की समूची प्रक्रिया ही अवरुद्ध हो गई। अन्य विद्वानों का मत है कि भारत जिसने अपनी विकास-यात्रा लगभग गतिहीनता के स्तर से आरंभ की थी, अब उसमें बचत में संवृद्धि, विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार का विकास जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। तथा कृषि उत्पादन की निरंतर वृद्धि द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो चुकी है।

वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोलियम, आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया **विदेशी मुद्रा भंडार** पंद्रह दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया था। इन सभी कारणों से सरकार ने कुछ नई नीतियों को अपनाया और इसने हमारी विकास रण-नीतियों की संपूर्ण दिशा को ही बदल दिया। इस अध्याय में हम उस आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि, सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर उन नीतियों के प्रभावों पर विचार करेंगे।

3.2 पृष्ठभूमि (Background)

इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। हम जानते हैं कि सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती है। जब व्यय आय से अधिक हो तो सरकार बैंकों, जनसामान्य तथा **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों** से उधार लेने को बाध्य हो जाती है। इस प्रकार वह अपने घाटे का वित्तीय प्रबंध कर लेती है। कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डॉलरों में भुगतान करना होता है और ये डॉलर हम अपने उत्पादन के निर्यात द्वारा प्राप्त करते हैं।

सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता इस अवधि में रही क्योंकि राजस्व कम होने पर भी बेरोज़गारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा। यही नहीं, सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई। जब सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ रहा था और यह स्पष्ट था कि उन क्षेत्रों से किसी शीघ्र प्रतिफल की संभावना नहीं थी तो इसकी आवश्यकता थी कि सरकार अपने बचे हुए राजस्व का बहुत ही सोच-विचार कर प्रयोग करती। बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति के लिये सार्वजनिक उद्यमों से भी अधिक आय अर्जित नहीं हो पा रही थी। कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा अन्य देशों से उधार ली गई **विदेशी मुद्रा** को उपभोग कार्यों पर ही खर्च कर दिया गया। इस प्रकार के अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का न तो कोई प्रयास किया गया और ना ही निरंतर बढ़ते आयात के लिए वित्त जुटाने की दृष्टि से निर्यात संवर्धन पर ही पर्याप्त ध्यान दिया गया।

1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि ऋण व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की संवृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, कि विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने क्षीण हो गए थे की देश की दो सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं का ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। इतना ही नहीं कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता था।

उस स्थिति में भारत ने **अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई. बी. आर. डी.)** जिसे सामान्यतः 'विश्व बैंक' के नाम से भी जाना जाता है और **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष** का दरवाजा खटखटाया। उनसे देश को 7 बिलियन डॉलर का ऋण उस संकट का सामना करने के लिए मिला। किंतु उस ऋण को पाने के लिए इन संस्थाओं ने भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगाई, जैसे, सरकार उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी तथा अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाए जायेंगे।

भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें मान लीं और **नई आर्थिक नीति** की घोषणा की। इस नई आर्थिक नीति में व्यापाक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया। इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी संवृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। इन नीतियों को दो उपसमूहों में विभाजित किया जा सकता है : **स्थायित्वकारी उपाय** तथा **संरचनात्मक सुधार** के उपाय। **स्थायित्वकारी उपाय** अल्पकालिक होते हैं, जिनका उद्देश्य **भुगतान सुतलन** में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना और **मुद्रास्फीति** का नियंत्रण करना था। सरल शब्दों में, इसका अर्थ पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश रखने की आवश्यकता थी। दूसरी ओर, **संरचनात्मक सुधार** वे दीर्घकालिक उपाय हैं जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की अनियमितताओं को दूर कर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना है। इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीतियां प्रारंभ की। इनके तीन उपवर्ग हैं : उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।

3.3 उदारीकरण (Liberalisation)

हमने प्रारंभ में चर्चा की है कि आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम-कानून ही संवृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को 'मुक्त' करने की नीति थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, **आयात-निर्यात नीति**, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में भी आरंभ किए गए थे। किंतु 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियाँ कहीं अधिक व्यापक थीं। आइए, हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए सुधारों की समीक्षा करें। ये क्षेत्र हैं- औद्योगिक क्षेत्रक, वित्तीय क्षेत्रक, कर-सुधार, **विदेशी विनियम बाज़ार**, व्यापार तथा निवेश क्षेत्रक, जिन पर 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया था।

औद्योगिक क्षेत्रक का विनियमीकरण (Deregulation of Industrial Sector) : भारत में नियमन प्रणालियों को अनेक प्रकार से लागू किया गया था (**क**) सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था की, जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने, बंद करने या उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी (**ख**) अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमियों का प्रवेश ही निषेध था (**ग**) कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे और सभी निजी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के निर्धारण तथा वितरण के बारे में भी अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था।

1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों ने इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। एल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिकी विमानन तथा औषधि-भेषज; इन छः उत्पाद श्रेणियों को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब **सार्वजनिक** क्षेत्रक के लिए सुरक्षित उद्योगों में भी केवल, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन की कुछ मुख्य गतिविधियाँ ही बची हैं। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुएँ भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई हैं। अधिकांश उद्योगों में अब बाज़ार को कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई है।

वित्तीय क्षेत्रक सुधार (Financial Sector Reforms) : वित्त के क्षेत्रक में व्यावसायिक और निवेश बैंक, **स्टॉक एक्सचेंज** तथा विदेशी मुद्रा बाज़ार जैसी वित्तीय संस्थाएँ सम्मिलित हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्रक का नियमन रिजर्व बैंक का दायित्व है। भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के कार्यों का नियमन होता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा रख सकता है। यही ब्याज की दरों को नियत करता है। विभिन्न क्षेत्रकों को उधार देने की प्रकृति इत्यादि को भी यही तय करता है। वित्तीय क्षेत्रक सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्रक के नियंत्रक की भूमिका से हटाकर उसे इस क्षेत्रक के एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्रक रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएगा।

सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्रक में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी पदार्पण करने का अवसर दिया। बैंकों की पूँजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74 प्रतिशत कर दी गई। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखाएँ खोल सकते हैं तथा पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्तिसंगत बना सकते हैं। यद्यपि बैंकों को अब देश-विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की भी

अनुमति है-पर खाता धारकों और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रक शक्ति अभी भी रिजर्व बैंक के पास ही हैं। **विदेशी निवेश संस्थाओं** (एफ. आई. आई) तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है।

कर व्यवस्था में सुधार (Tax Reforms) : इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है जिन्हें सामूहिक रूप से **राजकोषीय नीतियाँ** भी कहा जाता है। करों के दो प्रकार होते हैं : प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। **प्रत्यक्ष कर** व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं। 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लागू गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई है। इसके पीछे मुख्य धारणा यह थी कि उच्च कर दरों के कारण ही कर-वंचन होता है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि करों की दरें अधिक ऊँची नहीं हो तो बचतों को बढ़ावा मिलता है और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण दे देते हैं। **निगम कर** की दर जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे-धीरे कम कर दी गई है। **अप्रत्यक्ष करों** में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं जैसे, वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना की जा सके। वर्ष 2016 में, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत एवं सरल बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा **वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम-2016 (जी. एस. टी.-2016)** कानून को पारित किया गया। यह कानून जुलाई 2017 से लागू हुआ। इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने की, कर-वंचन कम होने की तथा 'एक राष्ट्र, एक टैक्स, एक बाजार' का निर्माण होने की आशा है। करदाताओं के द्वारा नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। साथ ही कर की दरों में भी पर्याप्त रूप से कमी की गई है।

विदेशी विनियम सुधार (Foreign Exchange Reforms) : विदेशी क्षेत्रक में पहला सुधार विदेशी विनियम बाजार में किया गया था। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपये का अवमूल्यन किया गया। इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत विदेशी विनियम बाजार में रुपये के मूल्य के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की पहल की गई। अब तो प्रायः बाजार ही विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित कर रहा है।

व्यापार और निवेश नीति सुधार (Trade and Investment Policy Reforms) : अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेशी तथा प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी था।

भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए **आयात के परिमाण को सीमित रखने** की नीतियाँ अपना रहा था। इसके लिए आयात पर कड़े नियंत्रणों और उच्च **प्रशुल्कों** का प्रयोग होता था। ये नीतियाँ कुशलता और स्पर्धा क्षमता को कम करती थी जिससे देश में विनिर्माण उद्योगों की संवृद्धि दर कम हुई। व्यापार नीतियों के सुधारों के लक्ष्य थे : (क) आयात और निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति (ख) प्रशुल्क दरों में कटौती और (ग) आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति। हानिकारक और पर्यावरण संवेदी उद्योगों के उत्पादों को

छोड़, अन्य सभी वस्तुओं पर से **आयात लाइसेंस** व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अप्रैल, 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिए गए। भारतीय वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें **निर्यात शुल्क** से मुक्त कर दिया गया है।

इन्हें कीजिए

- राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, निजी विदेशी बैंक, विदेशी निवेश संसाधन और म्युचुअल फंड का एक-एक उदाहरण दें।
- अपने अभिभावकों के साथ पास के किसी बैंक में जाएँ। देखें और पता करें कि वे किन कार्यों को करते हैं। अपने सहपाठियों से इस विषय में चर्चा करें और इनका एक चार्ट तैयार करें।
- अपने अभिभावकों से ज्ञात करें कि क्या वे कर चुकाते हैं? यदि हाँ, तो वे ऐसा क्यों और कैसे करते हैं?
- क्या आप जानते हैं कि काफी समय तक दुनिया के सभी देश, विदेशी भुगतानों के लिए सोने और चाँदी के भंडार जमा रखते थे? ज्ञात करें कि आज हम अपने विदेशी विनियम रिज़र्व को किस रूप में रखते हैं? आर्थिक सर्वेक्षण, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के माध्यम से यह भी जानने का प्रयास करें कि भारत के पास पिछले साल विदेशी विनियम रिज़र्व कितने थे? निम्न देशों की मुद्राओं के नाम तथा नवीनतम रुपयों में उनकी विनियम दरों की जानकारी भी प्राप्त करें।

देश	मुद्रा	भारतीय रुपयों में विदेशी मुद्रा की एक इकाई का मूल्य
संयुक्त राज्य अमेरिका		
इंग्लैंड		
जापान		
चीन		
कोरिया		
सिंगापुर		
जर्मनी		

3.4 निजीकरण (Privatisation)

इसका तात्पर्य है किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग। सरकारी उद्यम निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार से परिवर्तित हो रहे हैं : (क) सरकार का सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना तथा (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिष्ठानों को सीधे बेच दिया जाना।

किसी सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यमों द्वारा जनसामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को **विनिवेश** कहा जाता है। सरकार के अनुसार, इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था। यह भी अपेक्षा की गई थी कि निजी पूँजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग

इन सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने में प्रभावोत्पादक सिद्ध होगा। सरकार को यह भी आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को भी बढ़ावा मिलेगा।

बॉक्स 3.1 'नवरत्न' और सार्वजनिक उद्यम नीतियाँ

आपने बचपन में सम्राट विक्रमादित्य के राज-दरबार के नवरत्नों के विषय में पढ़ा होगा जो कला, साहित्य और विद्वता के क्षेत्रों के गणमान्य विशिष्टजन थे। नवउदारवादी वातावरण में सार्वजनिक उपक्रमों की कुशलता बढ़ाने, उनके प्रबंधन में व्यवसायीकरण लाने और उनकी स्पर्धा क्षमता में प्रभावी सुधार लाने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का चयन कर उन्हें 'महारत्न, नवरत्न और लघुरत्न' घोषित कर दिया। उन्हें कंपनी के कुशलतापूर्वक संचालन और लाभ में वृद्धि करने के लिए प्रबंधन और संचालन कार्यों में अधिक स्वायत्तता दी गई थी। लाभ कमा रहे उपक्रमों को भी अधिक परिचालन, वित्तीय और प्रबंधकीय स्वायत्तता प्रदान कर दी गई।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योगों को भिन्न पद प्रदान किये गए हैं। भिन्न पद वाले सार्वजनिक उद्योगों के उदाहरण इस प्रकार हैं : (i) महारत्न-(अ) इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और (ब) स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (ii) नवरत्न- (अ) हिन्दुस्तान एैरोनाटिक्स लिमिटेड, (ब) महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (iii) लघुरत्न - (अ) भारत संचार निगम लिमिटेड, (ब) एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया और (स) इंडियन रेलवे क्रेटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड।

लाभ अर्जित कर रहे अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना पहली बार 1950 और 1960 के दशकों में उस समय की गई थी जब सभी सार्वजनिक नीतियाँ आत्मनिर्भरता के विचार से प्रेरित थी। उनकी स्थापना का ध्येय आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करना था ताकि जनसामान्य तक उनका उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन नाममात्र लागत पर पहुँचाया जा सके। इस प्रकार इन कंपनियों को सभी पणधारियों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था।

इस नाम के अलंकरण के बाद से इन कंपनियों के निष्पादन में निश्चय ही सुधार आया है। विद्वानों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों के प्रसार को बढ़ावा देकर इन्हें विश्व-स्तरीय निकाय बनाने में सहायता देने के स्थान पर सरकार ने विनिवेश द्वारा आंशिक रूप से इनका निजीकरण कर दिया है। अभी कुछ समय पहले सरकार ने इन्हें सार्वजनिक स्वामित्व में ही रखने का निर्णय किया है और उन्हें वित्तीय बाजार से स्वयं संसाधन जुटाने और विश्व बाजारों में अपना विस्तार करने के योग्य बनाया है।

सरकार ने कल्पना की थी कि निजीकरण प्रत्यक्ष रूप में विदेशी निवेश (एफ. डी. आई.) के प्रवाह को एक सुदृढ़ प्रेरणा प्रदान कर सकता है।

सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्यकुशलता लिए कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को 'महारत्न', 'नवरत्न' और 'लघुरत्न' का विशेष दर्जा दिया गया है (देखें बॉक्स 3.1)

इन्हें कीजिए

- कुछ विद्वान विनिवेश को सार्वजनिक उद्यमों की कुशलता बढ़ाने के लिए निजीकरण की विश्वव्यापी लहर का नाम दे रहे हैं, तो कुछ का विचार यह है कि ये तो सार्वजनिक संपत्ति का निहित स्वार्थों को बिक्री मात्र हैं। आपका क्या विचार है?
- समाचार पत्रों से नवरत्नों से संबंधित ऐसी 10-15 कतरने एकत्र करें जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं तथा एक पोस्टर बनायें। इन सार्वजनिक उपक्रमों के विज्ञापन और शब्द चिह्न (Logos) एकत्र करें। उन्हें अपनी कक्षा के सूचना-पट पर लगाकर उनके विषय में चर्चा करें।
- क्या आपके विचार से केवल घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों का निजीकरण होना चाहिए? क्यों?
- 'सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के घाटे की भरपाई सरकारी बजट से होनी चाहिए।' क्या आप इस कथन से सहमत हैं? चर्चा करें।

3.5 वैश्वीकरण (Globalisation)

वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, जो एक जटिल परिघटना है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है, जिनका उद्देश्य है विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियों और संपर्क सूत्रों (नेटवर्क) का सृजन होता है। वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगे। यह समग्र विश्व को एक बनाने या सीमामुक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है।

बाह्य प्रापण (Outsourcing): वैश्वीकरण की प्रक्रिया का यह एक विशिष्ट परिणाम है। इसमें कंपनियाँ किसी बाहरी स्रोत (संस्था) से नियमित सेवाएँ प्राप्त करती हैं जिन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था जैसा कि कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन, सुरक्षा आदि। संचार के माध्यमों में आई क्रांति, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने अब इन सेवाओं को ही एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधि का स्वरूप प्रदान कर दिया है। इसी कारण से विदेशों से इन सेवाओं को प्राप्त करने (बाह्य प्रापण) की प्रवृत्ति बहुत सशक्त हो गई है। अब तो ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया प्रतिपादन, अभिलेखांकन, लेखांकन, बैंक सेवाएँ, संगीत की रिकॉर्डिंग, फिल्म संपादन, पुस्तक शब्दांकन, चिकित्सा संबंधी परामर्श और यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी बाह्य स्रोतों के सुपुर्द किया जाने लगा है। अनेक विकसित देशों की कंपनियाँ भारत की छोटी-छोटी संस्थाओं से ये सेवाएँ प्राप्त कर रही हैं। आधुनिक संचार साधनों के माध्यमों जैसे, इंटरनेट आदि से इन सेवाओं से जुड़ी रचनाओं, ध्वनियों और दृश्यों की जानकारी को तुरंत शून्य से नौ तक की संख्याओं में परिवर्तित कर देश ही नहीं बल्कि महाद्वीपों के बाहर तक प्रसारित कर दिया जाता है। अब तो अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ-साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियाँ भारत से ये सेवाएँ प्राप्त करने लगी हैं, क्योंकि भारत में इस तरह के कार्य बहुत कम लागत में और उचित रूप से निष्पादित हो जाते हैं। भारत की निम्न मजदूरी दरों तथा कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता ने सुधारोपरांत इसे विश्व स्तरीय 'बाह्य प्रापण' का एक गंतव्य बना दिया है।

बॉक्स 3.2 विश्वस्तरीय पद-छाप

वैश्वीकरण के कारण अब अनेक भारतीय कंपनियाँ भी विदेशों में अपने पैर फैलाने लगी हैं। उदाहरण के लिए, ओ.एन.जी.सी. विदेश, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक सहायक तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम है जो तेल और गैस की खोज में लगी हुई है और 16 देशों में इसकी उत्पादन परियोजनाएं हैं। टाटा स्टील, 1907 में स्थापित एक निजी कंपनी है जो 26 देशों में कार्यरत है और 50 देशों में अपने उत्पादों को बेचने के लिए दुनिया की शीर्ष दस वैश्विक स्टील कंपनियों में से एक है। यह अन्य देशों में लगभग 50,000 लोगों को रोजगार देती है। एच.सी.एल. टेक्नोलॉजीज, भारत में शीर्ष पांच आई.टी. कंपनियों में से एक है जिसके 31 देशों में कार्यालय हैं और लगभग 15,000 व्यक्ति विदेश में कार्यरत हैं। डॉ. रेड्डीज लैबोरेट्रीज, शुरू में बड़ी भारतीय कंपनियों को दवा के सामान की आपूर्ति के लिए एक छोटी-सी कंपनी थी जो आज दुनिया भर में विनिर्माण संयंत्र और अनुसंधान केन्द्र हैं।

स्रोत : www.rediff.com, दिनांक 14.10.2014

विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation (WTO)) : व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि (GATT) के पेरवर्ती विश्व व्यापार संगठन (WTO) का गठन 1995 में किया गया। उस महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी। उसका ध्येय सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना था। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसी नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना है जिसमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएँ खड़ी नहीं कर पाए। साथ ही, इसका ध्येय सेवाओं के सृजन और व्यापार को प्रोत्साहन देना भी है ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो और पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। विश्व व्यापार संगठन की संधियों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने हेतु वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं के विनिमय को भी स्थान दिया गया है। ऐसा सभी सदस्य देशों के प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधकों को हटाकर तथा अपने बाजारों को सदस्य देशों के लिए खोलकर किया गया है।



चित्र 3.1 बाह्य प्रापण : बड़े शहरों में रोजगार का एक नया अवसर

इन्हें कीजिए

- अनेक विद्वानों का तर्क है कि वैश्वीकरण एक चेतावनी है—इससे अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय सरकार का महत्व ही समाप्त हो जाता है। दूसरे, इसके विरोध में यह तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण एक सुअवसर है क्योंकि यह बाजारों को आपस में प्रतिस्पर्धा का और किसी एक देश को अपना वर्चस्व बनाने का अवसर प्रदान करता है। इस विषय में अपनी कक्षा में वाद-विवाद करें।
- भारत में व्यापारिक सेवाएँ प्रदान करने वाली पाँच कंपनियों की सूची और उनके मुनाफे का चार्ट तैयार करें।
- क्या आपने पिछले वर्ष के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लिया था या अपने शिक्षकों की या किसी अन्य शिक्षक की टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के माध्यम से वीडियो देखे थे? सूचना प्रौद्योगिकी (इन्फ़ॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) से संबंधित अपने अनुभव साझा करें।
- क्या 'कॉल सेंटरों' में रोज़गार स्थायी रूप धारण कर सकता है? नियमित आय कमाने के लिए इन कॉल सेंटरों में काम करने वाले को किस प्रकार के कौशल सीखने होंगे?
- यदि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत जैसे देशों से इसी प्रकार सेवा प्राप्त करती हैं तो उन देशों के वासियों का क्या होगा, जहाँ ये कंपनियाँ स्थित हैं? चर्चा करें।

विश्व व्यापार संगठन के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करते हुए न्यायपूर्ण विश्वस्तरीय व्यापार व्यवस्था के नियमों तथा सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की रचना में सक्रिय भागीदार रहा है। भारत ने व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। इसके लिए इसने आयात पर से अनेक परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए हैं और प्रशुल्क दरों को भी बहुत कम किया है।

सारणी 3.1

सकल घरेलू उत्पाद और प्रमुख क्षेत्रों की संवृद्धि दरें (प्रतिशत में)

क्षेत्रक	1980-91	1992-2001	2002-07	2007-12	2012-13	2013-14	2014-15
कृषि	3.6	3.3	2.3	3.2	1.5	4.2	- 0.2*
उद्योग	7.1	6.5	9.4	7.4	3.6	5	7.0*
सेवाएँ	6.7	8.2	7.8	10	8.1	7.8	9.8*
कुल योग	5.6	6.4	7.8	8.2	5.6	6.6	7.4

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण विभिन्न वर्षों के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

नोट : *सकल वर्धित मूल्य का आकलन सकल घरेलू उत्पादन पर सहायिकी को जोड़कर और अप्रत्यक्ष कर को घटाकर दिया जा सकता है।

कुछ विद्वानों को आशंका है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत की सदस्यता का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि विश्व व्यापार का अधिकांश भाग तो विकसित देशों के बीच ही होता है। उनका यह भी मानना है कि विकसित देश अपने देशों में जहाँ कृषि सहायिकी दिये जाने को लेकर शिकायत करते हैं, वहीं विकासशील देश

अपने बाजारों को विकसित देशों के लिए खोले जाने को मजबूर करने को लेकर छला हुआ महसूस करते हैं। वे देश विकासशील देशों को अपने बाजारों में किसी न किसी बहाने प्रवेश करने से रोकने का प्रयास भी करते रहते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि विश्व व्यापार संगठन तो गरीब देशों को छलने की व्यवस्था मात्र है?



चित्र 3.2 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का भारत के निर्यात में प्रमुख योगदान

3.6 सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा (Indian Economy During Reforms : An Assessment)

अब तो सुधार कार्यक्रम को आरंभ हुए तीन दशक हो चुके हैं। आइए, इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन की समीक्षा करें। अर्थशास्त्री किसी अर्थव्यवस्था की संवृद्धि का मापन सकल घरेलू उत्पाद द्वारा करते हैं।

सारणी 3.1 को देखें 1991 के बाद से भारत में दो दशकों तक सकल घरेलू उत्पाद की लगातार वृद्धि होती रही। सकल घरेलू उत्पाद 1980-91 में 5.6 प्रतिशत से बढ़कर 2007-2012 में 8.2 प्रतिशत हो गई। आर्थिक सुधारों की अवधि में कृषि क्षेत्रक की वृद्धि दर में कमी आयी। जहाँ औद्योगिक क्षेत्रक में उतार-चढ़ाव हुए वहीं सेवा क्षेत्रक में वृद्धि बढ़ गई। इससे यह पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्रक में वृद्धि के कारण हुई है। 2012-15 की अवधि में विभिन्न क्षेत्रकों में 1991 के बाद से होने वाली वृद्धि दरों में रुकावट आयी। जहाँ 2013-14 में कृषि की वृद्धि दर में बढ़ोतरी आयी वहीं बाद के वर्षों में इस क्षेत्रक की वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई। सेवा क्षेत्रक में ऊँची वृद्धि दर बनी रही जो 2014-15 के समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से भी अधिक थी। इस क्षेत्रक में अब तक का उच्च वृद्धि दर 9.8 प्रतिशत रिकार्ड किया गया। औद्योगिक क्षेत्रक में 2012-13 में तेज गिरावट आई, तत्पश्चात् बाद के वर्षों में बढ़ने लगा।

अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी विनिमय रिज़र्व में तेजी से वृद्धि हुई है। विदेशी निवेश (जिसमें **प्रत्यक्ष और संस्थागत विदेशी निवेश** दोनों ही सम्मिलित हैं) 1990-91 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर उठकर 2017-18 में 30 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुँच गया है। भारत के विनिमय रिज़र्व का आकार भी 1990-91 में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 413 बिलियन डॉलर हो गया है। दुनिया में भारत विदेशी विनिमय रिज़र्व के सबसे बड़े धारकों में से एक है।

1991 के बाद में भारत वाहन, कल-पुर्जों, दवा का सामान, इंजीनियरी उत्पादों, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों और वस्त्रादि के एक सफल निर्यातक के रूप में विश्व बाज़ार में जम गया है। बढ़ती हुई कीमतों पर भी नियंत्रण रखा गया है।

इन्हें कीजिए

- पिछले अध्याय में आपने कृषि सहित अनेक क्षेत्रों में आर्थिक सहायता दिये जाने के विषय में पढ़ा होगा। कुछ विद्वानों का कहना है कि कृषि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धाशील बनाने के लिए इस क्षेत्रक को मिल रही सहायिकी को बंद किया जाना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? यदि हाँ, तो यह कार्य कैसे किया जाना चाहिए? कक्षा में चर्चा करें।
- इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और कक्षा में इस पर चर्चा करें :
मूँगफली आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख तेलहन फसल है। आंध्र के अनंतपुर जिले का एक किसान सनदीप अपनी आधा एकड़ भूमि पर मूँगफली की खेती पर 10,000 रुपये खर्च किया करता था। इस लागत में बीज, उर्वरक, श्रम, बैलशक्ति और सामान्य हल पर हुए सभी खर्च सम्मिलित होते थे। औसतन सनदीप को दो क्विंटल उत्पादन प्राप्त हो जाता था जिसे बेचकर वह 7,000 रुपये प्राप्त कर लेता था। अतः वह 10,000 का खर्च कर 14,000 की कमाई कर लेता था। अनंतपुर जिले में अक्सर अकाल पड़ते रहते थे। आर्थिक सुधारों के बाद तो सरकार ने वहाँ किसी बड़ी सिंचाई योजना पर काम करने का विचार भी नहीं किया। अभी कुछ समय पहले अनंतपुर में मूँगफली की फसल किसी बीमारी की चपेट में आ गई। सरकारी व्यय में कमी के कारण अब उस दिशा में शोध और प्रसार कार्य भी शिथिल हो चुके हैं। सनदीप और उसके मित्रों ने कई बार सरकारी अधिकारियों का इस जवाबदेही की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया पर उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। बीज, उर्वरक आदि पर सहायिका भी घटा दी गई। महादेव की उत्पादन लागतों में इस कारण भी वृद्धि हुई। यहीं नहीं, स्थानीय बाज़ार में आयात किए गए सस्ते खाद्य तेलों की तो जैसे बाढ़ सी आ गई है—यह आयात प्रतिबंध हटाने का परिणाम है। सनदीप अब अपना उत्पादन बाज़ार में नहीं बेच पाता—बाज़ार की कीमतें उसकी उत्पादन की लागत को भी पूरा नहीं कर पातीं। सनदीप जैसे किसान को घाटे को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? कक्षा में चर्चा करें।

दूसरी ओर, सुधार कार्यक्रमों द्वारा अपने देश की अनेक मूलभूत समस्याओं का समाधान खोज पाने में विफलता के कारण कड़ी आलोचना भी होती रही है। ये समस्याएँ विशेषकर रोजगार सृजन, कृषि, उद्योग, आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा राजकोषीय प्रबंधन से जुड़ी हैं।

संवृद्धि और रोजगार (Growth and Employment) : यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर में वृद्धि हुई है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि सुधार प्रेरित संवृद्धि ने देश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं किया है। आपको रोजगार और संवृद्धि के विभिन्न आयामों के अंतर्संबंध अगली इकाई में विस्तार से समझाए जाएँगे।

कृषि में सुधार (Reforms in Agriculture) : सुधार कार्यों से कृषि को कोई लाभ नहीं हो पाया है और कृषि की संवृद्धि दर कम होती जा रही है।

1991 के बाद से सुधार अवधि में कृषि क्षेत्रक में सार्वजनिक व्यय विशेषकर आधारिक संरचना अर्थात् सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण, बाजार संपर्कों और शोध-प्रसार आदि पर व्यय में काफी कमी आई है (ध्यान रहे कि हरित क्रांति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी)। साथ ही, उर्वरक सहायिकी की आंशिक समाप्ति ने भी उत्पादन लागतों को बढ़ा दिया है। इसका छोटे और सीमांत किसानों पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही, कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती, कम न्यूनतम समर्थन मूल्यों और इन पदार्थों के आयात पर परिणात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के कारण इस क्षेत्रक की नीतियों में कई परिवर्तन हुए। इसके कारण भारत के किसानों को विदेशी स्पर्धा का भी सामना करना पड़ा है, जिसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

दूसरी तरफ, उत्पादन व्यवस्था निर्यातोन्मुखी हो रही है। आंतरिक उपभोग की खाद्यान्न फसलों के स्थान पर निर्यात के लिए नकदी फसलों पर बल दिया जा रहा है। इससे देश में खाद्यन्नों की कीमतों पर दबाव बढ़ा रहा है।

उद्योगों में सुधार (Reforms in Industry) : औद्योगिक संवृद्धि की दर में भी कुछ शिथिलता आई है। यह औद्योगिक उत्पादों की गिरती हुई माँग के कारण हैं। माँग में गिरावट के कई कारण हैं जैसे, सस्ते आयात, आधारित संरचना में अपर्याप्त निवेश आदि। वैश्वीकरण की व्यवस्था में विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित देशों की वस्तुओं और पूँजी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए खोल देने को बाध्य हुए हैं तथा उन्होंने अपने उद्योगों का आयतित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा का खतरा मोल ले लिया। सस्ते आयातों ने घरेलू वस्तुओं की माँग को प्रतिस्थापित कर दिया है। निवेश में कटौती के कारण, बिजली सहित, आधारिक संरचनाओं की पूर्ति अपर्याप्त ही बनी हुई है। इसी कारण, प्रायः यह समझा जा रहा है कि विदेशियों के माल में बेरोक-टोक आवागमन को सहज बनाकर गरीब देशों के स्थानीय उद्योगों और रोजगार की संभावनाओं के लिए वैश्वीकरण पूरी तरह से बर्बाद करने वाली परिस्थितियों की रचना कर रहा है।

यही नहीं, भारत जैसे गरीब देशों को अभी विकसित देशों में विद्यमान उच्च अप्रशुल्क अवरोधकों के कारण उनके बाजारों में प्रवेश के उपयुक्त अवसर भी नहीं मिल पा रहे हैं। यद्यपि भारत में वस्त्र-परिधान आदि के व्यापार से सभी कोटा आदि के प्रतिबंध हटा दिए हैं पर अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और चीन से इनके आयातों से अपने कोटा प्रतिबंध नहीं हटाए हैं।

विनिवेश (Disinvestment) : प्रतिवर्ष सरकार सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश के कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्ष 1991-92 में उसने विनिवेश द्वारा 2500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था। सरकार उस लक्ष्य से 3040 करोड़ अधिक जुटा पाने में सफल रही। वर्ष 2017-18 में लक्ष्य तो लगभग 1,00,000 करोड़ के विनिवेश का था और उपलब्धि लगभग 1,00,057 करोड़ की रही। इस प्रक्रिया के आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों की परिसंपत्तियों को औने-पौने दामों में निजी व्यापारियों को बेचा जा रहा है। दूसरे शब्दों में, इस प्रक्रिया से सरकार को बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है और सार्वजनिक संपत्ति की एकमुश्त बिक्री करनी पड़ रही है। साथ ही, विनिवेश से प्राप्त राशि का उपक्रमों के विकास के लिए प्रयोग नहीं किया गया, न ही इसे सामाजिक आधारिक संरचनाओं के निर्माण पर खर्च किया गया। यह राशि सरकार के बजट के राजस्व घाटे को कम करने में ही लग गई। क्या आप सोचते हैं कि सरकारी कंपनियों की कार्य कुशलता में सुधार लाने का सबसे अच्छा रास्ता उनकी परिसंपत्तियों के हिस्सों को बेचना है?

सुधार और राजकोषीय नीतियाँ (Reforms and Fiscal Policies) : आर्थिक सुधारों ने सामाजिक क्षेत्रकों में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि पर विशेष रूप से रोक लगा दी है। इस अवधि में कर घटाकर और कर वंचना

नियंत्रित कर राजस्व संग्रह बढ़ाने की नीतियों के यथोचित सकारात्मक प्रभाव भी नहीं मिल पाए हैं। यही नहीं, सीमाशुल्क दरों में कटौती तो सुधार कार्यों का आवश्यक अंग है। अतः उन दरों को बढ़ाकर अधिक राजस्व जुटाने का मार्ग बंद हो चुका है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशकों को कई प्रकार के कर प्रोत्साहन दिए गए हैं, इससे भी कर राजस्व को बढ़ा पाने की संभावनाएँ क्षीण हो गई हैं। इन सबका विकास और जनकल्याण आदि पर होने वाले व्यय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

3.7 निष्कर्ष (Conclusion)

उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण से भारत सहित अनेक देशों पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि वैश्वीकरण को एक सुअवसर की भाँति देखा जाना चाहिए क्योंकि यह विश्व बाजारों में बेहतर पहुँच तथा तकनीकी उन्नयन द्वारा विकासशील देशों के बड़े उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'महत्वपूर्ण' बनने का अवसर प्रदान कर रहा है।

बॉक्स 3.3 'सिरीसिला त्रासदी'

विद्युत क्षेत्र में सुधार बहुत से भारतीय राज्य में नहीं हुये हैं। उन्हें अनुनादित दरों पर बिजली की पूर्ति नहीं की जा रही है। बल्कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी की हुई है। इसका प्रभाव लघु उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों पर पड़ा है। इसका एक उदाहरण आंध्रप्रदेश का हथकरघा उद्योग है। इन उद्योगों में काम कर रहे बुनकरों की मजदूरी बुने गए कपड़े की मात्रा पर आधारित होती है। अतः बिजली में कटौती का अर्थ ऊँची दरों की मार झेल रहे बुनकरों की मजदूरी में भी कटौती है। इससे तो बुनकरों की अजीविका ही संकट में पड़ गई। कुछ वर्षों पहले आंध्र के एक छोटे से कस्बे सिरीसिला में विद्युत करघों पर काम करने वाले 50 बुनकरों को आत्महत्या करने को बाध्य होना पड़ा।

- क्या बिजली की दरें नहीं बढ़ानी चाहिए?
- सुधारों में प्रभावित लघु उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे?

दूसरी ओर, आलोचकों का मत है कि वैश्वीकरण तो अमीर देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक बाजारों पर कब्जा करने की साजिश है। इनके अनुसार वैश्वीकरण से गरीब देशवासियों का कल्याण ही नहीं वरन् उनकी पहचान भी खतरे में पड़ गई है। यह भी बताया जा रहा है कि बाजार प्रेरित वैश्वीकरण से विभिन्न देशों और जन समुदायों के बीच की खाई और विस्तृत हो रही है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में किए गए अनेक अध्ययनों का निष्कर्ष है कि भारत के 1990 का वित्तीय संकट उसकी आंतरिक संरचना में कई भीषण विषमताओं का ही परिणाम था। उस संकट के निदान के लिए बाहरी शक्तियों के परामर्श पर सरकार द्वारा प्रारंभ नीतियों ने उन विषमताओं को और भी गहन बना दिया है। इन्होंने केवल उच्च आयवर्ग की आमदनी और उपभोग स्तर का उन्नयन किया है तथा सारी संवृद्धि कुछ इने-गिने क्षेत्रों तक सीमित रही है। ये क्षेत्र हैं—दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, मनोरंजन, पर्यटन और परिचर्या सेवाएँ, भवन निर्माण और व्यापार आदि। कृषि, विनिर्माण जैसे आधारभूत क्षेत्रक (जो देश के करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं) इन सुधारों से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं।

पुनरावर्तन (Recap)

- भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी विनिमय भंडार में कमी, निर्यात में कमी के साथ-साथ आयात में वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। फलस्वरूप, उत्पन्न वित्तीय संकट के निदान के लिए विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता माँगने पर उनके दबाव के कारण भारत सरकार को 1991 में अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा।
- आंतरिक दृष्टि से उद्योग और वित्तीय क्षेत्रों में व्यापक और दूरगामी सुधार आरंभ किए गए। बाह्य दृष्टि से प्रमुख सुधार विदेशी विनिमय विनियंत्रण में कमी और आयात उदारीकरण रहे।
- सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए इसकी भूमिका को सीमित करने और इसमें निजी उद्यमियों को प्रवेश के अवसर प्रदान करने पर सहमति बनी। इस कार्य के लिए उदारीकरण और विनिवेश की नीतियाँ अपनाई गईं।
- वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव ही है। इसका अर्थ आंतरिक अर्थव्यवस्था को शेष विश्व से और बेहतर जोड़ना है।
- बाह्य प्रापण औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में एक प्रमुख गतिविधि के रूप में उभर रही हैं।
- विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसी नियम आधारित विश्व व्यवस्था की रचना करना है, जिसमें विश्व भर के संसाधनों का इष्टतम उपयोग संभव हो सके।
- सुधारोपरान्त कृषि और उद्योगों की संवृद्धि दर में कुछ गिरावट आई है और सेवा क्षेत्र में उछाल आया है।
- सुधारों से कृषि को लाभ नहीं पहुँचा है। इस क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में निश्चय ही कमी आई है।
- औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में कमी और सस्ते आयातों की बहुतायत के कारण शिथिलता ही आई है।

●●● अभ्यास ●●●

1. बहु-वैकल्पिक उत्तरों वाले प्रश्न (Multiple Choice Questions)

- (i) आर्थिक सुधार 1991 के विशेष-पक्ष हैं:-
- (क) उदारीकरण (ख) निजीकरण
- (ग) विश्वीकरण (घ) उपरोक्त सभी
- (ii) आर्थिक सुधार 1991 अपनाने के कारण थे:-
- (क) विदेशी-मुद्रा भण्डार में कमी
- (ख) सार्वजनिक उद्यमों के खर्च को आमदनी से बढ़ जाना
- (ग) कीमतों में बढ़ौतरी
- (घ) उपरोक्त सभी

- (iii) उदारीकरण-नीति के अर्न्तगत कौन-कौन से सुधार किये गये:-
- (क) औद्योगिक क्षेत्रक को नियन्त्रण मुक्त करना
 - (ख) वित्तीय क्षेत्रक में सुधार
 - (ग) विदेशी विनियम सुधार, व्यापार तथा निवेश-नीति में सुधार
 - (घ) उपरोक्त सभी
- (iv) निजीकरण में सरकारी कंपनियां किस ढंग से निजी कंपनियों में बदल दी जाती हैं:-
- (क) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की मालिकी तथा उनके प्रबंध को सरकार से वापिस लेकर
 - (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को पूरी तरह बेचकर
 - (ग) उपरोक्त दोनों
 - (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
- (v) सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पहचान करते समय उनको निम्न में से कौन सा पद देती है?
- (क) महारत्न
 - (ख) नवरत्न
 - (ग) मिनीरत्न
 - (घ) उपरोक्त सभी
- (vi) विश्वीकरण का उद्देश्य क्या है?
- (क) देश की आर्थिकता को विश्व आर्थिकता से जोड़ना
 - (ख) पूरे विश्व को अर्न्त-निर्भरता तथा एकीकरण की ओर ले जाना।
 - (ग) पूरे विश्व को आर्थिक रूप में खोल देना
 - (घ) उपरोक्त सभी
- (vii) भारत में आर्थिक सुधार लागू करने के बाद-
- (क) सेवा क्षेत्रक में विकास में बढ़ौतरी हुई है
 - (ख) औद्योगिक क्षेत्रक ने 2012-13 के पश्चात् सकारात्मक वृद्धि को दर्शाना शुरू किया
 - (ग) कृषि क्षेत्रक में विकास नाम मात्र ही रहा
 - (घ) उपरोक्त सभी

2. खाली स्थानों वाले प्रश्न (Fill in the Blanks)

- (i) भारत ने समाजवादी आर्थिक प्रणाली तथा आर्थिक प्रणाली के फायदों को जोड़कर मिश्रित-आर्थिक ढांचे को अपनाया है। (पूंजीवादी, लोकतांत्रिक)
- (ii) 1991 में भारत को अपने बाहरी कर्ज से सम्बन्धित का सामना करना पड़ा। (आर्थिक-संकट/राजनैतिक संकट)

- (iii) आर्थिक-सुधार 1991 में शुरू की गई सुधार-नीतियां ज्यादातर थी।
(व्यापक/संकुचित या सीमित)
- (iv) भारत में को भारतीय रिज़र्व बैंक (आर. बी. आई) द्वारा नियन्त्रित किया जाता है।
(वित्तीय क्षेत्रक/निजी क्षेत्रक)
- (v) सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों की भागीदारी (इकुयिटी) के भाग को बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों से किये गये निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। (सरकार/जनता)
- (vi) टाटा सटील 1907 में स्थापित की गई एक कंपनी थी। (सरकारी/निजी)
- (vii) विद्वानों के विचारों के अनुसार सुधारों के नेतृत्व वाले विकास ने देश में रोजगार के जरूरी अवसर है। (पैदा किये/पैदा नहीं किये)
- (viii) बाज़ार द्वारा संचालित विश्वीकरण ने देशों तथा लोगों में आर्थिक-असमनाताओं का दिया है। (बढ़ा दिया/कम कर दिया)

3. सही/गलत उत्तर वाले प्रश्न (True/False Questions)

- (i) 1991 में भारत को अपने बाहरी कर्ज से सम्बन्धित एक आर्थिक-संकट का सामना करना पड़ा।
- (ii) भारत में वित्तीय संकट का आरम्भ 1980 वाले दशक में भारतीय आर्थिकता के अनुकूल-प्रबंध से हुआ।
- (iii) 1991 से पहले औद्योगिक लाइसेंसिंग के तहत उद्योगपतियों को फर्म शुरू करने, फर्म को बंद करने या उत्पादन किये जाने वाले माल की मात्रा का फैसला करने के लिए सरकारी अधिकारियों से कोई आज्ञा लेनी नहीं पड़ती थी।
- (iv) वित्तीय क्षेत्रक में वित्तीय-संस्थाओं, जैसे-व्यापारिक बैंक, निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज संचालन तथा विदेशी मुद्रा बाज़ार शामिल किये जाते हैं।
- (v) विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी।
- (vi) व्यापार-नीति के सुधारों का एक उद्देश्य आयात तथा निर्यात तथा गणनात्मक पाबंदियों को समाप्त करना था।
- (vii) आऊट सोर्सिंग (बाह्य प्रापण) में एक कंपनी बाहरी स्रोतों अर्थात्, ज्यादातर दूसरे देशों से नियमित सेवा किराये पर लेती है, जो पहले देश के अन्दर से प्रदान की जाती थी।
- (viii) नये आर्थिक सुधार अपनाने के बाद घरेलू निर्माता आयातों से मुकाबले का सामना कर रहे हैं।
- (ix) कृषि क्षेत्रक के खाद-सहायिकी को आंशिक तौर पर हटाने से उत्पादन की लागत बढ़ गई है।

4. अति लघु उत्तरीय प्रश्न I (Very Short Answer Questions)

- (i) विश्व व्यापार संगठन से क्या अभिप्राय है?
- (ii) उदारीकरण किसे कहते हैं?
- (iii) निजीकरण किसे कहा जाता है?
- (iv) विश्वीकरण किसे कहते हैं?
- (v) आर्थिक सुधार कब अपनाये गये?
- (vi) विश्व व्यापार संगठन का क्या अर्थ है?
- (vii) आऊट सोर्सिंग (बाह्य प्रापण) से क्या तात्पर्य है?

Q.5. मिलान करें: (Match the following)

- (i) दोनों ओर दिये गये तथ्यों का मिलान करें:

तथ्य	वर्ष
विश्व व्यापार संगठन	1907
नई आर्थिक नीति	1995
वस्तु तथा सेवा कर लागू	1991
टाटा स्टील की स्थापना	2017

- (ii) वर्ष 2014-15 के दौरान दिये गये क्षेत्रों का उनके विकास दर से मिलान करो-

क्षेत्र	विकास दर
कृषि	- 0.2
उद्योग	9.8
सेवा	7.4
कुल घरेलू उत्पाद	7.0

- (iii) दिये गये अलग-अलग वर्षों के दौरान कुल घरेलू उत्पाद की विकास दरों का मिलान करो-

क्षेत्र	विकास दर
2007-12	6.6
2012-13	5.6
2013-14	7.4
2014-15	8.2

6. अति लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Questions)

इन प्रश्नों का उत्तर 30-35 शब्दों में दिया जाये

- (i) उदारीकरण की नीति के तहत अपनाये कोई दो सुधारों के नाम लिखों।
- (ii) निजीकरण की नीति में अपनाये गये सुधारों के नाम लिखों।
- (iii) विश्वीकरण की कोई दो विशेषतायें लिखो।
- (iv) विनिवेश-नीति से क्या तात्पर्य है?
- (v) टैरिफ क्यों लगाये जाते हैं?
- (vi) आर्थिक सुधार अपनाने के बाद कृषि-क्षेत्र की विकास दर पर नोट लिखो।
- (vii) आर्थिक सुधार अपनाने के बाद सेवा क्षेत्र की विकास दर पर नोट लिखो।

7. लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Questions)

- (i) आर्थिक सुधार के तहत अपनायी गयी वित्तीय नीतियों का विवरण करो।
- (ii) आर्थिक सुधारों के मूल्यांकन पर नोट लिखो।
- (iii) भिन्न-भिन्न विद्वानों के विश्वीकरण नीति अपनाने सम्बन्धी क्या विचार हैं?

8. अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न—

- (i) भारत द्वारा 1991 में आर्थिक सुधार क्यों अपनाये गये? विस्तारपूर्वक नोट लिखो।
- (ii) आर्थिक सुधारों का अर्थव्यवस्था के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के विकास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा ? वर्णन करो।

References

Books :

- ACHARYA, S. 2003. India's Economy: Some Issues and Answers. Academic Foundation, New Delhi
- ALTERNATIVE SURVEY GROUP. 2005. Alternative Economic Survey, India 2004-05, Disequalising Growth. Daanish Books, Delhi
- AHLUWALIA, I.J. and I.M.D. LITTLE. 1998. India's Economic Reforms and Development. Oxford University Press, New Delhi
- BARDHAN, PRANAB. 1998. The Political Economy of Development in India. Oxford University Press, Delhi
- BHADURI, AMIT and DEEPAK NAYYAR. 1996. The Intelligent Person's Guide to Liberalisation. Penguin, Delhi
- BHAGWATI, JAGDISH. 1992. India in Transition: Freeing the Economy. Oxford University Press, Delhi

- BYRES, TERENCE J. 1997. The State, Development Planning and Liberalisation in India. Oxford University Press, Delhi
- CHADHA, G.K. 1994. Policy Perspectives in Indian Economic Development. Har-Anand, Delhi
- CHELLIAH, RAJA J. 1996. Towards Sustainable Growth: Essays in Fiscal and Financial Sector Reforms in India. Oxford University Press, New Delhi
- DEBROY, B. and RAHUL MUKHERJI (Eds.). 2004. The Political Economy of Reforms. Bookwell Publication, New Delhi
- DREZE, JEAN and AMARTYA SEN. 1996. India: Economic Development and Social Opportunity. Oxford University Press, New Delhi
- DUTT, RUDDAR AND K.P.M. SUNDARAM. 2005. Indian Economy. S. Chand and Company, New Delhi
- GUHA, ASHOK (Ed.) 1990. Economic Liberalisation, Industrial Structure and Growth in India. Oxford University Press, New Delhi
- JALAN, BIMAL. 1993. India's Economic Crisis: The Way Ahead. Oxford University Press, New Delhi
- JALAN, BIMAL. 1996. India's Economic Policy: Preparing for the Twenty First Century. Viking, Delhi
- JOSHI, VIJAY and I.M.D. LITTLE. 1996. India's Economic Reforms 1991-2001. Oxford University Press, New Delhi
- KAPILA, Uma. 2020. Indian Economy: Performences and Policies. Academic Foundation, New Delhi
- MAHAJAN, V.S. 1994. Indian Economy Towards 2000 A.D. Deep & Deep, Delhi.
- PAREKH, KIRIT and RADHAKRISHNA, 2002, India Development Report 2001-02. Oxford University Press, New Delhi
- RAO, C.H. HANUMANTHA. and HANS LINNEMANN. 1996. Economic Reforms and Poverty Alleviation in India, Sage Publication, Delhi
- SACHS, JEFFREY D., ASHUTOSH VARSHNEY and NIRUPAM BAJPAI. 1999. India in the Era of Economic Reforms. Oxford University Press, New Delhi

Government Reports and Websites

- Economic Survey for various years. Ministry of Finance, Government of India. Published by Oxford University Press, New Delhi

- Tenth Five Year Plan 1997-2002. Vol. 1. Government of India, Planning Commission, New Delhi
- Appraisal Document of Twelfth Five Year Plan 2012-2017, NITI Aayog, Government of India.
- <https://dipam.gov.in>
- Handbook of Statistics on Indian Economy, Reserve Bank of India for various years, Mumbai



4

भारत में मानव पूँजी निर्माण

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप

- मानव संसाधन, मानव पूँजी निर्माण और मानव विकास की अवधारणाओं को समझ सकेंगे;
- मानव पूँजी में निवेश, आर्थिक संवृद्धि और मानव विकास के परस्पर संबंधों को जानेंगे।
- शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय की आवश्यकता को समझ पाएँगे और
- भारत की शैक्षिक उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

अध्याय – 4

भारत में मानव पूँजी का निर्माण

शिक्षा पर निजी और सार्वजनिक निधि के व्यय की सार्थकता का मूल्यांकन केवल उसके प्रत्यक्ष परिणामों के माध्यम से नहीं हो। इसमें निवेश-मात्र ही लोगों को उससे अधिक अवसर उपलब्ध कराने में पर्याप्त होगा, जितना कि वे स्वयं ही प्राप्त कर सकते थे। इनके माध्यम से कितने ही ऐसे व्यक्तियों की अंतर्निहित योग्यताएँ उजागर हो पाती हैं, जो अन्यथा बिना पहचान के ही मर जाते।

-अल्फ्रेड मार्शल

4.1 परिचय (Introduction)

मानव जाति के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करें। ये शायद मनुष्य के ज्ञान-संग्रह करने की और उसका प्रसारण करने की क्षमताएँ ही हैं, जो मनुष्य बातचीत, लोकगीत और बड़े-बड़े व्याख्यानों के माध्यम से करते आ रहे हैं। मनुष्य ने यह शीघ्र जान लिया कि हमें कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए अच्छे प्रशिक्षण तथा कौशल की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि किसी शिक्षित व्यक्ति के श्रम-कौशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होते हैं।



चित्र 4.1 किसानों को समुचित शिक्षा तथा प्रशिक्षण ही खेतों की उत्पादकता में वृद्धि कर सकती है

इसी कारण से पहला, दूसरे की अपेक्षा, अधिक आय का सृजन करता है और आर्थिक समृद्धि में उसका योगदान क्रमशः अधिक होता है। शिक्षा पाने का प्रयास केवल उपार्जन क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता

बल्कि उसके और भी अधिक मूल्यवान लाभ हैं। शिक्षा लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करती है। यह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर विकल्पों का चयन कर पाने के योग्य बनाता है, व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तनों की बेहतर समझ प्रदान करता है और नव परिवर्तनों को बढ़ावा देता है। शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नयी प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी सहायक होती है। देश शिक्षा के अवसरों के विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हैं, क्योंकि यह विकास प्रक्रिया को तेज करती है।

4.2 मानव पूँजी क्या है ? (What is Human Capital ?)

जिस प्रकार एक देश अपने भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखानों जैसी भौतिक पूँजी में परिवर्तित कर सकता है, उसी प्रकार वह अपने छात्र रूपी मानव संसाधनों को नर्स, किसान, अध्यापक, अभियंता और डॉक्टर जैसी मानव पूँजी में भी परिवर्तित कर सकता है। समाज को सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में मानव पूँजी की जरूरत है, जो ऐसे योग्य व्यक्तियों के रूप में अधिक होती है जो पहले स्वयं प्रशिक्षित हो चुके हों और प्रोफेसर्स आदि के रूप में कार्य करने योग्य हों। दूसरे शब्दों में, हमें अन्य मानव पूँजी जैसे-नर्स, किसान, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि को तैयार करने के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों के रूप में बेहतर मानव पूँजी की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि हमें मानव संसाधनों को मानव पूँजी के रूप में परिवर्तित करने के लिए मानव पूँजी निवेश करने की भी आवश्यकता है।

आइए, इन प्रश्नों के माध्यम से मानव पूँजी के अर्थ को कुछ आर्थिक रूप से स्पष्ट जानने का प्रयास करें :

- (क) मानव पूँजी के स्रोत क्या हैं?
- (ख) क्या किसी देश की आर्थिक संवृद्धि और वहाँ की मानव पूँजी में कोई संबंध होता है?
- (ग) क्या मानव पूँजी के निर्माण का संबंध मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है जिसे आमतौर पर मानव विकास के रूप में जाना जाता है?
- (घ) भारत में मानव पूँजी के निर्माण में सरकार की क्या भूमिका हो सकती है?

4.3 मानव पूँजी के स्रोत (Sources of Human Capital)

शिक्षा में निवेश (Investment in Education) : शिक्षा में निवेश को मानव पूँजी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रबंधन तथा सूचना आदि मानव पूँजी के निर्माण के अन्य स्रोत हैं।

इन्हें कीजिए

समाज के अलग-अलग वर्गों से तीन परिवारों का चयन करें और आंकड़े एकत्र करें (क) अति निर्धन (ख) मध्यमवर्गीय तथा (ग) संपन्न। इन परिवारों के लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा पर व्यय की प्रवृत्ति का आकलन करें।

आपके माता-पिता आपकी शिक्षा पर व्यय क्यों कर रहे हैं? व्यक्तियों द्वारा शिक्षा पर व्यय कुछ उसी प्रकार का खर्च है जैसा कि कंपनियाँ निश्चित अवधि में अपने दीर्घकालिक निश्चित लाभ को सुधारने के लिए पूँजीगत वस्तुओं पर करती हैं। इसी प्रकार व्यक्ति अपनी भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर निवेश करता है।

स्वास्थ्य पर व्यय (Expenditure on Health) : शिक्षा की भाँति ही स्वास्थ्य को भी किसी व्यक्ति के साथ-साथ देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आगत माना जाता है। किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कौन

कर सकता है एक बीमार व्यक्ति या एक स्वस्थ व्यक्ति? चिकित्सा सुविधाओं के सुलभ नहीं होने पर एक बीमार श्रमिक कार्य से विमुख रहेगा। इससे उत्पादकता में कमी आएगी। अतः इस प्रकार से स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूँजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान (टीकाकरण), चिकित्सीय आयुर्विज्ञान (बीमारियों के क्रम में उसकी चिकित्सा) तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान (स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता या ज्ञान का प्रसार) और इनके साथ-साथ स्वच्छ पेय जल का प्रावधान आदि पर खर्च होने वाली राशि स्वास्थ्य व्यय के विभिन्न रूप हैं। स्वास्थ्य पर किया गया व्यय स्वस्थ श्रमबल की पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है और इसी कारण यह मानव पूँजी निर्माण का एक स्रोत है।

सेवा के लिए प्रशिक्षण (On the Job Training) : फर्म अपने कर्मचारियों के कार्य-स्थल पर प्रशिक्षण में व्यय करती हैं। इसके कई तरीके हो सकते हैं। फर्म के अपने कार्य स्थान पर ही पहले से काम को जानने वाले कुशलकर्मी कर्मचारियों को काम सिखा सकते हैं। दूसरे, कर्मचारियों को किसी अन्य स्थान/संस्थान में प्रशिक्षण पाने के लिए भेजा जा सकता है। दोनों ही विधियों में फर्म अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कुछ व्यय वहन करती है। इसी कारण से फर्म इस बात पर बल देगी कि प्रशिक्षण के बाद वे कर्मचारी एक निश्चित अवधि तक अवश्य फर्म के पास ही कार्य करें। इस प्रकार फर्म उनके प्रशिक्षण पर किये गये व्यय की उगाही अधिक उत्पादकता से हुए लाभ के रूप में कर पाने में सफल रहती है। कार्य के दौरान प्रशिक्षण पर किया गया व्यय भी इस दृष्टि से मानव पूँजी का स्रोत बन जाता है। ऐसे खर्च की तुलना में श्रम उत्पादकता में वृद्धि से हुए लाभ कहीं अधिक होते हैं।

प्रवास (Migration) : व्यक्ति अपने मूल स्थान की आय से अधिक आय वाले रोजगार की तलाश में प्रवासन/पलायन करते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवासन मुख्यतः गाँवों में बेरोजगारी के कारण ही होता है। तकनीकी शिक्षा संपन्न अभियंता, डॉक्टर आदि भी अच्छे वेतनमानों की अपेक्षा में दूसरे देशों में चले जाते हैं। प्रवासनों की दोनों ही स्थितियों में परिवहन की लागत और उच्चतर निर्वाह लागत के साथ एक अनजाने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने की मानसिक लागतें भी प्रवासी श्रमिकों को सहन करनी पड़ती हैं। किंतु नये स्थान पर उनकी कमाई प्रवास से जुड़ी सभी लागतों से कहीं अधिक होती है। अतः प्रवासन पर व्यय भी मानवीय पूँजी निर्माण का स्रोत है।

सूचना प्राप्ति एवं व्यय (Expenditure on Receiving Information) : व्यक्ति श्रम बाजार तथा दूसरे बाजार जैसे, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए व्यय करते हैं। वे यह जानना चाहते हैं, कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में वेतनमान क्या हैं या फिर क्या शैक्षिक संस्थाएँ सही प्रकार के कौशल में प्रशिक्षण दे रही हैं और किस लागत पर? यह जानकारी मानव पूँजी में निवेश करने से प्राप्त मानव पूँजी के भंडार का सदुपयोग करने की दृष्टि से बहुत उपयोगी होती है। इसीलिए श्रम बाजार तथा अन्य बाजारों के विषय में जानकारी प्राप्त करने पर किया गया व्यय भी मानव पूँजी निर्माण का स्रोत है।

व्यसक शिक्षा कार्यक्रम (Programme for Adult Education) : विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा व्यसक शिक्षा की कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। शिक्षा देने से व्यसकों में काम करने की कुशलता और उत्पादकता में वृद्धि होती है। इस तरह व्यसक शिक्षा कार्यक्रम भौतिक पूँजी निर्माण के एक अच्छे स्रोत के रूप में काम करता है।

भौतिक पूँजी की आवश्यकता के आधार पर ही मानव पूँजी के वैचारिक आधार की रचना की गयी है। दोनों प्रकार की पूँजी के बीच कुछ समरूपताएँ तथा कुछ प्रभावशाली असमानताएँ हैं (देखें बॉक्स 4.1)।

बॉक्स 4.1 भौतिक और मानव पूँजी

दोनों ही प्रकार की पूँजी सुविचारित निवेश निर्णयों का परिणाम होता है। भौतिक पूँजी में निवेश का निर्णय अपने ज्ञान के आधार पर लिया जाता है। इस संबंध में उद्यमी के पास अनेक प्रकार के निवेश विकल्पों की आंतरिक प्रतिफल दर का आकलन कर पाने का ज्ञान होता है। इन गणनाओं के बाद ही वह अपना विवेक आधारित निवेश करता है। भौतिक पूँजी का स्वामित्व उस व्यक्ति के सुविचारित निर्णय का परिणाम होता है—भौतिक पूँजी निर्माण मुख्यतः एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है।

मानव पूँजी के निर्माण का महत्वपूर्ण भाग व्यक्ति के जीवन की उस अवधि में होता है, जब वह यह निर्णय लेने में असमर्थ होता है कि क्या वह अपनी आमदनी को अधिकतम कर पायेगा या नहीं। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित निर्णय उनके अभिभावक तथा समाज ही करते हैं। उनके समकक्षी शिक्षाविद् और समाज उच्चतर स्तरों (महाविद्यालय/विश्वविद्यालय) पर मानव पूँजी में निवेश संबंधी निर्णय को प्रभावित करते हैं। फिर भी इस स्तर पर मानव पूँजी निर्माण, विद्यालय स्तर पर मानव पूँजी निर्माण, पर निर्भर करता है। मानव पूँजी निर्माण आंशिक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है और अंशतः मानव पूँजी को धारण करने वालों के सुविचारित निर्णय का प्रतिफल है।

आप जानते हैं कि बस जैसी भौतिक पूँजी के स्वामी को सदैव वहाँ उपस्थित नहीं रहना होता, जहाँ वह बस यात्रियों/सामान के परिवहन में प्रयुक्त हो। किंतु उस वाहन को चलाने के ज्ञान से संपन्न चालक को वाहन के साथ ही रहना पड़ता है। भौतिक पूँजी किसी भी अन्य वस्तु की भाँति दृश्य होती है। उसे किसी भी वस्तु की तरह बाज़ार में बेचा जा सकता है। मानव पूँजी अदृश्य होती है—यह धारक के शरीर और मस्तिष्क में रची-बसी होती है। बाज़ार में मानव पूँजी को बेचा नहीं जा सकता, केवल उसकी सेवाओं की बिक्री की जा सकती है इसलिए मानव पूँजी के स्वामी को उसके उत्पादन के स्थान पर उपस्थित होना आवश्यक होता है। भौतिक पूँजी को उसके स्वामी से पृथक किया जा सकता है, किंतु मानव पूँजी का स्वामी से पृथक्करण संभव नहीं होता।

दोनों प्रकार की पूँजियों में उनके स्थानों की गतिशीलता के आधार पर अंतर होता है। प्रायः कुछ कृत्रिम अपवादों को छोड़ भौतिक पूँजी का विश्व भर में निर्बाध आवागमन चलता रहता है। किंतु मानव पूँजी का प्रवाह इतना निर्बाध नहीं होता, इसके मार्ग में राष्ट्रीयता और संस्कृति की ऊँची बाधाएँ आ जाती हैं। अतः भौतिक पूँजी का निर्माण तो आयात के सहारे भी हो जाता है, किंतु मानवीय पूँजी की रचना तो समाज तथा अर्थव्यवस्था की अंतर्भूत विशेषताओं के अनुरूप सुविचारित नीति निर्धारण संबंधी निर्णयों तथा सरकार और व्यक्तिगत व्यय के आधार पर होती है। समय के साथ-साथ दोनों ही प्रकार की पूँजियों में मूल्य हास होता है। किसी मशीन के निरंतर प्रयोग से वह घिस जाती है और प्रौद्योगिकीय परिवर्तन उसे पुराना घोषित कर देते हैं। मानव पूँजी में आयु के अनुसार कुछ 'हास' आता है। किंतु शिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर निवेश से उस 'हास' का काफी सीमा तक निराकरण हो सकता है। यह निवेश मानव पूँजी को प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों का सामना करने योग्य भी बना देता है—किंतु भौतिक पूँजी में किसी भी प्रकार से प्रौद्योगिकीय परिवर्तन का सामना करने की क्षमता नहीं आ पाती।

मानव पूँजी द्वारा सृजित हितलाभ के प्रवाह के स्वरूप भी भौतिक पूँजी से अलग होता है। मानव पूँजी से केवल उसका स्वामी ही नहीं वरन् सारा समाज लाभांविता होता है। इसे एक बाह्य हित लाभ कहा जा सकता है। एक सुशिक्षित व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रभावपूर्ण भागीदारी के माध्यम से राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक प्रगति में योगदान करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने वैयक्तिक स्तर पर तथा आस-पास में सफाई आदि के माध्यम से रोगों का संक्रमण रोग उन्हें महामारियों का रूप धारण नहीं करने देता। मानवीय पूँजी से व्यक्तिगत के साथ-साथ सामाजिक हितलाभों का भी सृजन होता है। किंतु भौतिक पूँजी तो प्रायः निजी लाभ को ही जन्म दे पाती है। पूँजीगत पदार्थों के लाभ उन्हीं को मिल पाते हैं जो उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत चुका सकें।

4.4 पूँजी निर्माण की आवश्यकता एवं भूमिका (Need and Role of Human Capital Formation)

किसी भी समाज अथवा राष्ट्र के विकास के लिए मानव पूँजी निर्माण की अत्यंत आवश्यकता होती है क्योंकि अच्छी मानवीय पूँजी ही देश के भौतिक साधनों का उचित प्रयोग करके देश के आर्थिक विकास की गति को तीव्र कर सकते हैं। यदि देश के नागरिक अशिक्षित, रोगी व कौशल रहित होंगे तो वे देश के भौतिक साधनों का श्रेष्ठ प्रयोग नहीं कर सकते। इस लिए भौतिक साधनों का विकास भी मानवीय पूँजी निर्माण पर निर्भर करता है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छी मानवीय पूँजी मिट्टी को भी सोने में बदल सकती है। जब कि बुरी मानवीय पूँजी सोने को भी मिट्टी बना सकता है। देश के आर्थिक विकास में मानवीय पूँजी का योगदान निम्नलिखित अनुसार है—

- **उत्पादकता में वृद्धि (Increase in Productivity) :** मानवीय पूँजी निर्माण के साथ श्रम बल की कुशलता एवं कार्य करने की सामर्थ्य में वृद्धि होती है। एक शिक्षित श्रमिक एक अनपढ़ श्रमिक से मशीन एवं साज समान को बढ़िया ढंग से प्रयोग करता है। ऐसा करने से देश के आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है और उत्पादन पहले से अधिक हो जाता है और साधनों का अपव्यय कम हो जाता है।
- **साधनों का सदुपयोग (Optimum Utilisation of Resources) :** मानवीय पूँजी निर्माण से आधुनिक व प्रगतिशील सोच उत्पन्न होती है। जिससे मानवीय संसाधनों, प्राकृतिक साधनों एवं वित्तीय साधनों का उत्तम उपयोग होना आरम्भ हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक पीढ़ी प्रयास करती है कि वह अपनी तथा आने वाला पीढ़ी के लिए समुचित मात्रा में साधन उपलब्ध करवाए।
- **नवपरिवर्तन एवं अनुसंधान (Innovation and Research) :** इस से अनुसंधान को भी प्रोत्साहन मिला है। भिन्न-भिन्न स्तरों पर आय वृद्धि एवं लागत कम करने के लिए नवपरिवर्तन एवं अनुसंधान के लिये निवेश किया जाता है। वैज्ञानिक व आधुनिक विचार धारा का प्रसार होता है एवम उपलब्ध श्रम बल परिवर्तन तकनीक के अनुसार स्वयं को उसके अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं।

- **गैर आर्थिक लाभ (Non-Economic Benefits) :** मानवीय पूंजी के निर्माण से राष्ट्र में शांति व स्थिरता में वृद्धि होती है। लोगों द्वारा नियमों व नैतिकता का सही ढंग से पालन किया जाता है। लोकतंत्र के प्रति सहभागिता बढ़ जाती है। यह सभी गैर आर्थिक तत्व राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि व विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। मानवीय पूंजी निर्माण ही सामाजिक परिवर्तन के लिए सही दिशा प्रदान करता है।
- **समानता व प्रतिभागिता में वृद्धि (Increase in Equality and Participation) :** श्रम बल की सामर्थ्य, उत्पादकता व कुशलता में वृद्धि होने से श्रम के लिए रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। इससे सामाजिक व आर्थिक स्तर पर समानता में वृद्धि होती है लोगो के जीवन स्तर में सुधार की गति तीव्र होने लगती है।
- **विकास के प्रति सहकारात्मक वातावरण का निर्माण (Formation of Constructive Environment Towards Development) :** जब लोग शिक्षित व स्वच्छ हो जाते हैं तो उनमें सकारात्मक व रचनात्मक भावनाओं विचारों के विकास में वृद्धि होती है। राष्ट्र में आर्थिक विकास के लिए एक अच्छे वातावरण का निर्माण होने लगता है, एवं आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं व रण नीतियों को लागू करने के लिए अधिक कुशल, निपुण व स्वस्थ श्रम बल उपलब्ध होती है।

इन्हें कीजिए

यदि एक निर्माण श्रमिक, नौकरानी, धोबी या फिर स्कूल का चपरासी बीमारी के कारण लंबे समय तक काम पर नहीं आ पाया हो तो जानने का प्रयास करें कि इन पर क्या प्रभाव पड़ा है :

(क) उसके रोजगार की सुरक्षा

(ख) उसकी मजदूरी/वेतन

इन प्रभावों के संभावित कारण क्या होंगे?

बाक्स 4.2 : मानव पूंजी एवं मानव विकास (Human Capital and Human Development)

दोनों शब्द एक जैसे प्रतीत होते हैं परन्तु इनमें व्यापक अंतर है। मानव पूंजी शिक्षा और सेहत को श्रम बल की उत्पादकता बढ़ाने का साधन मानती है जबकि मानवीय विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा व स्वास्थ्य मानवीय कल्याण के अभिन्न अंग हैं क्योंकि जब लोगों के पास पढ़ने लिखने व लम्बी स्वस्थ मानवीय कल्याण के अभिन्न अंग हैं क्योंकि जब लोगों के पास पढ़ने लिखने व लम्बी स्वस्थ जिंदगी जीने की योग्यता होगी तो वे अन्य विकल्पों के चयन करने के योग्य होंगे। जो उनके लिए मूल्यवान हो। मानवीय पूंजी मानव को उत्पादकता में वृद्धि के लिए एक साधन मानती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा व स्वास्थ्य में कोई भी निवेश गैर उत्पादक है यदि वह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि नहीं करता।

मानवीय विकास के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं में एक अंतिम उद्देश्य है। शिक्षा व स्वास्थ्य में निवेश के द्वारा मानवीय कल्याण में वृद्धि की जानी चाहिए। चाहे इस प्रकार के निवेशों के परिणामस्वरूप उत्पादकता न भी हो। इसलिए आधार भूत शिक्षा व बुनियादी स्वास्थ्य स्वयं में महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होने व स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए।

सारणी 4.1 शिक्षा व स्वास्थ्य दोनों में विकास के चयन सूचक

कथन		1951	1981	1991	2001	2016-17
वास्तविक प्रति व्यक्ति आय (रु. में)		7,651	12,174	15,748	23,095	77,659
मृत्यु दर (प्रति 1000 व्यक्ति)		25.1	12.5	9.8	8.1	6.3
शिशु मृत्युदर		146	110	80	63	33
जन्म के समय जीवन संभावना (वर्षों में)	पुरुष	37.2	54.1	59.7	63.9	67
	स्त्री	36.2	54.7	60.9	66.9	70
साक्षरता दर (%)		16.67	43.57	52.21	65.20	76

स्रोत : संबंधित वर्षों के आर्थिक सर्वेक्षण, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय साँख्यिकी कार्यालय एवं साँख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सारणी 4.1 दर्शा रही है कि शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों में वृद्धि एक साथ हो रही है। एक क्षेत्र में होने वाली वृद्धि दूसरे क्षेत्र में वृद्धि उत्साहित करती है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि आर्थिक वृद्धि व विकास के लिए मानवीय पूंजी अत्यावश्यक है। मानवीय पूंजी के द्वारा ही राष्ट्र के भौतिक साधनों का समुचित उपयोग संभव है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानवीय पूंजी जहाँ आर्थिक विकास को उत्साहित करती है वही आर्थिक विकास मानवीय पूंजी निर्माण में वृद्धि करता है। इस प्रकार इनमें परस्पर कारण व प्रभाव संबंध पाया जाता है। दोनों परस्पर प्रभावित होते हैं।

बाक्स 4.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं मानव पूंजी निर्माण (National Education Policy, 2020 and Human Capital Formation)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विश्व में ज्ञान प्राप्ति में तीव्र गति से परिवर्तन आ रहा है। बहुत सी वैज्ञानिक व आधुनिक तकनीक विकसित हो रही है। जैसे मशीन-शिक्षण (Machine-learning), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (artificial intelligence), आदि। आज विश्व में कई कौशल रहित कार्य मशीनें कर रही हैं परन्तु गणित, कंप्यूटर विज्ञान व साँख्यिकी में कुशल एवं निपुण श्रम बल की आवश्यकता है। इसके साथ ही विज्ञान व समाजिक विज्ञान के क्षेत्र में बहु-विषय (Multi disciplinary) योग्यता होने की माँग निरंतर बढ़ रही है।

वातावरण में आ रहे बहुत बड़े परिवर्तन, प्रदूषण वृद्धि तथा प्राकृतिक संसाधनों के शोषण में हो रही वृद्धि के कारण यह चिंता निरंतर बढ़ रही है कि हम विश्व के लिए ऊर्जा, पानी, भोजन व स्वच्छता जैसी जरूरतें कैसे पूरी करेंगे। इसलिए जीव शिक्षा, रसायन विज्ञान, भौतिकविज्ञान, कृषि जलवायु – विज्ञान व सामाजिकविज्ञान में निपुण व कुशल श्रम बल की आवश्यकता अधिक अनुभव की जा रही है। विश्वव्यापी महामारी (Epidemics)

व राष्ट्र व्यापी महामारी (Pandemics) के संभावित खतरों में वृद्धि के कारण रोग – प्रबंधन, टीका विकास व सामाजिक चेतन के क्षेत्र में सहयोगी अनुसंधान (Collaborative research) के लिए भी बहु विज्ञानों के ज्ञान की मांग भी हो रही है ।

जिस प्रकार भारत एक विकसित देश के साथ – साथ संसार की तीसरी बड़ी अर्थ व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में मानवता (Humanities) व कला (Art) से संबंधित विज्ञानों के प्रति ज्ञान की माँग में निरंतर वृद्धि होगी। इस प्रकार यह दृष्टिकोण सुझाव प्रदान करता है कि भारत में मानवीय पूँजी निर्माण अर्थ व्यवस्था को ज्ञान के आधार पर विकास की उच्च गति प्रदान करेगा।

यह किया करें

भारत में मानव पूँजी निर्माण के मार्ग में आ रही बाधाओं पर चर्चा करते हुए उनकी सूची बनाएं तथा उन बाधाओं को दूर करने के लिए सुझाव दें।

4.5 भारत में मानव पूँजी निर्माण की स्थिति (State of Human Capital Formation in India)

इस खंड में हम भारत में मानव पूँजी निर्माण का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मानव पूँजी निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य स्थल प्रशिक्षण, प्रवसन और सूचना निवेश का परिणाम है। इनमें से शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूँजी निर्माण के दो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हम जानते हैं कि भारत देश की प्रशासन व्यवस्था संघीय है जिसमें केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि) हैं। भारत के संविधान ने सभी स्तर के प्रशासकीय निकायों के कार्यों, दायित्वों को भी बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। इसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर व्यय तीनों ही प्रशासकीय स्तरों पर साथ-साथ वहन किया जाता है।

क्या आप जानते हैं कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की देख-रेख कौन करता है? भारत में शिक्षा क्षेत्रक के विश्लेषण से पूर्व यहाँ हम शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रकों में सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर विचार करेंगे। हम जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल निजी तथा सामाजिक लाभों को उत्पन्न करती है। इसी कारण इन सेवाओं के बाजार में निजी और सार्वजनिक संस्थाओं का अस्तित्व है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं और उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसलिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। मान लीजिए, जब भी किसी बच्चे को किसी स्कूल या फिर स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में भर्ती करा दिया जाता है, जहाँ आवश्यक सुविधाएँ नहीं प्रदान की जा रही हों तो इससे पहले कि बच्चे को किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित किए जाने का निर्णय लिया जाए, पर्याप्त मात्रा में हानि हो चुकी होगी। यही नहीं, इन सेवाओं के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को सेवाओं की गुणवत्ताओं और लागतों के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं होती। इन परिस्थितियों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करा रही संस्थाएँ एकाधिकार प्राप्त कर लेती हैं और शोषण करने लगती हैं। यहाँ सरकार की भूमिका का एक स्वरूप यह हो सकता है कि वह निजी सेवा प्रदायकों को उचित मानकों के अनुसार सेवाएँ देने तथा उनकी उचित कीमत उगाहने को बाध्य करें।

भारत में शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् आती हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग मंत्रालय और विभिन्न संस्थाओं के स्वास्थ्य विभाग तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् आदि कार्य कर रही हैं।

भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ जनसंख्या का एक विशाल वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहा है, लोग बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर पर्याप्त व्यय नहीं कर सकते। यही नहीं भारत की अधिकांश जनता अति विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल और उच्च शिक्षा का भार वहन नहीं कर पाती। जब बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को नागरिकों का अधिकार मान लिया जाता है, तो यह अनिवार्य है कि सभी सुपात्र नागरिकों को, विशेषकर सामाजिक दृष्टि से दलित रहे वर्गों को, सरकार ये सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान करे। शत-प्रतिशत साक्षरता और भारतीयों की औसत उपलब्धियों में प्राप्त वृद्धि के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें पिछले कई वर्षों से अपने शिक्षा क्षेत्र पर व्यय में वृद्धि करती आ रही हैं। ताकि 100 प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने में और भारतीयों की औसत विद्या प्राप्ति में वृद्धि हो सके।

यह क्रिया करें

NCERT, UGC, AICTE और ICMR के उद्देश्यों और गतिविधि कार्यों की पहचान करो।

4.6 भारत में शैक्षिक क्षेत्र (Education Sector in India)

4.6.1 शिक्षा पर किए जाने वाले राजकीय व्यय में वृद्धि (Growth in Government Expenditure on Education)

क्या आप जानते हैं कि सरकार शिक्षा पर कितना व्यय करती है? सरकार द्वारा किए गये शिक्षा पर कुल व्यय को अधिक सार्थक रूप से समझने के लिए हम इस व्यय को दो प्रकार से व्यक्त करेंगे (क) कुल सरकारी व्यय में इसका प्रतिशत तथा (ख) सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत।

कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत सरकारी योजनाओं में शिक्षा के महत्व का सूचक है। सकल घरेलू उत्पाद में शैक्षिक व्यय का प्रतिशत यह व्यक्त करता है कि व्यक्तियों की आय का कितना भाग देश के शैक्षिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 1952 से 2014 के बीच कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय 7.92 प्रतिशत से बढ़कर 15.7 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत 0.64 से बढ़कर 4.13 प्रतिशत हो गया है। इस संपूर्ण समयावधि में शैक्षिक व्यय की वृद्धि समान नहीं रही है इसमें अनियमित रूप से उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। यदि इस सरकारी व्यय के साथ हम व्यक्तियों के द्वारा किया गया निजी व्यय तथा परोपकारी (धर्मार्थ) संस्थाओं के शैक्षिक व्यय को शामिल कर लें तो शिक्षा पर कुल व्यय और अधिक होना चाहिए।

कुल शिक्षा व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होता है। उच्चतर/तृतीयक शैक्षिक संस्थाओं (उच्च शिक्षा के संस्थानों जैसे-महाविद्यालयों, बहुतकनीकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों आदि) पर होने वाले व्यय सबसे कम है। यद्यपि औसत रूप से सरकार उच्चतर शिक्षा पर बहुत कम व्यय करती है, किंतु प्रति विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा पर व्यय प्राथमिक शिक्षा की तुलना में अधिक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वित्तीय संसाधनों को उच्चतर शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा की ओर कर दिया जाना चाहिए।

जैसे-जैसे हम विद्यालय शिक्षा का प्रसार करेंगे तो हमें उच्चतर शैक्षिक संस्थानों से प्रशिक्षित और अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अतः शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यय में वृद्धि करनी चाहिए।

वर्ष 2014-15 प्रारंभिक शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी होने वाले सार्वजनिक व्यय में राज्यों के बीच काफी अंतर है। जहाँ हिमाचल प्रदेश में इसका उच्च-स्तर 34,651 रु. वहीं बिहार में यह मात्र 4,088 रु. है। इस प्रकार की विषमताओं के कारण ही विभिन्न राज्यों में शिक्षा के अवसरों और शैक्षिक उपलब्धियों के स्तर में बहुत भारी अंतर हो जाता है।



चित्र 4.2 शैक्षिक आधारिक संरचनाओं में निवेश अपरिहार्य है।

विभिन्न आयोगों के द्वारा शिक्षा व्यय के वांछित स्तर के साथ यदि शिक्षा व्यय की तुलना की जाय तो इसकी अपर्याप्तता समझ में आ सकती है। शिक्षा आयोग (1964-66) ने सिफारिश की थी कि शैक्षिक उपलब्धियों की संवृद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कम-से-कम 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कानून बनाया है जिसके अन्तर्गत 6-14 वर्ष के आयु-वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। 1999 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति ने अनुमान लगाया था कि देश के 6-14 वर्ष के आयु-वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए (1998-99 से 2000-07) के दस वर्षों की अवधि में लगभग 1.3 लाख करोड़ रु. व्यय करना होगा। सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत के स्तर की तुलना में वांछित वर्तमान 4 प्रतिशत व्यय का स्तर बहुत कम है। आने वाले वर्षों में 6 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुँचने की आवश्यकता है, जैसा कि सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया है।

भारत सरकार ने सभी केंद्रीय करों पर 2 प्रतिशत “शिक्षा उपकर” लगाना भी प्रारंभ किया है। शिक्षा उपकर से प्राप्त राजस्व को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने हेतु सुरक्षित रखा है। साथ ही सरकार ने उच्च शिक्षा संवर्धन के लिए भी विशाल धन राशि स्वीकृत करने की बात की है। उच्च शिक्षार्थियों के लिए एक नयी ऋण योजना की भी घोषणा की गयी है।

इन्हें कीजिए

- विभिन्न स्तरों पर विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों का अध्ययन कीजिए।
(क) प्राथमिक स्तर के विद्यालय छोड़ने वाले छात्र
(ख) आठवीं कक्षा के बाद छोड़ने वाले छात्र
(ग) दसवीं कक्षा के बाद छोड़ने वाले छात्र कारण ज्ञात कीजिए तथा कक्षा में चर्चा कीजिए।
- विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों से बाल श्रम को बढ़ावा मिल रहा है। बताएँ कि इससे कैसे मानव पूँजी की हानि हो रही है?

सारणी 4.2

भारत में शैक्षिक उपलब्धियाँ

क्र.सं.	विवरण	1990	2000	2011	2017-18
1	वयस्क साक्षरता दर (15 वर्ष से अधिक आयुवर्ग में साक्षरों का प्रतिशत)				
	1.1 पुरुष	61.9	68.4	79	82
	1.2 महिलाएँ	37.9	45.4	59	66
2	प्राथमिक शिक्षा संपूर्तिदर (संबद्ध वर्ग प्रतिशत)				
	2.1 पुरुष	78	85	92	93
	2.2 महिलाएँ	61	69	94	96
3.	युवा साक्षरता दर (15 से 24 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत)				
	3.1 पुरुष	76.6	79.7	90	93
	3.2 महिलाएँ	54.2	64.8	82	90

स्रोत : शैक्षिक साँख्यिकी (विहगय दृष्टिकोण) शिक्षा मंत्रालय (कई वर्षों के) भारत सरकार, वार्षिक रिपोर्ट, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

4.6.2 भारत में शैक्षिक उपलब्धियाँ (Educational Achievements in India)

सामान्यतया किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियों का आकलन वयस्क साक्षरता स्तर, प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर और युवा साक्षरता दर द्वारा किया जाता है। सारणी 4.2 में भारत की इन दरों के दो दशकों के आँकड़े दिये गये हैं।



चित्र 4.6 विद्यालय छोड़ने वाले छात्र बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं जिससे मानव पूँजी का क्षय होता है

4.7 भविष्य की संभावनाएँ (Future Prospects)

4.7.1 'सब के लिए शिक्षा' - अभी भी एक सपना है ('Education for All' - Still a Distant Dream)

यद्यपि वयस्क और युवा साक्षरता दरों में सुधार हो रहा है, किंतु आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी ही है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी। भारत की संविधान सभा ने 1950 में संविधान को पारित करते समय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट किया था कि सरकार संविधान पारित होने के दस साल के अंदर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी। इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते तो अब तक शत-प्रतिशत साक्षरता हो गई होती।

4.7.2 लिंग समता पहले से बेहतर (Gender Equity - Better than Before)

अब साक्षरता में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर कम हो रहा है जो लिंग-समता की दिशा में एक सकारात्मक विकास है। नारी शिक्षा को भारत में और प्रोत्साहन दिए जाने के कई कारण हैं। जैसे, शिक्षा नारी की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्तर में सुधार और साथ ही स्त्री शिक्षा, प्रजनन दर और स्त्रियों व बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल पर अनुकूल प्रभाव डालती है। अतः हमें साक्षरता स्तर सुधारने के अपने प्रयासों में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए। अभी हमें शत-प्रतिशत वयस्क साक्षरता दर प्राप्त करने के लिए अनेक मंजिलें को पार करनी है।



चित्र 4.7 उच्च शिक्षा : कम प्राप्तकर्ता

4.7.3 उच्च शिक्षा लेने वालों की कमी (Higher Education - a Few Takers)

भारत में शिक्षा का पिरामिड बहुत ही नुकीला है, जो दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा स्तर तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। यही नहीं, शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर भी उच्चतम है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्नातक व ऊपर अध्ययन किये हुए युवा पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर 19 प्रतिशत थी। उनके शहरी समकक्षों में 16 प्रतिशत अपेक्षाकृत कम स्तर पर बेरोजगारी दर थी। सबसे गंभीर रूप से प्रभावित लोगों में लगभग 30 प्रतिशत बेरोजगारी हैं जो युवा ग्रामीण महिलाएं थीं। इसके विपरीत, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के शिक्षित युवाओं में से केवल 3-6 प्रतिशत बेरोजगार थे। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार इस स्थिति में अभी तक सुधार अपेक्षित है। अतः सरकार को उच्च शिक्षा के लिए अधिक धन का आवंटन करना चाहिए तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के स्तर में सुधार लाना चाहिए ताकि वहाँ पढ़ रहे छात्र रोजगार योग्य कौशल प्राप्त कर सकें जब कम पढ़े-लिखे लोगों से तुलना की जाती है, तो शिक्षित लोगों का एक बड़ा अनुपात बेरोजगार है। क्यों?

4.8 स्वास्थ्य (Health)

2020 से, कोरोना महामारी के कारण आप हाथ धोने, मास्क पहनने और सामाजिक दूरी आदि नियमों से परिचित हैं। अच्छा स्वास्थ्य न केवल बीमारियों से मुक्त रहने के लिए बल्कि हमें हमारी सामर्थ्य को महसूस करने की योग्यता प्रदान करता है यह किसी भी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य का मापदंड है। स्वास्थ्य किसी राष्ट्र की संपूर्ण वृद्धि एवं विकास से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया है।

बेशक बीसवीं सदी में मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक विश्व व्यापी परिवर्तन देखने को मिला जो ऐतिहासिक दृष्टि से बेमिसाल है। परन्तु किसी भी राष्ट्र के स्वास्थ्य मापदंड को कुछ ही शब्दों में परिभाषित करना अत्यन्त कठिन है। प्रायः विद्वान जन स्वास्थ्य का मूल्यांकन कुछ सूचकों को ध्यान में रखकर करते हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जीवन संभावना, पोषण संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों के संक्रमण आदि।



चित्र 4.5 देश के अधिकांश क्षेत्र में अभी भी स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में कमियां हैं।

किसी भी देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिये जरूरत अनुसार स्वस्थ मनुष्यों की आवश्यकता होती है। इससे ही जन - स्वास्थ्य के मूलभूत ढाँचे के विकास की आवश्यकता को पूरा करना भी जरूरी हो जाता है। वर्तमान समय के विद्वानों का यह मत है कि जन स्वास्थ्य सुविधाएं सभी के लिये जरूरी हैं और सभी इंसानों का बुनियादी अधिकार भी। जन स्वास्थ्य के अधिकार को विश्वसनीय बनाना सरकार की जिम्मेदारी है जन स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे अस्पताल, डाक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, बिस्तर, अस्पतालों में आवश्यक सामान जैसे दवाइयाँ आदि से संबंधित उद्योग शामिल हैं।

यह भी सत्य है कि देश में स्वस्थ जन समुदाय होने के लिए जन स्वास्थ्य संबंधी ढाँचे के विकास के साथ-साथ यह सभी सुविधाएं भी जन समुदाय तक पहुँचनी जरूरी हैं। इसके लिये योजनाबद्ध तरीके से विकास के शुरूआती चरण में नीति निर्माताओं ने कल्पना की थी कि कोई भी व्यक्ति अपनी खराब आर्थिक स्थिति की वजह से डाक्टरी देखभाल, उपचार और रोगों की रोकथाम करने में असक्षम न हो। परन्तु क्या हम इस दृष्टि कोण को प्राप्त कर चुके हैं ? इससे पहले कि हम स्वास्थ्य संबंधित ढाँचे के अलग-अलग प्रारूपों पर चर्चा करें, आइये हम भारत में जन स्वास्थ्य स्थिति पर विचार करें।

4.8.1 स्वास्थ्य संबंधित आधारभूत (बुनियादी) की स्थिति (State of Health Infrastructure)

सरकार का यह संवैधानिक दायित्व बनता है कि स्वास्थ्य संबंधित सभी पहलुओं जैसे मेडिकल शिक्षा, भोजन में मिलावट, दवा और जहरों के उत्पादन, डाक्टरी व्यवसाय, स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण आँकड़े मानसिक समस्याएं आदि को नियंत्रित करें। सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के द्वारा व्यापक नीतियों और योजनाओं का निर्माण करती है। जिसका लक्ष्य जन स्वास्थ्य को बढ़ाना है। यह संस्था स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करती है और देश में जन स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लागू करने हेतु राज्य सरकारी, केन्द्र शसित प्रदेशों व अन्य संस्थाओं को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाती है।

समय के साथ-साथ भारत ने अलग-अलग चरणों में जन स्वास्थ्य संबंधित जरूरी ढाँचे का निर्माण किया है। ग्रामीण स्तर पर कई प्रकार के अस्पताल सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं जिन्हे तकनीकी रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PCH) के रूप में जाना जाता है। (देखें बाक्स 4.4)। भारत में समाजसेवी एवं निजी संस्थाओं द्वारा चलाये गये अस्पतालों की संख्या अधिक है। इनमें अस्पताल, मेडीकल कॉलेज, फार्मसी एवं नर्सिंग कालेजों में शिक्षित और पैरा मेडिकल शिक्षित व्यक्तियों को समिलित किया जाता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में जन स्वास्थ्य सेवाओं के भौतिक प्रबन्धन में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। 1951- 2018 के दौरान सरकारी अस्पताल एवं डिस्पेंसरियों की संख्या 9, 300 से बढ़ कर 53,800 से हो गई और अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों में बिस्तर की सुविधा 1.2 लाख से बढ़ाकर 7.1 लाख हो गयी। इसके साथ ही नर्सिंग कर्मचारियों की गिनती 18000 से बढ़ कर 30 लाख और ऐलोपैथिक डाक्टरों की गिनती 62000 से बढ़ कर 11.5 लाख हो गयी। जन स्वास्थ्य के ढाँचे में व्यापक विस्तार के कारण चेचक, कुष्ठरोग एवं पोलियो का लगभग उन्मूलन हो चुका है।

इन्हे करें

कोविड-19 महामारी से जन समुदाय को बचाने के लिए सरकार द्वारा किए गये प्रयत्नों के विषय में आप क्या सोचते हो? कक्षा में चर्चा करें।

4.8.2 निजी क्षेत्रक में स्वास्थ्य आधारभूत संरचना (Private Sector Health Infrastructure)

देखने में आया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रक अपने कर्तव्य के निर्वाहन में बहुत अधिक सफल नहीं हुआ है। लेकिन इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र ने बहुत प्रगति की है। भारत में 70 प्रतिशत अस्पतालों का संचालन निजी क्षेत्रक कर रहा है। अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों का 2/5वाँ हिस्सा निजी अस्पतालों में है। लगभग 60 प्रतिशत दवाखाने निजी क्षेत्र द्वारा चलाये जा रहे हैं। वे 80 प्रतिशत बाह्य रोगियों और 46 प्रतिशत अंतः रोगियों के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं।

वर्तमान में निजी क्षेत्रक मेडिकल शिक्षा व प्रशिक्षण; मेडिकल प्रौद्योगिकी तथा रोग निदान अन्वेषण; दवाइयों के निर्माण तथा बिक्री, अस्पताल निर्माण व मेडिकल सेवाओं की व्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है

बॉक्स 4.4 भारत में स्वास्थ्य-व्यवस्था (Health System in India)

भारत की स्वास्थ्य आधारभूत संरचना और स्वास्थ्य सुविधाओं की तीन स्तरीय व्यवस्था है – प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्रक सुविधाओं में प्रचलित स्वास्थ्य समस्याओं का ज्ञान तथा उन्हें पहचानने, रोकने और नियंत्रित करने की विधि तथा इसमें आगे चलकर खाद्य पूर्ति तथा उचित पोषण और जल की पर्याप्त पूर्ति तथा मूलभूत स्वच्छता को उत्साहित करना, शिशु एवं मातृत्व देखभाल, प्रमुख संक्रामक रोगों के विहद टीकाकरण, मानसिक स्वास्थ्य का संवर्द्धन और आवश्यक दवाओं का प्रावधान शामिल है। सहायिक नर्सिंग मिडवाइफ (ए. एन. एम.) द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। प्रायः प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए गाँवों तथा छोटे कस्बों में जो अस्पताल बनाये गये हैं, वहाँ एक डॉक्टर, एक नर्स और सीमित मात्रा में दवाएँ उपलब्ध होती हैं। इन्हे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र और उपकेंद्रों के नाम से जाना जाता है जब एक रोगी की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में सुधार नहीं हो पाता, तो उन्हें द्वितीयक या मध्य या उच्च श्रेणी के अस्पतालों में भेजा जाता है। जिन अस्पतालों में शल्य – चिकित्सा एक्सरे, ई. सी. जी. जैसी बेहतर सुविधाएँ होती हैं, उन्हें माध्यमिक चिकित्सा संस्थाएँ कहते हैं। ये स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के सहायक होते हैं और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करते हैं। माध्यमिक प्रायः जिला मुख्यालय और बड़े कस्बों में होते हैं। ऐसे सभी अस्पताल जहाँ उच्च स्तर के उपकरण और दवाइयाँ उपलब्ध हैं और जो ऐसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का निपटान जिसकी सुविधाएँ प्राथमिक या माध्यमिक अस्पतालों में न हो, तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। तृतीयक क्षेत्र में ऐसे प्रमुख संस्थान भी शामिल हैं जो कि न केवल उत्तम मेडिकल शिक्षा प्रदान करते हैं और अनुसंधान करते हैं बल्कि वे विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ भी प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट, नयी दिल्ली; पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़; नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, न्यूरो साइंस बंगलौर; और आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाईजीन पब्लिक हेल्थ, कोलकाता।

स्त्रोत - मेक्रोइकोनॉमिक्स एंड हेल्थ पर राष्ट्रीय कमिशन की रिपोर्ट, 2005

2001-2002 में 13 लाख से अधिक मेडिकल उद्योग थे जिनमें 22 लाख लोग काम कर रहे थे। इनमें से 80 प्रतिशत से अधिक एक व्यक्ति के स्वामित्व वाले थे जो समय-समय पर भाड़े के क्षमिकों से काम लेते थे विद्वानों ने यह कहा है कि भारत में निजी क्षेत्रक स्वतंत्र रूप से और बिना किसी बड़े विनियमन के विकसित हुआ है कुछ निजी चिकित्सकों का तो पंजीकरण भी नहीं हुआ है और उनमें पूर्णतः प्रशिक्षित डॉक्टर भी नहीं हैं।

1990 के दशक से उदारीकरण उपायों के कारण अनेक अप्रवासी भारतियों और औद्योगिक तथा दवा कंपनियों ने भारत के अमीरों और चिकित्सा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आधुनिकतम सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण किया (देखें बाक्स 4.5)। क्या आप सहमत हैं कि भारत के अधिकतर लोग इस प्रकार के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं ? अगर नहीं तो क्यों ? ऐसा करने के लिए क्या किया जा सकता है जिससे कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर सके ?

बॉक्स 4.5 चिकित्सा पर्यटन - एक विशिष्ट अवसर (Medical Tourism-A Great Opportunity)

आपने दूरदर्शन समाचार में देखा व सुना होगा तथा समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि बड़ी संख्या में विदेशी शल्य चिकित्सा, गुर्दारोपण, दंत और यहाँ तक कि सौंदर्यवर्द्धक उपचार के लिए भारत आ रहे हैं। क्योंकि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में आधुनिकतम चिकित्सा प्रौद्योगिकी है हमारे पास योग्य डाक्टर है और विदेशियों को उनके देश में ऐसी चिकित्सा के लिए लगने वाली कीमत की अपेक्षा हमारे यहाँ चिकित्सा सेवाएं काफी सस्ती है। वर्ष 2016 में 2,01,000 से भी अधिक पर्यटक चिकित्सा के लिए भारत आये और इस संख्या में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है। विशेषज्ञों की यह भविष्यवाणी है कि 2020 में भारत मेडिकल पर्यटन से 500 अरब रूपयों से अधिक आय अर्जित कर सकता है। अधिक विदेशियों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए स्वास्थ्य आधारिक संरचना को ऊँचा उठाया जा सकता है।

स्त्रोत : पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ; www.granttharton.in

बॉक्स :- 4.6 समुदाय और स्वास्थ्य देखभाल की अलाभकारी संस्थाएँ

सामुदायिक भागेदारी एक अच्छी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। यह इस विचार पर आधारित है कि लोगो को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रशिक्षित करके स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में लगाया जा सकता है। देश के कुछ हिस्सों में इस विधि का उपयोग पहले ही से किया जा रहा है। सेवा स्वनियोजित महिला समिति (SEWA), अहमदाबाद और नीलगिरि भारत में कार्य कर रही कुछ ऐसी ही गैर सरकारी संस्थाओं (NGO's) के कुछ उदाहरण हैं। व्यापार संघ ने अपने सदस्यों के लिए कुछ वैकल्पिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ उपलब्ध कराई हैं और आस पास के गाँव के लोगों को निम्न लागत पर स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएँ प्रदान की है। इस संबंध में सर्वाधिक अग्रणी और सुविख्यात पहल शाहिद अस्पताल ने की है। इस अस्पताल का निर्माण मध्य प्रदेश के दुर्ग में छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ के श्रमिकों द्वारा 1983 में किया गया। वैकल्पिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का निर्माण करने के लिए कुछ ग्रामीण संस्थाओं ने कुछ प्रयास किए है। थाणे, महाराष्ट्र में कबिलाई लोगों का संगठन काश्तकारी संगठन के संदर्भ में इसका उदाहरण है। यहाँ न्यूनतम लागत पर साधारण रोगों का गाँव के स्तर पर उपचार करने के लिए महिला स्वास्थ्य श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया है।

सारणी 4.3 अन्य देशों की तुलना में भारत का स्वास्थ्य सूचकांक 2016-2018

सूचक	भारत	चीन	यू.एस.ए.	श्री लंका
शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म दर (2018)	30	7.4	5.6	6.4

सूचक	भारत	चीन	यू.एस.ए.	श्री लंका
5 वर्ष से कम मृत्यु दर 1000 जन्म दर (2016)	37	8.6	6.5	7.4
प्रशिक्षित कमियों द्वारा जन्म (कुल का प्रतिशत) 2016	81	81	99	99
बच्चों का टीकाकरण (डी.पीटी.पी) (%) (2016)	89	89	94	99
सरकारी स्वास्थ्य व्यय जैसे GDP का प्रतिशत (2016)	3.7	5.7	17	3.9
वर्तमान स्वास्थ्य व्यय के रूप में जेब खर्च से बाहर (2016)	65	36	11.1	50

स्त्रोत : विश्व विकास सूचक 2019 विश्व बैंक, वाशिंगटन

4.8.3 चिकित्सा की भारतीय प्रणाली (Indian Systems of Medicine (ISM))

चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में 6 व्यवस्थाएं (ISM) हैं – आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्यो पैथी। आयुष इनके अंग्रेजी नामों के अनुसार भारतीय चिकित्सा प्रणाली को आयुष भी कहते हैं। (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, प्राकृतिक और होम्योपैथी)। वर्तमान में चिकित्सा की भारतीय प्रणाली के 3,943 आयुष अस्पताल और 27,700 दवाखाने और इनमें 7.4 लाख पंजीकृत चिकित्सक हैं। लेकिन चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में शैक्षिक मानकीकरण या अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किसी प्रकार की रूपरेखा बनाने हेतु कुछ नहीं किया गया है। चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में प्रबल संभवनाएं हैं और वे हमारे स्वास्थ्य की देखभाल की अनेक समस्याओं का निवारण कर सकती हैं। यह प्रणालियां प्रभावशाली, सुरक्षित और सस्ती हैं।

स्वास्थ्य और स्वास्थ्य आधारभूत संरचना के सूचक (Indicators of Health and Health Infrastructure — A Critical Appraisal)

जैसा कि पहले बताया गया है कि एक देश में स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन शिशु मृत्यु और मातृ – मृत्यु दर, जीवन – प्रत्याशा व पोषण स्तरों के साथ-साथ सक्रामक व गैर सक्रामक रोगों की घटनाएँ, जैसे सूचकों के द्वारा होता है। इनमें से कुछ स्वास्थ्य सूचकों और उनकी भारत में स्थिति के विषय में जानकारी सारणी 4.3 में दी गई है। विशेषज्ञों की यह राय है कि स्वास्थ्य क्षेत्रक में सरकार की भूमिका के लिए अधिकाधिक स्थान है। उदाहरण के लिए सारणी यह बतलाती है कि स्वास्थ्य क्षेत्रक में व्यय सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 3.7 प्रतिशत है जो कि अन्य विकसित व विकासशील देशों की तुलना में अत्यंत कम है।

एक अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग 17 प्रतिशत संख्या निवास करती है, लेकिन इस देश पर विश्व के कुल रोगियों का 20 प्रतिशत बोझ (GDB) है।

बाक्स 4.7 विश्व रोग भार (Global Burden of Disease)

यह एक सूचक है जिसका प्रयोग विशेषज्ञों द्वारा यह जानने के लिये किया जाता है कि देश में उन लोगों की संख्या कितनी है, जो किसी रोग विशेष के कारण समय से पूर्व मर गये हैं अथवा किसी रोग के कारण उन्हें कितने वर्ष अयोग्यता की स्थिति सहन करनी पड़ी है।

2017 का एक अध्ययन यह दर्शाता है कि जी. बी. डी. जिसे अब कुल रोग बोझ कहा जाता है में दो तिहाई हिस्से का कारण सक्रामक रोग हैं- जिनमें हृदय रोग, श्वास प्रणाली, फेफड़े, गुर्दे, मोटापा तथा जीवन शैली से संबंधित रोग शामिल है। अतिसार, निम्न श्वास प्रणाली से संबंधित तथा अन्य साधारण सक्रामक रोग भारत में कुल मृत्यु के छठे हिस्से का कारण है। वायु प्रदूषण के कारण वैश्विक स्तर पर होने वाली 4.8 मिलियन मृत्यु में 1.1 मिलियन मृत्यु अकेले भारत में होती है। भारत में कैंसर (8%), चोटें और धान (11%) आदि के कारण होने वाली मृत्यु का अनुपात गत दो दशकों से बढ़ रहा है। वर्तमान समय में 20% से कम जनसंख्या सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रयोग करती है। एक अध्ययन यह दर्शाता है कि केवल 38% प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHCs) के पास ही वाछिंत डाक्टर उपलब्ध है और केवल 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पास दवाइयों का वाछिंत भंडार है।

इन्हे करें

- भिन्न - भिन्न प्रकार के एक या दो (सरकारी एवं निजी अस्पतालों में जाकर डाक्टरों एवं नर्सों से उन उपायों एवं तरीकों के विषय में जानकारी प्राप्त करें जिनके माध्यम से उन्होंने कोविड - 19 की स्थिति का प्रबंधन किया।
- अपने क्षेत्र अथवा अड़ोस पड़ोस में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) में जाकर वहाँ उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की रिपोर्ट तैयार करें।
- अपने क्षेत्र में स्थित निजी अस्पतालों, मैडिकल लैबोरेटरीज, स्कैन सेंटर, दवा केन्द्र (दुकान) तथा अन्य ऐसी सुविधाओं की संख्या के विवरण एकत्र करें।
- “क्या हमे गरीब व्यक्तियों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए सहायक नर्सों (Midwife) की एक सेना तैयार करनी चाहिए?” जो हर वर्ष मेडिकल कालेजों में प्रतिशिक्षित चिकित्सकों की सेवाओं को प्राप्त करने के लिये व्यय नहीं कर सकते। इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद करें।
- एक अध्ययन यह दर्शाता है कि केवल चिकित्सा व्यय 2.2% जनसंख्या को प्रत्येक वर्ष गरीबी रेखा से नीचे धकेल देता है? कैसे ?
- अपने क्षेत्र के कुछ अस्पतालों में जाएं उन बच्चों की संख्या मालूम करें जिनका टीकाकारण हो चुका है। प्राप्त जानकारी पर कक्षा में चर्चा करें।
- क्या आपको प्रतीत होता है कि भारतीय नगरों को वैश्विक स्वास्थ्य सम्बन्धी बुनियादी संरचना प्रदान करनी चाहिए ताकि वे पर्यटकों को चिकित्सा पर्यटन के लिए आकर्षित कर सकें? अथवा सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो को स्वास्थ्य सम्बन्धी बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? वाद विवाद करें।

4.8.4 शहरी-ग्रामीण तथा धनी-निर्धन में स्वास्थ्य सुविधाओं संबंधी विभाजन (Urban-Rural and Poor-Rich Divide)

बेशक, भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भारत के केवल 1/5 अस्पताल (निजी क्षेत्र सहित) स्थित है। ग्रामीण भारत के पास कुल दवाखानों के लगभग आधे दवाखाने ही हैं। सरकारी अस्पतालों में लगभग 7.13 लाख बिस्तरों में से ग्रामीण इलाकों में केवल 30 प्रतिशत बिस्तर उपलब्ध हैं। अतः ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को पर्याप्त स्वास्थ्य आधारित संरचना उपलब्ध नहीं हैं। इससे भारत के लोगों में स्वास्थ्य की स्थिति में विभेद उत्पन्न हो गया है। जहाँ तक अस्पतालों का सवाल है, ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक एक लाख लोगों पर 0.36 अस्पताल है जबकि शहरी इलाकों में स्थापित प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में एक्सरे अथवा खून की जाँच जैसी सुविधाएँ नहीं हैं। जो कि एक शहरी के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं। भारत में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य स्वास्थ्य सुविधाओं में अपेक्षाकृत अधिक पीछे हैं। ग्रामीण इलाकों में उचित चिकित्सा से वंचित लोगों के प्रतिशत में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है।

ग्रामीणों को शिशु चिकित्सा (Paediatrics), स्त्री रोग (Gynaecology), चिकित्सा, संवेदनाहरण तथा प्रसूति विद्या जैसी विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। इसके बावजूद की 530 मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों से प्रतिवर्ष 50,000 मेडिकल स्नातक निकलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी बनी हुई है। इनमें से 1/5 डाक्टर बेहतर कमाई के लिए विदेश चले जाते हैं या अन्य निजी अस्पतालों में नौकरी करना पसंद करते हैं, जोकि अधिकांशतः शहरी इलाकों में स्थित होते हैं। इस आकर्षण का क्या कारण हो सकता है? अपने क्षेत्र में कार्यरत एक या दो चिकित्सकों के साथ बातचीत करें और कक्षा में चर्चा करें।



चित्र 4.6: भिन्न भिन्न स्वास्थ्य संभाल सुविधाओं का लाभ लेने के बावजूद माताओं का स्वास्थ्य चिन्ता का विषय है।

भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निर्धनतम लोग अपनी आय का 12 प्रतिशत स्वास्थ्य सुविधाओं में खर्च करते हैं, जबकि धनी केवल 2 प्रतिशत खर्च करते हैं। क्या होता है जब गरीब व्यक्ति बीमार पड़ता है ? उसे कुछ अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है या रहन रखी पड़ती है।

सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएँ न उपलब्ध होने के कारण गरीब लोगों को निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है, जिससे वे हमेशा के लिए ऋणग्रस्त हो जाते हैं या मौत के विकल्प को चुनते हैं। वर्तमान समय में केन्द्र व कुछ राज्य सरकारें स्वास्थ्य संभाल के लिए पहलकदमी कर रही हैं।

क्रिया करें

इससे संबंधित उपयुक्त जानकारी एकत्र कर कक्षा में समीक्षा करें।

इन्हे कीजिए

- गत वर्षों से भारत की समग्र स्वास्थ्य स्थिति में निश्चय ही सुधार हुआ है। जीवन प्रत्याशा बढ़ी हैं, शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। चेचक का उन्मूलन हो गया है। कुष्ठ तथा पोलियो के उन्मूलन का लक्ष्य भी प्राप्त होने वाला है। लेकिन ये आँकड़े तभी अच्छे लगते हैं जब उन्हें आप अलग करके देखें। इन आँकड़ों की तुलना शेष विश्व से करें। आप ये विवरण विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट से प्राप्त कर सकते हैं। आप प्राप्त जानकारी की व्याख्या करें।
- एक मास के लिए अपनी कक्षा का पर्यवेक्षण करें और पता करें कि कुछ छात्र अनुपस्थित क्यों रहते हैं? यदि अनुपस्थिति का कारण स्वास्थ्य समस्याएँ हैं, तो पता करें कि उन्हें किन किन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हे स्वास्थ्य समस्याओं का विवरण, उनके उपचार की प्रकृति और उनके अभिभावकों द्वारा उनके उपचार पर किये जा रहे खर्च का विवरण आदि पर जानकारी एकत्र करें और कक्षा में चर्चा करें।

4.8.5 महिला स्वास्थ्य (Women's Health)

महिला स्वास्थ्य भारत की जनसंख्या का लगभग आधा भाग महिलाओं का है। (Women's Health) पुरुषों की तुलना में उन्हें शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्रों में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। देश में शिशु-लिंग अनुपात की 2001 में 927 से 2011 में 919 की गिरावट एवं कन्या भ्रूण हत्या जैसी बढ़ती घटनाएँ इस ओर संकेत करती हैं कि देश में 15-19 वर्ष से कम की आयु लगभग 5 प्रतिशत लड़कियाँ न केवल विवाहित हैं बल्कि कम से कम एक बच्चे की माँ भी हैं। 15 से 49 वर्ष आयु समूह में शादीशुदा महिलाओं में 50 प्रतिशत से ज्यादा रक्ताभाव और रक्तक्षीणता से ग्रसित हैं। यह बीमारी लौह-न्यूनता के कारण होती है इसके परिणाम स्वरूप गर्भपात, भारत में स्त्रियों की अस्वस्थता और मौत का एक बहुत बड़ा कारण है। इनकी संख्या में नवजात शिशुओं में विकार (Neonatal disorder) के कारण समय से पहले मृत्यु स्तर (Premature death) स्तर 2007 और 2017 दोनों वर्षों में सर्वाधिक थी। इसमें भी 2005 के पश्चात् गिरावट नहीं आयी।

यह कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा एवं एक बुनियादी मानवाधिकार है। सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त हो सकती हैं। यदि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ विकेंद्रित हों। रोगों से दीर्घकालीन संघर्ष में सफलता शिक्षा और कार्यकुशल स्वास्थ्य आधारिक संरचना पर निर्भर करती है। इसीलिए स्वास्थ्य और सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करना और कार्यकुशल व्यवस्थाएँ प्रदान करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में दूर-संचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की भूमिका की अवहेलना नहीं की जा सकती। स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों की प्रभावशीलता प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर करती है। अंततः हमारा उद्देश्य लोगों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन की ओर ले जाना है। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं में शहर और गाँव के बीच स्पष्ट विभाजन है। यदि हम इस बढ़ते विभाजन की अवहेलना करते रहेंगे, तो हमारे देश के सामाजिक आर्थिक ढाँचे में अस्थिरता की आशंका रहेगी। सभी के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुँचाने (Accessibility) और सस्ते रेटों (Affordability) पर जोड़ने की जरूरत है।

4.9 मानवीय पूंजी के माप के सूचकांक (Indices for Measurement of Human Capital)

अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक हितों के सूचक के रूप में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय को दीर्घ काल से प्रयोग किया है तथा अभी तक उसका प्रयोग हो रहा है। जी. डी. पी (GDP) में वृद्धि पहले से अधिक वस्तुओं व सेवाओं की उपलब्धता को दर्शाता है जिससे अर्थ व्यवस्था के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। परन्तु भौतिक अथवा आर्थिक कल्याण की अपेक्षा सामाजिक विकास अधिक महत्वपूर्ण है। जी. डी. पी (GDP) अनुमान सामाजिक विकास के मापन में असफल सिद्ध हुआ है। सामाजिक विकास व सामाजिक कल्याण मानवीय विकास के व्यापक क्षेत्र से सलग्न है। इसलिए सामाजिक विकास के वैकल्पिक सूचकों की आवश्यकता अनुभव की गई। इस भाग में मानवीय विकास से संबंधित जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक (PQLI) तथा मानवी विकास सूचकांक (HDI) का संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है।

4.9.1 जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक (PQLI) (Physical Quality of Life Index (PQLI))

जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक मॉरिस. डी. मॉरिस द्वारा 1979 में सामाजिक विकास के माप के एक विकल्प सूचक के रूप में दिया गया था। आरंभ से ही सूचकांक में रुचि ली जा रही थी।

4.9.1.1 जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सूचकांक की अवधारणा और निर्माण (Concept and Construction of PQLI)

PQLI तीन सूचकों का एक संयुक्त सूचकांक है, अर्थात्

(1) एक वर्ष की आयु में जीवन प्रत्याशा (2) शिशु मृत्यु दर (3) साक्षरता

प्रत्येक संकेतक के लिए भिन्न भिन्न देशों के व्यक्तिगत प्रदर्शन को 1 से 100 के पैमाने में दर्ज किया गया है। जहाँ किसी भी देश के निकृष्ट (Worst) प्रदर्शन और 100 सर्वश्रेष्ठ (best) प्रदर्शन को दर्शाता है। किसी देश के लिए जीवन प्रत्याशा को 1 से 100 तक दर्ज किया गया है। फिर प्रत्येक देश के लिए तीनों रेटिंग के औसत द्वारा संयुक्त सूचकांक (PQLI) की गणना की जाती है, प्रत्येक रेटिंग को समान वर्चस्व (भार) प्रदान किया जाता है मॉरिस ने अपने परिणामों में प्रकाशित किया कि प्रायः देखा गया है कि जिन देशों की प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पाद (Per Capita GNPs) कम होती है तथा इसके विपरीत उनकी PQLI भी अधिक होती है। परन्तु यह परिणाम सर्वदा सत्य नहीं होता। अर्थात् GPP तथा PQLI के मध्य प्रत्यक्ष निकटतम में सहसम्बंध नहीं है। कुछ देशों का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद उच्च होने के बावजूद भी उनकी PQLI बहुत कम है। यहाँ तक कि सबसे निर्धन देशों की औसत से भी नीचे है।

चित्र 4.3 कुछ विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति GNP और PQLI की तुलना, 1981

देश	प्रति व्यक्ति GNP (\$)	पी.क्यू.एल.आई. PQLI
गाम्बिया	348	20
अंगोला	790	21
सूडान	380	34
पाकिस्तान	349	40

देश	प्रति व्यक्ति GNP (\$)	PQLI
सऊदी अरब	12,720	40
भारत	253	42
इराक	3,000	48
कतर	27,790	56
तंजानिया	299	58
ज़िम्बाब्वे	815	63
ब्राज़िल	2,214	72
चीन	304	75
श्रीलंका	302	82
सिंगापुर	5,220	86
ताइवान	2,503	87
कोस्टा रिका	1,476	89

स्रोत : टोडारो एम.पी. (1994) आर्थिक विकास का पाँचवा संस्करण

इस प्रकार प्रति व्यक्ति जीएनपी में कोई बड़ी वृद्धि होना बेहतर गुणवत्ता योग जीवन की गारंटी नहीं है। प्रति व्यक्ति जीएनपी में किसी उच्च विकास प्राप्त करने से पहले गुणवत्ता योग जीवन का स्तर प्राप्त किया जा सकता है या इसके विपरीत, PQLI मानवी विकास के माप का एक उपयोगी सूचकांक है।

पी.क्यू.एल.आई. (Construction of PQLI)

बाक्स 4.8 PQLI का निर्माण (Construction of PQLI) सारणी 4.4 PLQI के निर्माण के लिए भिन्न भिन्न सूचक के अधिकतम व न्यूनतम मूल्य			
माप	सूचक		विस्तार (Range)
	अधिकतम (Maximum value)	न्यूनतम (Minimum value)	
शिशु मृत्यु दर	229	9	220
एक वर्ष की आयु होने पर	77	38	39
जीवन प्रत्याशा	100	0	100
उपर्युक्त के आधार पर मोरिस ने निम्नलिखित सहसंबंध प्रकट किया है :			
कुल संख्या (N=150)	शिशु मृत्यु पर	जीवन प्रत्याशा	
एक वर्ष की आयु होने पर जीवन प्रत्याशा	(-) 0.919	- -	
साक्षरता दर	(-) 0.919	(+) 0.897	

पी.क्यू.एल.आई का निर्माण उपर्युक्त सारणी में भिन्न भिन्न सूचकों के दिए मूल्यों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार PQLI सूचकांक का निर्माण कर सकते हैं :

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \text{शिशु मृत्यु दर सूचक (IMRI)} &= \frac{229 - \text{वास्तविक IMR}}{220} \\ \text{(ii)} \quad \text{जीवन प्रत्याशा सूचक (LEI)} &= \frac{\text{वास्तविक जीवन प्रत्याशा} - 38}{39} \\ \text{(iii)} \quad \text{प्राथमिक साक्षरता सूचक (BLI)} &= \frac{\text{वास्तविक साक्षरता दर} - 0}{100} \end{aligned}$$

हम भारत के लिए 2021 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर PQLI की गणना करते हैं। जब IMR = 67, LE = 65 वर्ष और BL = 65%

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \text{शिशु मृत्यु दर सूचक (IMRI)} &= \frac{229 - 67}{220} = 0.74 \\ \text{(ii)} \quad \text{जीवन प्रत्याशा सूचक (LEI)} &= \frac{65 - 38}{39} = 0.69 \\ \text{(iii)} \quad \text{प्राथमिक साक्षरता सूचक (BLI)} &= \frac{65 - 0}{100} = 0.65 \\ \text{(iv)} \quad \text{पी क्यू एल आई (PQLI)} &= \frac{\text{IMRI} + \text{LEI} + \text{BLI}}{3} \\ &= \frac{0.74 + 0.69 + 0.65}{3} = \frac{2.08}{3} = 0.69 \end{aligned}$$

इस प्रकार भारत का 2001 में जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक PQLI = 0.69 था।

यह क्रिया करें

यदि 2011 में IMR = 47 प्रति 1000, BL = 74.04%, LE 67.13 वर्ष हो तो भारत के लिए 2011 का PQLI मालूम करें। (स्रोत : जनगणना रिपोर्ट, 2011)

4.9.2 मानव विकास सूचकांक (Human Development Index)

लार्ड मेधनाद देसाई तथा नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने HDI का निर्माण किया तथा मानव विकास सूचकांक पहली बार 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यू.एन.डी.पी. (UNDP) द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था।

4.9.2.1 एचडीआई की अवधारणा (Concept of HDI)

एचडीआई एक सरल, समग्र सूचकांक है जिस में मानव विकास के यथासंभव अधिक से अधिक पहलुओं को देखने और मानव विकास उपलब्धियों पर रैंकिंग तैयार करने का प्रयास करता है। मानव विकास की

अवधारणा अधिक गहरी और समृद्ध है। एचडीआई इस जटिल वास्तविकता को सरल बनाने का प्रयास करता है। एचडीआई तीन मौलिक आयामों – एक लंबा और स्वस्थ जीवन (Living a long & healthy life), ज्ञान (being educated) और सभ्य जीवन स्तर (Having Decent Standard of living) में बुनियादी मानव क्षमताओं में उपलब्धियों का एक समग्र सूचकांक है। इन तीन आयामों को दर्शाने के लिए तीन चर चुने गए हैं। (1) जीवन प्रत्याशा Life Expectancy (2) शैक्षिक उपलब्धि और Educational Achievement (3) प्रतिव्यक्ति कुल घरेलू उत्पाद (Per Capita GDP)।

4.9.2.2 HDI के निर्माण की विधि (Method of Construction of HDI)

HDI तीन संकेतकों पर आधारित है, (1) जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा मापी गई दीर्घायु (2) शैक्षिक उपलब्धि, जैसा कि वयस्क साक्षरता (दो तिहाई भार) और संयुक्त प्राथमिक माध्यमिक और तृतीयक नामांकन अनुपात (एक तिहाई भार) के संयोजन द्वारा मापा जाता है, और (3) अच्छा स्तरीय जीवन मापन जो कि वास्तविक जीडीपी द्वारा मापा जाता है इसे प्रति व्यक्ति पीपीपी (\$) द्वारा मापा गया जीवन स्तर। सूचकांक के निर्माण के लिए, इनमें से प्रत्येक संकेतक के लिए निश्चित न्यूनतम और अधिकतम मान स्थापित किए गए हैं, जो कि निम्नालिखित अनुसार हैं –

सारणी 4.5

सूचक (Index)	अधिकतम मूल्य	न्यूनतम मूल्य
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	85	25
व्यस्क साक्षरता दर (%)	100	0
संयुक्त सकल नामांकन अनुपात (%)	100	0
समायोजित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (PPPUS \$)	40,000	100

एचडी आई के किसी भी घटक के लिए अलग-अलग सूचकांकों की गणना तदनुसार की जा सकती है सामान्य सूत्र के अनुसार: तथा प्रत्येक मूल्य को 0 तथा 1 के बीच प्रस्तुत किया जाता है।

$$\text{सूचक का माप (Measurement of Index)} = \frac{\text{वास्तविक मूल्य} - \text{न्यूनतम मूल्य}}{\text{अधिकतम मूल्य} - \text{न्यूनतम मूल्य}}$$

प्रत्येक सूचक को प्राप्त करने के पश्चात मानवी विकास सूचकांक (HDI) तीनों सूचक मापों का ज्यामितिक औसत मालूम कर पता किया जा सकता है

$$\text{HDI} = \sqrt[3]{\text{जीवन प्रत्याश सूचकांक} \times \text{विद्यार्थी प्राप्ति सूचकांक} \times \text{वास्तविक प्रति व्यक्ति GDP सूचकांक}}$$

उदाहरण सहित मानवी विकास सूचकांक के माप के कदम (Steps for Construction of Human Development Index with Example)

1. **जीवन प्रत्याश सूचकांक (Life Expectancy Index)** : यदि किसी देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 75 वर्ष है तो उस देश के लिए जीवन प्रत्याशा सूचक होगा :

$$\text{जीवन प्रत्याशा सूचकांक} = \frac{75 - 25}{85 - 25} = \frac{50}{60} = 0.833$$

2. **शिक्षा सूचकांक (Education Index)** : शिक्षा सूचकांक व्यस्क साक्षरता सूचकांक तथा कुल दाखला सूचकांक संयुक्त रूप है। यदि किसी देश की व्यस्क साक्षरता दर 88 है तो व्यस्क साक्षरता सूचकांक होगा :

$$\text{व्यस्क साक्षरता सूचकांक} = \frac{88}{100 - 0} = 0.88$$

यदि किसी देश क संयुक्त प्रवेश दर 65 है तो कुल प्रवेश सूचकांक होगा :

$$\text{कुल प्रवेश सूचकांक} = \frac{65 - 0}{100 - 0} = 0.65$$

$$\begin{aligned} \text{शैक्षिक सूचकांक} &= \frac{2}{3} (\text{व्यस्क साक्षरता सूचकांक}) + \frac{1}{3} (\text{कुल प्रवेश सूचकांक}) \\ &= 0.88 + 0.65 \end{aligned}$$

$$= \frac{2}{3} (0.88) + \frac{1}{3} (0.65) = \left(\frac{1.76}{3} \right) + \left(\frac{0.65}{3} \right) = \frac{2.41}{3} = 0.803$$

3. **जी.डी.पी. (GDP Index)** : सूचकांक यदि देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (PPPUS &) 8840 हो तो जी. डी.पी सूचकांक होगा :

$$\text{जी.डी.पी. सूचकांक} = \frac{\text{Log}(8840) - \text{Log}(100)}{\text{Log}(40000) - \text{Log}(100)} = \frac{3.9465 - 2.0}{4.6021 - 2.0}$$

Log table का प्रयोग करने पर प्राप्त मूल्य

$$= \frac{2.93}{3} = 0.803$$

4. **मानवी विकास सूचकांक (Human Development Index)** : मानव विकास सूचकांक, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शैक्षिक सूचकांक व समयोजित प्रति व्यक्ति जी. डी. पी सूचकांक का ज्यामितिक औसत (Geometric mean) है जो निम्नलिखित अनुसार है :

$$\text{HDI} = \sqrt[3]{0.833 \times 0.803 \times 0.748}$$

$$\text{HDI} = \sqrt[3]{0.5003} = 0.794$$

सारणी 4.9 मानवी विकास सूचकांक श्रेणी बद्ध

क्रम	HDI का मूल्य	श्रेणी (Ranking)
(i)	0.80-1.00	उत्कृष्ट श्रेणी
(ii)	0.70-0.79	उच्च श्रेणी
(iii)	0.55-0.69	मध्यम श्रेणी
(iv)	0.55 से नीचे	निम्न श्रेणी

यह क्रिया करें

यदि किसी देश की जन्म समय जीवन प्रत्याशा 68 वर्ष, व्यस्क साक्षरता दर 82, सकल प्रवेश दर 71 तथा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (&PPP) 9330 हो तो HDI क्या होगा ? टिप्पणी करें

सारणी 4.10 भिन्न भिन्न देशों के मानवी विकास सूचकांक अनुसार श्रेणीबद्धता, 2019

क्रम	शीर्ष दस देश	HDI	क्रम	शीर्ष दस देश	HDI
1.	नार्वे	0.957	1.	नाइजर	0.394
2.	आयरलैंड	0.955	2.	केंद्रीय अफ्रीका गणतंत्र	0.397
3.	स्विटजरलैंड	0.955	3.	चैड	0.398
4.	हांगकांग (चीन)	0.949	4.	बुरुंडी	0.433
5.	आईसलैंड	0.947	5.	दक्षिणी सूडान	0.433
6.	जर्मनी	0.947	6.	माली	0.434
7.	स्वीडन	0.945	7.	बुकीना फासो	0.452
8.	ऑस्ट्रेलिया	0.944	8.	सियारा लियोन	0.452
9.	नीदरलैंड	0.944	9.	मोजाम्बीक	0.456
10.	डेनमार्क	0.940	10.	एरिट्रिया	0.459
भारत = 0.645 (क्रम 131)					

इस प्रकार मानवी विकास सूचकांक (HDI)= 0.794 है जो मानवी विकास के उच्च स्तर को दर्शाती है।

4.9.2.3 एच.डी.आई. का महत्व (Significance of HDI)

प्रत्येक देश के लिए HDI मूल्य यह दर्शाता है कि देश ने कुछ परिभाषित लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए कितनी दूरी तय की है। जैसे 85 वर्ष की औसत आय, सभी की शिक्षा तक पहुँच तथा अच्छा स्तरीय जीवन मापन। एच डी आई इन सभी तीन सूचकों को संयुक्त मापदंड के रूप में प्रस्तुत करता है तथा प्रत्येक चर (Variable) के लिए अधिकतम व न्यूनतम मूल्यों के 0 से 1 के मध्य एक स्केल में कम कर दिया जाता है। HDI दर्शाता है कि एक देश को अधिकतम 1 तक पहुँचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। एच डी आई के आधार पर भिन्न-भिन्न देशों की तुलना की जा सकती है। एच डी आई के अधिकतम मूल्य तथा किसी देश द्वारा एच डी आई के प्राप्त मूल्य में अंतर उस देश की विकास संबंधी कमी को दर्शाता है। इस कमी को कम से कम करने के उपाय खोजना प्रत्येक के लिए चुनौती पूर्ण कार्य है।

4.9.2.4 मानवी विकास सूचकांकी की उपयोगिता व सीमाएं (Usefulness and Limitations of HDI)

उपयोगिताएं (Usefulness)

1. भिन्न भिन्न समय के दौरान मानवी विकास के आधारभूत स्तर अथवा उसकी प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए एच डी आई (HDI) सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) का विकल्प प्रदान करता है। एचडीआई अन्य आर्थिक मापों को विस्थापित नहीं करता। बल्कि एक साधारण सामूहिक माप देकर अन्य माप जैसे GNP आदि के लिए पूरक का कार्य करता है।
2. कई देशों में भिन्न भिन्न जिलों अथवा क्षेत्रों की मानवी विकास दर की पहचान एच. डी आई के आधार पर की जाती है। अधिकांश देशों में HDI का प्रयोग योजना बद्धता के साधन के रूप में की जाती है।
3. एच डी आई का उपयोग विशेषतः उस समय किया जाता है जबकि अनुसंधान कर्ता विकास का संयुक्त माप चाहता है इस प्रकार के प्रयोग में अनुसंधान कर्ता द्वारा एच डी आई में कई सूचक कई बार जोड़ के प्रयोग करता है।

सीमाएं (Limitations)

HDI की कटु आलोचना हुई है, एक प्रभावशाली सामाजिक विकास के सूचक के रूप में HDI की कुछ सीमाएं हैं। HDI संबंधी कुछ प्रश्न उठाए गए हैं जिनकी संक्षिप्त समीक्षा इस प्रकार है :

1. एचडीआई के लिए केवल तीन ही सूचक क्यों लिए गए हैं ? क्या बहुत अधिक है अथवा कम ?
2. क्या विकास के मापन के लिए चयनित सूचक पर्याप्त है ? क्या प्रत्येक मापन के लिए संबंधित चर (Variables) बहुत ज्यादा है या बहुत कम ?
3. मानवी विकास सूचकांक बनाने के लिए प्रयोग किए गए आंकड़े कितने क नवीन हैं क्या सूचकांक तैयार करते समय कुछ त्रुटियाँ रह जाती हैं जो परिणामों को प्रभावहीन करती है।
4. क्या भिन्न भिन्न सूचकों के लिए न्यूनतम व अधिकतम मूल्यों का चयन उपयुक्त है? अथवा यह मनमानी है? किसी भी स्थिति में वैकल्पिक मूल्यों के लिए मापन कितना सुदृढ़ है ?
5. क्या सभी सूचकों को समान महत्वों (भार) देना उचित है ? और महत्व (भार) देने की योजनाएँ मापन के लिए कितनी संवेदनशील हैं?

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतर प्रश्न HDI की कार्यप्रणाली से संबंधित हैं। (UNDP) निरंतर इस कार्यप्रणाली के सुधार कार्य में लगा हुआ है।

4.10 निष्कर्ष (Conclusion)

मानव पूँजी निर्माण और मानव विकास के आर्थिक सामाजिक लाभों से तो सभी परिचित हैं। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान करती आ रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ समाज के सभी वर्गों को सुनिश्चित रूप से सुलभ करायी जानी चाहिए, ताकि आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ समता की प्राप्ति भी हो सके। भारत के पास वैज्ञानिक और तकनीकी जन शक्ति है। समय की माँग है कि गुणात्मकता में सुधार करें तथा इस प्रकार की परिस्थितियों का भी निर्माण करें कि इन्हें भारत में पर्याप्त रूप से प्रयुक्त किया जा सके।

पुनरावर्तन (RECAP)

- शिक्षा में निवेश मानव को मानव पूँजी में परिवर्तित करता है। इस प्रकार मानव पूँजी बढ़ी हुई उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक अर्जित योग्यता है और समझ बूझ से किए गए निवेश निर्णयों का परिणाम है, जो भविष्य में आय के स्रोतों में वृद्धि की अपेक्षा से किए हैं।
- शिक्षा में निवेश, कार्य स्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, प्रवसन और सूचना मानव पूँजी निर्माण के स्रोत हैं।
- भौतिक पूँजी की संकल्पना मानव पूँजी की संकल्पना निर्धारण का आधार है। पूँजी निर्माण के दोनों प्रकारों में कुछ समानताएँ और कुछ विषमताएँ हैं।
- मानव पूँजी निर्माण में निवेश को प्रभावपूर्ण तथा संवृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है।
- मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मनुष्यों के कल्याण के लिए अभिन्न हैं, क्योंकि जब लोगों के पास पढ़ने और लिखने तथा दीर्घायु तथा स्वस्थ जीवन की योग्यता होगी, तभी वे उन मूल्यों का मापन करने में समक्ष होंगे जिनको वे महत्व देते हैं।
- कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय का प्रतिशत सरकार द्वारा शिक्षा को दिए गए महत्व को दर्शाता है।
- सेहत मानव कल्याण, शारीरिक एवं मानसिक तंदरुस्ती का मापदंड है।
- स्वतंत्रता के बाद सेहत सुविधाओं के भौतिक प्रबंधन एवं सेहत सूचकों में महत्वपूर्ण सुधार आया है।
- सरकारी सेहत प्रणाली एवं सुविधाएँ बहुत से लोगों के लिए अप्रयाप्त हैं।
- सेहत सुविधाएँ का उपभोग करने में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में और अमीर-गरीब में बहुत अंतर है।
- कन्या भ्रूण हत्या और मृत्यु दर में बढ़ते मामलों से भारत में औरतों की सेहत एक चिंता का कारण बन चुकी है।
- नियंत्रण निजी क्षेत्रक में सेहत सुविधाएँ स्थिति में सुधार कर सकती है। परंतु गैर-सरकारी संगठनों और समुदायिक भागीदारी द्वारा सेहत सुविधाएँ प्रदान करना और सेहत के प्रति जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है।
- दवाईयों की कुदरती प्रणालियों पर खोज होनी चाहिए और इसके प्रयोग से जनतक सेहत सुविधाओं को सुदृढ़ करना चाहिए। भारत में मेडिकल टुरिज्म की वृद्धि की बहुत संभावनाएँ हैं।
- जीवन का भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक एक साल की आयु होने तक जीवन की संभावना, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर पर आधारित है।
- मानव विकास लोगों द्वारा चुनाव और उनके द्वारा प्राप्त किए गए कल्याण के स्तर को बढ़ाने की प्रक्रिया है।
- मानव विकास सूचकांक एक देश में लंबी आयु, शिक्षा और जीवन स्तर में औसत प्राप्ति का मापन करता है।

अभ्यास

1. बहु-वैकल्पिक प्रश्न (Multiple Choice Questions)

- (i) शिक्षा मनुष्य को क्या प्रदान करती है?
- (क) बढ़िया पद (ख) समायोजन (Adjustment) का सामर्थ्य
- (ग) समझने की योग्यता (घ) उपरोक्त सभी
- (ii) निम्नलिखित में से भौतिक पूंजी कौन सी है?
- (क) व्यक्तिगत (ख) भूमि
- (ग) डाक्टर (घ) अध्यापक
- (iii) मानव पूंजी के निर्माण से होता है।
- (क) उत्पादकता में कमी
- (ख) साधनों का उपयुक्त उपयोग
- (ग) सहभागिता में कमी
- (घ) नव-परिवर्तन तथा अनुसंधान की कमी
- (iv) मानव पूंजी के निर्माण के माप से कौन सा सूचक संबंधित हैं?
- (क) CPI (उपभोगिता सूचक अंक) (ख) HDI
- (ग) PQLI (घ) ख और ग दोनों
- (v) भारत में मानव पूंजी निर्माण के मार्ग में कौन सी रुकावट नहीं है?
- (क) निम्न जीवन स्तर (ख) कम जनसंख्या
- (ग) साधनों की कमी (घ) निपुणता का विकास

2. खाली स्थान भरो (Fill in the Blanks)

- (i) स्वास्थ्य तथा शिक्षा के ऊपर निवेश निर्माण करने में मदद करता है।
- (ii) मानव-पूंजी निर्माण तथा आर्थिक विकास में सम्बन्ध है।
- (iii) एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को कहा जाता है।
- (iv) HDI दर्जे में सुधार को दर्शाता है।
- (v) मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा कानून का सम्बन्ध आयु के बच्चों से है।

3. सही/गलत वाले प्रश्न (True/False)

- (i) किसी राष्ट्र के लिए अध्यापक, डाक्टर तथा इंजीनियर मानव-पूंजी है।
- (ii) मानव-पूंजी निर्माण तथा आर्थिक विकास में विपरीत सम्बन्ध है।

- (iii) भारत में शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर जरूरत से ज्यादा खर्च होता है।
- (iv) मानव विकास सूचकांक (HDI) आबादी में बढ़ौतरी का माप करता है।
- (v) निपुणता का निकास मानव-पूंजी निर्माण की समस्या नहीं है।

4. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (Very Short Answer Questions)

- (i) मानव-पूंजी क्या होती है?
- (ii) मानव-पूंजी निर्माण के प्रमुख स्रोत कौन से हैं?
- (iii) मानव-पूंजी निर्माण की आवश्यकता क्यों है?
- (iv) प्रवास से क्या अभिप्राय है?
- (v) AYUSH (आयुष) क्या है?

5. लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Questions)

- (i) मानव-पूंजी तथा मानव विकास में अन्तर बताओ।
- (ii) सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) पर नोट लिखो।
- (iii) PQLI का निर्माण किस आधार पर किया जाता है?
- (iv) 'सब के लिए शिक्षा' (Education For All) पर नोट लिखो।
- (v) HDI की दो सीमाएं बताओ।
- (vi) मानव विकास सूचकांक के उपयोग का वर्णन करो।
- (vii) भारत में स्वास्थ्य संभाल प्रणाली की कमियों को संक्षेप में बताइये।
- (viii) मानव पूंजी निर्माण में कौन से कारक योगदान देते हैं ?
- (ix) भारत में मानव पूंजी निर्माण की प्रमुख समस्याएं कौन-कौन सी हैं ?
- (x) शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता के पक्ष में दलील दें।

6. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Questions)

- (i) मानव-पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं? मानव-पूंजी के स्रोतों का विस्तार सहित वर्णन करो।
- (ii) किसी देश के लिए मानव-पूंजी निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है? आर्थिक विकास में इसकी भूमिका की व्याख्या करो।
- (iii) भारत में शिक्षा तथा स्वास्थ्य की स्थिति सम्बन्धी विस्तार सहित व्याख्या करो।
- (iv) भारत में मानव-पूंजी निर्माण की प्रमुख समस्याएं कौन-कौन सी हैं? भारत में मानव-पूंजी निर्माण की गति तेज करने के लिए सुझाव दें।
- (v) भारत में स्त्रियों का स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण चुनौती कैसे है? स्वास्थ्य संभाल कार्यक्रम की प्रभावशीलता में बढ़ौतरी कैसे की जा सकती है?

सुझायी गई अन्य गतिविधियां (Suggested Additional Activities)

- मानव विकास सूचकांक (HDI) की गणना कैसे की जाती है? विश्व-मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है?
- क्या भारत, भविष्य में एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है? अपनी कक्षा में विचार चर्चा करो।
- सारणी 4.2 में दिये गये आंकड़ों की व्याख्या करो।
- एक पढ़े-लिखे व्यक्ति के रूप में शिक्षा के विकास के लिए आपका योगदान क्या होगा? (उदाहरण : प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति को पढ़ाये) (Each one-Teach one)
- उन स्रोतों की सूची बनाओ जो शिक्षा, स्वास्थ्य तथा श्रम सम्बन्धी ज्ञान प्रदान करते हैं।
- केन्द्रीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्टों को पढ़ो तथा प्राप्त जानकारी को संक्षेप में लिखो। आर्थिक-सर्वेक्षण में सामाजिक-क्षेत्र सम्बन्धी पाठ को पढ़ो। यह सूचना केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित मंत्रालय की वेबसाइटों से डाउनलोड की जा सकती है।

References

Books :

- BECKER, GARY S. 1964. Human Capital. 2nd Edition, Columbia University Press, New York
- FREEMAN, RICHARD. 1976. The Over Educated American. Academic Press, New York
- IGNOU NOTES. 2017. Alternative Recent Indicators of Social Development, Unit -22 (Block-8), School of Social Sciences, Indira Gandhi National Open University, New Delhi. -<http://egyankosh.ac.in>
- IGNOU NOTES. 2017. Social Indicators of Development, Unit-6 (Block-2), School of Social Sciences, Indira Gandhi National Open University, New - <http://egyankosh.ac.in>
- KALAM, A.P.J. ABDUL WITH Y.S. RAJAN. 2002. India 2020: A Vision for the New Millennium. Penguin Books, Delhi
- PARIKH, KIRIT S. AND RADHAKRISHNA (Eds.). 2005. India Development Report 2004-05. Oxford University Press, Delhi
- SIDDHARTHAN, N.S. AND K. NARAYANAN (Eds.). 2013. Human Capital and Development - The Indian Experience. Springer, New Delhi

Government Reports

- Annual Reports (for various years), Ministry of Education, Government of India
- Educational Statistics At a Glance, Ministry of Education, (for various years), Government of India

- India Human Development Report 2011: Towards Social Inclusion, Planning Commission, Government of India
- ICMR et al. 2017. India: Health of the Nation States: The India State Level Disease Burden Initiative, Indian Council of Medical Research, Public Health Foundation of India and, Institute for Health Metrics and Evaluation, New Delhi
- National Health Profile (NHP) of India (for various years), Central Bureau of Health Intelligence, Government of India, New Delhi
- National Family Health Survey (NFHS-4) 2015-16, Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India
- National Education Policy 2020, Ministry of Education, Govt. of India, New Delhi
- Report of the National Commission on Macroeconomics and Health-2005 Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, New Delhi
- The World Health Report 2002. Reducing Risks, Promoting Healthy Life, World Health Organisation, Geneva
- UNDP: 2005. Human Development Report (Annual), Oxford University Press.
- World Development Report 2004. The World Bank, Washington DC. India Infrastructure Report 2004. Oxford University Press, New Delhi
- World Health Statistics 2014, World Health Organisation, Geneva

Websites

- | | |
|--|---|
| • http://egyankosh.ac.in | • http://epathshala.nic.in |
| • www.education.nic.in | • www.cbse.nic.in |
| • www.ugc.ac.in | • www.aicte.ernet.in |
| • www.ncert.nic.in | • www.finmin.nic.in |
| • www.mospi.nic.in | • http://nroer.gov.in |

On Health Related Issues

- <http://www.aiims.edu>
- <http://www.whoindia.org>
- <http://mohfw.nic.in>
- www.apollohospitalsgroup.com
- www.worldbank.org
- www.cbhidghs.nic.in



इकाई तीन

भारतीय अर्थविवस्था :
वर्तमान चुनौतियाँ

5

ग्रामीण विकास

यह पाठ पढ़ने के बाद, आप निम्नलिखित के बारे में जानने के योग्य हो जाएंगे :-

- ग्रामीण विकास की स्थिति और इसकी महत्वपूर्ण मुद्दे ;
- ग्रामीण ऋण आवश्यकता : पूर्व और वर्तमान स्थिति ;
- ग्रामीण ऋण के विभिन्न स्रोत : संस्थागत, गैर-संस्थागत और सहायक स्रोत ;
- पुनर्वित्त एजेंसी के रूप में नाबार्ड की भूमिका ;
- नाबार्ड द्वारा किया गया ऋण-वितरण विश्लेषण ;
- संस्थागत और गैर-संस्थागत स्रोतों की तुलना ;
- ग्रामीण विकास के लिए सरंचना ।

अध्याय – 5

ग्रामीण विकास (ग्रामीण ऋण के माध्यम से)

“गांव राष्ट्रीय शरीर की कोशिका (शक्ति) है और राष्ट्रीय शरीर के तंदरूस्त और सही ढंग से विकसित होने के लिए इस कोशिका का तंदरूस्त और सही ढंग से विकसित होना जरूरी है।”

श्री अरविंदो

5.1 भूमिका (Introduction)

ग्रामीण विकास व्यापक शब्द विकास का ही एक भाग है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक विकास की आवश्यकता है। अधिकांश आबादी अभी भी ग्रामीण है। उनका जीवन स्तर औसत है। ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 3/4 भाग हैं। उनमें से 2/3 से अधिक कृषि निर्भर हैं। 22 फीसदी ग्रामीण लोगों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही इसलिए इन्हें ‘गरीबी रेखा’ (Below poverty line) से नीचे माना जाता है। इसलिए भारत को प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।

समग्र दृश्य (Overall Scenario):

- पिछले कई दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अधिकतम हिस्सा लगभग उच्च से औसत की ओर जा रहा है।
- आर्थिक सुधारों (1991) के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर लगभग कोई ध्यान नहीं दिया गया बल्कि उद्योग और सेवा क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया गया। 1991-2012 में कृषि विकास दर लगभग 3% थी।
- वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में ग्रामीण हिस्सेदारी काफी हद तक घट रही है।

हमारे योजनाकारों के अनुसार उत्पादक सार्वजनिक निवेश में गिरावट, अपर्याप्त आधारभूत संरचना, अन्य क्षेत्रों में रोजगार के विकल्पक अवसरों की कमी, अस्थायी रोजगार में वृद्धि और अकुशल ऋण वितरण प्रणाली ने ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को और धीमा कर दिया है। इसलिए ग्रामीण विकास हमारी अर्थव्यवस्था के विकास की कुंजी है।

विकास के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार : ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण वित्त ही एकमात्र आवश्यक ईंधन है जो अभी तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचा है।

5.2 ग्रामीण विकास क्या है ? (Meaning of Rural Development)

‘ग्रामीण विकास’ एक व्यापक शब्द है। यह मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं। साधारण शब्दों में ग्रामीण विकास का अर्थ ग्रामीण लोगों के जीवन गुणवत्ता में सुधार से है।

“ग्रामीण विकास, ग्रामीण-कृषि क्षेत्र के तकनीकी परिवर्तन के साथ-साथ औद्योगीकरण और शहरीकरण के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है”

आधुनिक सिद्धांत

भारत के विकास के लिए जिन क्षेत्रों में नई और सार्थक पहल करने की आवश्यकता बनी हुई है, वे इस प्रकार हैं :

5.2.1 ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नई चुनौतियाँ (New Challenges for Rural Development)

- मानव संसाधन विकास :
 - साक्षरता, विशेषकर नारी साक्षरता, शिक्षा और कौशल का विकास
 - स्वास्थ्य, जिसमें स्वच्छता और जन-स्वास्थ्य दोनों शामिल हैं।
- भूमि-सुधार
- प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादक संसाधनों का विकास
- बुनियादी ढांचे का विकास जैसे बिजली, सिंचाई, ऋण प्रणाली, कृषि विपणन, गांव का निर्माण और आसपास के राजमार्गों के साथ लिंक सड़कों का निर्माण, कृषि अनुसंधान और विस्तार के लिए सुविधाएं, ग्रामीण परिवहन सुविधाएं और आवश्यक जानकारी का प्रसार।
- गरीबी उन्मूलन के लिए विशेष उपाय और समाज के कमजोर वर्गों को उत्पादक रोजगार प्रदान करना।

इन्हें कीजिए

- अपने क्षेत्र के समाचार पत्रों का अध्ययन कर मासिक आधार पर उनमें उठाई गई ग्रामीण समस्याओं से जुड़े प्रश्नों तथा सुझाए गए उपायों की जानकारी संग्रह करें। आप निकट के किसी गाँव में जाकर क्षेत्र के जन समुदाय की समस्याओं की पहचान करें। कक्षा में इसकी चर्चा करें।
- उपरोक्त समस्याओं के बारे में आपकी क्या राय है, इनका समाधान कैसे किया जा सकता है ?

“ग्रामीण विकास का अर्थ है : कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों से जुड़े ग्रामीण जीवन के सामाजिक और आर्थिक उत्थान की एक निरंतर और व्यापक प्रक्रिया जिसमें विशेष रूप से ग्रामीण निवेश की आवश्यकता है।”

5.3 ग्रामीण साख / ग्रामीण वित्त (Rural Credit / Rural Finance)

अब तक हमने ग्रामीण विकास के अर्थ और प्रक्रिया के बारे में पढ़ा है। ग्रामीण वित्त या ग्रामीण ऋण, ग्रामीण विकास की संपूर्ण प्रक्रिया की वास्तविक कुंजी है। इसका सीधा सा मतलब है ग्रामीण लोगों की सबसे बुनियादी आवश्यकता वित्तपोषण है इसके अलावा, छोटे और सीमांत किसानों के साथ ग्रामीण परिवारों के फसल की बिजाई और आय सृजन के बीच अंतर के कारण वित्त के विभिन्न स्रोतों से प्रभावी ऋण की सख्त आवश्यकता

होती है। किसान बीज, औज़ार, खाद और परिवार के अन्य खर्चें आदि पर आरंभिक निवेश को पूरा करने के लिए ऋण के विभिन्न सुलभ स्रोतों से उधार लेते हैं। इसलिए वास्तविक आय को अपेक्षित/संभावित आय में स्थानांतरित करने के लिए एक प्रभावी और कुशल ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली महत्वपूर्ण है।

“ग्रामीण विकास की रुकावटों को दूर करने के लिए ग्रामीण ऋण ही मुख्य कारक/समाधान है, जो सभी बाधाओं को दूर करने के लिए बहुत ध्यान की मांग करता है।”

5.3.1 ग्रामीण ऋण के प्रकार (Types of Rural Credit)

- **अल्पकालीन ऋण (Short Term credit) :** यह ऋण मुख्यतः बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए होता है। इसकी अवधि 15 महीने है। इसकी प्रकृति आवर्ती है। फसल की कटाई के बाद इसका भुगतान किया जाता है।
- **मध्य-अवधि ऋण (Medium Term credit) :** यह ऋण मुख्य रूप से कृषि उपकरणों और बिजली के पंप सेट, उपकरण, बीज-ड्रिल जैसी छोटी मशीनरी के लिए है। यह 5 साल की अवधि तक के लिए है। कभी-कभी यह 10 साल तक भी हो सकता है।
- **दीर्घकालीन ऋण (Long Term credit) :** यह पूंजी निवेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जैसे अतिरिक्त भूमि की खरीद, पुराने ऋण जिन्हें चुकाया नहीं जा सकता है, ट्रैक्टर / कंबाइन की खरीद आदि के लिये। आम तौर पर इसकी सीमा 10-20 साल होती है।

इन्हें कीजिए

- सरकार की वेबसाइट <https://www.rural.nic.in> से हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं तथा उनके उद्देश्यों की सूची तैयार करें। अपने क्षेत्र/ग्रामीण पड़ोस के क्षेत्रों में इन योजनाओं में से किसी एक को कैसे लागू किया जाता है, इसका विवरण एकत्र करें। कक्षा में अपने अवलोकन पर चर्चा करें।

5.3.2 ग्रामीण ऋण के स्रोत (Sources of Rural Credit)

विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद की अवधि के दौरान और आधुनिक समय में ग्रामीण कृषि के आधुनिकीकरण के साथ ही ऋण की आवश्यकता कई गुना बढ़ गई है। ग्रामीण ऋण के स्रोतों का मुख्य वर्गीकरण इस प्रकार है :

- (i) गैर-संस्थागत स्रोत (Non-Institutional Sources)
- (ii) संस्थागत स्रोत (Institutional Sources)

गैर-संस्थागत स्रोत (Non-institutional Sources)

- साहूकार
- व्यापारी और कमीशन एजेंट
- अमीर जमींदार
- रिश्तेदार और दोस्त

संस्थागत स्रोत (Institutional Sources)

- पंचायत (तीन स्तरीय व्यवस्था)
- सहकारी ऋण समितियां
- व्यावसायिक बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
- वित्त व्यवस्था के अन्य स्रोत : स्वै वित्त के लिए स्वयं सहायता समूह

(i) गैर-संस्थागत स्रोत (Non-Institutional Sources) : ये पारंपरिक स्रोत हैं जो अभी भी ग्रामीण ऋण में 44% की हिस्सेदारी रखते हैं। इनका विवरण निम्नलिखित दिया गया है :-

(a) साहूकार (Money Lenders) : साहूकार बिना जमानत के भी ऋण प्रदान करते हैं लेकिन बहुत अधिक ब्याज दर वसूलते हैं। यह 2 प्रकार के हैं :-

- (i) किसान साहूकार (जो खेती और उधार देने का काम साथ-साथ करते हैं)
- (ii) पेशेवर साहूकार (जो मूल रूप से व्यापारी हैं) ग्रामीण क्षेत्रों में, उधार देने में इनकी भूमिका कम हो रही है लेकिन वे अभी भी ग्रामीण लोगों के बीच लोकप्रिय हैं।

साहूकार प्रणाली के दोष :-

- बहुत अधिक ब्याज दर
- भूमि पर अतिक्रमण
- ऋण खातों में हेराफेरी
- सस्ती उत्पाद बिक्री के लिए मजबूर करना

(b) व्यापारी और कमीशन एजेंट (Traders & Commission Agents) : वे किसानों को उनकी फसल गिरवी रखकर, उच्च ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं। वह फसलों को सिर्फ अपने निश्चित किये मूल्य पर ही खरीदते हैं।

(c) अमीर जमींदार (Rich Landlord) : ये भी जमानत पर ही कर्जा देते हैं। वे वास्तव में पेशेवर साहूकार जैसे हैं। वे अत्यधिक ब्याज लेते हैं और छोटे किसानों को लूटते हैं। हालांकि, सीमांत और छोटे किसान अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिकतर उनसे ऋण लेते हैं क्योंकि इसमें लगभग कोई कानूनी औपचारिकता शामिल नहीं होती है।

(d) रिश्तेदार और दोस्त (Relatives & Friends) : किसान अपने रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों से भी उधार लेते हैं। इन अनौपचारिक ऋणों पर आमतौर पर कोई ब्याज दर नहीं होती है और इन्हें फसल के बाद चुकाया जाता है। लेकिन कभी-कभी इन ऋणों का उपयोग अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है।

(ii) संस्थागत संसाधन (Institutional Sources) : ये उधार देने और उचित ब्याज दर वसूलने के औपचारिक तरीके हैं। ये स्रोत मुख्य रूप से 1969 के बाद उभरे जब भारत ने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से संस्थागत ऋण की एक प्रणाली को अपनाया।

संस्थागत स्रोतों के उद्देश्य (Objectives of institutional sources) :

- जरूरतमंद किसानों को उचित ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना।
- छोटे और सीमांत किसानों को उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करके सहायता करना।

सारणी 5.1 ग्रामीण ऋण में संस्थागत स्रोत का (%) हिस्सा

स्रोत	1980-81	2000-01	2021-22
सहकारी बैंक (Cooperative Bank)	61.6	39.4	12.30
व्यावसायिक बैंक (Commercial Bank)	38.4	52.6	76.60
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs)	-	8.0	11.10
कुल	100	100	100

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण (2013-14, 2015-16 और 2022-23), RBI की ग्रामीण साख रिपोर्ट, (2021-2022)

प्रमुख संस्थागत संसाधनों की भूमिका और योगदान को नीचे समझाया गया है :-

(a) पंचायतें (Panchayat) : देश के वास्तविक विकास के लिए स्थानीय स्वशासन का होना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थानीय स्तर ही वास्तविक क्षेत्र है जहाँ नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया जाना है और इस प्रकार सरकार स्थानीय वर्तमान समस्याओं और मुद्दों को जान सकती है। यह राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ही थे जिन्होंने ग्राम पंचायत के महत्व को ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में महसूस किया और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायत के विशेष योगदान की बात कही। उनके आग्रह पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में खंड (iv) को जोड़ा गया। सामुदायिक विकास (Community Development Programme) कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को ग्रामीण व्यक्तियों की बुद्धिमान और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से स्थानीय लोगों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अस्तित्व को बहाल और पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया था। सरकार की सिफारिश पर बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में एक बहुत ही वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' शब्द पहली बार इस समिति ने ही दिया।

इनकी महत्वपूर्ण सिफारिश त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना थी अर्थात् ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। अपनी अनूठी भूमिका के माध्यम से यह प्रणाली ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में भारत ने संविधान में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों के माध्यम से स्थानीय सरकारों की शुरुआत की जिसमें पंचायत और नगर पालिकाएं शामिल थीं। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सार्थक क्रियान्वयन में अनूठी भूमिका निभाने के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।

3-स्तरीय प्रणाली के विकास कार्य :

- विभिन्न सरकारी विकास योजनाओं और कार्यक्रमों का लागू करना।
- विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान भी करती है।
- यह ग्रामीणों से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में नकद या गैर-नकद या दोनों तरह की सहायता का अनुरोध करता है।

- यह विभिन्न सार्वजनिक समस्याओं, शिक्षा, परिवार कल्याण कार्यक्रमों और योजनाओं का समर्थन करता है।
- यह कर या शुल्क आदि पर और ग्राम पंचायत से जुड़े मामलों पर भी विचार करती है।
- यह गावों में सार्वजनिक निर्माण और रख-रखाव के कार्य जैसे : सड़क, पुल, स्कूल और अस्पताल निर्माण आदि भी करती है।

(b) सहकारी ऋण समितियां (Cooperative Credit Societies) : प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACs) और कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (ARDBs) लघु और दीर्घकालिक ग्रामीण ऋण प्रदान करते हैं। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य कम ब्याज दर और समय पर ऋण प्रदान करना है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसी) द्वारा अल्पकालिक ऋण प्रदान किया जाता है। इसके बावजूद साहूकारों के प्रभाव को कम नहीं किया जा सका। 1980-81 में इन समितियों की हिस्सेदारी 61.6% थी जो 2021-22 में घटकर 13% रह गई है। यह मुख्य रूप से वाणिज्यिक बैंकों के बेहतर प्रदर्शन का परिणाम था।

सीमाएं (Limitations) :

- अमीर किसानों पर अधिक ध्यान देना
- ऋण का तुलनात्मक रूप से कम वितरण
- कर्ज की वसूली में देरी
- कम नकद भंडार और खराब नकद प्रबंधन
- वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी

(c) व्यावसायिक बैंक (Commerical Banks) : 1969 तक ग्रामीण वित्त में इन बैंकों की हिस्सेदारी बहुत कम (1%) थी। हालांकि, राष्ट्रीयकरण (1969) के बाद इन बैंकों ने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दोनों माध्यमों से ग्रामीण ऋण उपलब्ध कराना शुरू किया। उर्वरकों, बीजों और कई अन्य उत्पादन कारकों के लिए भी अप्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ये बैंक भंडारण, विपणन, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए भी ऋण प्रदान करते हैं। यह भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य सरकार को कृषि फसलों की खरीद के लिए ऋण भी प्रदान करते हैं। कुल ग्रामीण ऋण में उनका हिस्सा सहकारी समितियों की तुलना में कम था लेकिन 1991 के बाद उनका हिस्सा बढ़कर 52.6% (2000-01) हो गया और वर्तमान में यह 76% है।

एसबीआई और कुछ अन्य बैंक 'ग्राम दत्तक ग्रहण कार्यक्रम' योजनाओं को अपना रहे हैं। 2010 में एसबीआई ने उस योजना को एक नए नाम 'एसबीआई का अपना गांव' के साथ पुनर्जीवित किया है।

(d) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) : ये लगभग हर गांव में स्थापित हैं। ये बैंक उन क्षेत्रों में खोले जाते हैं जहां बैंकिंग सुविधा नहीं है। यह प्राथमिक स्तर पर, वित्तीय समावेशन लाना चाहता है। इस बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को छोटे किसानों, खेत मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों और अन्य जरूरतमंद ग्रामीण लोगों को सीधे ऋण प्रदान करने के लिए की गई थी। ये बैंक अपने ऋण का 90% समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को देते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 56 है लेकिन उनमें से 2020 में केवल 43 बैंक ही कार्यशील हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आर.आर.बी. हैं। 2000-01 में कुल संस्थागत ऋण में उनकी हिस्सेदारी 8% थी लेकिन अब यह 2021-22 में बढ़कर 11% हो गई है। समय के साथ इनका महत्व बढ़ता गया।

(e) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD

/ नाबार्ड) : ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इससे वित्त की मांग कई गुना बढ़ गई। आर.बी.आई. ने ग्रामीण ऋण की आवश्यकता को देखते हुए शिवारामन समिति का गठन किया। अतः इस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसके गठन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 50% हिस्सेदारी और बाकी हिस्सा आर.बी.आई. द्वारा किया गया। आरबीआई गवर्नर, नाबार्ड के अध्यक्ष भी हैं। यह (नाबार्ड) विभिन्न संस्थागत स्रोतों जैसे राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंकों, कृषि-ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों आदि को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रियायती ऋण प्रदान करने के लिए, सभी आश्रित संस्थानों को रियायती पुनर्वित्त सहायता भी प्रदान करता है। यह विश्व बैंक और अन्य संस्थागत एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को चलाने में भी मदद करता है। यह विभिन्न कृषि और ग्रामीण विकास अनुसंधानों को भी बढ़ावा देता है।



कार्य (Functions) :

- अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है।
- राज्य और अनुमोदित संस्थानों को पुनः ऋण प्रदान करता है।
- संगठनों के समन्वय में मदद करता है।
- शोध कार्य को प्रोत्साहित करता है।
- पुनर्वित्त और सहायता एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- एक निरीक्षण एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है।

सारणी 5.2 नाबार्ड द्वारा वित्त का वितरण (स्रोत के अनुसार) (2019-21)

S.No.	वित्त-स्रोत	2019-20		2020-21		2021-22 (provisional GLC data)	
		वितरित राशि [cr.]	% हिस्सा	वितरित राशि [cr.]	% हिस्सा	वितरित राशि	% हिस्सा
1	SCBs	52042	67	57095	61.53	76736	66.24
2	RRBs	10849	14	15157	16.34	14389	12.42
3	StCBs	8069	10	6200	6.68	11454	9.89
4	SCARDBS	2147	3	2976	3.21	2541	2.19
5	NABARD Subsidiaries	1163	1	1121	1.21	1400	1.21
6	NBFCs	3910	5	10237	11.03	9320	8.05
		78180	100	92786	100	115840	100

स्रोत : नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22

SBCs अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, RRBs-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, StCBs-राज्य सहकारी समितियां, StCBS-राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, NBFCs-गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां

सारणी नं : 5.2 पुनर्वित्त एजेंसी के रूप में नाबार्ड के कार्य को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

- दूसरे वित्त संस्थानों की तुलना में नाबार्ड ने SCBs को अधिकतम वित्तीय सहायता दी है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को (2019-20) में 67% और (2021-22) में 66.24% वित्तीय सहायता दी गई थी।
- राज्य सहकारी बैंकों और आरआरबी को किया गया वितरण (9-13)% के बीच रहा।
- SCARDBs, नाबार्ड सहायक कंपनियां और एनबीएफसी सबसे कम वित्तपोषित थे।

वित्त के कुछ अन्य स्रोत (Some Other Sources of Finance)

(a) सेवा क्षेत्र पहुंच (Service Area Approach) : इसे 1 अप्रैल, 1989 को लॉन्च किया गया था। यह ग्रामीण वित्त के लिए 'अग्रणी बैंकों' द्वारा शुरू किया गया था। इसके तहत प्रत्येक अर्ध-शहरी और ग्रामीण वाणिज्यिक बैंक शाखाओं के आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं और संबंधित शाखा के तहत क्षेत्र की ग्रामीण ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसने वित्त प्रक्रिया की खामियों (दोहराव) को खत्म करने में मदद की। यह योजना 5 चरणों में लागू की गई :-

- सेवा क्षेत्र की पहचान।
- लाभार्थियों की पहचान करना और उनके लिए आवश्यक वित्तपोषण का मूल्यांकन करना।
- उनकी आवश्यकताओं के लिए ऋण योजनाएँ तैयार करना।
- उपरोक्त योजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन के लिए समन्वय।
- आवृत्ति वितरण और ऋण दुहराव से बचाव के लिए निरंतर निगरानी।

(b) स्थानीय क्षेत्रीय बैंक (Local Area Bank) : इन बैंकों की स्थापना निजी क्षेत्र द्वारा 1996 में ग्रामीण बचत बढ़ाने और ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इन बैंकों का कार्य क्षेत्र राज्य के निकटवर्ती 3 जिलों तक होता है। ये बैंक आरबीआई के दायरे में आते हैं और कृषि और ग्रामीण क्षेत्र सहित स्थानीय क्षेत्र की जरूरतों के लिए प्रभावी ढंग से काम करते हैं।

(c) कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजनाएं (Agricultural & Rural Credit Support Scheme) : किसान और ग्रामीण जनसंख्या लगातार कर्ज के बोझ से जूझ रही है इसलिए उनके बोझ को कम करने के लिए यह योजना 15 मई 1990 को शुरू की गई थी। इन वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से, आरआरबी और सहकारी समितियों द्वारा दिए गए 10000 रुपये तक के ऋण को माफ किया गया था। 2008-09 के बजट में सरकार ने कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना को फिर से शुरू किया। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया गया। यहाँ तक की धनी जमींदार को भी उचित ऋण राहत मिली। इसके तहत 4 करोड़ किसान लाभान्वित हुए।

(d) किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCCs) : यह योजना विशेष रूप से उत्पादक किसानों के लिए शुरू की गई थी जो 5000 रुपये या उससे अधिक के ऋण के लिए पात्र थे। अब इस योजना के अंतर्गत 3,00,000 रुपये

का कर्जा 4% व्याज पर लिया जा सकता है। इसे 1998 में लॉन्च किया गया था। उन्हें पासबुक के साथ किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए। बिना किसी औपचारिकता के इस योजना के तहत ऋण प्रदान किये गए। भुगतान अवधि 12 महीने थी। के.सी.सी. धारकों के लिए कम से कम ब्याज दर 2 प्रतिशत और औसत ब्याज दर 4 प्रतिशत तक थी यह कार्ड **किसान सम्मान निधि योजना** के साथ जोड़ दिए गए हैं और इसके अंतर्गत किसान 6000 रुपये तक की आमदन सहायता ले सकते हैं। के.सी.सी. धारक के पास आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए व्यक्तिगत बीमा कवर था। अब तक 13 करोड़ पात्र लाभार्थियों को KCCs जारी किये गये हैं।

(e) कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (Agricultural & Rural Development Bank) : प्राथमिक कृषि विकास बैंक 15-20 साल के कार्यकाल के लिए ऋण प्रदान करते हैं। ये बैंक ट्रैक्टर/ट्र्यूबवेल/भूमि भराव आदि के लिए वित्तपोषण प्रदान करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं : प्राथमिक भूमि विकास बैंक और केंद्रीय भूमि विकास बैंक। 1950-51 में इनकी संख्या 286 और 5 थी। अब उनकी संख्या क्रमशः 745 और 9 है।

(f) सूक्ष्म वित्त (माइक्रो फाइनेंस) : इस योजना को 'गरीबों के साथ बैंकिंग' भी कहा जाता है। यहां ऋण मुख्य रूप से स्वयं सहायता समूहों (SHGs) / गैर सरकारी संगठनों द्वारा छोटी राशि के रूप में दिया जाता है। ये संगठन (एनजीओ) बिना किसी जमानत के जरूरतमंद किसानों को कृषि ऋण के लिए 100,000 रुपये तक प्रदान करते हैं। सूक्ष्म ऋण के तहत बिना किसी जमानत के गरीब लोगों को 25000 रुपये की राशि दी जाती है। चूंकि इस योजना ने बांग्लादेश में बहुत अच्छे परिणाम दिए थे, इसलिए नाबार्ड ने भी इसे भारत में पेश किया। बाद में अन्य संस्थागत स्रोतों ने भी इस सूक्ष्म क्रेडिट का प्रयोग अपनाया।

आए निम्न गतिविधियों पर काम करें

- अपने इलाके / पड़ोस में आप स्वयं सहायता समूहों की तलाश कर सकते हैं जो साख प्रदान करते हैं। ऐसे स्वयं सहायता समूहों की कुछ बैठकों में भाग लें। स्वयं सहायता समूह पर रिपोर्ट लिखें। इस रिपोर्ट में यह शामिल हो सकता है- इसे कब शुरू किया गया था, तब सदस्यों की संख्या कितनी थी, ऋण का प्रकार, उधारकर्ता ऋण कैसे प्राप्त करता है और कैसे प्रयोग किया जाता है।
- आप यह भी देख सकते हैं कि जो लोग स्वरोजगार गतिविधियों को शुरू करने के लिए ऋण लेते हैं लेकिन इसे अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं। ऐसे ही कुछ कर्जदारों से बात करें। स्वरोजगार के लिए गतिविधियों को शुरू न करने के कारणों को कक्षा में जाना जा सकता है और उन पर चर्चा की जा सकती है।

बॉक्स 1. गरीब महिला बैंक

'कुटुम्बश्री' एक महिला-आधारित समाज में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। इसे केरल में लागू किया गया था। 1995 में बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गरीब महिलाओं के लिए एक छोटे बचत बैंक के रूप में एक बचत और क्रेडिट सोसायटी शुरू की गई थी। बचत और साख सोसायटी ने सूक्ष्म पूंजी के रूप में 1 करोड़ रूपए जुटाये। बचत और क्रेडिट के मामले में इन समितियों को एशिया के सबसे बड़े अनौपचारिक बैंकों के रूप में जाना जाता है।

स्रोत : www.kudumbashree.org. इस वेबसाइट पर इस संगठन द्वारा किए गए कई अन्य कार्यों का विश्लेषण करें। उनकी सफलता में योगदान देने वाले कुछ कारकों की पहचान करें और कक्षा में चर्चा करें।

सारणी 5.3 ग्रामीण ऋण में गैर-संस्थागत और संस्थागत हिस्सा (प्रत्येक 20 साल की तुलना)
(Institutional & Non-Institutional share in Rural Credit) each 20 year comparsion

(ii) गैर-संस्थागत				
स्त्रोत	वर्ष			
	1951	1971	1991	2013
जमींदार	1.5	8.6	4.0	-
कृषि साहूकार	24.9	23.1	6.3	9.8
पेशेवर ऋणदाता	44.8	13.8	9.4	23.4
व्यापारी और एजेंट	5.5	8.7	7.1	0.1
रिश्तेदार और दोस्त	14.2	13.8	6.7	8.5
अन्य	1.9	2.8	2.5	2.1
कुल	92.8	70.8	36	44
(ii) संस्थागत				
सरकारी	3.3	6.7	5.7	1.2
सहकारी ऋण सोसायटी	3.1	20.1	18.6	24.8
वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0.8	2.2	29.0	25.1
एल. आई. सी.	-	0.1	0.5	0.1
भविष्य निधि	-	0.1	0.9	0.2
अन्य	-	-	9.3	4.6
कुल	7.2	29.2	64	56
कुल योग (i + ii)	100	100	100	100

स्त्रोत : अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण (1954), अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण [1951-52, 1971-72, 1991-92 और 2003], अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण, एनएसएसओ, डेटा संग्रह का 70वां दौर [जनवरी-दिसंबर 2013]

- उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि गैर-संस्थागत ग्रामीण ऋण का हिस्सा 92.8% से घटकर 44% हो गया है। 1991 में यह हिस्सा (36%) काफी कम हो गया। हालांकि, यह 50% फीसदी के करीब है। जमींदार का हिस्सा लगभग शून्य हो गया। हालांकि, पेशेवर ग्रामीण वित्त में ऋणदाता की अभी भी 23.4% हिस्सेदारी है। संस्थागत ऋण के प्रसार के कारण, गैर-संस्थागत स्रोतों ने भी ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना शुरू कर दिया। यह ब्याज मुक्त साख 2002 में एक बार 8% था लेकिन अब 2019 में यह 12% हो गया था।

- अगर हम संस्थागत स्रोतों के प्रदर्शन को देखें तो उनका हिस्सा पहले (7.2%) था। लेकिन फिर 1991 में उनका हिस्सा बढ़कर 64% हो गया। 2013 में उनका हिस्सा 56% था, जो इन सभी वर्षों में कुल 8 गुना वृद्धि दर्शाता है। संस्थागत संसाधनों में सहकारी समितियों/बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अधिकतम वृद्धि दिखाई गई।
- सारणी से यह बहुत स्पष्ट है कि सरकार ने ग्रामीण वित्त के संस्थागत स्रोतों को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया है लेकिन गैर-संस्थागत स्रोत अभी भी लगभग 44% के आसपास हैं जो ग्रामीण विकास के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है।
- ग्रामीण साख में सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी सिर्फ 1.2 प्रतिशत है।

5.4 ग्रामीण विकास के लिए संरचना / ग्रामीण विकास के उद्देश्य और कार्य (Road-map For Rural Development [Objectives & Actions For Rural Development])

ग्रामीण विकास के लिए निम्नलिखित तरीकों से ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है :-

1. **मानव पूंजी का विकास (Development of Human Capital) :** यह निम्नलिखित उपायों के माध्यम से किया जाएगा :
 - महिला शिक्षा और शिक्षा के वैश्वीकरण को बहुत महत्व देना
 - उत्पादक रोजगार कौशल प्रदान करना
 - शारीरिक विकास के लिए बेहतर और अधिक किफायती सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं
 - कार्यस्थलों और घरों में स्वच्छता सुविधाएं
 - कार्य के अवसर बढ़ा कर आय में वृद्धि करना
2. **बुनियादी ढांचे का विकास (Development of Basic Infrastructure) :** इसमें निम्नलिखित कारकों पर ध्यान पर होना चाहिए :
 - आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुधार (बिजली, सिंचाई, कृषि विपणन, ऋण सुविधाएं और प्रमुख गांव और लिंक सड़कें, पर्याप्त परिवहन सुविधाएं)
 - कृषि अनुसंधान का विस्तार और नवीनतम जानकारी
 - बाजार और रोजगार संबंधी जानकारी का प्रसार।
3. **संस्थागत / जमीनी सुधार :**
 - संभावित भूमि उत्पादन समर्था की प्राप्ति का वास्तवीकरण (प्रति हेक्टेयर प्रतिस्पर्धी उत्पादकता) और वास्तविक उत्पादकों को लाभ प्रदान करना
 - बेहतर सामाजिक और आर्थिक स्थिति के लिए भूमि सुधार
4. **आर्थिक ग्रामीण सुदृढ़ीकरण :** क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बीपीएल जनसंख्या ग्रामीण है इसलिए कमजोर ग्रामीण वर्गों की जीवन स्थितियों में महत्वपूर्ण सुधार लाने की बहुत आवश्यकता है।
5. **स्थानीय संभावनाएं बढ़ाएं :** किसी विशेष इलाके (कृषि के अलावा) के लिए विशिष्ट स्थानीय रोजगार के अवसरों का विकास करना।
6. **ग्रामीण ऋण / वित्तीय सहायता :** ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण वित्त प्रणाली का सुदृढ़ीकरण। (गैर-संस्थागत या संस्थागत)

ग्रामीण विकास का गांधीवादी दृष्टिकोण (Gandhian Approach of Rural Development)

ग्रामीण विकास के लिए गांधी के दृष्टिकोण को 'आदर्शवादी' कहा जा सकता है। गाँव गांधीवादी आदर्श सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई है। “यदि गाँव नष्ट हो जाता है तो भारत भी नष्ट हो जाएगा सो, हमें 'गाँवों के भारत' के बीच चयन करना होगा जो स्वयं के रूप में प्राचीन है और 'शहरों का भारत' जो विदेशी प्रभुत्व का निर्माण है”। गांधी के आदर्श गाँव स्वशासित स्वायत्त गणराज्यों के संघ को माना जाता है।

पीएम नरेंद्र मोदी के अनुसार “गाँवों में रोशनी लाने के लिए आपको बिजली के खंभों की जरूरत नहीं है : सच्चा ज्ञान मूल्यों, सामुदायिक भावना और अच्छी शिक्षा को आकार देने से आता है।”

दुहराई (REVISION)

- **ग्रामीण विकास के उद्देश्य :** मानव पूंजी का विकास, बुनियादी ढांचे का विकास, संस्थागत भूमि सुधार, आर्थिक ग्रामीण सुदृढ़ीकरण, स्थानीय सशक्तिकरण, आर्थिक सहायता।
- ग्रामीण ऋण का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों को उनकी सबसे अधिक मांग वाली जरूरतों के लिए ऋण।
- **ग्रामीण ऋण के स्रोत हैं :** (i) गैर संस्थागत और (ii) संस्थागत
- संस्थागत स्रोतों का उद्देश्य है—
 - जरूरतमंद किसानों को कम ब्याज दरों पर कर्जा प्रदान करना ;
 - छोटे और सीमांत किसानों को उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनका मार्गदर्शन कर उनकी मदद करना।
- नाबार्ड सर्वोच्च पुनर्वित्त एजेंसी है जो सीधे तौर पर ग्रामीण विकास से जुड़ी औपचारिक संस्थानों से जुड़ी हुई है।
- नाबार्ड ने अन्य ऋण संस्थानों की तुलना में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को अधिकतम ऋण दिया।
- बिना किसी संदेह के ग्रामीण ऋण में संस्थागत संसाधनों की हिस्सेदारी में सुधार हुआ है लेकिन यह अभी भी लगभग 56% है। गैर-संस्थागत स्रोतों का भी हिस्सा 44% है।
- ग्रामीण ऋण में प्रत्यक्ष सरकारी भागीदारी सिर्फ 1.2% है।

●●● अभ्यास ●●●

1. बहुविकल्पिक प्रश्न (Multiple Choice Questions)

- (i) किसानों को कौन से कर्ज स्रोत से कर्ज लेना चाहिए?
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| (क) गैर-संस्थागत स्रोत | (ख) संस्थागत स्रोत |
| (ग) ऋणदाता | (घ) इनमें से कोई नहीं |

- (ii) निम्नलिखित विकल्पों में से संस्थागत स्रोत का चयन करें :
- (क) आरआरबी (ख) राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक
(ग) एन.बी.एफ.सी. (घ) ये सभी
- (iii) साहूकार, कमिशन ऐजेंट और दोस्त साख के स्रोत हैं:-
- (क) संस्थागत (ख) एनबीएफसी
(ग) गैर-संस्थागत (घ) इनमें से कोई नहीं
- (iv) कौन और ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के लिए किस पुनर्वित्त एजेंसी की स्थापना की गई थी ?
- (क) एनबीएफसी (ख) एससीबी
(ग) एसबीआई (घ) नाबार्ड
- (v) योजना 1998 में कृषि और ग्रामीण ऋण के प्रसंस्करण को कारगर बनाने के लिए शुरू की गई थी ।
- (क) स्थानीय क्षेत्र दृष्टिकोण (ख) एससीआरडीबी
(ग) केसीसी (घ) सूक्ष्म वित्त
- (vi) SHGs द्वारा छोटी राशि के ऋण देने की विधि को क्या कहते हैं ?
- (क) कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना (ख) केसीसी
(ग) सूक्ष्म वित्त (घ) इनमें से कोई नहीं
- (vii) मध्यम-अवधि के ऋण की समय अवधि क्या है?
- (क) 7 वर्ष (ख) 2 वर्ष
(ग) 5 वर्ष (घ) इनमें से कोई नहीं
- (viii) आरआरबी में स्थापित किए गए थे ।
- (क) 1975 (ख) 1974
(ग) 1990 (घ) इनमें से कोई नहीं
- (ix) निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि विपणन की कमी है ?
- (क) अकुशल भंडारण सुविधा (ख) नियन्त्रित बाजारों की कमी
(ग) ग्रेडिंग की कमी (घ) ये सभी
- (x) यदि लुधियाना ज़िले में किसी किसान को पूंजीगत साख की जरूरत है तो उसको किस संस्था से साख लेनी चाहिए ।
- (क) संस्थागत स्रोत (ख) सूक्ष्म वित्त-संस्थाएं
(ग) गैर-संस्थागत स्रोत (घ) इनमें से कोई नहीं

2. रिक्त स्थान भरें (Fill in the blanks)

- (i) NBFCs का अर्थ है।
- (ii) नाबार्ड का पूरा रूप है।
- (iii) नाबार्ड ने ग्रामीण पुनर्वित्त का अधिकतम हिस्सा संस्थागत एजेंसी को दिया है।
- (iv) स्वयं सहायता समूह द्वारा कम राशि के कर्ज देने को कहा जाता है।
- (v) गरीब लोगों के साथ बैंकिंग को भी कहा जाता है।

3. सही/गलत (True/False)

- (i) ग्रामीण ऋण वसूली एक गंभीर समस्या है।
- (ii) स्थानीय क्षेत्रीय बैंक की शुरुआत 1996 में हुई थी।
- (iii) पी.ए.सी. और एस.ए.आर.डी.बी. सहकारी बैंकों का हिस्सा हैं।
- (iv) गैर-संस्थागत स्रोत भी ब्याज मुक्त सहायता प्रदान करते हैं।
- (v) वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों का ग्रामीण ऋण संवितरण में सबसे बड़ा हिस्सा है।
- (vi) अग्रणी बैंकों द्वारा 01 अप्रैल, 1989 को सेवा क्षेत्र का दृष्टिकोण पेश किया गया था।

4. अति लघु उत्तरीय प्रश्न (Very Short Answer Type Questions)

- (i) ग्रामीण विकास का अर्थ बताओ।
- (ii) ग्रामीण विकास की एक विशेष परिभाषा दें।
- (iii) आरआरबी की स्थापना कब हुई थी ?
- (iv) 'पैक्स' का पूरा नाम बताएं।
- (v) नाबार्ड द्वारा अनुसूचित सहकारी बैंक को कितने प्रतिशत ऋण आवंटन किया गया था ?
- (vi) एस.बी.आई. के द्वारा अपनाई गई 'ग्राम दत्तक योजना' का नाम क्या है ?
- (vii) गैर-संस्थागत स्रोतों से ब्याज मुक्त ऋण क्यों दिया जा रहा है ?
- (viii) 2013 में ग्रामीण ऋण में सरकार का हिस्सा कितना था ?

5. मिलान करो (Match the column)

- (i) निम्नलिखित साख-संस्थान की स्थापना कब की गई थी?

योजना/स्रोत	वर्ष
1. के. सी. सी (किसान क्रेडिट कार्ड)	1996
2. आर. आर. बी	1998
3. स्थानीय क्षेत्रीय बैंक	1975
4. नाबार्ड	1982

(ii) निम्नलिखित का वैकल्पिक नाम/पूरा रूप लिखो।

1. पी. ए. सी	गरीब लोगों से साथ बैंकिंग
2. सूक्ष्म वित्त	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां
3. ए.आर.डी.आर.एस.	कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजनाएं
4. ए.आर.डी.बी.	कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

6. अति लघु उत्तरीय प्रश्न (Very Short Ans. Type Questions)

- ग्रामीण वित्त से क्या तात्पर्य है?
- ग्रामीण विकास की एक परिभाषा दो।
- किन्हीं 2 संस्थागत स्रोतों के नाम और उनकी स्थापना की तारीख बताएं।
- नाबार्ड के 2 उद्देश्य बताओ।
- संस्थागत संसाधनों की क्या आवश्यकता थी ?
- ‘ग्राम दत्तक ग्रहण कार्यक्रम’ की योजना के बारे में आप क्या जानते हैं ?
- ग्रामीण वित्त में सहकारी बैंक क्या भूमिका निभाते हैं ?

7. लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Ans. Type Questions)

- ग्रामीण ऋण के किन्हीं चार संस्थागत स्रोतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
- नाबार्ड और उसके उद्देश्य पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।
- सेवा क्षेत्रक पहल के बारे में आप क्या जानते हैं ?
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना की व्याख्या करें।
- ग्रामीण विकास के चार उद्देश्य बताइए।
- माइक्रो वित्त पोषण योजना (सूक्ष्म वित्त) की व्याख्या कीजिए।

8. दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 150-200 शब्दों में दें। (Long Ans. Type Ques)

- आप ग्रामीण विकास के लिए रोड मैप कैसे तैयार करेंगे ? इस संबंध में कोई 4 कारण बताएं।
- आँकड़ों की सहायता से एक पुनर्वित्त एजेंसी के रूप में नाबार्ड की भूमिका की व्याख्या कीजिए।
- संस्थागत ऋण के किन्हीं चार स्रोतों की व्याख्या कीजिए।

9. निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

आज़ादी के समय साहूकारों और व्यवसायियों ने छोटे और मध्यमवर्गीय किसानों और भूमिहीन मजदूरों को उच्च ब्याज दरों पर ऋण देकर और उन्हें कर्ज के जाल में फंसाने के लिए खातों में हेराफेरी करके उनका शोषण किया। 1969 के बाद एक बड़ा बदलाव आया जब भारत ने ग्रामीण ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए सामाजिक बैंकिंग और बहु-एजेंसी दृष्टिकोण की शुरुआत की।

ग्रामीण बैंकिंग के संस्थागत ढांचे में आज बहु-एजेंसी संस्थानों का एक समूह शामिल है अर्थात् वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), सहकारी समितियां और भूमि विकास बैंक। उनसे सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण ऋण प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। 1982 में बहु-वित्तीय संस्थानों को वित्त प्रदान करने

के लिए नाबार्ड को एक पुनर्वित्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। हाल ही में औपचारिक ऋण प्रणाली में अंतर को भरने के लिए स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) उभरे हैं। SHGs प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान के माध्यम से छोटे अनुपात में बचत को बढ़ावा देता है। एकत्र किए गए धन से जरूरतमंद सदस्यों को उचित ब्याज दरों पर छोटी किस्तों में चुकाने के लिए यह ऋण दिया जाता है। 2019 तक, भारत में लगभग 6 करोड़ महिलाएँ 54 लाख महिला SHGs की सदस्य बन चुकी थीं। मई 2019 तक 10-15,000 प्रति SHG और 2.5 लाख प्रति SHG, सामुदायिक निवेश सहायता कोष (CISF) के माध्यम से फंड के नवीनीकरण की मदद से आय वृद्धि करने के लिए, स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये गए।

- (i) नाबार्ड की स्थापना कब की गई?
- (ii) CISF का पूरा नाम बताओ।
- (iii) बहु-वित्तीय संस्थाओं के दो उदाहरण लिखो।
- (iv) माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (एस.एच.जी.) को पुनर्वित्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

References

- NABARD ANNUAL REPORT 2020-21 ; 2021-22
- ALL INDIA RURAL CREDIT SURVEY, 2013
- ALL INDIA DEBT & INVESTMENT SURVEY (2019), VARIOUS YEARS (1971-2003)
- 70th & 77TH(Jan-dec 2019) Round of collection by NSSO
- GLC and GoI data
- Rural Development : Economist Kartar Singh
- Kapila, Uma (2020) Indian Economy: Performances & Policies. Academic Foundation, New Delhi
- Dutt & Sundram: Indian Economic Development (2018)

Websites

- <http://egyankosh.ac.in>
- <http://epathshala.nic.in>
- www.education.nic.in
- www.cbse.nic.in
- www.ugc.ac.in
- www.aicte.ernet.in
- www.ncert.nic.in



6

रोज़गार : संवृद्धि, अनौपचारीकरण एवं अन्य मुद्दे

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप

- रोज़गार विषयक मूल अवधारणाओं को समझेंगे जो आर्थिक गतिविधियों, मजूदर, श्रमशक्ति और बेरोज़गारी से संबंधित हैं ;
- विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी के स्वरूप से परिचित होंगे ;
- बेरोज़गारी के स्वरूप और विस्तार को जान पाएँगे और ;
- देश के विभिन्न भागों और क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों का सृजन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करने योग्य हो पायेंगे ।

अध्याय – 6

रोज़गार : संवृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे

मेरी आपत्ति मशीन से नहीं, मशीन के प्रति सनक को लेकर है। इसी सनक का नाम 'श्रम की बचत' करने वाले मशीनें हैं। हम उस सीमा तक श्रम की बचत करते जाएँगे जब तक कि हजारों लोग बेरोज़गार होकर भूखों मरने के लिए सड़कों पर नहीं फेंक दिए जाते।

-महात्मा गाँधी

6.1 परिचय (Introduction)

लोग तरह-तरह के काम करते हैं। कुछ लोग खेतों, कारखानों, बैंकों, दुकानों, आदि अनेक प्रकार के कार्यस्थलों पर काम करते हैं। कुछ व्यक्ति घर पर भी अन्य काम करते हैं। घर पर होने वाले काम अब बुनाई, फीते बनाना या हस्तकलाओं जैसे पारंपरिक कामों तक सीमित नहीं रह गए हैं बल्कि इनमें सूचना-प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रोग्राम बनाने जैसे आधुनिक काम भी शामिल हो चुके हैं। पहले कारखाने में काम करने का अर्थ किसी शहर में स्थित कार्यालया में काम करना होता था परंतु अब तो प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों ने



चित्र 6.1 बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ पंजाब के जालंधर शहर के एक घर में निर्मित फुटबाल की बिक्री करती हैं

गाँव के घरों में ही औद्योगिक उत्पादन संभव बना दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान 2020-21 में लाखों श्रमिकों ने घर से काम के माध्यम से अपने उत्पादों और सेवाओं को वितरित किया।

व्यक्ति कार्य क्यों करते हैं? कार्य की हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। लोग आजीविका के लिए कार्य करते हैं। कुछ लोगों को उत्तराधिकार के माध्यम से कार्य किए बिना भी धन मिल जाता है। किंतु ऐसे धन से किसी को पूर्ण संतोष नहीं होता। किसी कार्य से जुड़ा रहना हमें अपनी सार्थकता की अनुभूति प्रदान करता है। इसी के माध्यम से हम अन्य व्यक्तियों से सही अर्थों में संपर्क स्थापित करते हैं। प्रत्येक कार्यरत व्यक्ति सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आय में योगदान करता है। इसी के माध्यम से वह विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में भाग लेकर देश के आर्थिक विकास में हिस्सेदार बनता है। यही सही अर्थों में आजीविका उपार्जन है। हम केवल अपने लिए काम नहीं करते; अपने ऊपर निर्भर व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करके भी

उपलब्धि का अनुभव करते हैं। कार्य के इसी महत्व को समझ कर महात्मा गाँधी ने शिक्षा और हस्तकलाओं सहित विभिन्न प्रकार के कामों के माध्यम से प्रशिक्षण पर बल दिया था। कार्य कर रहे व्यक्तियों के अध्ययन से हमें देश में रोज़गार की प्रकृति और गुणवत्ता के विषय में एक गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। इससे हमें अपने मानवीय संसाधनों को जानने और उनके उपयुक्त प्रयोग की योजनाएँ बनाने में भी सहायता मिलती है। इससे विभिन्न उद्योगों तथा क्षेत्रों के राष्ट्रीय आय में योगदान का विश्लेषण करने में भी सहायता मिलती है। ये समाज के सीमांत-वर्गों, बाल-श्रमिकों आदि के शोषण की समस्याओं का निदान करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं।

6.2 श्रमिक और रोज़गार (Workers and Employment)

रोज़गार क्या है? श्रमिक कौन होता है? जब एक किसान खेतों में काम करता है तो वह खाद्यान्न और उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। कपास ही कपड़े के कारखानों और विद्युतकर्मियों में कपड़े का रूप धारण कर लेता है। गाड़ियाँ सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाती हैं। हम जानते हैं कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य इसका 'सकल घरेलू उत्पाद' कहलाता है। हमें निर्यात से मूल्य प्राप्त होता है और आयात का मूल्य चुकाना पड़ता है, इसमें हम देखते हैं कि देश का निवल अर्जन धनात्मक हो सकता है (यदि निर्यात का मूल्य आयात की अपेक्षा अधिक रहे) या ऋणात्मक हो सकता है (यदि आयात का मूल्य निर्यात की अपेक्षा अधिक रहे) या शून्य हो सकता है (यदि आयात और निर्यात के मूल्य समान हों)। हम प्राप्त अर्जनों का योग करते हैं (+ या -) तो हमें उस वर्ष के लिए देश का **सकल राष्ट्रीय उत्पाद** प्राप्त होता है।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों को हम **आर्थिक क्रियाएँ** कहते हैं। वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं से संलग्न होते हैं, श्रमिक कहलाते हैं, चाहे वे उच्च या निम्न किसी भी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। यदि इनमें से कुछ लोग बीमारी, ज़ख्म होने आदि शारीरिक कष्टों, खराब मौसम, त्योंहार या सामाजिक-धार्मिक उत्सवों के कारण अस्थायी रूप से काम पर नहीं आ पाते तो भी उन्हें श्रमिक ही माना जाता है। इन कामों में लगे मुख्य श्रमिकों की सहायता करने वालों को भी हम श्रमिक ही मानते हैं। आमतौर पर हम ऐसा सोचते हैं कि जिन्हें काम के बदले नियोक्ता द्वारा कुछ भुगतान किया जाता है, उन्हें श्रमिक कहा जाता है। पर ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति स्व-नियोजित होते हैं, वे भी श्रमिक ही होते हैं।

भारत में रोज़गार की प्रकृति बहुमुखी है। कुछ लोगों को वर्ष भर रोज़गार प्राप्त होता है तो कुछ लोग वर्ष में कुछ महीने ही रोज़गार पाते हैं। अधिकांश मजदूरों को अपने कार्य की उचित मजदूरी नहीं मिल पाती। वैसे श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाते समय जितने भी व्यक्ति आर्थिक कार्यों में लगे होते हैं, उन सबको रोज़गार में लगे लोगों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। आप विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे व्यक्तियों की संख्याएँ जानने को उत्सुक होंगे। वर्ष 2017-18 में भारत की कुल श्रम-शक्ति का आकार लगभग 471 मिलियन आँका

इन्हें कीजिए

आपके घर और पास-पड़ोस में कितनी ही महिलाएँ ऐसी होंगी जिनके पास तकनीकी डिग्री तथा डिप्लोमा है। उनके पास काम करने के लिए समय भी है पर वे कुछ नहीं करती। उनसे पूछ कर देखें कि वे काम क्यों नहीं कर रहीं। उन सभी कारणों की सूची बनाएँ और कक्षा में चर्चा करें कि क्या उन्हें काम पर जाना चाहिए। क्यों और कैसे उन्हें काम पर भेजा जा सकता है। कुछ समाजशास्त्रियों का तो आग्रह है कि घर सँभालने वाली गृहणियों का भी राष्ट्रीय आय में योगदान होता है, वे भी आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रही हैं। भले ही उन्हें इसके लिए वेतन नहीं मिल रहा हो। अतः उन्हें भी श्रमबल का अंग माना जाना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं?

गया था। क्योंकि देश के अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं इसीलिए ग्रामीण श्रमबल का अनुपात भी शहरी श्रमबल से कहीं अधिक है। इन 471 मिलियन श्रमिकों में दो-तिहाई श्रमिक ग्रामीण हैं। भारत में श्रमशक्ति में पुरुषों की बहुलता है। श्रमबल में लगभग 77 प्रतिशत पुरुष तथा शेष महिलाएँ (इसमें महिला, बाल श्रमिकों को भी शामिल किया गया है) हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिला श्रमिक कुल श्रमबल का एक चौथाई हैं तो शहरों में केवल 20 प्रतिशत महिलाएँ ही श्रमबल में भागीदार पाई गई हैं। महिलाएँ खाना बनाने, पानी लाने, ईंधन बीनने के साथ-साथ खेतों में भी काम करती हैं। उन्हें नकद या अनाज के रूप में मजदूरी नहीं मिलती-कितने ही मामलों में तो कुछ भी भुगतान नहीं किया जाता। इसी कारण उन महिलाओं का श्रमिक वर्ग में भी शामिल नहीं किया जाता। अर्थशास्त्रियों का आग्रह है कि इन महिलाओं को भी श्रमिक ही माना जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं?

6.3 लोगों की रोज़गार में भागीदारी (Participation of People in Employment)

श्रमिक जनसंख्या अनुपात जिसका प्रयोग देश में रोज़गार की स्थिति के विश्लेषण के लिए सूचक के रूप में किया जाता है, यह जानने में सहायक है कि जनसंख्या का कितना अनुपात वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। यदि यह अनुपात अधिक है, तो इसका तात्पर्य है जनता की काम में भागीदारी अधिक होगी। यदि यह अनुपात मध्यम या कम हो तो इसका अर्थ होगा कि देश की जनसंख्या का बहुत अधिक अनुपात प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में संलग्न नहीं है।

आपने 'जनसंख्या' शब्द का अर्थ तो पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया होगा। जनसंख्या शब्द का अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय विशेष पर रह रहे व्यक्तियों की कुल संख्या से है। यदि भारत के श्रमिक जनसंख्या अनुपात का आकलन करना चाहें तो हमें भारत में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों की संख्या को देश की जनसंख्या से भाग कर उसे 100 से गुणा करना होगा। इस प्रकार हमें श्रमिक जनसंख्या अनुपात ज्ञात हो जायेगा (6.1 सारणी देखें)।

सारणी 6.1 भारत में कार्यकर्ता-जनसंख्या अनुपात, 2017-2018

लिंग	(श्रमिक) कार्यकर्ता-जनसंख्या अनुपात		
	कुल	ग्रामीण	शहरी
पुरुष	52.35	51.7	53.0
स्त्री	15.85	17.5	14.2
कुल	34.1	34.6	33.6

स्रोत : भारत सरकार (2019)

सारणी 6.1 भारत में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लोगों की भागीदारी के विभिन्न स्तरों को स्पष्ट कर रही है। भारत में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से लगभग 34 श्रमिक है। शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात लगभग 34 है जबकि ग्रामीण भारत में यह अनुपात लगभग 35 है। ऐसा अंतर क्यों है? ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च आय के अवसर सीमित हैं, इसी कारण रोज़गार बाज़ार में उनकी भागीदारी अधिक है। अधिकांश व्यक्ति स्कूल, महाविद्यालय या किसी प्रशिक्षण संस्थान में नहीं जा पाते। यदि कुछ जाते भी हैं तो वे बीच में ही छोड़कर श्रमशक्ति में शामिल हो जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में एक बड़ा भाग विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययन कर सकने में सक्षम है। शहरी जनसमुदाय

को रोज़गार के भी विविधतापूर्ण अवसर सुलभ हो जाते हैं। वे अपनी शिक्षा और योग्यता के अनुरूप रोज़गार की तलाश में रहते हैं। किंतु ग्रामीण क्षेत्र के लोग घर पर नहीं बैठ सकते क्योंकि उनकी आर्थिक दशा उन्हें ऐसा नहीं करने देती।

शहरी और ग्रामीण, दोनों ही वर्गों में पुरुषों की श्रमशक्ति भागीदारी महिलाओं की तुलना में अधिक है। शहरी क्षेत्रों में तो पुरुष और महिला भागीदारी का अंतर बहुत ही बड़ा है—केवल 14 प्रतिशत शहरी महिलाएँ ही किसी आर्थिक कार्य में व्यस्त दिखाई दे रही हैं। किंतु, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की रोज़गार बाज़ार में भागीदारी 18 प्रतिशत आँकी गई।

महिलाएँ सामान्य और विशेष रूप से शहरों में काम क्यों नहीं कर रही हैं? यह बात देखने में आई है कि जहाँ कहीं भी पुरुष पर्याप्त रूप से उच्च आय अर्जित करने में सफल रहते हैं, परिवार की महिलाओं को घर से बाहर रोज़गार प्राप्त करने से प्रायः निरुत्साहित किया जाता है।

हमने पहले भी कहा है कि महिलाओं द्वारा भी की जाने वाली घरेलू गतिविधियों को आर्थिक या उत्पादन कार्य ही नहीं माना जाता। कार्य या रोज़गार की यह संकीर्ण परिभाषा देश में महिला-वर्ग की श्रमबल में भागीदारी को नहीं मानती तथा इसलिए देश में महिला श्रमिकों की संख्या को कम आँका जाता है। जरा सोचकर देखिए, कि घर के भीतर और खेतों में महिलाएँ कितने ऐसे काम करती हैं, जिनका उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता। चूँकि वे परिवार तथा खेतों के रख-रखाव में निश्चित रूप से योगदान देती हैं, क्या आपको नहीं लगता की उनकी संख्या भी महिला श्रमिकों में सम्मिलित की जानी चाहिए?

6.4 स्वनियोजित तथा भाड़े के श्रमिक (Self-Employed And Hired Workers)

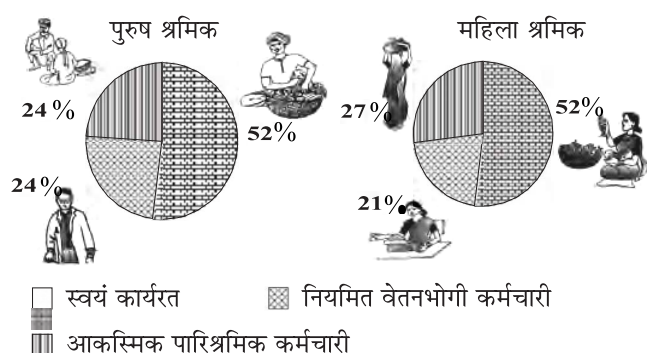
क्या श्रमिक जनसंख्या अनुपात समाज में श्रमिकों की स्थिति और कार्य की दशाओं के विषय में भी कुछ जानकारी देता है? यदि किसी उद्यम में श्रमिक के स्तर या पद की जानकारी मिल सके तो निश्चय ही देश में रोज़गार के गुणवत्ता के आयामों की जानकारी प्राप्त करना संभव होगा। इससे हम यह भी जान सकेंगे कि श्रमिक का अपने काम से कितना लगाव है और अपने सहकर्मियों तथा उद्यम के प्रति उसके अधिकार क्या है? आइए, निर्माण उद्योग के तीन कर्मियों की तुलना करें : एक सीमेंट की दुकान का स्वामी है, दूसरा निर्माण मजदूर है तो तीसरा निर्माण करने वाली कंपनी का एक सिविल इंजीनियर है। इन तीनों के पद अथवा प्रतिष्ठा में अंतर है, जिन्हें विभिन्न नामों से भी संबोधित किया जाता है। जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक हैं, उन्हें स्वनियोजित कहा जाता है। इस प्रकार सीमेंट की दुकान का स्वामी स्वनियोजित है।

भारत का लगभग आधा श्रमबल (52 प्रतिशत) इसी श्रेणी में आता है। निर्माण मजदूर

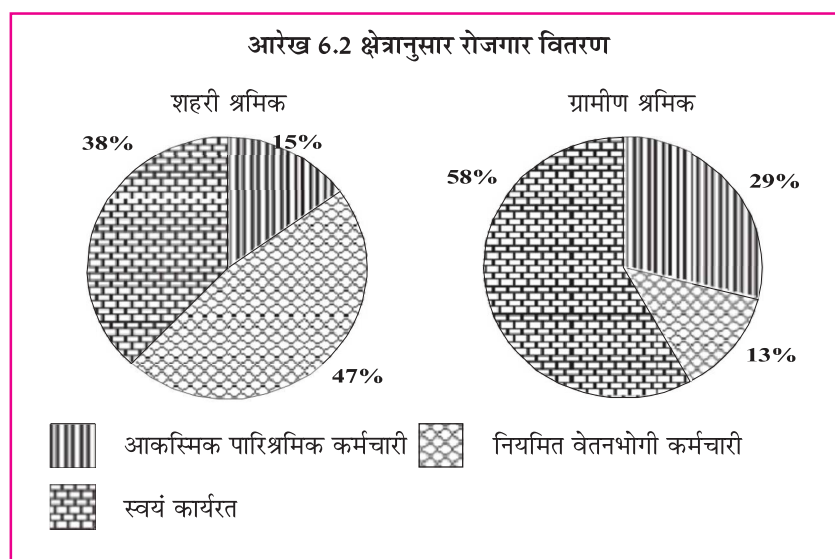
इन्हें कीजिए

- रोज़गार संबंधी कोई भी अध्ययन श्रमिक जनसंख्या अनुपात से ही आरंभ होना चाहिए। क्यों?
- आपने शायद देखा होगा कि कुछ समुदायों में यदि पुरुषों की आय पर्याप्त नहीं हो तो भी वे अपने घर की महिलाओं को बाहर काम करने के लिए नहीं भेजते। ऐसा क्यों होता है?

आरेख 6.1 रोज़गार स्त्री-पुरुष वर्गानुसार वितरण



स्रोत : भारत सरकार, 2019



अनियत मजदूरी वाले श्रमिक कहलाते हैं। ये भारत की श्रमशक्ति का लगभग 25 प्रतिशत है। ऐसे ही मजदूर अन्य लोगों के खेतों में अनियत रूप से कार्य करते हैं और उसके बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। निर्माण कंपनी के अभियंता के रूप में काम कर रहे व्यक्ति श्रमशक्ति का मात्र 23 प्रतिशत ही हैं। जब किसी श्रमिक को कोई व्यक्ति या उद्यम नियमित रूप से काम पर रख उसे मजदूरी (वेतन) देता है, तो वह श्रमिक नियमित वेतन भोगी कर्मचारी कहलाता है। (सारणी 6.2 देखें)

सारणी 6.2 रोजगार पद्धति की प्रवृत्तियां (क्षेत्रक और स्थिति अनुसार), 1972-2018 (प्रतिशत में)

मद	1972-73	1983	1993-94	2011-12	2017-18
क्षेत्रक					
प्राथमिक	74.3	68.6	64	48.9	44.6
द्वितीयक	10.9	11.5	16	24.3	24.4
सेवा	14.8	16.9	20	26.8	31.0
योग	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
स्थिति					
स्वनियोजित	61.4	57.3	54.6	52.0	52.2
नियमित वेतनभोगी कर्मचारी	15.4	13.8	13.6	18.0	22.8
आकस्मिक दिहाड़ी मजदूर	23.2	28.9	31.8	30.0	25.0
योग	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

आरेख 6.1 को ध्यान से देखिए। इसे पता चल रहा है कि भारत में पुरुष और महिला श्रमिकों के 50 प्रतिशत से अधिक तो स्वरोजगारी वर्ग में ही आते हैं। अतः स्वरोजगार ही देश की आजीविका का सबसे प्रमुख स्रोत है। अनियत मजदूरी कार्य पुरुषों और महिलाओं के लिए रोजगार का दूसरा प्रमुख स्रोत है। इस अनियत रोजगार में

महिलाओं का अंश (24-27 प्रतिशत) पुरुषों से अधिक पाया गया है। नियमित वेतनभोगी रोजगारधारियों में पुरुष एवं महिलाएँ, दोनों अधिक अनुपात में लगे हुए हैं। देश के 24 प्रतिशत पुरुष नियमित वेतनभोगी हैं और इस वर्ग में 21 प्रतिशत महिलाएँ हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर बहुत कम है।

यदि ग्रामीण और शहरी श्रमबल के वितरण की तुलना करें तो आरेख 6.2 के अनुसार, हमें ज्ञात होता है कि अनियत मजदूरी पाने वाले श्रमिक स्वनियोजित तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक हैं। शहरों में



चित्र 6.2 ईंट निर्माण : अनियत कार्य का एक प्रकार

स्वनियोजित और नियमित वेतन वाले रोजगार की संख्या अधिक है। गाँवों में अधिकांश ग्रामीण अपनी जमीन के टुकड़ों पर निर्भर हैं जो स्वतंत्र रूप से खेती करते हैं, अतः स्वनियोजन में उनकी भागीदारी अधिक है।

शहरी क्षेत्रों में काम का स्वरूप भी अलग होता है। हर व्यक्ति कारखाने, दुकान और कार्यालयों का संचालक नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त शहरी उद्यमों में नियमित रूप से श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

इन्हें कीजिए

आमतौर पर हम यह मान लेते हैं कि जो लोग नियमित या अस्थायी आधार पर कृषि श्रमिक, कारखाना मजदूर या किसी बैंक अथवा कार्यालय में सहायक लिपिक हैं, वही श्रमिक हैं। इस अध्याय की अब तक की चर्चा से आप समझ चुकें होंगे कि स्वनियोजित जैसे, पटरी पर सब्जियाँ बेचने वाले, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि सभी व्यक्ति श्रमिक या कामगार होते हैं। निम्न श्रेणियों के कामगारों का (स्वनियोजन, नियमित वेतनभोगी कर्मचारी तथा आकस्मिक दिहाड़ी मजदूरों में) वर्गीकरण करने हेतु इन्हें इंगित करने के लिए इनके सामने 'क' 'ख' और 'ग' अंकित करें :

1. नाई की दुकान का मालिक
2. चावल मिल का कर्मचारी, जो नियमित रूप से नियुक्त हो किंतु जिसे नियमित रूप से दैनिक मजदूरी मिलती हो।
3. भारतीय स्टेट बैंक का एक कोषपाल
4. राज्य सरकार के कार्यालय का टाइपिस्ट जिसे दैनिक मजदूरी आधार पर रखा गया है पर मासिक भुगतान किया जाता है।
5. हथकरघा बुनकर

6. थोक सब्जी की दुकान पर माल ढोने वाले मजदूर
 7. शीतल पेय की दुकान का स्वामी जो पेप्सी, कोक, लिम्का आदि बेचता है।
 8. किसी निजी अस्पताल में 5 वर्षों से नियमित कार्य कर रही नर्स, जिसे मासिक वेतन मिलता है।
- अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अनियत दिहाड़ी मजदूर की दशा तीनों वर्गों में सबसे अधिक असुरक्षित है। क्या आप जानते हैं कि ये मजदूर कौन हैं, इन्हें कहाँ पाया जाता है और क्यों?
 - क्या हम कह सकते हैं कि स्वनियोजित व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरों और वेतनभोगियों से अधिक कमा लेते हैं? रोज़गार की गुणवत्ता के कुछ अन्य सूचकों की भी पहचान करें।

6.5 फर्मों, कारखानों तथा कार्यालयों में रोज़गार (Employment in Firms, Factories and Offices)

देश के आर्थिक विकास के साथ श्रमशक्ति का कृषि तथा अन्य संबंधित क्रियाकलापों से उद्योगों और सेवाओं की ओर प्रवाह होता है। इसी प्रक्रिया में मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में प्रवासन करते हैं। धीरे-धीरे उद्योग भी सकल रोज़गार में अपना अंश खोने लगते हैं क्योंकि सेवा क्षेत्र में बहुत तीव्र दर पर प्रसार होने लगता है। श्रमशक्ति के कार्यानुसार या उद्योगवार वितरण से रोज़गार स्वरूप के ये परिवर्तन सहज ही स्पष्ट हो जाते हैं। सामान्यतया आर्थिक क्रियाओं को आठ विभिन्न औद्योगिक वर्गों में विभाजित करते हैं। ये हैं : (क) कृषि (ख)



चित्र 6.3 सिले-सिलाए वस्त्रों के कारीगर : महिलाओं को भविष्य में प्राप्त होने वाले रोज़गार के केंद्र
सारणी 6.3 उद्योग में कार्यबल का वितरण, 2017-18 (प्रतिशत में)

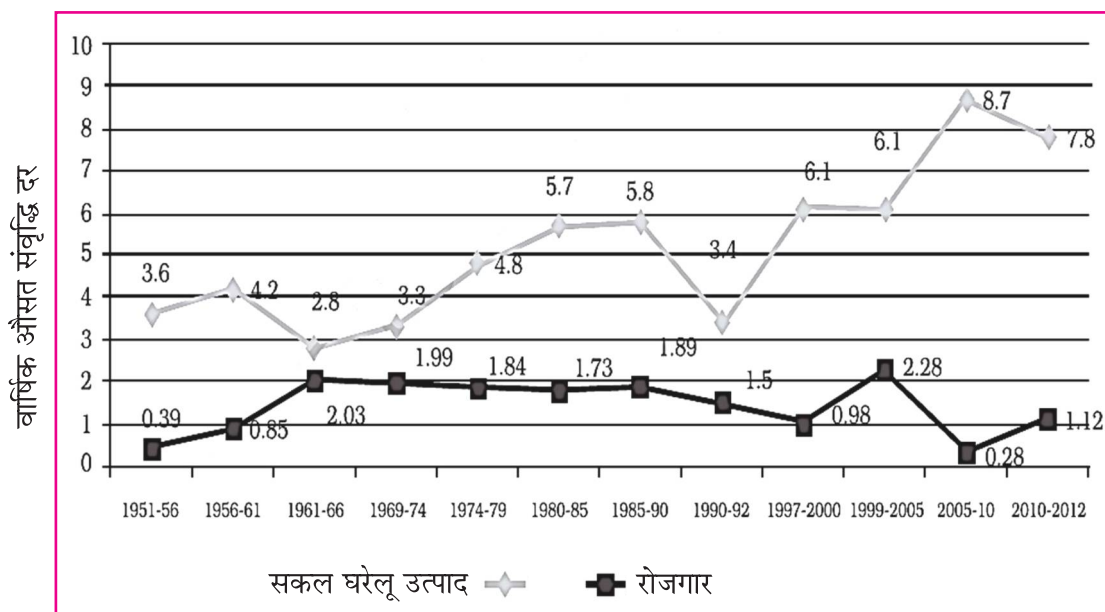
औद्योगिक वर्ग	निवास स्थान		लिंग		कुल
	ग्रामीण	शहरी	पुरुष	महिला	
प्राथमिक क्षेत्रक	59.8	6.6	40.7	57.1	44.6
द्वितीयक क्षेत्रक	20.4	34.3	26.5	17.7	24.4
तृतीयक / सेवा क्षेत्रक	19.8	59.1	32.8	25.2	31.0
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

खनन और उत्खनन (ग) विनिर्माण (घ) विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति (ङ) निर्माण कार्य (च) वाणिज्य (छ) परिवहन और भंडारण तथा (ज) सेवाएँ। सरलता के लिए सभी कार्ययुक्त व्यक्तियों को तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये हैं : (1) प्राथमिक क्षेत्रक, जिसमें (क) तथा (ख) सम्मिलित है। (2) द्वितीयक क्षेत्रक जिसमें (ग) (घ) तथा (ङ) को शामिल किया जाता है। (3) इसे सेवा क्षेत्रक कहते हैं और इसमें शेष तीनों उपवर्ग (च), (छ) तथा (ज) को रखा जाता है।

सारणी 6.3 में हम भारत में वर्ष 2017-18 में विभिन्न उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के विषय में जानकारी दे रहे हैं। भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत प्राथमिक क्षेत्रक है। द्वितीयक क्षेत्रक केवल लगभग 24 प्रतिशत श्रमबल को नियोजित कर रहा है। लगभग 31 प्रतिशत सेवा क्षेत्रक में संलग्न हैं। सारणी 6.3 भी यह स्पष्ट कर रही है कि ग्रामीण भारत की लगभग 60 प्रतिशत श्रमशक्ति कृषि, वन और मत्स्य पर निर्भर है। लगभग 20 प्रतिशत ग्रामीण श्रमिक ही विनिर्माण उद्योगों, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में लगे हुए हैं। केवल 20 प्रतिशत ग्रामीण श्रमिकों को सेवा श्रम से ही रोजगार मिलता है। किंतु, शहरी क्षेत्रकों में कृषि और खनन रोजगार के प्रमुख स्रोत नहीं हैं, जहाँ अधिकांश लोग सेवा क्षेत्रक में कार्यरत हैं। 60 प्रतिशत शहरी श्रमिक सेवा क्षेत्रक में हैं। लगभग एक-तिहाई शहरी श्रमिक द्वितीयक क्षेत्रक में नियोजित हैं।

यद्यपि प्राथमिक क्षेत्रक में पुरुष और महिला दोनों ही प्रकार के श्रमिक संकेंद्रित हैं, पर वहाँ महिलाओं का संकेंद्रण बहुत अधिक है। इस प्राथमिक क्षेत्रक में लगभग 57 प्रतिशत महिलाएं कार्यरत हैं—जबकि इस क्षेत्र में काम कर रहे पुरुषों की संख्या आधे से कम है। पुरुषों को द्वितीयक और सेवा क्षेत्रक दोनों में ही रोजगार के अवसर प्राप्त हो जाते हैं।

आरेख 6.3 : रोजगार तथा सकल घरेलू उत्पाद में संवृद्धि, 1951-2012 (प्रतिशत में)



*यह वर्ष है जिसके लिए तुलनीय और प्रामाणिक आधार-सामग्री उपलब्ध है।

स्रोत : की इंडिकेटर्स ऑफ एंप्लॉयमेंट एंड अनएंप्लॉयमेंट इन इंडिया, 2011-12, 68 राउंड, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑरगेनाइजेशन, नेशनल सेंपल सर्वे ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, भारत सरकार, जनवरी 2014

इन्हें कीजिए

सभी समाचार-पत्रों में रोज़गार अवसरों से जुड़ा एक भाग होता है। कुछ तो प्रति सप्ताह (दैनिक भी) रोज़गार पर एक विशेष परिशिष्ट भी निकालते हैं—चाहे द हिन्दू का 'ऑपॉर्चुनिटीज' हो या द टाइम्स ऑफ़ इंडिया का 'एसेंट'। अनेक कंपनियाँ अपनी रिक्तियों का विज्ञापन इनमें करती हैं। इन स्तंभों को काट लीजिए और एक सारणी बनाइए, जिसके चार स्तंभ हो : कंपनी, (सार्वजनिक या निजी), पद का नाम, रिक्तियाँ, क्षेत्रक (प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक) और आवश्यक योग्यताएँ। इस सारणी के आधार पर कक्षा में समाचार-पत्रों में विज्ञापित रोज़गार अवसरों पर चर्चा करें।

6.6 संवृद्धि एवं परिवर्तनशील रोज़गार संरचना (Growth and Changing Structure of Employment)

आपने अध्याय 2 और 3 में विस्तार से नियोजन-रणनीतियों के बारे में पढ़ा था। यहाँ हम केवल दो विकास सूचकों पर विचार करेंगे। ये हैं, रोज़गार संवृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद। लगभग सत्तर वर्षों से चल रहे योजनाबद्ध विकास का ध्येय राष्ट्रीय उत्पाद और रोज़गार में वृद्धि के माध्यम से अर्थव्यवस्था का प्रसार रहा है। 1950-2010 की अवधि में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सकारात्मक वृद्धि हुई है और यह संवृद्धि दर रोज़गार वृद्धि दर से अधिक रही है। किंतु, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में कुछ उतार-चढ़ाव भी आते रहे हैं। पर इस अवधि में रोज़गार की वृद्धि लगभग 2 प्रतिशत बनी रही।

आरेख 6.3, 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में एक अन्य चिंताजनक घटनाक्रम की ओर भी इंगित कर रहा है : रोज़गार वृद्धि दर कम होकर उसी स्तर पर पहुँच गई, जहाँ से योजनाकाल के प्रारंभिक चरणों में शुरू हुई थी। इन्हीं वर्षों के दौरान हम सकल घरेलू उत्पाद और रोज़गार की वृद्धि दरों के बीच काफी बड़ा अंतर पाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था में रोज़गार सृजन के बिना ही अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में समक्ष रहे हैं। इस परिघटना को विद्वान 'रोज़गारहीन संवृद्धि' का नाम दे रहे हैं।

अभी तक हमने देखा कि रोज़गार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की तुलना में किस तरह बढ़ा है। अब यह जानना भी आवश्यक है कि रोज़गार और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरों के इन स्वरूपों ने विभिन्न वर्गों के श्रमबल पर किस प्रकार के प्रभाव डाले। इससे हम समझ पाएँगे कि हमारे देश में किस प्रकार के रोज़गार अवसरों का सृजन हो रहा है।

आइए, पिछले खंड में बताए गए दो सूचकों पर एक बार फिर से विचार करें। ये सूचक हैं, विभिन्न उद्योगों में लोगो को मिले रोज़गार तथा उनकी स्थितियाँ। हम जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में बसा है और यह अपनी मुख्य आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत सहित अनेक देशों के विकास रणनीतियों का ध्येय कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात को कम करना रहा है।

औद्योगिक क्षेत्रों के आधार पर श्रमबल का वितरण यह दिखाता है कि श्रमबल कृषि कार्यों से हटकर गैर कृषि कार्यों की ओर बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है (सारणी 6.2 देखें)। जहाँ 1972-73 में प्राथमिक क्षेत्रक में 74 प्रतिशत श्रम बल लगा था, वहीं 2011-12 में यह अनुपात घटकर 50 प्रतिशत रह गया है। द्वितीयक और सेवा क्षेत्रक भारत के श्रमबल के लिए आशावादी भविष्य का संकेत दे रहे हैं। आप देखेंगे कि इन क्षेत्रकों की हिस्सेदारी क्रमशः 11 से बढ़कर 24 और 15 से बढ़कर 27 प्रतिशत हो गई है।

इन्हें कीजिए

- क्या आप जानते हैं कि भारत जैसे देश में रोज़गार वृद्धि की दर को 2 प्रतिशत स्तर पर बनाए रखना इतना आसान काम नहीं है? क्यों?
- यदि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त रोज़गार के सृजन बिना ही अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में सफलता मिल जाए, तो क्या होगा? यह रोज़गारहीन संवृद्धि कैसे संभव हो पाती है?
- अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यदि श्रम के अनियतीकरण से जनता की आय में वृद्धि हो रही हो, तो इस प्रक्रिया का स्वागत होना चाहिए। कल्पना करें कि एक सीमांत किसान को पूर्णकालिक कृषि मजदूर बना दिया जाए। क्या आप सोचते हैं कि दिहाड़ी मजदूरी के इस कार्य से यदि उसकी आय में वृद्धि हो जाए, तो क्या वह अधिक प्रसन्न होगा? या, औषधि उद्योग के एक श्रमिक को दिहाड़ी मजदूर बना दिया और उसकी संपूर्ण आय भी बढ़ जाये, तो क्या वह प्रसन्न होगा? कक्षा में इन दोनों उदाहरणों के सभी पक्षों पर चर्चा करें।

विभिन्न स्थितियों में श्रमबल के वितरण को देखें तो पिछले पाँच दशकों (1972-2018) में लोग स्वरोज़गार और नियमित वेतन-रोज़गार से हटकर अनियत श्रम की ओर बढ़ रहे हैं। फिर भी स्वरोज़गार, रोज़गार का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। सारणी 6.2 के अंतिम कॉलम को देखें। वर्ष 2011-18 के दौरान माध्यमिक क्षेत्र में स्थिरता और स्वरोज़गार में मध्यम वृद्धि से क्या समझते हैं? कक्षा में चर्चा करें। विशेषज्ञ स्वरोज़गार तथा नियमित वेतन से अनियत श्रम रोज़गार की ओर जाने की प्रक्रिया को श्रम बल के अनियतीकरण का नाम देते हैं। इससे मजदूरों की दशा बहुत नाजुक हो जाती है। यह कैसे हो रहा है? बॉक्स 6.2 में वर्णित अहमदाबाद का विशेष अध्ययन देखें। आप इसी बीच में (2017-18) नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों के हिस्से में मध्यम वृद्धि को भी देखिए। आप इस प्रक्रिया को कैसे समझाएँगे?

6.7 भारतीय श्रमबल का अनौपचारिकरण (Informalisation of Indian Workforce)

पिछले खंड में हमने पाया कि श्रमबल में अनियत श्रमिकों का अनुपात निरंतर बढ़ रहा है। स्वतंत्रता के बाद से विकास योजनाओं का एक ध्येय जनसामान्य के लिए सम्मानपूर्ण आजीविका का प्रबंध सुनिश्चित करना भी बताया गया है। यह कहा गया था कि औद्योगीकरण की रणनीति कृषि से अतिरिक्त श्रमिकों को उद्योगों में आकर्षित कर उन्हें विकसित देशों की भाँति उच्च जीवन स्तर सुलभ कराएगी। किंतु हम यह पिछले अनुभाग में देख ही चुके हैं कि योजनाबद्ध विकास के सत्तर वर्षों बाद भी देश के श्रमबल के आधे से अधिक सदस्यों के लिए कृषि ही रोजी-रोटी का प्रमुख साधन बनी हुई है।

अर्थशास्त्रियों का यह भी तर्क है कि अनेक वर्षों से रोज़गार की गुणवत्ता में निरंतर हास हो रहा है। आखिर 10-20 वर्षों तक काम कर चुके न जाने कितने ही श्रमिक मातृत्व लाभ, भविष्यनिधि, ग्रेच्युटी और पेंशन आदि से वंचित क्यों रह जाते हैं? निजी क्षेत्रक में कार्य करने वाला व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्रक में उसी काम को करने वाले से कम वेतन क्यों पाता है?

आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि भारत के सकल श्रमबल के बहुत छोटे से वर्ग को ही नियमित आय मिल पा रही है। सरकार **श्रम कानूनों** के द्वारा उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ बनाती है। यही

वर्ग अपने **श्रमिक संघों** को गठित कर रोज़गारदाताओं से बेहतर मजदूरी और अन्य **सामाजिक सुरक्षा** उपायों के लिए सौदेबाजी भी करता है। ये कौन लोग हैं? इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम श्रमबल को औपचारिक तथा अनौपचारिक वर्गों में विभाजित कर रहे हैं। इन्हीं को संगठित और असंगठित क्षेत्रक भी कहा जाता है। सभी सार्वजनिक क्षेत्रक प्रतिष्ठान तथा 10 या अधिक कर्मचारियों को रोज़गार देने वाले निजी क्षेत्रक प्रतिष्ठान **संगठित क्षेत्रक** माने जाते हैं। इन प्रतिष्ठानों में काम करने वालों को संगठित क्षेत्रक के कर्मचारी कहा जाता है। अन्य सभी उद्यम और उनमें कार्य कर रहे श्रमिक मिल कर अनौपचारिक क्षेत्रक की रचना करते हैं। इस प्रकार इस अनौपचारिक क्षेत्रक में करोड़ों किसान, कृषि श्रमिक, छोटे-छोटे काम-धंधे चलाने वाले और उनके कर्मचारी तथा सभी स्वनियोजित व्यक्ति, जिनके पास भाड़े का श्रमिक नहीं हैं, सम्मिलित हैं। इसमें सभी गैर-कृषि दैनिक वेतनभोगी मजदूर जैसे विनिर्माण मजदूर तथा सिरपर बोझा ढोने वाले मजदूर जो एक से अधिक नियोक्ता के लिए कार्य करते हैं, उन्हें भी शामिल किया जाता है। आप देखेंगे की यह श्रमिकों को वर्गीकृत करने का एक तरीका है। हालाँकि, वर्गीकरण के अन्य तरीके भी हो सकते हैं, कक्षा में संभावित तरीकों पर चर्चा करें।

बॉक्स 6.1 औपचारिक क्षेत्रक में रोजगार

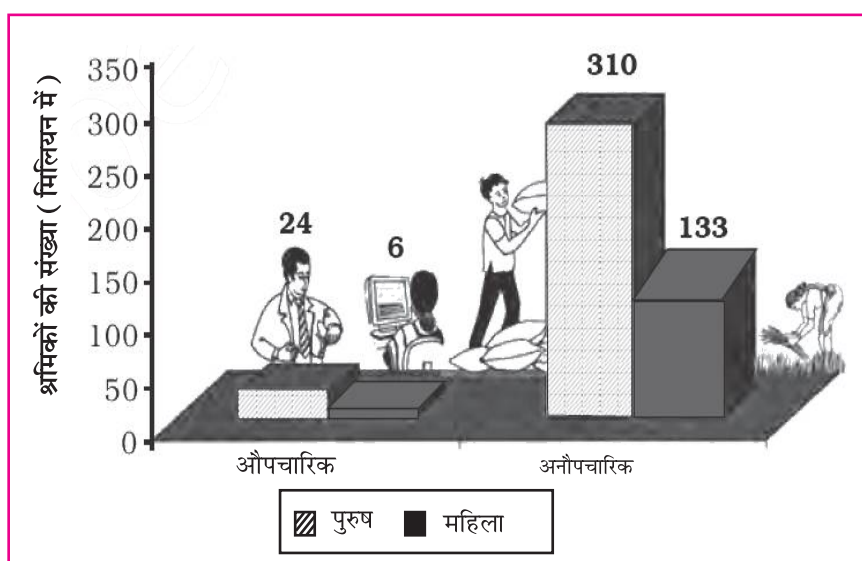
केन्द्रीय श्रम मंत्रालय देश के विभिन्न भागों में स्थित रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार संबंधित जानकारीयें एकत्र करता है। क्या आप जानते हैं कि औपचारिक क्षेत्रक में सबसे बड़ा रोज़गारदाता कौन है? वर्ष 2012 में इस क्षेत्रक में कार्य कर रहे 30 मिलियन कर्मचारियों में से 18 मिलियन कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्रक में कार्यरत थे। यहाँ भी पुरुषों का ही वर्चस्व है—महिलाएँ औपचारिक क्षेत्रक के कर्मचारियों की केवल 1/6वां अंश ही थी। अर्थशास्त्रियों ने पाया है कि 1991 से आर्थिक सुधार प्रक्रिया ने औपचारिक क्षेत्रक में कार्य कर रहे कर्मियों की संख्या को कम किया है। आपका क्या मत है?



चित्र 6.4 सड़कों के किनारे दुकानदारी : अनौपचारिक क्षेत्रक में बढ़ती विविधता

सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं। इनकी कमाई भी असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों से अधिक होती है। विकास योजनाओं में सैद्धांतिक रूप से यह माना गया था कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी, अधिकाधिक श्रमिक औपचारिक क्षेत्र में सम्मिलित होते जाएंगे और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों का अनुपात बहुत कम रह जाएगा। किंतु वास्तव में भारत में क्या हुआ? आरेख 6.4 को देखें जिसमें संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में श्रमबल का वितरण दर्शाया गया है।

सन् 2017-18 में 473 मिलियन श्रमिक थे। केवल 30 मिलियन श्रमिक ही औपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। क्या आप इनका प्रतिशत अनुपात आकलित कर पाएँगे? ये मात्र 6 प्रतिशत हैं $[(30/473) \times 100]$ । दूसरे शब्दों में, देश के 94 प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 2011-12 में, जिस वर्ष के लिए लिंग-आधारित औपचारिक-अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार का डेटा उपलब्ध है (आरेख 6.4), उसके अनुसार औपचारिक क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत और अनौपचारिक क्षेत्र का लगभग 30 प्रतिशत महिलाएँ हैं।



आरेख 6.4 औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रों में श्रमिक, 2011-12

बॉक्स 6.2 अहमदाबाद में अनौपचारिकीकरण

अहमदाबाद एक समृद्ध नगर है। यहाँ की समृद्धि का आधार 60 से अधिक कपड़े के कारखाने का उत्पाद है, जिनमें 1,50,000 श्रमिक काम करते हैं। पिछली एक शताब्दी में इन श्रमिकों ने एक निश्चित सीमा में आय की सुरक्षा हासिल कर ली थी। इनके निश्चित रोजगार थे और इन्हें मिल रहे वेतन निर्वाह के लिए पर्याप्त थे। साथ ही इन्हें अनेक प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभ भी मिलने लगे, जो उनकी स्वास्थ्य और वृद्धावस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे। उनका एक सशक्त श्रमिक संघ भी था जो न केवल श्रम विवादों में उनका प्रतिनिधित्व करता था बल्कि श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए अनेक जनहितकारी क्रियाओं का संचालन भी करता था। किंतु, 1980 दशक के प्रारंभ में संपूर्ण देश में कुछ कपड़ा मिलें बंद होने लगीं। मुम्बई जैसी कुछ जगहों में मिलें तेजी से बंद हो गई। अहमदाबाद में मिल बंदी की यह प्रक्रिया कुछ धीमी रही और दस वर्षों तक खिंच गई। इस अवधि में कम से कम 80,000 स्थायी तथा 50,000 गैर स्थायी कपड़ा मजदूरों का रोजगार छिन गया और वे अनौपचारिक क्षेत्र का सहारा लेने को विवश हो गए। इन्हीं परिस्थितियों में नगर में आर्थिक मंदी और जन आक्रोश के साथ-साथ सांप्रदायिक दंगे भी भड़क उठे।

श्रमिकों के एक पूरे वर्ग को मध्यम वर्गीय सुरक्षित जीवन शैली से उखाड़ कर अनौपचारिक क्षेत्रक की निर्धनता झेलने के लिए छोड़ दिया गया। कितने ही कपड़ा श्रमिक शराब की लत के सहारे अपने कष्ट भुलाने के प्रयास करने लगे, कुछ ने शराब के माध्यम से आत्महत्या का रास्ता चुना और कितने ही परिवारों को बच्चों की शिक्षा अधूरी रोक कर उन्हें भी काम की तलाश के लिए भेजना पड़ा।

स्रोत : रेनाना झालवालों, रत्ना एम. सुदर्शन एंड जी मील उन्नी (एडि.) इंफोर्मल इकॉनामी एट सेंटर स्टेज, न्यू स्ट्रक्चर्स ऑफ एंपलायमेंट, सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली 2003, पृष्ठ 265।



चित्र 6.5 एक घर में शक्ति संतुलन में परिवर्तन : एक बेरोजगार कारखाना श्रमिक घर में लहसुन छीलता हुआ, जबकि उसकी पत्नी को बीड़ी बनाने का एक काम मिल गया।

1970 के दशक के अंत में भारत सहित अनेक विकासशील देशों ने पाया कि औपचारिक-क्षेत्रक में रोजगार वृद्धि नहीं हो पा रही। इसीलिए उन्होंने अनौपचारिक क्षेत्रक पर ध्यान देना आरंभ किया। किंतु, अनौपचारिक क्षेत्रक के उद्यमों और उनके श्रमिकों की आय नियमित नहीं होती और उन्हें सरकार से भी किसी प्रकार का संरक्षण और नियमन नहीं मिल पाता। श्रमिकों को बिना क्षति पूर्ति के ही काम से निकाल दिया जाता है। अनौपचारिक क्षेत्रक उपक्रमों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी पुरानी हो चुकी है तथा ये किसी प्रकार के लेखा-खाते भी नहीं रखते हैं। इस क्षेत्रक के श्रमिक प्रायः गंदी बस्तियों में तथा झुग्गियों में रहते हैं। कुछ समय से **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** के प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र के आधुनिकीकरण और इस क्षेत्रक के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया है।

इन्हें कीजिए

इनमें से असंगठित क्षेत्रकों की क्रियाओं में लगे व्यक्तियों के सामने चिन्ह अंकित करें :

- एक ऐसे होटल का कर्मचारी जिसमें सात भाड़े के श्रमिक एवं तीन पारिवारिक सदस्य हैं।
- एक ऐसे निजी विद्यालय का शिक्षक जहाँ 25 शिक्षक कार्यरत हैं।
- एक पुलिस सिपाही
- सरकारी अस्पताल की एक नर्स
- एक रिक्शाचालक
- कपड़े की दुकान का मालिक, जिसके यहाँ नौ श्रमिक कार्यरत हैं।
- एक ऐसी बस कंपनी का चालक, जिसमें 10 से अधिक बसें और 20 चालक, संवाहक तथा अन्य कर्मचारी हैं।
- दस कर्मचारियों वाली निर्माण कंपनी का सिविल अभियंता
- राज्य सरकारी कार्यालय में अस्थायी आधार पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर
- बिजली दफ्तर का एक क्लर्क

6.8 बेरोज़गारी (Unemployment)

आपने समाचार-पत्रों में रोज़गार की तलाश करते हुए व्यक्तियों को देखा होगा। कुछ लोग अपने मित्रों और सगे संबंधियों के माध्यम से रोज़गार तलाशते हैं। कई शहरों में कुछ चुने हुए स्थानों पर ऐसे अनेक लोग खड़े दिखाई दे जाते हैं, जिन्हें उस दिन के लिए काम देने वाले की प्रतीक्षा रहती है। कुछ लोग दफ़्तरों-कारख़ानों में अपना जीवन-वृत्त सौंप कर वहाँ पता लगा रहे होते हैं कि क्या उनके योग्य कोई स्थान रिक्त है। कई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर जाकर काम के बारे में पूछताछ नहीं करते हैं और घर पर ही बैठे रहते हैं, जब उन्हें कोई काम नहीं होता। कुछ व्यक्ति रोज़गार कार्यलयों में उनके

माध्यम से अनुसूचित रिक्तियों के लिए अपने नाम पंजीकृत कराते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (पहले इसे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के रूप में जाना जाता था) ने बेरोज़गारी को इस प्रकार परिभाषित किया है कि यह वह अवस्था है, जिसमें व्यक्ति काम के अभाव के कारण बिना काम के रह जाते हैं। वे कार्यरत व्यक्ति नहीं हैं, परंतु रोज़गार कार्यलयों, मध्यस्थों, मित्रों, संबंधियों आदि के माध्यम से या संभावित रोज़गारदाताओं को आवेदन देकर या वर्तमान परिस्थितियों और प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने की अपनी इच्छा प्रकट कर कार्य तलाशते हैं। किसी बेरोज़गार व्यक्ति की पहचान विभिन्न तरीकों से की जाती है। अर्थशास्त्री उसे **बेरोज़गार** कहते हैं जो आधे दिन की अवधि में एक घंटे का रोज़गार भी नहीं पा सकता।

भारत में बेरोज़गारी के आँकड़ों के तीन स्रोत हैं ; भारत की जनगणना रिपोर्ट ; राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय की रोज़गार और बेरोज़गारी की अवस्था संबंधी वार्षिक रिपोर्ट ; PLFS की वार्षिक रिपोर्ट ; तथा रोज़गार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत आँकड़ें। यद्यपि इन स्रोतों से बेरोज़गारी के भिन्न-भिन्न अनुमान किए हैं, ये हमें बेरोज़गारी के लक्षणों तथा देश में प्रचलित बेरोज़गारी के प्रकारों के विषय में जानकारीयाँ उपलब्ध कराते हैं। क्या हमारी अर्थव्यवस्था में बेरोज़गारी भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं? इस अनुच्छेद के प्रथम गद्यांश में वर्णित स्थिति को **खुली बेरोज़गारी** कहते हैं। भारत में कृषि में फैली बेरोज़गारी को अर्थशास्त्री प्रच्छन्न बेरोज़गार कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोज़गारी क्या होती है?



चित्र 6.6 गन्ने की कटाई करने वाले मजदूर, कृषि श्रमिकों में प्रच्छन्न बेरोज़गारी आम होती है



चित्र 6.5 बेरोज़गार मिल श्रमिक, अनियत रोज़गार की प्रतीक्षा में

मान लीजिए कि किसी एक किसान के पास चार एकड़ का भूखंड है और उसे अपने खेत में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को निष्पादित करने में दो श्रमिकों की आवश्यकता है किंतु, यदि वह अपने परिवार के पाँच सदस्यों (पत्नी, बच्चों आदि) को कृषि कार्य में लगा ले तो यह स्थिति **प्रच्छन्न बेरोज़गारी** के नाम से जानी जाती है। 1950 के दशक के अंत में किए गए एक अध्ययन के द्वारा भारत में एक तिहाई कृषि श्रमिकों को प्रच्छन्नरूप से बेरोज़गार दिखाया गया था।



चित्र 6.7 बांध निर्माण कार्य में सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होता है

आपने यह भी देखा होगा कि बड़ी संख्या में लोग शहरों की ओर प्रवासन करते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं और सीमित अवधि तक वहाँ रहते हैं। पर, वर्षा ऋतु आरंभ होते ही वे अपने गाँव लौट आते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? कारण यही है कि कृषि का कार्य मौसमी होता है—वर्ष भर गाँव में रोजगार के अवसर नहीं होते हैं। जब खेत में काम नहीं होता है तो लोग शहर की ओर जाते हैं और काम खोजते हैं। ऐसी बेरोजगारी की अवस्था को **मौसमी बेरोजगारी** कहते हैं। भारत में बेरोजगारी का ये प्रकार भी बहुत बड़े स्तर पर प्रचलित है।

यद्यपि हमने देखा है कि रोजगार संवृद्धि दर बहुत धीमी रही है। पर क्या आपने लोगों को बहुत लंबे समय तक रोजगार से वंचित देखा है? विद्वानों का कहना है कि भारत में व्यक्ति बहुत लंबे समय तक पूर्णतः बेरोजगार नहीं बैठे रह पाते क्योंकि उनकी आर्थिक दशा इतनी निराशाजनक होती है कि कोई भी काम स्वीकार करना पड़ जाता है। आप उन्हें ऐसे काम भी करते हुए देख सकते हैं जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। इनमें बहुत ही असुविधाजनक, अस्वास्थ्यकर, अस्वच्छ तथा जौखिम भरे कार्य भी होते हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारों ने निम्न आय परिवारों के बेहतर रहन-सहन के लिए विभिन्न रोजगार सृजित किए हैं और इसके लिए पहल की है। इस विषय में अगले परिच्छेद में चर्चा की जायेगी।

6.9 सरकार और रोजगार सृजन (Government and Employment Generation)

भारत की संसद ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 पारित किया था। यह देश के ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने को 100 दिन की दिहाड़ी उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्हें नौकरी की आवश्यकता है उनके लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए यह सरकार द्वारा संचालित अनेक उपायों में से एक है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही संघीय और राज्य सरकारें रोजगार सृजन हेतु अवसरों की रचना करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हैं। इनके प्रयासों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है : प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। जैसा कि आपने पिछले अनुभाग में पढ़ा कि प्रथम श्रेणी में सरकार अपने विभिन्न विभागों में प्रशासकीय कार्यों के लिए नियुक्तियाँ करती है। सरकार अनेक उद्योग, होटल और परिवहन कंपनियाँ भी चला रही है। इन सबमें भी यह प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती हैं। जब सरकारी उद्यमों में उत्पादन स्तर में वृद्धि होती है तो उन उद्यमों को वस्तुओं की पूर्ति करने वाले निजी उद्यमों को भी अपना उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिलता है। इससे

भी अर्थव्यवस्था में नए रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए, एक सरकारी इस्पात मिल में उत्पादन वृद्धि से उस सरकारी कंपनी में रोज़गार में प्रत्यक्ष वृद्धि होती है। साथ ही, उस इस्पात मिल को उत्पादनों की पूर्ति करने वाली और उससे इस्पात खरीदने वाली निजी कंपनियों को भी अपने-अपने उत्पादन और रोज़गार बढ़ाने का अवसर मिल जाता है। यह सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में रोज़गार के अवसरों का सृजन है।

आपने ध्यान दिया होगा कि सरकारों द्वारा गरीबी निवारण के लिए चलाए जा रहे अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी रोज़गार सृजन के माध्यम से ही होता है। उन्हें **रोज़गार सृजन कार्यक्रम** भी कहा जाता है। इस तरह के कार्यक्रम केवल रोज़गार ही उपलब्ध नहीं कराते, इनके सहारे प्राथमिक जनस्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण जलापूर्ति, पोषण, लोगों की आय तथा रोज़गार सृजन करने वाली परिसंपत्तियाँ खरीदने में सहायता, दिहाड़ी रोज़गार का सृजन करने वाली सामुदायिक परिसंपत्तियों का विकास, गृह और स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण, गृह-निर्माण के लिए सहायता, ग्रामीण सड़कों का निर्माण और बंजर भूमि आदि के विकास के कार्य पूरे किए जाते हैं।

6.10 निष्कर्ष (Conclusion)

भारत की श्रमबल संरचना में परिवर्तन आ चुका है। सेवा क्षेत्रक में रोज़गार के नये अवसरों का सृजन हो रहा है। सेवा क्षेत्रक का विस्तार तथा इसमें नयी प्रौद्योगिकी के प्रादुर्भाव के कारण अब निर्बाध रूप से लघु उद्योग तथा कुछ विशिष्ट उपक्रम तथा विशेषज्ञ श्रमिक ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में टिक सकते हैं। कार्य की बाह्य प्रापण (आउटसोर्सिंग) एक सामान्य बात हो गयी है। इसका तात्पर्य यह है कि एक बड़ी फर्म के लिए यह लाभप्रद है कि वह अपने विशिष्ट विभागों (जैसे, विधि, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या ग्राहक सेवा-अनुभाग) को बंद कर छोटे उद्यमियों को बड़े पैमाने पर छोटे-छोटे रोज़गार उपलब्ध कराए जो कि दूसरे देशों में भी स्थित हो सकते हैं। आधुनिक कारखाने की परंपरागत अवधारणा इस प्रकार बदल रही है कि घर ही कार्य-स्थलों में परिवर्तित हो रहे हैं। यह समस्त परिवर्तन व्यक्तिगत श्रमिक के पक्ष में नहीं हो रहा है। श्रमिकों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता के कारण रोज़गार का स्वरूप और अधिक अनौपचारिक हो गया है। इसके बावजूद पिछले कुछ दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि हुई है। लेकिन इसके साथ ही रोज़गार के अवसरों का सृजन नहीं होने के कारण सरकार को विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों का सृजन करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

पुनरावर्तन (RECAP)

- जो व्यक्ति आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हैं और इस प्रकार सकल राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान दे रहे हैं, उन्हें हम श्रमिक कहते हैं।
- देश की जनसंख्या के पाँच में से दो व्यक्ति विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हैं।
- मुख्यतः ग्रामीण पुरुष देश के श्रमबल का सबसे बड़ा वर्ग हैं।
- भारत में अधिकांश श्रमिक स्वनियोजक है। अनियत दिहाड़ी मजदूर तथा नियमित वेतनभोगी कर्मचारी मिलकर भी भारत की समस्त श्रम शक्ति के अनुपात के आधे से भी कम ही रह जाते हैं।
- भारत की कुल श्रमबल के लगभग पाँच में से तीन श्रमिक कृषि और संबद्धित कार्यों से ही अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं।

- हाल के कुछ वर्षों से रोजगार वृद्धि में शिथिलता आई है।
- सुधारोपरांत भारत में सेवा क्षेत्रक में नए रोजगार के अवसरों का उदय हुआ है। ये नए रोजगार मुख्यतः अनौपचारिक क्षेत्र के ही अंतर्गत आते हैं तथा इनके कार्य की प्रकृति अधिकांशतः अनियत है।
- सरकार देश में सबसे बड़ा औपचारिक क्षेत्रक नियोक्ता है।
- प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी का एक रूप है।
- भारत की श्रमबल की संरचना में बड़ा परिवर्तन आया है।
- अपनी विभिन्न योजनाओं और नीतियों द्वारा सरकार प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से रोजगार सृजन के लिए प्रयास करती है।

●●● अभ्यास ●●●

1. वैकल्पिक चुनाव वाले प्रश्न (Multiple Choice Questions)

(i) अलग चुनो:-

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| (क) नाई की दुकान का मालिक | (ख) एक मोची |
| (ग) वेरका दूध प्लांट का प्रबन्धक | (घ) ट्यूशन पढ़ाने वाला अध्यापक |

(ii) अलग चुनो:-

- | | |
|---------------|------------------------|
| (क) एक भिखारी | (ख) एक चोर |
| (ग) एक तस्कर | (घ) एक सरकारी कर्मचारी |

(iii) असंगठित क्षेत्र में कौन शामिल नहीं होता?

- | | |
|------------------------|-----------------|
| (क) पुलिस वाला | (ख) रिक्शा वाला |
| (ग) होटल वाला कर्मचारी | (घ) रेहड़ी वाला |

(iv) इन क्रियाओं को सेवा-क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है?

- | | |
|-------------|---------------------|
| (क) व्यापार | (ख) परिवहन (आवाजाई) |
| (ग) बैंकिंग | (घ) निर्माण |

(v) कौन-सी क्रियाओं को द्वितीयक क्षेत्रक में शामिल किया जाता है?

- | | |
|---------------------|-----------------|
| (क) उत्पादन | (ख) निर्माण |
| (ग) बिजली की सप्लाई | (घ) उपरोक्त सभी |

(vi) गैर-आर्थिक क्रिया चुनो:-

- | | |
|-------------|-----------------|
| (क) उत्पादन | (ख) उपभोग |
| (ग) निवेश | (घ) कोई भी नहीं |

(vii) बेरोज़गारी के आंकड़ों के स्रोत कौन से हैं?

- (क) भारत की जनगणना की रिपोर्टें (ख) एन. एस. ओ. की रिपोर्टें
(ग) रोज़गार दफ़्तर के आंकड़े (घ) उपरोक्त सभी

(viii) ठीक मिलान करो (Match the Column)

	रोज़गार उत्पत्ति कार्यक्रम		विशेषतायें
1.	मनरेगा	i	केन्द्रीय सरकार की कौशल सृजन की योजना
2.	निपुण भारत	ii	शहरी रोज़गार योजना
3.	मेक इन इण्डिया	iii	ग्रामीण रोज़गार योजना
4.	राष्ट्रीय न्यूनतम मज़दूरी दर	iv	संगठित क्षेत्रक के मज़दूरों के कल्याण के लिए उठाया गया कदम

2. सही या गलत (True / False)

- (i) ग्रामीण पुरुष देश के कार्य-बल का सबसे बड़ा भाग हैं।
(ii) 1991 के आर्थिक सुधारों के पश्चात् सेवाओं के क्षेत्र में रोज़गार के ज्यादा अवसर पैदा हुए हैं।
(iii) ग्रामीण क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोज़गारी कम पायी जाती है।
(iv) भारत के श्रम विभाजन के स्वरूप में परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा।
(v) भारत में रोज़गार की गुणवत्ता में कमी आ रही है।

3. खाली स्थान भरो (Fill in the blanks)

- (i) कुल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाली सभी क्रियाओं को कहा जाता है।
(आर्थिक क्रियाएँ/गैर-आर्थिक क्रियाएँ)
(ii) रोज़गार की परिभाषा देश में श्रम-शक्ति में औरतों की भागीदारी को नहीं मानती।
(विस्तृत/संकुचित)
(iii) भारत में रोज़गार की प्रकृति है।
(सरल/बहुपक्षीय)
(iv) देश के कार्य-बल का सबसे बड़ा भाग है।
(स्त्री/पुरुष)
(v) क्षेत्र भारत में ज्यादातर मज़दूरों के लिए रोज़गार का स्रोत है। (प्राथमिक/गौण)
(vi) आर्थिक विकास से क्षेत्रक में काम करने वाले मज़दूरों की संख्या में वृद्धि हुई है।
(संगठित/असंगठित)
(vii) नियमित वेतन वाले रोज़गार से दिहाड़ीदार मज़दूरी वाले काम की ओर जाने वाली प्रक्रिया को श्रम शक्ति का होना कहते हैं।
(रस्मीकरण/गैर-रस्मीकरण)
(viii) भारत में क्षेत्रक रोज़गार के नये साधन पैदा कर रहा है।
(उद्योग/सेवा)

4. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (Very Short Answer Type Questions)

- (i) श्रमिक/मजदूर से क्या अभिप्राय है?
- (ii) कार्य शक्ति सहभागिता दर या श्रम जनसंख्या अनुपात से क्या तात्पर्य है?
- (iii) राज स्कूल जाने के पश्चात खेतों में काम करने जाता है। लेकिन, जब वह स्कूल में नहीं होता तो वह प्रायः अपने खेतों में काम करते देखा जाता है। क्या आप उसे मजदूर मानोगे?
- (iv) विल्सन दिन में केवल चार घण्टे काम करता है, बाकी समय में वह काम ढूँढता है। क्या वह बेरोजगार कहलायेगा?
- (v) विल्सन जैसे लोगों को किस तरह के रोजगार के अवसर मिलते हैं?
- (vi) दिहाड़ीदर मजदूर से क्या अभिप्राय है?
- (vii) मीना एक घर-गृहस्थी संभालने वाली औरत है। वह घरेलू काम खत्म करके अपने पति की कपड़े की दुकान पर काम में हाथ बंटाती है। क्या उसे मजदूर माना जायेगा?

5. लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

- (i) शहरी औरत मजदूरों के मुकाबले ग्रामीण औरत मजदूरों की बहुतायत क्यों है?
- (ii) शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले नियमित कर्मचारियों की बहुतायत क्यों पायी जाती है?
- (iii) गत 70 वर्षों के दौरान रोजगार के जो अवसर पैदा हुए हैं क्या वे आर्थिक विकास की दर के अनुरूप हैं? कैसे?
- (iv) 'मनरेगा' पर नोट लिखें।
- (v) 'रोजगारहित आर्थिक विकास' से क्या अभिप्राय है?

6. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

- (i) आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हो। अपनी पंचायत को आप किस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएँ शुरू करने की सलाह देंगे जिससे रोजगार में बढ़ौतरी हो सके?
- (ii) आपको कैसे मालूम होगा कि एक मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है? असंगठित क्षेत्र की विशेषताएँ लिखो।
- (iii) भारत में वर्तमान क्षेत्रीय श्रम विभाजन पर विचार चर्चा करो।
- (iv) क्या यह जरूरी है कि विकास से संबंधित क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र की अपेक्षा रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होने चाहिये? क्यों?
- (v) भारत सरकार द्वारा बेरोजगारी को कम करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के उठाये गये कदमों का वर्णन करो।

Q.7. आंकड़ों को देखकर प्रश्नों के उत्तर दे। (Analyse the Data & Answer the Questions)

- (i) निम्न सारणी 1999-2000 के दौरान, श्रम-शक्ति को दर्शाती है। इसका विश्लेषण करके श्रम-शक्ति के विभाजन के स्वरूप सम्बन्धी टिप्पणी करो तथा इस विभाजन के लिए उत्तरदायी कारणों के बारे बताओ।

क्षेत्र	अनुमानित जनसंख्या (करोड़ में)	श्रम-जनसंख्या अनुपात	मजदूरों की संख्या (करोड़ में)
ग्रामीण	71.88	41.9	$\frac{71.88}{100} \times 41.9 = 30.12$
शहरी	28.52	33.7	?
कुल जोड़	100.40	39.5	?

- (ii) इस सारणी में 1972-73 में भारत की जनसंख्या तथा श्रम जनसंख्या अनुपात दिया गया है। इससे आय भारत के शहरी तथा कुल मजदूरों की संख्या का अनुमान लगाओ।

क्षेत्र	कार्य-शक्ति (करोड़ में)		
	पुरुष	स्त्री	कुल
ग्रामीण	125	70	195
शहरी	32	7	39

प्रस्तावित क्रियात्मक गतिविधियां (Suggested Additional Activities)

1. एक मोहल्ला चुनो या एक गली तथा इसे तीन से चार उप क्षेत्रों में बांटो। एक सर्वेक्षण करो। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की सभी आर्थिक क्रियाओं के तथ्यों को इकट्ठा करो। इसके उपरान्त सभी उप क्षेत्रों के लिए अलग तौर पर श्रम जनसंख्या अनुपात का अनुमान लगाओ। इन अनुपातों के बीच अन्तर समझाओ।
2. प्रदेश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करने की जिम्मेवारी विद्यार्थियों के तीन से चार समूहों में बांटो। धान की खेती पहले क्षेत्र में मुख्य रूप से होती हो। दूसरे क्षेत्र में बागवानी प्रमुख कार्य हो। तीसरे क्षेत्र में कपास की खेती होती हो। चौथा क्षेत्र नदी के नजदीक हो तथा यहां बहुतायत में पशु-पालन किया जाता हो। विद्यार्थी समूहों को उन क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की आवश्यकता सम्बन्धी अपनी रिपोर्टें तैयार करने के लिए कहें।
3. सरकार के द्वारा आपके क्षेत्र में सड़कों के निर्माण, छप्पड़ों की सफाई, स्कूलों की इमारतों, अस्पतालों तथा अन्य सरकारी दफ्तरों का निर्माण, चैक-डैमों का निर्माण, निर्धन-वर्ग के लोगों के लिए मकानों के निर्माण आदि के कई काम किये जा सकते हैं। एक काम से सम्बन्धित एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करो। कुछ ऐसे विषयों के आंकड़ें इकट्ठा करो, जैसे (क) काम की पहचान कैसे की गई?

(ख) मंजूर की गई राशि (ग) स्थानीय लोगों का योगदान, यदि कुछ है (घ) काम में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या-स्त्री तथा पुरुष समेत (ङ) अदा की गई मजदूरी की राशि (च) क्या उस क्षेत्र में उस काम की सचमुच ही आवश्यकता थी जिस योजना के अधीन यह काम किया जा रहा है। इस सम्बन्धी भी एक आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक टिप्पणी की जा सकती है।

4. वर्तमान में कुछ वर्षों के दौरान आप ने बहुत सी स्वयं सेवक संस्थाओं को कंडी तथा शुष्क क्षेत्रों में रोज़गार पैदा करने सम्बन्धी गतिविधियों में लीन पाया होगा। यदि आप के इलाके में भी ऐसी कोई संस्था काम कर रही है तो उस परियोजना (प्रोजैक्ट) को देखकर अपनी रिपोर्ट तैयार करो।

REFERENCES

- CHADHA, G.K. and P.P. SAHU, 2002. 'Post-reform Setbacks in Rural Employment: Issues that need further scrutiny.' *Economic and Political Weekly*, May 25, pp.1998-2026
- DESAI, S and M.B.DAS. 2004. 'Employment Driving India's Growth Surge', *Economic and Political Weekly*, July 3, pp. 3045-3051
- GHOSE, AJIT K. 1999. 'Current Issues of Employment Policy in India.' *Economic and Political Weekly*, September 4, pp. 2592- 2608
- HIRWAY, INDIRA. 2002. 'Employment and Unemployment Situation in 1990s: How Good are NSS Data.' *Economic and Political Weekly*, May 25, pp. 2027-2036
- JACOB, PAUL. 1986. 'Concept of 'work' and estimates of 'workforce' — An appraisal of the treatment of activities relating to non- marketed output,' *Sarvekshana*, Vol.IX, No.4, April
- KULSHRESHTHA, A.C., GULAB SINGH, ALOK KAR and R.L. MISHRA. 2000. 'Workforce in the Indian National Accounts Statistics,' *The Journal of Income and Wealth*, Vol.22, No.2, July, pp. 3-39
- PRADHAN, B.K. and M.R.SALUJA. 1996. 'Labour Statistics in India: A Review.' *Margin*, July- September, Vol.28, Number 4, pp. 319-347
- RATH, NILAKANTHA. 2001. 'Data on Employment, Unemployment and Education: Where to go from here?' *Economic and Political Weekly*, June 9, pp. 2081-2087
- SUNDARAM, K. 2001. 'Employment-Unemployment Situation in the Nineties: Some Results from NSS 55th Round Survey', *Economic and Political Weekly*, March 17, pp. 931-940
- SUNDARAM, K. 2001. 'Employment and Poverty in 1990s: Further Results from NSS 55th Round Employment-Unemployment Survey, 1999-2000,' *Economic and Political Weekly*, August 11, pp. 3039-3049

- VISARIA, PRAVIN. 1996. 'Structure of the Indian Workforce, 1961- 1994,' The Indian Journal of Labour Economics, Vol.39, No.4, pp. 725-740

Government Reports

- Annual Reports, Ministry of Labour, Government of India, Delhi. Census of India 2011, Primary Census Abstract, Registrar General of Census Operations, Ministry of Home Affairs, Government of India, Delhi
- Economic Survey, Ministry of Finance, Government of India
- Reports on Employment and Unemployment Situation in India, Ministry of Statistics and Planning, Government of India
- Annual Report of Periodic Labour Force Survey 2017-18, National Statistical Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India, New Delhi

Websites

- www.censusofindia.nic.in
- www.mospi.nic.in



7

पर्यावरण और धारणीय विकास

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप

- पर्यावरण की अवधारणा को समझेंगे ;
- 'पर्यावरण अधोगति और संसाधन अपक्षय' के कारणों तथा प्रभावों का विश्लेषण कर सकेंगे ;
- भारत के समक्ष पर्यावरण चुनौतियों की प्रकृति को समझेंगे ;
- पर्यावरण मुद्दों को धारणीय विकास के व्यापक संदर्भ से जोड़ सकेंगे ।

पर्यावरण को यदि यथावत् छोड़ दिया जाये तो वह निरंतर लाखों वर्षों तक जीवन का सहारा बन सकता है। इस योजना में एकमात्र सर्वाधिक अस्थिर और संभावित विनाशकारी शक्ति मानव प्रजाति है। मनुष्य आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से पर्यावरण में जाने-अनजाने दूरगामी और अपरिवर्तनीय बदलाव लाने की क्षमता रखता है।

अध्याय – 7

पर्यावरण और धारणीय विकास

7.1 परिचय (Introduction)

पिछले अध्यायों में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की है। अभी तक प्राप्त आर्थिक विकास की हमने भारी कीमत चुकाई है। इसके लिए हमें पर्यावरण की गुणवत्ता की बलि देनी पड़ी है। अब जैसे-जैसे हम वैश्वीकरण में जिसका सकल्प उच्च आर्थिक संवृद्धि है, प्रवेश करते हैं वैसे-वैसे हमें पहले के विकास पथ के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखना होगा और ध्यानपूर्वक धारणीय विकास के पथ को चुनना होगा। हमारे द्वारा अपनाये गये विकास के अधारणीय पथ और धारणीय विकास की चुनौतियों को समझने के लिए सबसे पहले हमें आर्थिक विकास में पर्यावरण के महत्व और योगदान को समझना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय को तीन भागों में बाँटा गया है। पहला भाग पर्यावरण के कार्यों व भूमिका से संबंधित है। दूसरे भाग में भारत में पर्यावरण की स्थिति पर चर्चा की गई है और तीसरे भाग में धारणीय विकास प्राप्त करने के लिए उठाये गये कदमों और युक्तियों पर विचार किया गया है।

7.2 पर्यावरण : परिभाषा और कार्य (Environment - Definition and Functions)

पर्यावरण को समस्त भूमंडलीय विरासत और सभी संसाधनों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें वे सभी जैविक और अजैविक तत्व आते हैं, जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सभी जीवित तत्व-जैसे, पक्षी, पशु, पौधे, वन, मत्स्य आदि जैविक तत्व हैं जबकि हवा, पानी, भूमि, अजैविक तत्व हैं। चट्टान और सूर्य किरण पर्यावरण के अजैविक तत्व के उदाहरण हैं। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इन्हीं जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतर्संबंधों का अध्ययन किया जाता है।

पर्यावरण के कार्य (Functions of the Environment) : पर्यावरण चार आवश्यक कार्य करता है

(क) यह संसाधनों की पूर्ति करता है, जिसमें नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधन शामिल होते हैं। नवीकरणीय-योग्य संसाधन वे हैं जिनका उपयोग संसाधन के क्षय या समाप्त होने की आशंका के बिना किया जा सकता है, अर्थात् संसाधनों की पूर्ति निरंतर बनी रहती है। नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरणों में, वनों में पेड़ और समुद्र में मछलियाँ हैं। दूसरी ओर, गैर-नवीकरणीय योग्य संसाधन वे हैं जो कि निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जीवाश्म ईंधन।

परिभाषा

डगलेस और हालैंड के अनुसार, “पर्यावरण एक ऐसा शब्द है जो जीवित जीवों के जीवन, व्यवहार, प्रकृति, वृद्धि, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करने वाली सभी ब्राह्म शक्तियों, प्रभावों और स्थितियों का वर्णन करता है।”

(ख) यह अवशेष को समाहित कर लेता है।

(ग) यह जननिक और जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का पोषण करता है।

(घ) यह सौंदर्य विषयक सेवाएँ भी प्रदान करता है, जैसे कि कोई सुंदर दृश्य।



चित्र 7.1 ताजा पानी के कुछ स्रोत जो प्रदूषण रहित हैं

पर्यावरण इन कार्यों को बिना किसी व्यवधान के तभी कर सकता है, जब तक कि ये कार्य उसकी धारण क्षमता की सीमा में हैं। इसका अर्थ है कि संसाधनों का निष्कर्षण इनके पुनर्जनन की दर से अधिक नहीं है और उत्पन्न अवशेष पर्यावरण की समावेशन क्षमता के भीतर है। जब ऐसा नहीं होता, तो पर्यावरण जीवन पोषण का अपना तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य करने में असफल हो जाता है और इससे पर्यावरण संकट पैदा होता है। पूरे विश्व में आज यही स्थिति है। विकासशील देशों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और विकसित देशों के समृद्ध उपभोग तथा उत्पादन मानकों ने पर्यावरण के पहले दो कार्यों पर भारी दबाव डाला है। अनेक संसाधन विलुप्त हो गये हैं और सृजित अवशेष पर्यावरण के अवशोषी क्षमता के बाहर हैं। अवशोषी क्षमता का अर्थ पर्यावरण की

इन्हें कीजिए

- जल एक आर्थिक उपभोक्ता वस्तु क्यों बन गया है? चर्चा कीजिए।
- नीचे की सारणी में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के कारण होने वाले कुछ आम रोगों और बीमारियों के नाम भरें।

वायु प्रदूषण	जल प्रदूषण	ध्वनि प्रदूषण
दमा	हैजा	

बॉक्स 7.1 : वैश्विक उष्णता

वैश्विक उष्णता पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को कहते हैं। वैश्विक उष्णता औद्योगिकी क्रांति से गरीन हाउस गैसों में वृद्धि के परिणामस्वरूप पृथ्वी के निचले वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक बढ़ोत्तरी है। वर्तमान में और आने वाले दिनों में वैश्विक उष्णता में अधिकांश मानव-उत्प्रेरित है। यह मानव द्वारा **वनविनाश** तथा **जीवाश्म ईंधन** के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य **ग्रीन हाउस** गैसों की वृद्धि के कारण होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन गैस तथा दूसरी गैसों (जिनमें गर्माहट को सोखने की क्षमता है) वातावरण में मिलने से हमारे भूमंडल की सतह गर्म होती जायेगी। 1750 की पूर्व-औद्योगिक स्तरों से अब तक कार्बन डाइऑक्साइड और CH_4 के वायुमंडलीय संकेंद्रण में क्रमशः 31 प्रतिशत और 149 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछली शताब्दी में वायुमंडलीय तापमान में 1.1°f (0.6°C) की वृद्धि हुई है और समुद्र तल कई इंच ऊपर उठा गया है। वैश्विक उष्णता के कुछ दीर्घकालीन परिणाम हैं-ध्रुवीय हिम का पिघलना जिसके परिणामस्वरूप समुद्र स्तर में वृद्धि और बाढ़ का प्रकोप, हिम पिघलाव पर निर्भर पेयजल की पूर्ति में पारिस्थितिक असंतुलन के कारण प्रजातियों की विलुप्ति; उष्ण कटिबंधीय तूफानों की बारंबारता और उष्ण कटिबंधीय रोगों के प्रभाव में बढ़ोत्तरी। वैश्विक उष्णता में योगदान करने वाले अन्य तत्व हैं : कोयला व पेट्रोल उत्पाद का प्रज्वलन (ये कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन के स्रोत हैं), वनविनाश जो कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि करता है, जानवरों की अपशिष्ट से निकलने वाली मिथेन गैस और पशुओं की बढ़ती संख्या जो कि वनविनाश, मिथेन उत्पादन और जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में योगदान करती है। 1997 में क्योटो, जापान में जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ जिसमें वैश्विक उष्णता का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। इस समझौते में औद्योगिकीकृत राष्ट्रों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने की माँग की गई।

स्रोत : www.wikipedia.org

अपक्षय को सोखने की योग्यता से है। इसके कारण ही आज हम पर्यावरण संकट की दहलीज पर खड़े हैं। विकास के क्रम में नदियाँ और अन्य जल स्रोत प्रदूषित हुए हैं और सूख गये हैं, इसने जल को एक आर्थिक वस्तु बना दिया है।

इसके साथ ही नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय संसाधनों के गहन और विस्तृत निष्कर्षण से अनेक महत्वपूर्ण संसाधन विलुप्त हो गये हैं और हम नये संसाधनों की खोज में प्रौद्योगिकी व अनुसंधान पर विशाल राशि व्यय करने के लिए मजबूर हैं। इसके साथ जुड़ी है पर्यावरण अपक्षय की स्वास्थ्य लागत। जल और वायु की गुणवत्ता की गिरावट (भारत में 70 प्रतिशत जल प्रदूषित है) से साँस और जल-संक्रामक रोगों की घटनाएँ बढ़ी हैं। परिणामस्वरूप, व्यय भी बढ़ता जा रहा है। वैश्विक पर्यावरण मुद्दों जैसे, **वैश्विक उष्णता** और ओजोन क्षय ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है, जिसके कारण सरकार को अधिक धन व्यय करना पड़ा।

अतः यह स्पष्ट है कि नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों की **अवसर लागत** बहुत अधिक है।

बॉक्स 7.2 : ओजोन अपक्षय

ओजोन अपक्षय का अर्थ समतापमंडल में ओजोन की मात्रा की कमी है। ओजोन अपक्षय की समस्या का कारण समतापमंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के ऊँचे स्तर हैं। इन यौगिकों के मूल हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स (CFC) जिनका प्रयोग रेफ्रिजरेटर और एयरकंडीशन को ठंडा रखने वाले पदार्थ या एरासोल प्रोपेलैन्ट्स में तथा अग्निशामकों में प्रयुक्त किए जाने वाले ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स में होता है। ओजोन स्तर के अपक्षय के परिणामस्वरूप परा बैंगनी विविकरण (UV) पृथ्वी की ओर आते हैं और जीवों को क्षति पहुँचाते हैं। ऐसा लगता है कि विकारण से मनुष्यों में त्वचा कैंसर होता है, यह पादपप्लवक (फीटोप्लैंकटन) के उत्पादन को कम कर जलीय जीवों को प्रभावित करता है। यह स्थलीय पौधों की संवृद्धि को भी प्रभावित करता है। 1979 से 1990 के बीच ओजोन स्तर में लगभग 5 प्रतिशत की कमी आई। चूँकि ओजोन स्तर सर्वाधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में आने से रोकता है, इसलिए अनुमानित ओजोन में कमी विश्व भर में चिंता का विषय है। इसके कारण मांट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाना पड़ा। इसके तहत CFC यौगिकों तथा अन्य ओजोन अपक्षयक रसायनों के प्रयोग पर रोक लगानी पड़ी जैसे : कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्रिक्लोरोथेन (जिन्हें मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं) तथा ब्रोमाइन यौगिक तत्व जिन्हें हैलोन कहा जाता है।

स्रोत : www.ceu.hu

यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या पर्यावरण समस्याएँ इस शताब्दी के लिए नई हैं? यदि ऐसा है तो क्यों? इस प्रश्न के उत्तर के लिए कुछ विस्तार में जाने की आवश्यकता है। प्रारंभ के दिनों में जब सभ्यता शुरू ही हुई थी या जनसंख्या में इस असाधारण वृद्धि के पूर्व और देशों द्वारा औद्योगीकरण अपनाने के पहले पर्यावरण संसाधनों की माँग और सेवाएँ उनकी पूर्ति से बहुत कम थी। इसका अर्थ हुआ कि प्रदूषण, पर्यावरण की अवशोषी क्षमता के भीतर था और संसाधन निष्कर्षण की दर इन संसाधनों के पुनः सर्जन की दर से कम थी। इसलिए पर्यावरण समस्याएँ उत्पन्न नहीं हुई थी। लेकिन जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक क्रांति के आगमन से स्थिति बदल गई। परिणामस्वरूप उत्पादन और उपभोग के लिए



चित्र 7.2 दमोदर घाटी भारत के सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्रों में एक है। भारी उद्योगों से प्रदूषणकारी तत्व दामोदर नदी के किनारे जमा होकर पर्यावरण-संकट उत्पन्न कर रहे हैं

संसाधनों की मांग संसाधनों के पुनः सृजन की दर से बहुत अधिक हो गई ; पर्यावरण की अवशोषी क्षमता पर दबाव बुरी तरह से बढ़ गया। यह प्रवृत्ति आज भी जारी है। इस तरह से, पर्यावरण की गुणवत्ता के मामले में माँग-पूर्ति संबंध पूरी तरह से उलट गये हैं-अब हमारे सामने पर्यावरण संसाधनों और सेवाओं की माँग अधिक है, लेकिन उनकी पूर्ति सीमित है। जिसके कारण अधिक उपयोग और दुरुपयोग हैं। इसीलिए, अवशिष्ट सृजन और प्रदूषण के पर्यावरण मुद्दे आजकल बहुत गंभीर हो गये हैं।

7.3 भारत की पर्यावरण स्थिति (State of India's Environment)

भूमि की उच्च गुणवत्ता, सैंकड़ों नदियाँ व उप नदियाँ, हरे-भरे वन, भूमि के सतह के नीचे बहुतायत में उपलब्ध खनिज-पदार्थ, हिन्द महासागर का विस्तृत क्षेत्र, पहाड़ों की श्रृंखला आदि के रूप में भारत के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन हैं। दक्षिण के पठार की काली मिट्टी विशिष्ट रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसके कारण ही इस क्षेत्र में कपड़ा उद्योग केंद्रित है। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक गंगा का मैदान है, जो कि विश्व के अत्यधिक उर्वर क्षेत्रों में से एक है और विश्व में सबसे गहन खेती और घनत्व जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भारतीय वन वैसे तो असमान रूप से वितरित हैं, फिर भी वे उसकी अधिकांश जनसंख्या को हरियाली और उसके वन्य-जीवन को प्राकृतिक आवरण प्रदान करते हैं। देश में लौह-अयस्क, कोयला और प्राकृतिक गैस के भारी भंडार हैं। भारत में ही विश्व के समस्त लौह-अयस्क भंडार का 8 प्रतिशत उपलब्ध है। हमारे देश के विभिन्न भागों में बॉक्साइट, तांबा, क्रोमेट, हीरा, सोना, सीसा, भूरा कोयला, मैंगनीज, जिंक, यूरेनियम इत्यादि भी मिलते हैं। लेकिन, भारत में विकास गतिविधियों के फलस्वरूप उसके सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। इसके साथ-साथ मानव स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि पर भी उसका असर पड़ रहा है। भारत के पर्यावरण को दो तरफा खतरा है-एक तो गरीबी के कारण पर्यावरण का अपक्षय और दूसरा खतरा साधन-संपन्नता और तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक क्षेत्रों के प्रदूषण से है। भारत की अत्यधिक गंभीर पर्यावरण समस्याओं में वायु प्रदूषण, दूषित जल, मृदा-क्षरण, वन्य-कटाव और वन्य-जीवन की विलुप्ति है। इनमें से प्रमुख ये हैं-(क) भूमि अपक्षय, (ख) जैविक विविधता की हानि, (ग) शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण से उत्पन्न वायु प्रदूषण, (घ) ताजे



चित्र 7.3 वन-कटाव द्वारा भूमि अपक्षय, जैव विविधता की क्षति तथा वायु प्रदूषण

पानी का प्रबंधन और (ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। भारत में भूमि का अपक्षय विभिन्न मात्रा और रूपों में हुआ है, जो कि मुख्य रूप से अस्थिर प्रयोग और अनुपयुक्त (प्रबंधन) कार्य-प्रणाली का परिणाम है।

बॉक्स 7.3 चिपको या अम्पिको-नाम में क्या रखा है?

आप चिपको आंदोलन के बारे में जानते होंगे, जिसका उद्देश्य हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना है। कर्नाटक में एक ऐसे ही आंदोलन ने एक दूसरा नाम लिया-अम्पिको, जिसका अर्थ है बाहों में भरना। 8 सितंबर, 1983 को सिरसी जिले के सलकानी वन में वृक्ष काटे जा रहे थे। तब 160 स्त्री-पुरुष और बच्चों ने पेड़ों को बाहों में भर लिया और लकड़ी काटने वालों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे अगले 6 सप्ताह तक वन की पहरेदारी करते रहे। इन स्वयंसेवकों ने वृक्षों को तभी छोड़ा जब वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वृक्ष वैज्ञानिक आधार पर और जिले की वन संबंधी कार्य योजना के तहत काटे जाएंगे।



जब ठेकेदार द्वारा वाणिज्यिक कटाई से अनेक प्राकृतिक वनों को हानि पहुँची तो वृक्षों को बाहों में भर लेने के विचार ने लोगों में यह आशा और विश्वास उत्पन्न किया कि वे वनों का संरक्षण कर सकते हैं। उस विशेष घटना से जब वृक्षों की कटाई रूक गई तो लोगों के द्वारा 12,000 वृक्षों को बचाया गया। कुछ ही महीनों में यह आंदोलन पास के कई जिलों में भी फैल गया।

ईंधन की लकड़ी और औद्योगिकी प्रयोग के लिए पेड़ों की बेरोक-टोक कटाई से अनेक पर्यावरण समस्याओं का जन्म हुआ। उत्तर कनारा क्षेत्र में एक कागज मिल बनने के 12 साल बाद उस क्षेत्र में बाँस विलुप्त हो गये। एक किसान ने यह बतलाया कि बड़ी-बड़ी पत्तियों वाले पेड़ जो कि भूमि की वर्षा के प्रत्यक्ष आक्रमण से रक्षा करते थे, समाप्त कर दिये गये। इससे मिट्टी वर्षाजल के साथ बह गई और अब सिर्फ कंकड़ वाली मिट्टी रह गई। अब घास के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं पैदा होता। किसान यह भी शिकायत करते हैं कि नदियाँ और उप नदियाँ जल्दी सूख रही हैं और वर्षा की मात्रा भी अनियमित हो गई है। ऐसी बीमारियाँ और कीटाणु जो पहले नहीं थे, फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं।

अम्पिको स्वयंसेवक, ठेकेदारों और वन अधिकारियों से यह चाहते हैं कि वे कुछ नियमों तथा प्रतिबंधों का पालन करें। उदाहरण के लिए, वे चाहते हैं कि काटने के लिए वृक्षों को चिह्नित करने के पूर्व स्थानीय जनता से परामर्श लिया जाए और किसी जल स्रोत के 100 मीटर क्षेत्र में और 30 डिग्री और उसके ऊपर की ढलान के वृक्षों को न काटा जाए।

क्या आप जानते हैं कि उद्योगों को सरकार वन भूमि प्रदान करती है, ताकि वे औद्योगिक उत्पादों के लिए वनों से कच्चे माल उपलब्ध करा सकें। भले ही एक कागज मिल 10,000 मजदूरों को और एक प्लाईवुड फैक्टरी 800 लोगों को नौकरी देती हो, परंतु यदि यह दस लाख लोगों को उनकी दैनिक आवश्यकताओं से वंचित कर देती है, तो क्या यह स्वीकार्य है? आप क्या सोचते हैं?

स्रोत : स्टेट ऑफ इंडियास एनवायरमेंट 2:द सेकेंड सिटीजंस रिपोर्ट, 1984-85, सेंटर साइस एंड एनवायरमेंट, 1996, नई दिल्ली।

भूमि के अपक्षय के लिए उत्तरदायी कुछ प्रमुख कारण हैं :

- (क) वन विनाश के फलस्वरूप वनस्पति की हानि
- (ख) अधारणीय जलाऊ लकड़ी और चारे का निष्कर्षण
- (ग) खेती-बाड़ी
- (घ) वन-भूमि का अतिक्रमण
- (ङ) वनों में आग और अत्यधिक चराई
- (च) भू-संरक्षण हेतु समुचित उपायों को न अपनाया जाना
- (छ) अनुचित फसल चक्र
- (ज) कृषि रसायन का अनुचित प्रयोग जैसे, रासायनिक खाद और कीटनाशक
- (झ) सिंचाई व्यवस्था का नियोजन तथा अविवेकपूर्ण प्रबंधन
- (ट) भूमि जल का पुनः पूर्ण क्षमता से अधिक निष्कर्षण
- (ठ) संसाधनों की निर्बाध उपलब्धता और
- (ड) कृषि पर निर्भर लोगों की दरिद्रता।

इन्हें कीजिए

- आर्थिक विकास में पर्यावरण के योगदान को छात्रों को समझाने के लिए निम्न खेल खेला जा सकता है। एक छात्र किसी उद्यम द्वारा प्रयुक्त किसी उत्पाद का नाम ले और दूसरा छात्र उसकी जड़ों को प्रकृति और पृथ्वी में खोज सकता है।

ट्रक	←	स्टील और रबर				
स्टील	←	लोहा	←	खनिज	←	पृथ्वी
रबर	←	वृक्ष	←	वन	←	पृथ्वी
पुस्तकें	←	कागज	←	वृक्ष	←	वन ← पृथ्वी
वस्त्र	←	कपास	←	पौधा	←	प्रकृति
पेट्रोल	←	पृथ्वी				
मशीनें	←	लोहा	←	खनिज	←	पृथ्वी

- एक ट्रक ड्राइवर को काले धुएँ का उत्सर्जन करने के कारण 10,000 रुपये चालान के रूप में भुगतान करना पड़ा। क्या आपने समझा कि उसे क्यों दंड दिया गया ? क्या यह सही था ? चर्चा कीजिए।

भारत विश्व जनसंख्या के लगभग 17 प्रतिशत और विश्व पशुधन के 20 प्रतिशत को विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र के मात्र 2.5 प्रतिशत क्षेत्र में आश्रय देता है। जनसंख्या और पशुधन का अधिक घनत्व और वानिकी, कृषि, चराई, मानव बस्तियाँ और उद्योगों के प्रतिस्पर्धी उपयोगों से देश के निश्चित भू-संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है। देश में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि केवल 0.06 हेक्टेयर है, जबकि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह संख्या 0.47 हेक्टेयर होनी चाहिए। परिणामस्वरूप, वनों की कटाई स्वीकार्य सीमा से लगभग 15 मिलियन क्यूबिक मीटर अधिक होती है।

मृदा-क्षरण के अनुमान यह दर्शाते हैं कि पूरे देश में एक वर्ष में भूमि का क्षरण 5.3 बिलियन टन प्रतिशत की दर से हो रहा है और इससे देश को प्रत्येक वर्ष 0.8 मिलियन टन नाइट्रोजन, 1.8 मिलियन टन फॉस्फोरस और 26.3 मिलियन टन पोटेशियम का नुकसान होता है। भारत सरकार के अनुसार प्रत्येक वर्ष भूमि क्षय से 5.8 मिलियन टन से 8.4 मिलियन टन पोषक तत्वों की क्षति होती है।

बॉक्स 7.4 : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

भारत में वायु तथा जल प्रदूषण की दो प्रमुख पर्यावरण चिंताओं से निपटने के लिए सरकार ने 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की स्थापना की। इसके बाद, राज्य स्तर पर सभी पर्यावरण चिंताओं से निपटने के लिए राज्यों ने अपने-अपने बोर्ड बनाये। ये बोर्ड (CPCB) जल, वायु और भूमि प्रदूषण से संबंधित सूचनाओं का संकलन और वितरण करते हैं। वे कचड़े/व्यापार निकास और उत्सर्जन के मानक निर्धारित करते हैं। ये बोर्ड सरकारों को जल प्रदूषण के रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए जल-धाराओं द्वारा नदियों और कुओं की स्वच्छता के संवर्धन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। इनका कार्य वायु की गुणवत्ता में सुधार भी है। ये देश में वायु प्रदूषण के नियंत्रण द्वारा भी सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।

ये बोर्ड जल व वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं की जाँच व अनुसंधान भी करते हैं और ऐसी जाँच व अनुसंधान को प्रायोजित करते हैं। इसके लिए वे जनसंचार के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम संगठित करते हैं। PCB कचरे व वाणिज्य अपशिष्टों के निपटान और उपचार से संबंधित नियमावली, संहिता और मार्गदर्शक सूचिका तैयार करते हैं।

उद्योगों के विनियमन द्वारा वे वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन करते हैं। वास्तव में अपने जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से राज्य बोर्ड अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रत्येक उद्योग का समय-समय पर निकास और गैसीय उत्सर्जन के हेतु उपलब्ध उपायों की पर्याप्तता का विश्लेषण करने के लिए निरीक्षण करता है। वे उद्योग-स्थान निर्धारण व नगर नियोजन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तथा वायु गुणवत्ता आँकड़े भी प्रदान करता है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल प्रदूषण से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकी आँकड़ों का संकलन, संपादन और वितरण करते हैं। ये 125 नदियों (इसमें उपनदियाँ भी शामिल हैं), कुएँ, झील, खाड़ी, तालाब, टैंक, नाले और नहरों में जल की गुणवत्ता की देखरेख करते हैं।

- निकट के कारखाने/सिंचाई विभाग में जाइए और जल तथा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उनके द्वारा अपनाये गये उपायों का विवरण इकट्ठा कीजिए।
- वायु तथा जल प्रदूषण से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों को आप समाचार-पत्रों, रेडियो और दूरदर्शन या अपने स्थानीय इलाकों में विज्ञापन-पत्रों में देखते होंगे। कुछ समाचार कतरनें, पैंफलेट और अन्य सूचनाएँ एकत्र करें और कक्षा में उन पर चर्चा करें।

भारत में शहरी इलाकों में वायु-प्रदूषण बहुत है, जिसमें वाहनों का सर्वाधिक योगदान है। कुछ अन्य क्षेत्रों में उद्योगों के भारी जमाव और थर्मल पावर संयंत्रों के कारण वायु प्रदूषण होता है। वाहन उत्सर्जन चिंता का प्रमुख कारण है क्योंकि यह धरातल पर वायु प्रदूषण का स्रोत है और आम जनता पर अधिकतम प्रभाव डालता है। मोटर वाहनों की संख्या 1951 के 3 लाख से बढ़कर 2019 में 30 करोड़ हो गई। 2016 में व्यक्तिगत परिवहन, वाहन (केवल दो पहिये वाहन और कार) संख्या कुल पंजीकृत वाहनों का 85 प्रतिशत थी। इस तरह ये, कुल वायु प्रदूषण बोझ में उल्लेखनीय योगदान करते हैं। भारत विश्व का दसवाँ सर्वाधिक औद्योगिक देश है। लेकिन, इसके कारण से अनचाहे और अप्रत्याशित परिणाम जैसे, अनियोजित शहीरकरण प्रदूषण और दुर्घटनाओं का जोखिम जुड़े हुए हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) ने उद्योगों की 17 श्रेणियों की पहचान बढ़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के रूप में की है। (बॉक्स 7.4 देखें)

उपर्युक्त बिंदु भारतीय पर्यावरण की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं। पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा उठाये गये विभिन्न कदम तब तक कारगर नहीं होंगे, जब तक कि हम सोच-समझ कर धारणीय विकास के रास्ते को नहीं चुनते। भावी पीढ़ियों के भविष्य की दृष्टि के लिए किया गया विकास ही चिरस्थायी होगा। बिना भावी पीढ़ी की चिंता किए, अपने वर्तमान जीवन-स्तर को बढ़ाने के लिए किए विकास-कार्य संसाधनों तथा पर्यावरण का अपक्षय इस गति से करेंगे, जिससे पर्यावरण संबंधी तथा आर्थिक संकट दोनों पैदा हो सकते हैं।

इन्हें कीजिए

- आप किसी भी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में वायु प्रदूषण के माप का कालम देख सकते हैं। इस पर दिवाली से एक सप्ताह पूर्व, दिवाली के दिन और दिवाली के दो दिन बाद के समाचार काटिये। क्या आप इनके माप में कोई महत्वपूर्ण अंतर देखते हैं? अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए।

7.4 धारणीय विकास (Sustainable Development)

पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। अतः पर्यावरण पर होने वाले परिणामों की अवहेलना करने वाला विकास उस पर्यावरण का विनाश कर देगा, जो जीवन को धारण करता है। अतः आवश्यकता है, ऐसे विकास की जो कि भावी पीढ़ियों को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे, जो कम से कम वर्तमान पीढ़ी के द्वारा उपभोग की गई सुविधाओं के बराबर हो। धारणीय विकास की अवधारणा पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन (UNCED) ने बल दिया, जिसने इसे इस प्रकार परिभाषित किया—‘ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता का समझौता किये बिना पूरा करें।’

इस परिभाषा को दुबारा पढ़ें। आप देखेंगे कि ‘आवश्यकता’ और ‘भावी पीढ़ियाँ’ ये दो महत्वपूर्ण अवधारणाएँ हैं। परिभाषा में आवश्यकता की अवधारणा का संबंध संसाधनों के वितरण से है। सम्मेलन की रिपोर्ट-आवर कॉमन फ्यूचर (Our Common Future) जिसने उपर्युक्त परिभाषा दी है, धारणीय विकास की व्याख्या “सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति और एक अच्छे जीवन की आकांक्षाओं की संतुष्टि के लिए सभी को अवसर प्रदान करने के रूप में की है।” सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों के पुनर्वितरण की आवश्यकता होगी, इसीलिए यह एक नैतिक प्रश्न है। एडवर्ड बारबियर ने धारणीय विकास की परिभाषा बुनियादी स्तर पर गरीबों के जीवन के भौतिक मानकों को ऊँचा उठाने के संदर्भ में दी है जिसे आय, वास्तविक आय, शैक्षिक सेवाएँ, स्वास्थ्य देखभाल, सफाई, जल पूर्ति इत्यादि के रूप में परिणात्मक रूप से मापा जा सकता है। अधिक स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि धारणीय विकास का लक्ष्य गरीबों की समग्र दरिद्रता को कम करके उन्हें चिरस्थायी व सुरक्षित जीविका निर्वाह साधन प्रदान करना है जिससे संसाधन अपक्षय, पर्यावरण अपक्षय, सांस्कृतिक विघटन और सामाजिक अस्थिरता न्यूनतम हो। इस अर्थ में धारणीय विकास का अर्थ उस विकास से है जो सभी की, विशेष रूप से बहुसंख्यक निर्धनों की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे-रोजगार, भोजन, ऊर्जा, जल, आवास आदि की पूर्ति करे और इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि, विनिर्माण, बिजली और सेवाओं की वृद्धि सुनिश्चित करे।

ब्रुन्डलैंड कमीशन (Brundtland Commission) ने भावी पीढ़ी को संरक्षित करने पर जोर दिया। यह पर्यावरणविदों के उस तर्क के अनुकूल है, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम भावी पीढ़ी को एक व्यवस्थित भूमंडल प्रदान करें। दूसरे शब्दों में, वर्तमान पीढ़ी को आगामी पीढ़ी द्वारा एक बेहतर पर्यावरण उत्तराधिकार के रूप में सौंपा जाना चाहिए। कम से कम हमें आगामी पीढ़ी के जीवन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों का भंडार छोड़ना चाहिए, जो कि हमें उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है।

वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है कि ऐसे विकास का संवर्द्धन कर प्राकृतिक और निर्मित पर्यावरण का सामंजस्य स्थापित करें जो (क) प्राकृतिक संपदा का संरक्षण (ख) विश्व की प्राकृतिक पारिस्थितिक व्यवस्था की पुनर्जनन क्षमता की सुरक्षा और (ग) भविष्य की पीढ़ियों के ऊपर अतिरिक्त खर्चें या जोखिम को हटाने के अनुकूल हो।

हरमन डेली, एक विख्यात पर्यावरणवादी अर्थशास्त्री के अनुसार धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएँ हैं :

- (क) मानव जनसंख्या को पर्यावरण की धारण क्षमता के स्तर पर सीमित करना होगा। पर्यावरण की धारण क्षमता एक जहाज के भार ढोने की क्षमता के समान है। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की क्षमता के अभाव में मनुष्यों की संख्या पृथ्वी की धारण-क्षमता से अधिक हो जाती है, जो हमें धारणीय विकास से दूर ले जाते हैं।
- (ख) प्रौद्योगिक प्रगति आगत-निपुण हो न कि आगत उपभोगी।
- (ग) नवीकरणीय संसाधनों का निष्कर्षण धारणीय आधार पर हो ताकि किसी भी स्थिति में निष्कर्षण की दर पुनर्सृजन की दर से अधिक न हो।
- (घ) गैर-नवीकरणीय संसाधनों का अपक्षय दर नवीनीकृत प्रतिस्थापकों से अधिक नहीं होनी चाहिए और
- (ङ) प्रदूषण के कारण उत्पन्न अक्षमताओं का सुधार किया जाना चाहिए।

2015 में, संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वर्ष 2030 तक हासिल किए जाने वाले 17 स्थायी विकासात्मक लक्ष्य तैयार किए थे। उन लक्ष्यों का विवरण एकत्र करें और भारत के संदर्भ में उन पर चर्चा करें।

7.5 धारणीय विकास की रणनीतियाँ (Strategies for Sustainable Development)

ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग (Use of Non-conventional Sources of Energy)

: जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अपनी विद्युत आवश्यकताओं के लिए थर्मल और हाइड्रो पॉवर संयंत्रों पर बहुत अधिक निर्भर है। इन दोनों का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। थर्मल पॉवर संयंत्र बड़ी मात्रा में कार्बन-डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। थर्मल पॉवर प्लांटों में बड़ी मात्रा में धुएँ के रूप में राख भी निकलती है, जिसका उचित उपयोग न हो तो, जल, भूमि और पर्यावरण के अन्य संघटकों के प्रदूषण का कारण हो सकता है। जल-विद्युत परियोजनाओं से वन जलमग्न हो जाते हैं और नदी प्रवाह क्षेत्रों तथा नदी की घाटियों की प्राकृतिक प्रवाह में हस्तक्षेप करते हैं। वायु शक्ति और सौर किरणें पारंपरिक ऊर्जा के अच्छे उदाहरण हैं। हाल के वर्षों में, इन ऊर्जा संसाधनों का लाभ उठाने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। अपने क्षेत्र में स्थापित किसी भी इकाई का विवरण एकत्र करें (यदि कोई हो) और कक्षा में चर्चा करें।

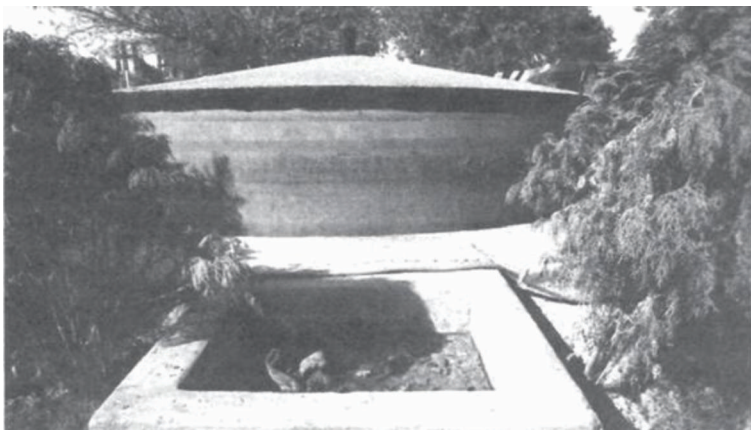
ग्रामीण क्षेत्रों में एल. पी. जी. और गोबर गैस (LPG, Gobar Gas in Rural Areas) :

ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार प्रायः लकड़ी, उपले और अन्य जैविक पदार्थों का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। इससे वन विनाश, हरित-क्षेत्र में कमी, मवेशियों के गोबर का अप्रत्यय और वायु प्रदूषण जैसे अनेक प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए सहायिकी द्वारा कम कीमत पर तरल पेट्रोलियम गैस (LPG) प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, गोबर गैस संयंत्र आसान ऋण और सहायिकी देकर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जहाँ तक तरल पेट्रोलियम गैस का संबंध है, यह एक स्वच्छ ईंधन है जो कि परिवारों में प्रदूषण को काफी हद तक कम करता है। इसमें ऊर्जा का अपव्यय भी न्यूनतम होता है। गोबर गैस संयंत्र को चलाने के लिए गोबर को संयंत्र में डाला जाता है और उससे गैस का उत्पादन होता है, जिसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो बच जाता है, वह एक बहुत ही अच्छा जैविक उर्वरक और मृदा अनुकूलक है।

ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को ऊर्जा के गैर-नवीनकरणीय स्रोतों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जिनका उपयोग लम्बे समय से किया जा रहा है। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि।

ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों को ऊर्जा के नवीनकरणीय स्रोतों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा।

शहरी क्षेत्रों में उच्चदाब प्राकृतिक गैस (CNG in Urban Areas) : दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में उच्चदाब प्राकृतिक गैस (CNG) के ईंधन के रूप में प्रयोग में वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर कम हुआ है और पिछले कुछ वर्षों से हवा स्वच्छ हुई है। अन्य भारतीय शहरों में भी सीएनजी के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।



चित्र 7.4 गोबर गैस संयंत्र में ईंधन उत्पाद के लिए गोबर का प्रयोग

इन्हें कीजिए

दिल्ली में बसें और अन्य सार्वजनिक जन परिवहन पेट्रोल या डीजल के बजाय उच्चदाब गैस CNG का उपयोग करते हैं तथा कुछ वाहन परिवर्तनीय इंजनों का उपयोग करते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग स्ट्रीट लाइट के लिए किया जाता है। दिल्ली में भी सम/विषम व्यवस्था के अन्तर्गत तथाकथित विशिष्ट दिनों के लिए पंजीकृत वाहन संख्या के अनुरूप सड़कों पर वाहनों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया। इन परिवर्तनों के बारे में आप क्या सोचते हैं? भारत में धारणीय विकास की आवश्यकता पर अपनी कक्षा में परिचर्चा का आयोजन कीजिए।

वायु शक्ति (Wind Power) : जिन क्षेत्रों में हवा की गति आमतौर पर तीव्र होती है, वहाँ पवन चक्की से बिजली प्राप्त की जा सकती है। ऊर्जा का यह स्रोत पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं डालता। हवा के साथ-साथ टरबाइन घूमते हैं और बिजली पैदा होती है। इसमें शक नहीं कि इसमें प्रारंभिक व्यय बहुत है, लेकिन इसके लाभ ऐसे हैं जो इसकी अधिक लागत को आत्मसात् कर लेते हैं।

फोटोवोल्टीय सेल द्वारा सौर शक्ति (Solar Power through Photovoltaic Cells) : प्राकृतिक रूप से भारत में सूर्य किरण के माध्यम से सौर ऊर्जा भारी मात्रा में उपलब्ध हैं। हम इसका प्रयोग विभिन्न तरीकों से करते हैं। उदाहरण के लिए, हम कपड़े, अनाज तथा अन्य कृषि उत्पाद और दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुओं को सुखाते हैं। सर्दी में सूर्य किरण का उपयोग हम गरमाहट के लिए करते हैं। पौधे सौर ऊर्जा का प्रयोग प्रकाश-संश्लेषण के लिए करते हैं। अब फोटोवोल्टिक सेलों की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन किया जा सकता है। ये सेल सौर ऊर्जा को एक विशिष्ट प्रकार के उपकरण से पकड़ते हैं और फिर ऊर्जा को बिजली में बदल देते हैं। यह प्रौद्योगिकी दूरदाज के क्षेत्रों और ऐसी जगहों के लिए उपयोगी है, जहाँ ग्रिड अथवा तारों द्वारा विद्युत पूर्ति या तो संभव नहीं है अथवा खर्चीली है। यह प्रौद्योगिकी प्रदूषण से पूर्णतया मुक्त है। हाल के वर्षों में भारत सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय (ISA) का भी नेतृत्व कर रहा है।

लघु जलीय प्लांट (Mini-hydel Plants) : पहाड़ी इलाकों में लगभग सभी जगहों में झरने मिलते हैं। इन झरनों में से अधिकांश स्थायी होते हैं। मिनिहाइडल प्लांट इन झरनों की ऊर्जा से छोटी टरबाइन चलाते हैं। टरबाइन से बिजली का उत्पादन होता है, जिसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। इस प्रकार के पॉवर प्लांट पर्यावरण के लिए हितकर होते हैं क्योंकि जहां वे लगाये जाते हैं वहाँ भू-उपयोग की प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं करते। इसका यह भी अर्थ है कि ऐसे प्लांटों के उपयोग से बड़े-बड़े संचरण टावर (transmission towers) और तारों की इसमें जरूरत नहीं होती है और संचरण की हानि को रोका जा सकता है।

पारंपरिक ज्ञान व व्यवहार (Traditional Knowledge and Practices) : पारंपरिक रूप से भारतीय लोग पर्यावरण के निकट रहे हैं। वे पर्यावरण के एक अंग के रूप में रहे हैं, न कि उसके नियंत्रक के रूप में। यदि हम अपनी कृषि व्यवस्था, स्वास्थ्य-सुविधा व्यवस्था, आवास, परिवहन आदि को पीछे मुड़कर देखें तो पता चलेगा कि हमारे सभी क्रियाकलाप पर्यावरण के लिए हितकर रहे हैं। लेकिन, आजकल हम अपनी पारंपरिक प्रणालियों से दूर हो गये हैं, जिससे हमारे पर्यावरण और हमारी ग्रामीण विरासत को भारी मात्रा में हानि पहुँची है। अब समय आ गया है कि हम पारंपरिक ज्ञान पर ध्यान दें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्वास्थ्य की देखभाल है। भारत बहुत ही सौभाग्यशाली है। यहाँ औषधिगुण से युक्त पौधों की लगभग 15,000 प्रजातियाँ हैं। इनमें से लगभग 8,000 जड़ी-बूटियों का प्रयोग उपचार की विभिन्न प्रणालियों में लोक-परंपरा सहित नियमित रूप से होता है। उपचार की पश्चिमी पद्धति के अचानक आ जाने से हमने पारंपरिक प्रणालियों जैसे, आयुर्वेदिक, यूनानी, तिब्बती व लोक प्रणालियों को अवहेलना शुरू की। अब इन स्वास्थ्य प्रणालियों की माँग पुराने रोगों के उपचार के लिए फिर से हो रही है। आजकल सभी सौंदर्य उत्पाद जैसे, बालों के लिए तेल, टूथपेस्ट, शरीर के लिए लोशन, चेहरे की क्रीम इत्यादि हर्बल हैं। ये उत्पाद न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं बल्कि उनसे कोई हानि नहीं होती और उनके लिए बड़ी मात्रा में किसी औद्योगिक और रासायनिक प्रक्रिया का सहारा भी नहीं लेना पड़ता।

जैविक कंपोस्ट खाद (Biocomposting) : पिछले पाँच दशकों में कृषि उत्पादन बढ़ाने की कोशिश भी हमने जैविक कंपोस्ट खाद की अवहेलना की और पूरी तरह से रासायनिक खाद का उपयोग करने लगे। इससे अधिक मात्रा में उर्वर भूमि पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। रासायनिक प्रदूषण से जल व्यवस्था, विशेषकर भूतल जल प्रणाली दूषित हुई। यह भी सही है कि प्रत्येक वर्ष सिंचाई की माँग में बढ़ोत्तरी हो रही है।

पूरे देश में अब भारी संख्या में किसान विभिन्न जैविक अवशिष्टों जैसे, करकट से बनी कंपोस्ट खाद का उपयोग कर रहे हैं। देश के कुछ भागों में जानवर इसलिए पाले जाते हैं क्योंकि वे गोबर दे सकें, जो महत्वपूर्ण खाद है और मिट्टी को उर्वर बनाता है। केंचुए सामान्यतः कंपोस्ट खाद प्रक्रिया की अपेक्षा तीव्रता से जैविक वस्तुओं को कंपोस्ट में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया का अब व्यापक तौर पर प्रयोग हो रहा है। इससे नागरिक प्रशासन अधिकारियों को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है क्योंकि उन्हें कम कूड़ा हटाना पड़ता है।

जैविक-कीट नियंत्रण (Biopest Control) : हरित क्रांति के आगमन के बाद, अधिक उत्पाद के लिए पूरे देश में रासायनिक कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा। इसके बहुत जल्दी प्रतिकूल प्रभाव दिखने लगे। भोज्य पदार्थ दूषित हो गये। मृदा, जलाशय, यहाँ तक कि भूतल जल भी कीटनाशकों के कारण प्रदूषित हो गये। दूध, माँस और मछलियाँ भी दूषित पाई गईं।

इस चुनौती का सामना करने के लिए अब बेहतर कीट नियंत्रक तरीकों को बनाने के प्रयास हो रहे हैं। इनमें से एक उपाय पौधों के उत्पाद पर आधारित कीटनाशकों का उपयोग है। नीम के पेड़ इसमें काफी उपयोगी साबित हो रहे हैं। नीम से अनेक प्रकार के कीट नियंत्रक रसायन बनाये गये हैं और उनका उपयोग हो रहा है। मिश्रित फसल और एक ही भूमि पर लगातार कई वर्षों तक अलग-अलग फसलों के उत्पादन से भी किसानों को लाभ पहुँचा है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न जानवर और पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ी है जो कीट नियंत्रण में सहायक है। उदाहरण के लिए, साँप चूहों और अनेक प्रकार के कीड़ों को खा जाता है। इसी प्रकार उल्लू, मोर जैसे पक्षी अनेक हानिकारक कीटों का भक्षण करते हैं। यदि हम इन्हें कृषि क्षेत्र में रहने दे तो वे काफी संख्या में कीटों का नाश कर देंगे। इस संबंध में छिपकली भी उपयोगी हैं। हमें उनकी कीमत समझनी चाहिए और उनका संरक्षण होना चाहिए।

आजकल धारणीय विकास शब्द बहुत लोकप्रिय हो गया है। विकास की विचारधारा में निश्चय ही यह एक दृष्टांत परिवर्तन है। कई प्रकार से इसकी व्याख्या भी कई गई है। लेकिन, इस मार्ग को अपनाने से चिरस्थायी विकास और सभी के लिए कल्याण सुनिश्चित होगा।

7.6 जैविक कृषि (Organic Farming)

हम में से अधिकांश लोग प्रयोग किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की ओर अधिक ध्यान नहीं देते। भोजन व पानी में कीट नाशकों व अन्य रासायनिक दूषित तत्वों के मिले होने के विषय में मीडिया में ज्यादा और लगातार रिपोर्टों के बावजूद भी हमने अभी तक गैर-विषैले ढंग से उगाए जाने वाले भोजन की खोज और माँग करनी आरंभ नहीं की है। यथार्थ में हममें से बहुत से लोग भोजन – उत्पादन प्रक्रिया जहाँ यह की जाती है, चाहे खेत

या फिर उद्योग में उससे पूर्णतः अनभिज्ञ है। हममें से कई लोगों को तो इसका अनुमान भी नहीं कि हमारे सामने पैकेट व बोतलों में आने वाला भोजन कैसे बनता है। कृषि अब व्यापार बन गया है। परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति द्वारा तैयार किया हुआ भोजन अब एक औद्योगिक उत्पाद के रूप में बाजार में उपलब्ध है। ये उत्पादक मात्र अपने लाभ के प्रति चिंतित है न कि भोजन की सुरक्षा अथवा गुणवत्ता के प्रति।

जैविक कृषि अधिकांशतः प्रकृति अनुकूल है एवं उपज अधिक पौष्टिक। उत्पादन की प्रक्रिया भी स्थानिक तौर पर की जाती है। इस प्रकार की कृषि में अपनाया गये सिद्धांत के अनुसार भोजन कुदरती तरीके से तैयार किया जाता है जिसमें मिट्टी केंद्रीय महत्व रखती है। किसान मिट्टी व इसके जैविक वातावरण को पोषण प्रदान करते हैं। वे कभी भी रसायनों द्वारा पौधों को कृत्रिम ढंगों से तीव्र गति से वृद्धि के लिये प्रयत्न नहीं करते। पशु पालन के संबंध में पशुओं की देखरेख स्नेह व सम्मान पूर्वक की जाती है। यहाँ कोई पिंजरे नहीं, पशु स्वच्छन्द घूमते हैं, घास व प्राकृतिक चारागाहों पर चरते हैं। प्राचीन काल में जैविक कृषि हर स्थान पर होती थी। विश्व के लगभग 120 देशों में जैविक कृषि की जा रही है। कृषि में प्रयोग किए जाने वाले रसायनों के दुर्प्रभावों ने पश्चिमी देशों के उपभोक्ताओं के मानसिकता को बदल दिया गया है। वे अब प्रीमियम मूल्यों पर जैविक उत्पाद क्रय कर रहे हैं। नीति निर्माता बेहतर वातावरण सृजन के उपाय करने के साथ मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनः सृजन हेतु जैविक कृषि को भी उत्साहित कर रहे हैं। जैविक कृषि का प्रबंधन व कृषि उत्पादन की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो उच्च स्तरीय जैविक विभिन्नता (bio diversity) को वातावरण अभ्यासों को साथ जोड़ता है, जो प्राकृतिक स्रोतों को सुरक्षित रखते हैं, पशुओं के हित के लिए कठोर मापदंड रखते हैं। इसके अतिरिक्त जैविक प्राकृतिक उत्पादों की उपभोगताओं की बढ़ रही माँग को पूरा करते हैं तथा साथ ही ग्रामीण विकास के संदर्भ में पर्यावरण को सुरक्षित रखने की आज्ञा देती है।

बाक्स 9.5 सिक्किम जैविक मिशन - एक अध्ययन

सिक्किम सरकार की एक स्वदेशी फलैगशिप परियोजना 'सिक्किम जैविक मिशन' को 2012 में एक लोकप्रिय टॉक शो 'सत्यमेव जयते' के माध्यम से लाखों भारतीय दर्शकों के लिए पेश किया गया था।

'सिक्किम जैविक मिशन' कृषि उत्पादों में रसायनिक पदार्थों (कीटनाशकों व उर्वरकों) के स्थान पर जैविक पदार्थों का प्रयोग करना था।

जैविक कृषि को अपनाने से राज्य को कई लाभ होंगे (क) इससे किसानों को कृषि उत्पादों का अधिक मूल्य मिलेगा। (ख) राज्य के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। (ग) पर्यटन में वृद्धि होगी क्योंकि लोग जैविक कृषि का अध्ययन एवं जैविक उत्पादों का सेवन कर स्वास्थ्य लाभ अर्जित करने हेतु यहाँ का भ्रमण करेंगे। (घ) राज्य की आय में वृद्धि होगी।

जैविक कृषि को इतने व्यापक स्तर पर अपनाने वाले देशों में क्यूबा प्रथम स्थान पर आता है। हालांकि क्यूबा ने ऐसा कृषि अभ्यास मजबूरी के रूप में सहारा लिया परंतु सिक्किम ने स्वेच्छा से इसे अपनाया है।

जैविक कृषि के लिए सहायक कारक (Facilitating Factors for Organic Farming)

जैविक कृषि भिन्न भिन्न प्रतिभागियों के लिए आर्थिक अवसर प्रदान करती है। भारत में जैविक कृषि के विकास में सहायक कुछ कारक इस प्रकार से हैं-

- जैविक रूप से उत्पन्न फसलों के लिए बढ़ रहा निर्यात बाजार ।
- 10 से 100% तक जैविक रूप से तैयार किए कृषि उत्पादों के लिए मूल्य में वृद्धि ।
- देशभर में विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र जो कि फसलों की विशाल श्रेणियों के लिए वातावरण प्रदान करते हैं, बाजार की मांगों को पूर्ण कर सकते हैं ।
- विशेषतः : घरेलू उपभोक्ताओं में जागृति तथा स्वास्थ्य चेतना में वृद्धि ।
- श्रम आधारित जैविक कृषि के लिए सस्ते श्रम का उपलब्ध होना ।
- बड़ी संख्या में परंपरागत कृषि करने वाले छोटे किसानों के पास महंगे रसायनिक निवेशों को सहन करने का सामर्थ्य बहुत सीमित है। अतः वे जैविक कृषि का चयन कर सकते हैं ।
- भिन्न भिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में जैविक कृषि के प्रचारकों के रूप में गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) का प्रस्तुत होना ।
- कृषि विस्तार, व्यापार, परामर्श व सहायक सेवाओं के क्षेत्र में व्यस्त कंपनियों की बढ़ रही प्रतियोगिता ।
- भिन्न भिन्न प्रयासों ने योजना कार्यक्रमों द्वारा जैविक खेती के लिए सरकार का ध्यान व समर्थन बढ़ाया गया है ।

जैविक कृषि से संबंधित सीमाएं (Constraints for Organic Farming)

जैविक कृषि भारत में बाजार के अवसरों का एक विलक्षण समूह प्रदान करती है। हालाँकि यह अपने बाजार के लिए पूँजी को उस गति से आकर्षित नहीं कर पा रहा। लघु तथा मध्यम स्तर के जैविक किसानों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि निवेश तथा वित्त की कमी इत्यादि। जैविक खेती के विकास के मार्ग में निम्नलिखित रुकावटें हैं-

1. जैविक उत्पादन वर्तमान दौर में एक शिक्षण प्रक्रिया से गुजर रहा है जिसे अपनी पूर्ण समर्था प्राप्त करने में काफी समय चाहिए।
2. संस्थाएं जैसे अनुसंधान केंद्र, सहायकी, शिक्षित कर्मचारी, आदि जो जैविक कृषि के लिए सहायक हैं, पर्याप्त नहीं हैं।
3. उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए आदान-प्रदान की लागतें लघु उत्पादकों के लिए बाधा हो सकती है। भिन्न भिन्न बाजारों के मापडंड भिन्न हैं तथा आपस में मेल नहीं खाते। यह प्रमाणीकरण की लागतों में वृद्धि करता है तथा इसे संभालना अधिक कठिन बनाता है।
4. उपभोक्ताओं की जागरूकता कम होने के साथ स्थानीय बाजारों की मांग भी कम है।

चाय, मसाले, चवाल के प्रकार, आर्युवैदिक वनस्पतियाँ आदि के उच्च गुणात्मक उत्पादन में भारत की स्थिति मजबूत है। भारत के कई क्षेत्रों में कृषि, कृषि रसायनों पर आधारित नहीं है विशेषतः पर्वतीय व कबायली क्षेत्रों में कृषि रसायनों का प्रयोग बहुत कम है जो कि जैविक कृषि को अधिक सुचारू रूप से बदलने की सुविधा प्रदान करती है। भारत में जैविक कृषि का क्षेत्र उज्ज्वल है क्योंकि सस्ती दर पर पर्याप्त श्रम संख्या उपलब्ध है। अब बहुत गैर सरकारी संगठन जैविक कृषि को उत्साहित करने में लगे हैं तथा किसान समूह को प्रशिक्षण विस्तार सेवाएं, सूचना व मंडीकरण सेवाएं प्रदान करते हैं। भारत सरकार ने देश के लिए जैविक कृषि के संभावित महत्व को जान लिया है तथा हाल ही में बड़े पैमाने व भिन्न भिन्न स्तरों पर जैविक कृषि को समर्थन देना आरंभ किया है।

भारत में जैविक कृषि के लिए राजकीय योजनाएं : भारत में जैविक कृषि के लिए भिन्न भिन्न सरकारी योजनाएं हैं –

1. परम्परागत कृषि विकास योजना (The Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) 2015.)
2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (Rashtriya Krishi Vikas Yojana 2007)
3. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन आर्गेनिक वैल्यू चैन डिवेलपमेंट (Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region (MOVCDNER) 2015)
4. जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना (National Programme for Organic Production 2000.)
5. तिलहन और तेल पाम योजना पर राष्ट्रीय मिशन (NMOOP) जैविक खेती (National Mission on Oil seeds and Oil Palm (NMOOP) Scheme for Organic Farming 2014.

7.7 निष्कर्ष (Conclusion)

आर्थिक विकास से, जिसका लक्ष्य बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाना है, पर्यावरण पर बहुत दबाव पड़ता है। विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में पर्यावरण संसाधनों की माँग पूर्ति से कम थी। अब विश्व के समक्ष पर्यावरण संसाधनों की बढ़ती माँग है, लेकिन उनकी पूर्ति अत्यधिक उपयोग व दुरुपयोग की वजह से सीमित है। धारणीय विकास का लक्ष्य उस प्रकार के विकास का संवर्द्धन है, जो कि पर्यावरण समस्याओं को कम करे और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता से समझौता किए बिना, वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे।

पुनरावर्तन (RECAP)

- पर्यावरण के चार कार्य हैं : संसाधन पूर्ति, अपशिष्ट-विसर्जन, जननिक और जैविक विविधता प्रदान करते हुए जीवन का पोषण तथा सौन्दर्य सेवाएँ प्रदान करना।
- जनसंख्या विस्फोट, प्रचुर मात्रा में उपभोग और उत्पादन ने पर्यावरण पर भारी दबाव डाला है।
- भारत में विकास कार्यों ने प्राकृतिक संसाधनों की निश्चित स्रोतों पर दबाव डाला है। इससे मानव स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

- भारत के पर्यावरण पर दो प्रकार के संकट मँडरा रहे हैं—पहला संकट तो निर्धनताजनित पर्यावरण क्षय का है और दूसरा संकट संपन्नता तथा तेजी से बढ़ते औद्योगिक क्षेत्रों से हो रहे प्रदूषण का है।
- यद्यपि सरकार अनेक प्रकार के प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा करने का यत्न कर रही है फिर भी धारणीय विकास का मार्ग अपनाना आवश्यक है।
- धारणीय विकास का अर्थ वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना है कि भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने में किसी बाधा का सामना न करना पड़े।
- प्राकृतिक संसाधनों के संवर्द्धन, संरक्षण और पारिस्थितिक पुनर्जनन क्षमता को बनाए रखने और भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरणीय संकटों के निवारण से ही धारणीय विकास संभव हो पाएगा।

●●● अभ्यास ●●●

1. वैकल्पिक चुनाव वाले प्रश्न (Multiple Choice Questions)

- (i) निम्नलिखित में से कौन से कारकों ने वातावरण पर भारी दबाव डाला है?

(क) जनसंख्या-विस्फोट	(ख) प्रचूर मात्रा में उपभोग
(ग) उत्पादन	(घ) उपरोक्त सभी
- (ii) जंगलों की कटाई के कारण हैं :-

(क) भूमि का विनाश	(ख) जैव-विभिन्नता का नुकसान
(ग) वायु-प्रदूषण	(घ) उपरोक्त सभी
- (iii) ब्रुटलैंड कमीशन कौन सी पीढ़ी की सुरक्षा पर जोर देता है?

(क) वर्तमान	(ख) भविष्य
(ग) उपरोक्त दोनों	(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

2. खाली स्थान भरो (Fill in the blanks)

- (i) भारत में पानी का प्रतिशत भाग प्रदूषित है। (71, 70)
- (ii) काली मिट्टी की काश्त के लिए विशेष रूप में ठीक है। (गन्ना, कपास)
- (iii) विश्व के कुल लोहे के भण्डारों का लगभग प्रतिशत भारत में है। (8, 10)
- (iv) भारत विश्व के भौगोलिक क्षेत्र के मात्र प्रतिशत हिस्से में विश्व के लगभग प्रतिशत जनसंख्या को आश्रय देता है। (17, 20, 2.5)
- (v) भारत अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा पावर-प्लांटों पर ज़्यादा निर्भर है। (ताप, सौर, जल, परमाणु)
- (vi) सलरी जो कि गोबर-गैस प्लांट का बचा हुआ तत्व है, भाग बहुत बढ़िया खाद तथा अनुकूलक है। (जैविक, वायु, मृदा)

- (vii) कई-प्रकार के कीट नियंत्रक-रसायनों को वृक्षों से प्राप्त किया गया है। (आम, नीम)
 (viii) जैविक खेती प्रधान है। (पूँजी, श्रम)

3. सही या गलत (True or False)

- (i) पर्यावरण में सभी जैविक तथा अजैविक कारक शामिल होते हैं, जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
 (ii) केन्द्रीय-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों की 20 श्रेणियां (बड़े तथा मध्यम पैमाने) की पहचान बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के रूप में की है।
 (iii) दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सी. एन. जी (CNG) के ईंधन के उपयोग ने वायु प्रदूषण में बढौत्तरी की है।
 (iv) गैर-नवीनीकरण संसाधन वे होते हैं जो उपयोग करने से खत्म हो जाते हैं।
 (v) चिपको आंदोलन का उद्देश्य हिमालय में जंगलों की रक्षा करना है।
 (vi) फोटोवोल्टिक सेलों के द्वारा सौर-ऊर्जा को बिजली में बदलने की तकनीक दूरदराज के क्षेत्रों के लिए सस्ती है।
 (vii) बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे देश में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि 0.47 हेक्टेयर होनी चाहिए।

4. मिलान करो (Match the following)

(i)	तथ्य	व्याख्या
	वैश्विक उष्णता	मिट्टी की ऊपरी सतह का हट जाना।
	औद्योगिक क्रांति	पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सतह का मानव दखलअंदाजी के कारण पतला हो जाना।
	वन विनाश	अर्थव्यवस्था में उद्योगों का अधिक महत्त्व
	मृदा-क्षरण	औसत-तापमान में बढौत्तरी
	ओजोन अपक्षय	वन के वृक्षों की कटाई

(ii)	तथ्य	व्याख्या
	जैविक तत्व	चट्टानें तथा सूर्य किरण
	अजैविक तत्व	जीवाश्म ईंधन
	नवीकरणीय संसाधन	सभी जीवित-तत्व
	गैर-नवीकरणीय संसाधन	वृक्ष, मछलियां आदि

5. अति लघु उत्तरीय प्रश्न (इन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दिया जाये) Very Short Answer Type Questions (answer to these questions should be given in one word or one sentence)

- (i) धारणी-विकास शब्द की रचना किसने की?
- (ii) हरमन डेली अनुसार धारणी-विकास को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिये?
- (iii) हम उन क्षेत्रों में बिजली कैसे पैदा कर सकते हैं, जहां हवा की गति ज्यादा है?
- (iv) प्रदूषण से मुक्त ऊर्जा-स्रोतों के नाम बताओ।
- (v) किस सैल की मदद से सौर ऊर्जा को बिजली में बदला जा सकता है?
- (vi) कौन से क्षेत्रों में लघु जलीय-प्लांट छोटी टर्बाईनों को चलाने के लिए स्ट्रीम की ऊर्जा का उपयोग करते हैं?
- (vii) पुरानी सेहत-समस्याओं को ठीक करने के लिए स्वास्थ्य-संभाल की पारम्परिक-प्रणाली का नाम बताओ।
- (viii) पूर्ण रूप लिखो:- (Full Form)
CPCB, UNCED, LPG, CNG
- (ix) निम्नलिखित को नवीकरणीय तथा गैर-नवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत करें।
 - (क) वृक्ष (ख) मछली
 - (ग) पेट्रोलियम (घ) कोयला
 - (ङ) लौह अयस्क (च) जल

Q.6. लघु उत्तरीय प्रश्न (इन प्रश्नों का उत्तर 30-35 शब्दों में लिखो) Short Answer Type Questions (answer to these questions should be given in 30-35 words)

- (i) वैश्विक उषणता से आपका क्या अभिप्राय है?
- (ii) जैविक खेती से आपका क्या अभिप्राय है?
- (iii) भारत की प्रमुख पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किये गये दो बोर्डों के नाम बताओ।
- (iv) वायु प्रदूषण के दो मुख्य कारण बताओ।
- (v) औद्योगीकरण के कोई दो अनचाहे परिणाम बताओ।
- (vi) ऊर्जा के पारम्परिक स्रोतों के दो उदाहरण लिखो।
- (vii) जैविक खाद की दो किस्मों के नाम लिखो।
- (viii) उन पक्षियों तथा जानवरों के नाम बताओ जो कीटों को नियंत्रण करने में सहायता करते हैं ?
- (ix) पर्यावरण से आपका क्या अभिप्राय है?

- (x) निम्न कारक भारत में कैसे पर्यावरण संकट में योगदान दे रहे हैं तथा सरकार के समक्ष वे कौन-सी समस्याएँ पैदा करते हैं :
- (क) बढ़ती जनसंख्या
 - (ख) वायु प्रदूषण
 - (ग) जल-प्रदूषण
 - (घ) संपन्न उपभोग माक
 - (ङ) अनपढ़ता
 - (च) औद्योगीकरण
 - (छ) शहरीकरण
 - (ज) वन-क्षेत्र में कमी
 - (झ) अवैध वन कटाई
 - (ञ) वैश्विक उष्णता
- (xi) धारणी विकास क्या है?
- (xii) जैविक कृषि की समस्याएँ लिखो।
- (xiii) जैविक कृषि के लिए सहायक कारकों के सम्बन्ध में लिखो।

7. मध्य उत्तरीय प्रश्न (इन प्रश्नों का उत्तर 60-70 शब्दों में लिखो) Short Answer Type Questions (answer to these questions should be given in 60-70 words)

- (i) जब संसाधन निस्मरण की दर उनके पुनर्जनन की दर से बढ़ जाती है, तो क्या होता है ?
- (ii) पर्यावरण के कार्य कौन-कौन से हैं?
- (iii) भारत में भू-क्षय के लिए उत्तरदायी छः कारकों की पहचान करो।
- (iv) व्याख्या करो कि नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों की अवसर लागत कैसे ऊंची हैं?
- (v) भारत में धारणीय विकास को प्राप्त करने में शामिल कदमों की रूप-रेखा तैयार करो।
- (vi) क्या वातावरण संकट एक नवीन परिघटना है? यदि हां, तो क्यों?
- (vii) भारत की वातावरण सम्बन्धी चार चिंताओं के बारे में बताओ। पर्यावरण क्षय में सुधार के लिए अवसर लागत शामिल होती है इसे समझाओ।
- (viii) पर्यावरणीय संसाधनों की पूर्ति-मांग उत्क्रमण कर देने की व्याख्या करो।
- (ix) आपके इलाके को ध्यान में रखते हुए धारणी विकास की किन्हीं चार रणनीतियों का वर्णन करो।

8. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (इन प्रश्नों का उत्तर 150-200 शब्दों में दिया जाये) Long Answer Type Questions (answer to these questions should be given in 150-200 words)

- (i) भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है-इस कथन के समर्थन में तर्क दें।

- (ii) निम्न की दो उदाहरणें लिखो:-
 (क) पर्यावरणीय संसाधनों का अति प्रयोग
 (ख) पर्यावरणीय संसाधनों का दुरुपयोग।
- (ii) वर्तमान पर्यावरण संकट का वर्णन करो।
- (iv) भारत में विकास के किसी भी दो प्रकार के गंभीर प्रतिकूल पर्यावरण सम्बन्धी नतीजों की व्याख्या करो। भारत की पर्यावरण समस्या में एक विरोधाभास है। एक तो यह निर्धनताजनित है और दूसरे जीवन-स्तर में संपन्नता का कारण भी है। क्या यह सत्य है?
- (v) धारणी विकास की परिभाषा में वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के बीच समानता के विचार की व्याख्या करो।

अतिरिक्त गतिविधियां (Suggested Additional Activities)

- (i) मान लो कि महानगरों की सड़कों पर हरेक वर्ष 70 लाख कारें शामिल हो रही हैं। आपके विचार में कैसे संसाधनों की कमी हो रही है? चर्चा करें।
- (ii) उन वस्तुओं की सूची बनाओ जिनको दोबारा उपयोगी बनाया जा सकता है।
- (iii) भारत में मिट्टी के कटाव के कारणों तथा बचाव की युक्तियों सम्बन्धी एक चार्ट तैयार करो।
- (iv) जनसंख्या विस्फोट पर्यावरण संकट में कैसे योगदान देता है। कक्षा में विचार-चर्चा का प्रबन्ध करो।
- (v) 'पर्यावरण हानि की भरपाई करने के लिए राष्ट्र को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।' चर्चा करें।
- (vi) आपके गांव में एक कागज का कारखाना लगाया जाना है। सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योगपति और ग्रामीणों के समूह के साथ इस विषय पर एक छोटे नाटक का आयोजन करें।

REFERENCES

BOOKS

- AGARWAL, ANIL and SUNITA NARAIN. 1996. Global Warming in an Unequal World. Centre for Science and Environment, Reprint Edition, New Delhi
- BHARUCHA, E. 2005. Textbook of Environmental Studies for Undergraduate Courses, Universities Press (India) Pvt Ltd
- CENTRE FOR SCIENCE AND ENVIRONMENT. 1996. State of India's Environment 1: The First Citizens' Report 1982. Reprint Edition, New Delhi
- CENTRE FOR SCIENCE AND ENVIRONMENT. 1996. State of India's Environment 2: The Second Citizens' Report 1985, Reprint Edition, New Delhi
- KARPAGAM, M. 2001. Environmental Economics: A Textbook. Sterling Publishers, New Delhi

- RAJAGOPALAN, R. 2005. Environmental Studies: From Crisis to Cure. Oxford University Press, New Delhi
- SCHUMACHER, E.F. Small is Beautiful. Abacus Publishers, New York

Reports

- State of India's Environment (for various years), Centre for Science and Environment, New Delhi

Journals

- Scientific American, India, Special Issue, September 2005 Down to Earth, Centre for Science and Environment, New Delhi

Websites

- <http://envfor.nic.in>
- <http://cpcb.nic.in>
- <http://www.cseindia.org>



इकाई IV

पंजाब के भौतिक और मानव
संसाधन

पंजाब में रहते और पढ़ते विद्यार्थियों के लिए पंजाब की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इससे वे अपने प्रांत की अर्थव्यवस्था को जान पाएंगे और इसकी कार्यप्रणाली को समझ सकेंगे। इसके साथ-साथ वे पंजाब के साधनों व उनके उपयुक्त प्रयोग के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे यत्नों, पंजाब के लोगों के व्यवसाय आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

8

पंजाब के भौतिक और मानव संसाधन

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप :

- पंजाब के भौतिक संसाधन, जैसे पंजाब की भौतिक विशेषताएं, पंजाब का भौगोलिक विभाजन, जलवायु, पंजाब में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टी, पंजाब के जल संसाधन, खनिज संसाधन, वन संसाधन, ऊर्जा संसाधनों आदि के बारे में जानेगे ;
- पंजाब की जनसंख्या की संरचना और आकार, जनसंख्या की वृद्धि-दर, लिंगानुपात, साक्षरता-अनुपात, जनसंख्या का घनत्व, शहरीकरण के रुझान, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना के बारे में जानेगें।

अध्याय – 8

पंजाब के भौतिक और मानव संसाधन

8.1 परिचय (Introduction)

जैसा कि हम जानते हैं कि 'पंजाब' शब्द फ़ारसी के दो शब्दों 'पंज' और 'आब' से मिलकर बना है जिसमें 'पंज' का अर्थ है पांच और 'आब' का अर्थ है जल। पंजाब का नाम इसकी पांच नदियों—सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम से पड़ा है। ऋग्वैदिक काल में सिंधु और सरस्वती नदियाँ भी पंजाब में बहती थीं। इस लिए प्राचीन काल में पंजाब को सप्त सिंधु कहा जाता था।

8.2 पंजाब की भौतिक विशेषताएं (Physical Features of Punjab)

1947 में पंजाब को दो भागों में विभाजित किया गया— पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब। वर्तमान में तीन नदियाँ—सतलुज, ब्यास और रावी पंजाब से होकर बहती हैं। इसके बाद 1 नवंबर, 1966 को पंजाब को भाषा के आधार पर तीन भागों में बांट दिया गया। हरियाणा को पंजाब से अलग राज्य बनाया गया। इसके अतिरिक्त, पंजाब के कुछ पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए। इस कारण पंजाब का क्षेत्रफल काफी कम हो गया। वर्तमान में पंजाब का भौगोलिक क्षेत्रफल 50,362 वर्ग कि.मी. है जो इसे भारत का बीसवां सबसे बड़ा राज्य बनाता है। इसमें कुल 23 जिले हैं और मलेरकोटला इसका सबसे नया जिला है जो मई 2021 में आस्तित्व में आया।



अपने अध्यापक के मार्ग दर्शन में यह क्रिया करें :-

- पंजाब के भिन्न-भिन्न जिलों के क्षेत्रफल तथा उनकी जनसंख्या से संबंधित एक चार्ट तैयार करें।
- मालूम करें कि 1 नवंबर, 1966 को भाषा के आधार पर पंजाब का विभाजन क्यों किया गया ?
- क्षेत्रफल के आधार पर पंजाब के सब से छोटे और सबसे बड़े जिले के विषय में जानकारी लें।

पंजाब के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य

1. कुल क्षेत्रफल : 50362 वर्ग किलो मीटर
2. कुल शहरी क्षेत्रफल : 2097 वर्ग किलो मीटर
3. कुल ग्रामीण क्षेत्रफल : 48265 वर्ग किलो मीटर
4. भारत के कुल क्षेत्रफल का भाग : 1.53 प्रतिशत
5. भौगोलिक स्थिति : 29. 30° उत्तर से 32. 32° उत्तर समतल अक्षांश तथा 73.55° पूर्व से 76.50° पूर्व लंबंकार रेखाओं के बीच
6. पड़ोसी राज्य / केंद्रशासित प्रदेश : हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ (पंजाब की राजधानी)
7. राज्य भाषा : पंजाबी (गुरमुखी लिपि)
8. तहसील : 97
9. ब्लॉक (खंड) : 153
10. जिले : 23

8.3 पंजाब के भौतिक संसाधन (Physical Resources of Punjab)

भौतिक संसाधनों का अर्थ उन सभी संसाधनों से है जो मूर्त हैं। सामान्यतः किसी क्षेत्र के भौतिक संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। ये वे संसाधन हैं जो हमें प्रकृति से उपहार के रूप में प्राप्त होते हैं। जहां तक पंजाब के भौतिक संसाधनों का संबंध है, उपजाऊ भूमि पंजाब का प्रमुख भौतिक संसाधन है। पंजाब के भौतिक संसाधनों का अध्ययन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है :-

8.3.1 पंजाब का भौगोलिक विभाजन (Geographical Division of Punjab)

भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर पंजाब में विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं। मुख्य रूप से यह इस प्रकार हैं :

पहाड़ी क्षेत्र (Hilly Region) : पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र में पंजाब का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र शामिल है। यह क्षेत्र शिवालिक पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित है। परन्तु इस क्षेत्र के पहाड़ बहुत ऊँचे नहीं हैं। इस क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं और गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी पथरीली है जिसके कारण कृषि उत्पादकता कम है। पंजाब के गुरदासपुर, रूपनगर, पठानकोट, होशियारपुर और शहीद भगत सिंह नगर जिलों के कुछ भाग इस क्षेत्र में आते हैं।

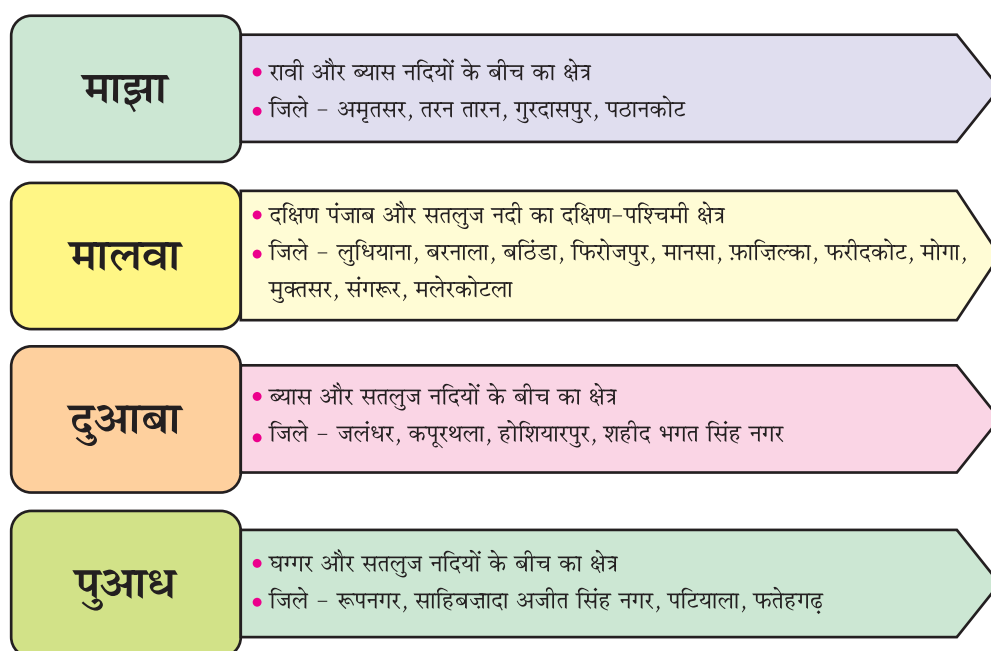
मैदानी क्षेत्र (Plain Region) : पंजाब का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र का भाग है। चूंकि यह क्षेत्र नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है इसलिए इस क्षेत्र की मिट्टी बहुत उपजाऊ और उत्पादकीय है। इस क्षेत्र में कृषि अत्यधिक विकसित है और एक वर्ष में कई फ़सलों की खेती की जाती है। यह क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित है। इसमें जालंधर, अमृतसर, पटियाला, लुधियाना, बरनाला, फरीदकोट, फतेहगढ़, फिरोज़पुर, कपूरथला, मलेरकोटला, मोगा, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, संगरूर और तरनतारन जिलों को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र की मुख्य फसलें गेहूँ, धान, मक्का, गन्ना और कपास हैं। इस क्षेत्र में मध्यम वर्षा होती है। सर्दियाँ अधिक ठंडी होती हैं और गर्मियाँ अधिक गर्म होती हैं।

अर्ध-रेगिस्तानी क्षेत्र (Semi-Desert Region) : पंजाब का वह क्षेत्र जो राजस्थान के साथ सीमा सांझी करता है, अर्ध-रेगिस्तानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में फ़ाज़िल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा जिलों के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। इस क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र से दूर होने के कारण इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। ग्रीष्मकाल अपेक्षाकृत गर्म और सर्दियाँ ठंडी होती हैं। रेतीली मिट्टी के कारण इस क्षेत्र में कृषि-उत्पादकता कम है। इस क्षेत्र की मुख्य फ़सलें कपास, गेहूँ, धान और तिलहन हैं।

8.3.2 पंजाब का सामाजिक-सांस्कृतिक विभाजन (Socio-Cultural Division of Punjab)

अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता के आधार पर पंजाब को चार क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। जो नीचे दिए गए चार्ट में दिखाए गए हैं :

चार्ट 1.1 पंजाब का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभाजन



पंजाब की जलवायु

पंजाब की जलवायु को मुख्यतः तीन ऋतुओं में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं :

- गर्मी का मौसम :** पंजाब में गर्मी का मौसम मुख्य रूप से अप्रैल से जून के महीने के दौरान होता है। इन महीनों में तापमान 40° सेल्सियस से ऊपर हो जाता है और 'लू' नामक गर्म हवा चलती है।
- मानसून ऋतु :** यह ऋतु जुलाई से सितंबर के महीनों में होती है। पंजाब में इन महीनों के दौरान भारी वर्षा होती है जो खरीफ़ फ़सलों के लिए अच्छी होती है। बारिश से तापमान में भी काफी कमी आती है।
- शीत ऋतु :** पंजाब में शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च के महीनों तक चलती है। लेकिन भीषण सर्दी दिसंबर और जनवरी के महीनों में पड़ती है। यहां तक कि पंजाब में कुछ जगहों पर तापमान 0° सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है। इस मौसम में बारिश रबी की फ़सल के लिए अच्छी होती है।

8.3.3 पंजाब की मिट्टी के प्रकार (Types of Soil of Punjab)

विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के कारण पंजाब में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये इस प्रकार हैं :

- **बेट मिट्टी :** यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और इसका रंग पीला-भूरा होता है। यह रूपनगर से फ़ाज़िल्का तक सतलुज नदी के पश्चिमी किनारे पर पाई जाती है। यह मिट्टी गेहूँ, धान, गन्ना और सब्जियों की खेती के लिए बहुत उपयोगी है।
- **दोमट मिट्टी :** यह मिट्टी पंजाब की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी पटियाला, नाभा, संगरूर, मलेरकोटला, बठिंडा, मुक्तसर, मोगा और जालंधर जिले के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। यह मिट्टी गेहूँ और धान की खेती के लिए अच्छी होती है।
- **पहाड़ी मिट्टी :** यह मिट्टी पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। अतः यह पथरीली है जो कृषि कार्यों के लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन यह बागवानी के लिए अच्छी है।
- **अर्द्ध-मरुस्थली मिट्टी :** यह मिट्टी अबोहर, जीरा और मानसा के कुछ भागों में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश की भारी कमी पाई जाती है। यह मिट्टी का उपयोग कपास, बाजरा, गेहूँ और अन्य खरीफ फसलों के लिए किया जाता है।
- **बालूई मिट्टी :** यह मिट्टी दक्षिण-पश्चिम तथा मध्य दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। यह एक प्रकार की शुष्क मिट्टी होती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से पीले रंग की होती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी होती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। लेकिन सिंचाई की सुविधा विकसित कर इसका उपयोग कपास, तिलहन, गेहूँ आदि फसलों की खेती के लिए किया जा सकता है।

गतिविधियाँ

- रबी व खरीफ की फसलों का चार्ट तैयार करो।
- अपनी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी का नमूना एकत्र करें तथा इसकी विशेषताओं का पता करें।
- पंजाब में पाई जाने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी और यह कौन सी फसल की उपज के लिए अच्छी है इस विषय पर चर्चा करें।

8.3.4 पंजाब के जल संसाधन (Water Resources of Punjab)

जल संसाधनों के मामलों में पंजाब एक समृद्ध राज्य है। पंजाब के मुख्य जल संसाधन इस प्रकार हैं :

- **पंजाब की प्रमुख नदियाँ :** पंजाब के जल संसाधनों में सतलुज, ब्यास और रावी नदियाँ शामिल हैं। सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। ब्यास, मनाली के पास ब्यास कुंड से निकलती है और हरीके पतन के पास सतलुज में मिल जाती है। रावी, हिमाचल प्रदेश में चंबा के पास रोहतांग दर्रे से निकलती है। इनमें साल भर पानी रहता है और ज्यादातर सिंचाई के लिए इनका उपयोग किया जाता है।

- **छोटी नदियाँ, नहरें और चो :** उपरोक्त प्रमुख नदियों के अलावा पंजाब में काली बेई, सफेद बेई, घग्गर जैसी कई छोटी नहरों का एक अच्छा जाल है। (तालिका 8.1 देखें)। बरसात के मौसम में, इनमें अधिकांश पानी होता है और जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है।

सारणी 8.1 पंजाब का नहरी प्रबंधन

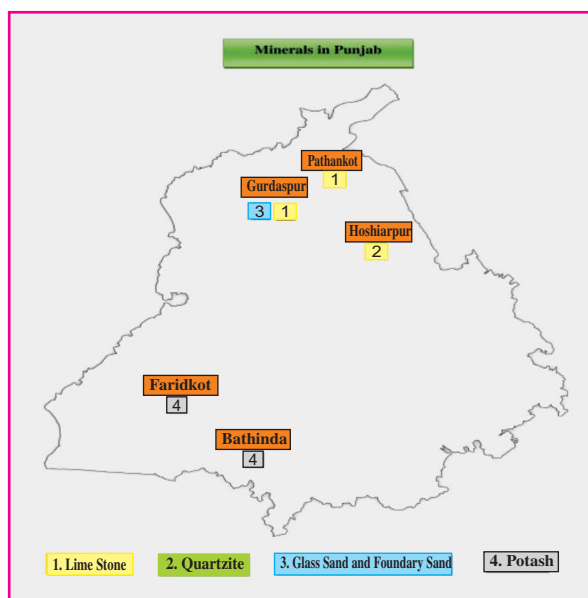
नहर का नाम	लम्बाई (कि. मी. में)	आरंभिक स्थान
सरहिंद	59.44	रोपड़ हैडवर्क्स
बिसत दुआब	43.00	रोपड़ हैडवर्क्स
अपर बारी दुआब	42.35	माधोपुर हैडवर्क्स
सरहिंद फीडर-II	136.53	हरीके हैडवर्क्स
पूर्वी नहर	8.02	हुसैनीवाला हैडवर्क्स
भाखड़ा मुख्य लाइन	161.36	नगल बैराज
शाह नहर	2.23	मुकेरीयां हाइडल चैनल
राजस्थान फीडर	149.53	हरीके हैडवर्क्स (तरनतारन)

स्त्रोत : www.Pbrrigation.gov.in

चार्ट 8.2

8.3.5 पंजाब के खनिज संसाधन (Mineral Resources of Punjab)

पंजाब में खनिज-संसाधन बहुत सीमित हैं। पंजाब में कोयले, पेट्रोलियम आदि के भंडार नहीं हैं। इसके लिए पंजाब पूरी तरह दूसरे राज्यों और देशों पर निर्भर करता है। पंजाब में पहाड़ी क्षेत्रों से केवल पत्थर प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग घर या सड़क बनाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त पंजाब के कुछ भागों में रेत/बजरी भी पाई जाती है जिसका उपयोग निर्माण-कार्य के लिए किया जाता है। इनमें गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, बठिंडा, फरीदकोट आदि जिले शामिल हैं।



Source:

www.minesandgeology.punjab.gov.in

8.3.6 पंजाब के वन संसाधन (Forest Resources of Punjab)

पंजाब में मुख्य रूप से दो प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो कि सरकारी और निजी वन हैं। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, सरकारी वन सरकार के स्वामित्व में हैं और निजी वन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं। पंजाब में तीन प्रकार के सरकारी वन हैं, जो इस प्रकार हैं:-

चार्ट 8.3 पंजाब में सरकारी वनों का वर्गीकरण

आरक्षित वन	सुरक्षित वन	अवर्गीकृत वन
<ul style="list-style-type: none"> वे वन जो बाढ़ को रोकने, जल वायु को ठीक रखने, मरूस्थल के विकास को रोकने के लिए आवश्यक हैं। सरकार की इच्छा के बिना इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। 	<ul style="list-style-type: none"> जिनमें मुख्य रूप से औद्योगिक लकड़ी पाई जाती है। कुछ शर्तों के अनुसार सरकार इन वनों के प्रयोग करने की आज्ञा देती है। 	<ul style="list-style-type: none"> इनमें पाई जाने वाली लकड़ी की कटाई के लिए सरकार इन्हे ठेके पर देती है ताकि इस लकड़ी का उपयोग व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

इसके अलावा पंजाब में निजी क्षेत्र के द्वारा भी वन लगाए जाते हैं। तालिका 8.2 पंजाब में विभिन्न प्रकार के वनों से भरपूर क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

सारणी 8.2 पंजाब में वनाधीन भूमि क्षेत्रफल
(वर्ग कि०मी० में)

वर्ष	सरकारी वन				निजी वन			वनाधीन कुल क्षेत्रफल (सरकारी वन + निजी वन)	वनाधीन कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में
	आरक्षित वन	सुरक्षित वन	अवर्गीकृत वन	कुल	भू-संरक्षण अधिनियम 1990 की धारा '4' एवं '5' के अर्न्तगत वन	भारत वन अधि- नियम 1927 के सैक्शन 38 के अर्न्तगत वन	कुल		
1980-81	44	994	262	1300	1264	39	1303	2603	517
1990-91	44	1094	211	1349	1482	14	1496	2845	565
2000-01	44	1111	197	1352	1702	4	1706	3058	607
2010-11	44	1154	187	1385	1668	5	1673	3058	601
2017-18	44	1127	157	1328	1110	4	1114	2442	485
2018-19	44	1127	157	1328	1110	4	1114	2442	485
2019-20	44	1127	157	1328	1110	4	1114	2442	485
2020-21	44	1127	157	1328	1110	4	1114	2442	485

स्रोत : पंजाब सरकार का सांख्यिकीय सार, 2021

पंजाब में वनों के बारे में उल्लेखनीय तथ्य

- वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक पंजाब में वनों के अधीन क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
- पंजाब के कुल क्षेत्रफल यानी 50362 वर्ग किमी में से केवल 2442 वर्ग किमी में ही वन हैं, जो कि पंजाब के कुल क्षेत्रफल का 4.85 प्रतिशत है। जबकि भारत का 24.62 प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन है।
- पंजाब में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र केवल 0.02 हेक्टेयर है, जबकि भारत में यह 0.18 हेक्टेयर है।
- पूरे पंजाब में वनों का वितरण एक समान नहीं है। पंजाब में सबसे अधिक वन गुरदासपुर जिले में पाए जाते हैं जहां कुल क्षेत्रफल का 32.95 प्रतिशत भाग वनों में अंतर्गत आता है। जबकि वनों के अंतर्गत सबसे कम क्षेत्रफल फतेहगढ़ साहिब जिले (0.45 प्रतिशत) में हैं।

यह क्रिया करें

- 'पंजाब में खनिज पदार्थों की कमी का पंजाब के विकास पर प्रभाव' इस विषय पर एक लिखित परियोजना तैयार करें।
- पंजाब में वनों के अंतर्गत कम क्षेत्रफल के लिए कौन-कौन से कारण जिम्मेदार है? विचार करें।
- पंजाब की अर्थव्यवस्था में वनों का क्या योगदान है? चर्चा करें।

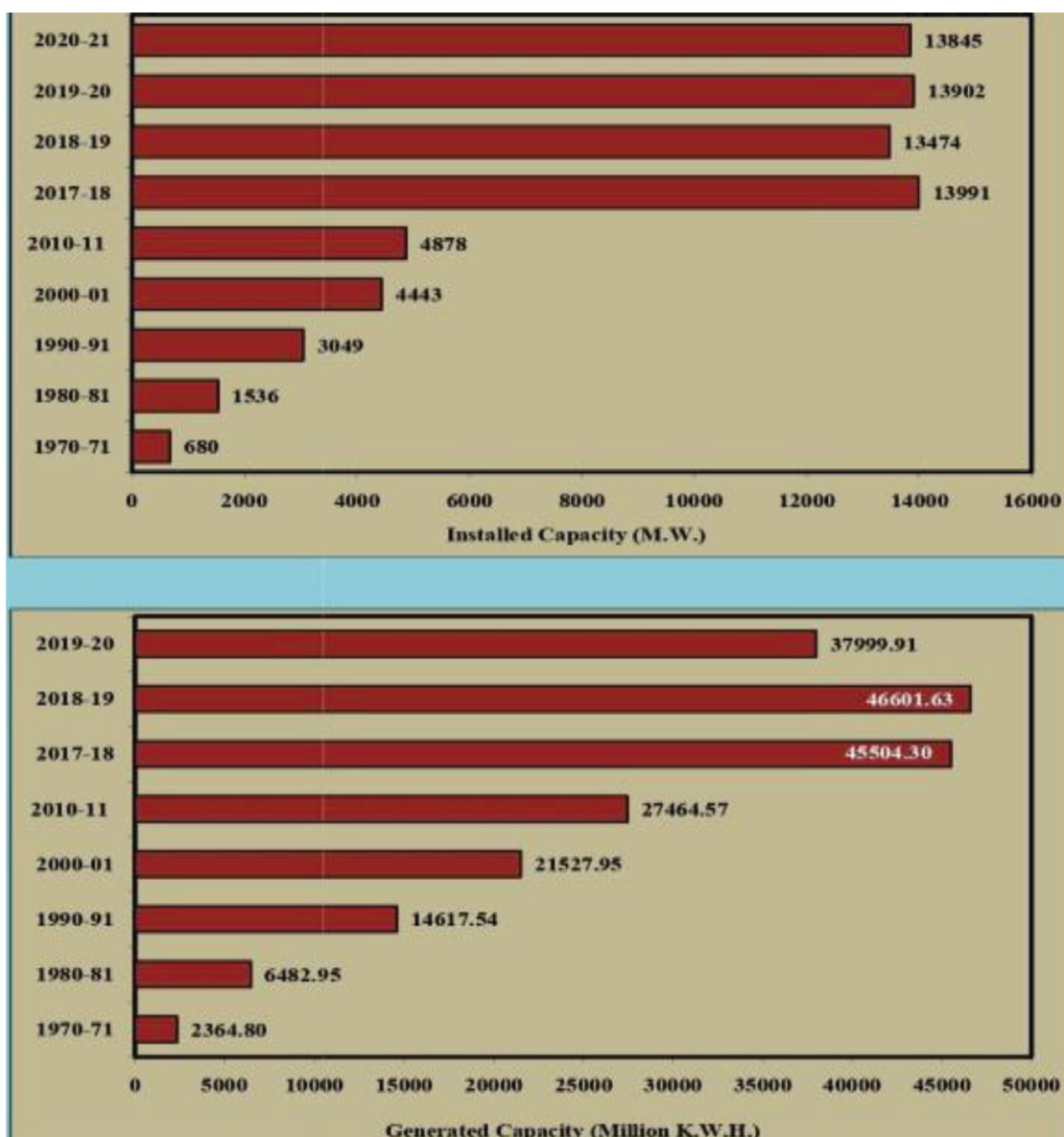
8.3.7 पंजाब के शक्ति संसाधन (Power Resources of Punjab)

शक्ति-संसाधन से तात्पर्य उन सभी संसाधनों से है, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये संसाधन किसी भी देश के विकास में योगदान करते हैं। इन संसाधनों में मुख्य रूप से मानव-शक्ति, पशु-शक्ति, कोयला, पेट्रोलियम, जल-ऊर्जा, पवन-ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैविक गैस ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि शामिल हैं। बिजली को ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है। पंजाब में बिजली उत्पादन और उपभोग का स्तर, पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ा है और पंजाब इस मामले में भारत का एक विकसित राज्य है। वर्ष 2020-21 के दौरान पंजाब में स्थापित बिजली संयंत्रों की कुल-उत्पादन क्षमता 13,845 मेगावट थी और प्रति-व्यक्ति उपभोग 1699 किलोवाट था (पंजाब का सांख्यिकीय सार, 2021) जो कि विकसित क्षेत्रों में लोगों द्वारा बिजली के उपभोग के बराबर है।

पंजाब में विद्यमान भिन्न भिन्न शक्ति संसाधन

- **जल विद्युत परियोजनाएं :** भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, पोंग पावर हाउस, अपर बारी दुआब पावर हाउस, ब्यास प्रोजेक्ट, शानन प्रोजेक्ट, आनंदपुर साहिब जल विद्युत परियोजना, मुकेरीया हाइडल प्रोजेक्ट, रणजीत सागर बाँध (थीन डैम), शाहपुर कण्डी प्रोजेक्ट
- **ताप विद्युत परियोजनाएं :** गुरु गोबिन्द सिंह ताप बिजली घर, रूपनगर ; गुरु हरगोबिन्द सिंह ताप बिजली घर, लहरा मुहब्बत ; तलवंडी साबो पावर लिमिटेड ; गोइंदवाल साहिब पावर प्रोजेक्ट ; राजपुरा थर्मल पावर स्टेशन
- **सौर ऊर्जा परियोजनाएं :** मीरपुर कला (मानसा), ब्यास, सरदारगढ़ और चुधे कला बठिंडा

चार्ट 1.4 पंजाब में विद्यमान बिजली घरों की उत्पादन शक्ति एवं बिजली उत्पादन



स्त्रोत : पंजाब का आंकड़ा सार, 2021

पंजाब में प्राकृतिक स्रोतों की कमी है जिसका इसके आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। परन्तु प्रदेश की उपजाऊ ज़मीन होने के कारण पंजाब के किसान राज्य में कृषि का विकास कर इस कमी को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं।

8.4 पंजाब के मानवीय संसाधन (Human Resources of Punjab)

प्रायः हम मानव व मानवीय संसाधनों को एक ही समझते हैं। परन्तु वास्तव में इनमें अत्यधिक अंतर है। एक क्षेत्र में रहने वाले सभी मनुष्य मानवीय संसाधन नहीं होते। केवल वही व्यक्ति जो किसी कार्य को करने की योग्यता, कौशल व दक्षता रखते हैं तथा उस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देते हैं उन्हें मानवीय संसाधन कहते

है। इस में प्रमुख रूप से एक क्षेत्र में रहने वाले किसान, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी जैसे पंलबर, बढ़ई, अध्यापक, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, वकील, आदि सम्मिलित होते हैं।

सरल शब्दों में, “मानवीय पूंजी से अभिप्राय है देश के समर्थ व निपुण लोगों का कुल भंडार। ये वही लोग हैं जो अपनी योग्यता के साथ अपने देश का भविष्य निश्चित कर सकते हैं।”

मानवीय संसाधनों की दृष्टि से पंजाब हमेशा ही बहुत समृद्ध क्षेत्र रहा है। यहाँ के लोग बहादुर, परिश्रमी तथा कुशल माने जाते हैं। पंजाब के इन्ही मानवीय संसाधनों का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित बातों का ज्ञान होना आवश्यक है।

8.4.1 जनसंख्या का आकार व वृद्धि (Size and Growth of Population)

2011 की जनगणना के अनुसार, पंजाब की कुल जनसंख्या 2.43 करोड़ थी। जो 2011 में बढ़कर 2.77 करोड़ हो गई। इस दशक में पंजाब की जनसंख्या 1.39 प्रतिशत की दर से बढ़ी जबकि इस समय के दौरान भारत की जनसंख्या में 1.77 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि इस दशक में पंजाब की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि से कम थी। जनसंख्या की दृष्टि से पंजाब भारत का 16 वां सबसे बड़ा राज्य था तथा इसकी जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 2.3 प्रतिशत है।

8.4.1.1 जनसंख्या की वृद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व (Factors Determining Growth Rate of Population)

किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या की वृद्धि दर दो कारकों पर निर्भर करती है – जन्मदर व मृत्यु दर। किसी क्षेत्र की जन्मदर जितनी ऊँची होती है उतने अधिक बच्चे वहाँ पैदा होते हैं तथा मृत्यु दर कम होने का अर्थ होता है कि कम लोग मरते

जन्मदर और मृत्युदर
जन्मदर से अभिप्राय प्रति 1000 की जनसंख्या के पीछे पैदा होने वाले बच्चों की संख्या से होता है तथा मृत्यु पर से अभिप्राय प्रति 1000 की जनसंख्या के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या से होता है।

हैं जिसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है। अतः पंजाब की जनसंख्या में वृद्धि का पता करने के लिए इसकी जन्म व मृत्यु दर के विषय में जानकारी प्राप्त करनी आवश्यक है।

- **जन्मदर :** 2011 की जन्म दर के अनुसार पंजाब की जन्म दर 16.2 प्रति हजार थी जोकि उस समय भारत की जन्मदर 21.8 प्रति हजार से कम थी।
- **मृत्युदर :** 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब की मृत्यु पर 6.8 प्रति हजार थी जो कि उस समय भारत की मृत्यु दर 7.1 प्रति हजार से कम थी।

सारणी 8.3 पंजाब की जन्म दर व मृत्युदर का शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसार अध्ययन

(2011 की जनगणना के अनुसार)

क्षेत्र	जन्म दर	मृत्यु दर
शहरी	15.2	5.6
ग्रामीण	16.8	7.5
संयुक्त	16.2	6.8

स्रोत : पंजाब का आंकड़ा सार, (2021)

उपरोक्त से मालूम होता है कि क्योंकि पंजाब की जन्म दर, इसकी मृत्यु दर से अधिक थी इसलिए पंजाब की जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी परन्तु यदि जनसंख्या होने वाली इस वृद्धि को ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों की दृष्टि से अलग-अलग देखा जाए तो सारणी 8.3 में दर्शाये परिणाम प्राप्त होते हैं ।

8.4.2 पंजाब में लिंग अनुपात (Sex Ratio in Punjab)

लिंग अनुपात को प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह अनुपात समाज में स्त्रियों की स्थिति व सशक्तिकरण को दर्शाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में लिंग अनुपात 895 था। जबकि भारत में इस समय यह लिंग अनुपात 940 था। इसलिए समूचे भारत की तुलना में पंजाब में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए प्रतिकूल है। जिले के अनुसार विश्लेषण दर्शाता है कि होशियारपुर जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात यानि 961 प्रति हजार था (जो कि समस्त भारत के औसत से अधिक है) जबकि बठिण्डा जिले में सबसे कम लिंग अनुपात 868 प्रति हजार था। इन अंतरों ने पंजाब में लिंग अनुपात की दृष्टि से क्षेत्रीय असमानताओं को उजागर किया है।

ध्यान दें

पंजाब में कम हो रहे लिंग अनुपात का प्रमुख कारण कन्या भ्रूण हत्या, पिता प्रधान समाज, पुत्र जन्म को प्राथमिकता, अनपढ़ता व रूढ़िवादी दृष्टिकोण, जीवन के अधिकार के प्रति सोच की कमी तथा लोगों में पाए जाने वाले अंधविश्वास हैं। परन्तु यह भी सत्य है कि पंजाब में लिंग अनुपात में निरंतर सुधार हो रहा है।

8.4.3 पंजाब में साक्षरता दर (Literacy Rate in Punjab)

साक्षरता दर से अभिप्राय है, एक क्षेत्र में प्रति सौ व्यक्तियों के पीछे शिक्षित लोगों की संख्या। साक्षरता दर में वे सभी लोग सम्मिलित होते हैं जो कम से कम एक भाषा को पढ़ना, लिखना व बोलना जानते हैं। किसी क्षेत्र की साक्षरता दर जितनी ऊँची होगी वह उतना ही विकसित होगा क्योंकि शिक्षित उस क्षेत्र के संसाधनों का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने के योग्य होंगे।

2011 की जनगणना के अनुसार, पंजाब की साक्षरता दर 75.84 प्रतिशत थी जबकि समग्र भारत की साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत थी। इस प्रकार पंजाब की साक्षरता दर समग्र भारत की साक्षरता दर से अधिक थी। इसकी तुलना में केरल में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर थी जो कि 93.91 प्रतिशत थी और बिहार की सबसे कम साक्षरता दर 63.82 प्रतिशत थी।

यह क्रिया करें

- आपको क्या लगता है कि पंजाब को केरल की साक्षरता दर के निकट पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए ? विचार करें ।
- पंजाब के साक्षरता दर के संबंध में पाई जाने वाली क्षेत्रीय असमानता के लिए कौन से संभावित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं?

पंजाब की साक्षरता दर के विषय में एक झलक

- 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में पुरुष साक्षरता दर 80.4 प्रतिशत तथा स्त्री साक्षरता दर 70.7 प्रतिशत थी। अभिप्राय यह है कि अभी भी लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की शिक्षा पर अधिक जोर दिया जा रहा है जो साक्षरता दर में लिंग असमानता को दिखाता है। यह भी सत्य है कि साक्षरता दर में यह अंतर न केवल वर्तमान पक्षपात के कारण है अपितु अतीत में भी स्त्री शिक्षा में पक्षपात के कारण भी है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब की शहरी साक्षरता दर 83.2 प्रतिशत थी और ग्रामीण साक्षरता दर 71.4 प्रतिशत थी जो नगरों में मिलने वाली अधिक शैक्षिक सुविधाओं की ओर संकेत करती है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब के पठानकोट और होशियारपुर जिलों में सबसे अधिक साक्षरता दर 84.6 प्रतिशत थी और मानसा जिले में सब से कम साक्षरता 61.8 प्रतिशत थी।

यह क्रिया करें

- 1971 से 2021 तक पंजाब की जनसंख्या के आकार, जन्म दर, मृत्यु दर के आंकड़ों का चार्ट तैयार करें तथा इसके आधार पर जनसंख्या वृद्धि के रुझान का पता लगाएँ।
- भिन्न-भिन्न वर्षों के दौरान भारत व पंजाब के लिंग अनुपात की तुलना दर्शाता चार्ट तैयार करें।
- पंजाब में स्त्रियों के विरुद्ध लिंग अनुपात के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हो सकते हैं ? अपने अध्यापक महोदय के साथ इस विषय में चर्चा करें।

8.4.4 पंजाब में जनसंख्या का घनत्व (Density of Population in Punjab)

जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे लोगों की संख्या को दर्शाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल 5 वर्ग कि.मी. है और उस क्षेत्र में 1000 लोग रहते हैं, तो उस क्षेत्र का जनसंख्या का घनत्व $1000/5$ अर्थात् 200 होगा। इसे मालूम करने के लिए निम्नलिखित सूत्र प्रयोग किया जा सकता है ;

$$\text{जनसंख्या का घनत्व} = \frac{\text{कुल जनसंख्या}}{\text{क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)}}$$

2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब का जनसंख्या घनत्व 551 था। जबकि उस समय के दौरान भारत का जनसंख्या का घनत्व 382 था। जोकि यह दर्शाता है कि पंजाब में जनसंख्या का घनत्व भारत से अधिक है। यह पंजाब में जनसंख्या के अधिक दबाव को दर्शाता है। पंजाब में लुधियाना जिले में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व अर्थात् 978 तथा मुक्तसर जिले में सबसे कम जनसंख्या का घनत्व अर्थात् 348 था।

8.4.5 पंजाब में शहरीकरण की प्रवृत्ति (Trends of Urbanization in Punjab)

शहरीकरण नगरों में रह रहे लोगों की कुल जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाता है। नगरीकरण का रुझान किसी

क्षेत्र के लोगों को जीवन स्तर के विषय में बताता है जैसे कि नगरीय क्षेत्र अधिक सुविधाएँ प्रदान करते हैं इसलिए नगरीय क्षेत्रों का जीवन स्तर बेहतर होता है।

पहले पंजाब को गाँवों का राज्य कहा जाता था क्योंकि इसकी अधिकांश जनसंख्या गाँवों में रहती थी। अब भी तुलनात्मक रूप से पंजाब की बहुसंख्यक जनसंख्या गाँवों में रहती है, परन्तु समय के साथ गाँवों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कम हो रहा है तथा लोग नगरों में रहने के लिए जा रहे हैं।

सारणी 1.4 पंजाब व भारत में शहरीकरण का रूझान

क्षेत्र	वर्ष	
	1971	2011
पंजाब	23.73	37.50
भारत	19.91	31.16

स्त्रोत : पंजाब का आंकड़ा सार, 2021

उपर्युक्त सारणी से मालूम होता है कि पंजाब में शहरीकरण की प्रवृत्ति भारत की तुलना में अधिक है।

पंजाब में शहरीकरण की प्रवृत्ति के बढ़ने के कारण

- गाँवों की अपेक्षा नगरों में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य आधारभूत सुविधाएँ अधिक हैं।
- गाँवों की अपेक्षा नगरों में उच्च गुणवत्ता के जीवन स्तर की उपलब्धता है।
- कृषि के विकास के कारण किसानों की आय में तीव्रता से वृद्धि हुई तथा वे उच्च जीवन स्तर के लिए नगरों की ओर चले गए।
- यातायात के साधनों के विकास के कारण ग्राम निवासियों की नगरों तक पहुँच आसान हो गई है।
- औद्योगिक विकास व आजीविका के अवसर अधिक उपलब्ध होने के कारण लोग गाँवों से नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं।

पंजाब से प्रवास

गत कुछ वर्षों से पंजाब के नवयुवकों के विदेशों की ओर जाने के रूझान में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। पंजाब के नवयुवक रोजगार, स्थायी आवास तथा स्वर्णिम भविष्य की तलाश में दूसरे देशों में जा रहे हैं। यही कारण है कि प्रत्येक बाजार में इस प्रकार के केन्द्र देखे जा सकते हैं जो नवयुवकों को विदेश भेजने का व्यवसाय करते हैं। राज्य में अच्छी गुणवत्ता व बेहतर वेतन के रोजगार के अवसरों की कमी इसका प्रमुख कारण है। राज्य व लोगों के बेहतर भविष्य के लिए राज्य को प्रवास नीति पर पुनःविचार करने की आवश्यकता है।

8.4.6 पंजाब में जनसंख्या का व्यावसायिक विभाजन (Occupational Distribution of Population in Punjab)

जनसंख्या के व्यावसायिक विभाजन से अभिप्राय है कि किस क्षेत्र की कार्यरत जनसंख्या किस क्षेत्रक से

अपनी आजीविका कमाती है अर्थात प्राथमिक, गौण अथवा सेवा क्षेत्रक। किसी क्षेत्र की जनसंख्या का व्यवसायिक विभाजन उस क्षेत्र के विकास के स्तर के बारे में जानकारी देता है। यदि किसी क्षेत्र के अधिकतर लोग प्राथमिक क्षेत्रक में काम करते हैं, तो उसे कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाएगा और यदि किसी क्षेत्र के अधिकतर लोग गौण व सेवा क्षेत्रक में काम करते हैं तो उस क्षेत्र को गैर-कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है।

अर्थव्यवस्था के भिन्न भिन्न क्षेत्रक

व्यावसायिक जनसंख्या के विभाजन के आधार पर किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्रक होते हैं। यह क्षेत्रक हैं :-

- **प्राथमिक क्षेत्रक :** इसमें कृषि व सहायक गतिविधियाँ जैसे कि मुर्गी-पालन, मछली पालन, पशु पालन तथा खनन आदि शामिल हैं।
- **गौण क्षेत्रक :** इसमें सभी प्रकार के उद्योग जैसे कि बड़े, मध्यम लघु तथा कुटीर उद्योग तथा सभी निर्माण संबंधी गतिविधि शामिल हैं।
- **सेवा क्षेत्रक :** इस क्षेत्रक में बैंकिंग, बीमा, यातयात, संचार, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी कई सेवाएं शामिल हैं।

सारणी 8.5 पंजाब में जनसंख्या का व्यावसायिक विभाजन

क्षेत्रक	कार्यशील प्रतिशत जनसंख्या
प्राथमिक क्षेत्रक	25.8
गौण क्षेत्रक	31.8
सेवा क्षेत्रक	42.4
कुल जोड़	100

स्त्रोत : पंजाब का आंकड़ा सार, 2021

सारणी 8.5 में दिये गए आंकड़ों से हमने देखा है कि पंजाब में कार्यरत 74.2 प्रतिशत लोग गैर-कृषि क्षेत्रकों में लगे हुए हैं। यही एक कारण है कि पंजाब को भारत के विकसित राज्यों में एक माना जाता है। परन्तु वर्तमान में इसका नौजवान विदेशों में जा रहा है तथा कुछ विद्वानों का यह मानना है कि इसका पंजाब की विकास दर पर कुप्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आशा है कि सरकार इस प्रकार की नीतियों का निर्माण करेगी जिससे पंजाब में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रयास किए जाएं ताकि इस प्रांत के नवयुवक पंजाब के विकास के लिए कार्य करें।

1.5 निष्कर्ष (Conclusion)

पंजाब अपने भौतिक संसाधनों अर्थात भौगोलिक विशेषताओं मिट्टी, जलवायु आदि की दृष्टि से भारत का एक अत्यन्त विविधताओं से सम्पन्न राज्य है। चाहे खनिज स्रोतों तथा वन क्षेत्र की दृष्टि से इस में कमियाँ पाई

जाती है परन्तु इस कमी को इस की प्राचीन नदियों व उपजाऊ मिट्टी ने पूरा किया है। इन संसाधनों ने पंजाब को भारत का एक विकसित राज्य बना दिया है। जहाँ तक मानवीय साधनों का संबंध है यद्यपि इसका लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से नीचे है परन्तु समय के साथ-साथ इसमें सुधार हो रहा है। इसकी साक्षरता दर, जनसंख्या का घनत्व, शहरीकरण के रूझान राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। इसकी जनसंख्या वृद्धि की दर भारत से कम है यह सभी तथ्य इसके सामाजिक विकास को दर्शाते हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि पंजाब एक समृद्ध राज्य है तथा जहाँ तक इसके आर्थिक व सामाजिक विकास का संबंध है इसमें निरंतर सुधार हो रहा है।

पुनरावृत्ति (RECAP)

- पंजाब शब्द दो शब्दों पंज तथा आब से बना है जिसमें पंज का अर्थ है पाँच तथा आब का अर्थ है पानी। इसलिए पंजाब का अर्थ है – ‘पाँच पानियों की धरती’। पंजाब का नाम पंजाब में बह रही पाँच नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, चनाव व झेलम के नाम पर पड़ा है। परन्तु इस समय पंजाब में केवल तीन नदियाँ सतलुज, ब्यास व रावी बहती हैं।
- वर्तमान में पंजाब का क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का बीसवाँ सबसे बड़ा राज्य है। इसमें कुल 23 जिले हैं।
- पंजाब भौगोलिक दृष्टि से तीन भागों में विभाजित है – पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र व अर्द्ध मरुस्थली क्षेत्र।
- पंजाब में दो प्रकार के वन पाए जाते हैं जो कि सरकारी वन व निजी वन हैं। सरकारी वन आरक्षित, सुरक्षित व गैर वगीकृत प्रकार के होते हैं।
- वर्ष 2020-21 के दौरान पंजाब में लगाए गए पॉवर प्लांटों की कुल उत्पादन समर्था 13845 मैगावाट थी तथा प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग 1669 किलोवाट था।
- 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब की जन्मदर 16.2 प्रति हजार थी तथा मृत्युदर 6.8 प्रति हजार थी।
- 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में लिंग अनुपात 895 प्रति हजार था।
- 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब की साक्षरता दर 75.84 प्रतिशत थी।
- 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब की जनसंख्या का घनत्व 551 प्रति वर्ग किलोमीटर था।
- 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब की 37.50 प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब की 25.8 प्रतिशत जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्रक में, 31.8 प्रतिशत गौण क्षेत्रक में तथा 42.4 प्रतिशत सेवा क्षेत्रक में कार्यरत है।

- (x) भाखड़ा नंगल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है ?
क) सरस्वती ख) सतलुज
ग) सिंध घ) ब्यास
- (xi) 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब की जनसंख्या कितनी है ?
क) 2.34 करोड़ ख) 2.43 करोड़
ग) 2.52 करोड़ घ) 2.77 करोड़
- (xii) 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में लिंग अनुपात कितना था ?
क) 832 ख) 857
ग) 895 घ) 940
- (xiii) 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब की साक्षरता दर कितनी थी?
क) 75.84% ख) 70.04%
ग) 63.82% घ) 93.91%
- (xiv) 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब का जनसंख्या घनत्व कितना था ?
क) 550 ख) 551
ग) 555 घ) 560
- (xv) 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती थी ?
क) 31.50% ख) 32.50%
ग) 35.50% घ) 37.50%

- (i) वर्तमान समय में पंजाब में दरिया बहते हैं। (तीन/पांच)
- (ii) पंजाब के भौगोलिक क्षेत्र को भागों में विभाजित किया जा सकता है। (तीन/चार)
- (iii) सतलुज नदी से निकलती है। (ब्यासकुंड/मानसरोवर)
- (iv) रणजीत सागर बाँध का दूसरा नाम है। (शाहपुर कंडी बांध/तीन बांध)
- (v) पंजाब मानवीय संसाधनों की दृष्टि से एक प्रांत रहा है। (समृद्ध/गरीब)
- (vi) पंजाब की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि की दर भारत की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि की तुलना में रही है। (अधिक/कम)
- (vii) पंजाब में लिंग अनुपात स्त्रियों के है। (पक्ष में/विरुद्ध)
- (viii) जनसंख्या घनत्व का माप प्रति वर्ग रूप में किया जाता। (सैंटीमीटर/किलोमीटर)
- (ix) पंजाबी की जनसंख्या का घनत्व भारत की जनसंख्या घनत्व से है। (अधिक/कम)
- (x) पंजाब में शहरीकरण की प्रवृत्ति में निरन्तर हो रही है। (वृद्धि/कमी)
- (xi) पंजाब की अधिकांश जनसंख्या क्षेत्रक में कार्य करती है। (कृषि/सेवा)

Q.3. सही या गलत लिखें (True or False)

- (i) ऋग्वैदिक काल में पंजाब में सात नदियां बहती थीं।
- (ii) वर्तमान पंजाब में कुल 22 जिले हैं।
- (iii) पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र में सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है।
- (iv) पंजाब के मैदानी भाग बहुत ज्यादा ऊपजाऊ हैं।
- (v) पंजाब में सर्दियों का मौसम सितंबर से दिसंबर तक रहता है।
- (vi) पंजाब में खनिज पदार्थों की कमी पाई जाती है।
- (vii) पिछले कुछ समय से पंजाब में लन अधीन क्षेत्रफल में बहुत वृद्धि हुई है।
- (viii) मानव और मानवीय साधनों में कोई अंतर नहीं है।
- (ix) जनसंख्या के पक्ष से, पंजाब, भारत का सातवा सबसे बड़ा राज्य है।
- (x) पंजाब में लिंग अनुपात भारत के औसत लिंग अनुपात से अधिक है।
- (xi) साक्षरता दर का मापन प्रति हजार के रूप में किया जाता है।
- (xii) पंजाब में लुधियाना जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है।
- (xiii) शहरीकरण में होने वाली वृद्धि किसे क्षेत्र के अर्थिक विकास का सूचक होती है।

4. अति लघु उत्तरीय प्रश्न (एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर) (Very Short Answer Questions)

- (i) पंजाब शब्द का क्या अर्थ है? वर्तमान पंजाब का क्षेत्रफल कितना है?
- (ii) भौतिक संसाधनों से क्या अभिप्राय है ?
- (iii) पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों से कौन सी नदियां निकलती है ?
- (iv) पंजाब के माझा क्षेत्र से क्या भाव है ?
- (v) दुआबा क्षेत्र से क्या भाव है ?
- (vi) मालवा क्षेत्र से क्या भाव है?
- (vii) पंजाब के खनिज संसाधनों पर एक नोट लिखें।
- (viii) शक्ति संसाधनों से क्या भाव है?
- (ix) शक्ति के संसाधनों के कौन से प्रकार हैं?
- (x) आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत वन कौन से हैं ?
- (xi) जन्म दर और मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है ?
- (xii) पंजाब की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि के लिए जिम्मेवार दो कारणों की व्याख्या करें।
- (xiii) लिंगानुपात से क्या भाव है ? पंजाब के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है ?
- (xiv) साक्षरता दर से क्या भाव है ? इसका माप कैसे किया जाता है?
- (xv) जनसंख्या घनत्व से क्या भाव है ? इसके माप का सूत्र लिखें।
- (xvi) जनसंख्या के व्यवसायिक विभाजन से क्या भाव है?
- (xvii) प्राथमिक क्षेत्रक से क्या भाव है ? इसमें किन गतिविधियों को शामिल किया जाता है ?

(xviii) गौण क्षेत्रक से क्या भाव है ? इसमें किन गतिविधियों को शामिल किया जाता है ?

(xix) सेवा क्षेत्रक से क्या भाव है ? इसमें किन गतिविधियों को शामिल किया जाता है ?

5. मिलान करें :- (Match the Following)

(i) दोनों ओर दिए गए तथ्यों का सही मिलान करें :-

तथ्य	वर्ष
वर्तमान पंजाब	1947
मलेर कोटला	1966
भारत का विभाजन	2021

(ii) दोनों ओर दिए तथ्यों का सही मिलान करें -

पंजाब का मैदानी भाग	क्षेत्र
माझा	पंजाब के दक्षिण और सतलुज के दक्षिण पश्चिम में स्थित
मालवा	ब्यास व सतलुज दरिया के मध्य का क्षेत्र
दोआबा	रावी तथा ब्यास दरिया के मध्य का क्षेत्र

(iii) दोनों ओर के तथ्यों का सही मिलान करें :-

पंजाब का मौसम	महीना
ग्रीष्म	अक्टूबर से मार्च
सर्दी	अप्रैल से जून
मानसून	जुलाई से सितंबर

(iv) दोनों ओर दिए गए तथ्यों का सही मिलान करें :-

पंजाब के वन	विशेषता
आरक्षित	औद्योगिक लकड़ी प्रदान करने वाले
सुरक्षित	ठेके पर दिए जाने वाले
अवर्गीकृत	बाढ़ को रोकने वाले

(v) 2011 की जनगणना के अनुसार प्राप्त होने वाले आंकड़ों का एक दूसरे से सही मिलान करें :-

तथ्य	आंकड़े
जन्म दर	895
मृत्यु दर	2.77 करोड़
जनसंख्या का आकार	16.2 प्रति हजार
लिंग अनुपात	6.8 प्रति हजार

6. लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Question)

- (i) पंजाब की भौगोलिक विशेषताओं पर टिप्पणी लिखें।
- (ii) पंजाब के मौसम पर नोट लिखें।
- (iii) पंजाब में पाई जाने वाली मिट्टी पर नोट लिखें।
- (iv) पंजाब के जल संसाधनों पर नोट लिखें।
- (v) पंजाब में उपलब्ध भिन्न-भिन्न प्रकार के सरकारी वनों की व्याख्या करें।
- (vi) पंजाब के शक्ति संसाधनों पर नोट लिखें।
- (vii) पंजाब में स्त्रियों के विरुद्ध लिंग अनुपात के लिए ज़िम्मेवार कारणों की व्याख्या करें।
- (viii) पंजाब की साक्षरता दर पर नोट लिखें।
- (ix) पंजाब की जनसंख्या के व्यावसायिक विभाजन पर नोट लिखें।

7. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

- (i) पंजाब के भौगोलिक विभाजन की विस्तृत व्याख्या करें।
- (ii) पंजाब की अर्थव्यवस्था में वनों के महत्व पर निबंध लिखें।
- (iii) पंजाब की जनसंख्या की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें।
- (iv) शहरीकरण से क्या अभिप्राय है? पंजाब में शहरीकरण की निरंतर बढ़ रही प्रवृत्ति के लिए कौन से कारण ज़िम्मेवार हैं ?

References

- Handbook of Statistics on Indian Economy (2020). "Reserve Bank of India Publication", Available at [https://www.rbi.org.in/scripts/AnnualPublications.aspx?head=Handbook of Statistics on Indian Economy](https://www.rbi.org.in/scripts/AnnualPublications.aspx?head=Handbook%20of%20Statistics%20on%20Indian%20Economy)
- Handbook of Statistics on Indian Economy (2021). "Reserve Bank of India Publication", Available at [https://www.rbi.org.in/scripts/AnnualPublications.aspx?head=Handbook 20of 20Statistics 20on 20Indian 20Economy](https://www.rbi.org.in/scripts/AnnualPublications.aspx?head=Handbook%20of%20Statistics%20on%20Indian%20Economy)
- H K Manmohan Singh (2016). "The Punjab". The Encyclopedia of Sikhism, Editor-in-Chief Harbans Singh. Punjabi University, Patiala
- Rajesh Bala (2005). "Foreign Invasions and their Effect on Punjab". In Sukhdial Singh (ed.). Punjab History Conference, Thirty-seventh Session, March 18-20, 2005: Proceedings. Punjabi University, p. 80. ISBN 978-81-7380-990-3

- Singh, Pritam (2008). “Federalism, Nationalism and Development: India and the Punjab Economy”, February 19, Routledge
- GoP (2020). Statistical Abstract of Punjab. “Economic and Statistical Organization”, Department of Planning, Government of Punjab, Publication No. 962
- GoP (2021). Statistical Abstract of Punjab. “Economic and Statistical Organization”, Department of Planning, Government of Punjab, Publication No. 964



9

पंजाब में कृषि और औद्योगिक विकास

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप

- पंजाब में कृषि की मुख्य विशेषताएं, मुख्य फ़सलें, पंजाब में कृषि-विपणन और हरित-क्रांति नीतियों के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि इसकी प्राप्तियों सीमाओं, आदि को समझ पायेंगे ;
- औद्योगीकरण की आवश्यकता, पंजाब में विभिन्न उद्योग, औद्योगिक विकास के रास्ते में आने वाली समस्याओं और उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों, आदि के बारे में जानेंगे।

अध्याय – 9

पंजाब में कृषि और औद्योगिक विकास

9.1 परिचय (Introduction)

जैसा कि हम पिछले अध्याय में पहले ही पढ़ चुके हैं कि अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से तीन क्षेत्रक होते हैं—प्राथमिक क्षेत्रक, गौण क्षेत्रक और तीसरा क्षेत्रक। इसलिए, इस अध्याय में हम पंजाब की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्रक और गौण क्षेत्रक के योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राथमिक क्षेत्रक में हम कृषि और उस से सम्बन्धित गतिविधियों के योगदान की जांच करेंगे। इसी प्रकार गौण क्षेत्रक में विभिन्न उद्योगों के योगदान का अध्ययन किया जायेगा।

9.2 पंजाब का कृषि विकास (Agricultural Development of Punjab)

AGRICULTURE दो लातीनी शब्दों से मिलकर बना है जोकि AGRI और CULTURE है। इनमें से AGRI का अर्थ है 'भूमि' और CULTURE का अर्थ है 'खेती'। इसलिए कृषि का अर्थ, फसल उगाने के लिए भूमि पर जुताई करना और अन्य सम्बन्धित गतिविधियों में संलग्न होना है।

एबेलानोसा ए. एल. और पॉवा एच. एम. के अनुसार (1987), “कृषि मानव-आवश्यकताओं के लिए पौधों और जानवरों दोनों का विकास है।”

सरल शब्दों में, कृषि का अर्थ है भूमि पर फसलों की खेती के साथ-साथ, सभी सम्बन्धित गतिविधियों जैसे पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि को अपनाना है।

पंजाब की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्व इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि पंजाब को भारत के अनाज कटोरे के रूप में जाना जाता है क्योंकि भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कृषि उत्पादन में पंजाब का योगदान अपेक्षाकृत अधिक रहा है।

पंजाब ने भारत के कुल अनाज भंडार में 2019-20 और 2020-21 में क्रमशः 37.8 प्रतिशत और 32.6 प्रतिशत गेहूं का और 2019-20 और 2020-21 में क्रमशः 20.9 प्रतिशत और 22.6 प्रतिशत धान का योगदान दिया।

पंजाब में, खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 82 प्रतिशत है। पंजाब में विभिन्न फसलों के अंतर्गत कुल बोए गए क्षेत्र और उनके उत्पादन को सारणी 9.1 में दिखाया गया है :

सारणी 9.1 पंजाब में विभिन्न फसलों के तहत कुल बोया गया क्षेत्र और उत्पादन

क्रम संख्या	फ़सल	2010-11		2019-20	
		बोया क्षेत्र	उत्पादन	बोया क्षेत्र	उत्पादन
1	गेहूँ	3510	16472	3521	17616 2
2.	चावल	2826	10819	3142	12675
3	कपास	701	1822	248	1207
4	मक्का	133	491	115	410
5	गन्ना	70	4904	91	7302

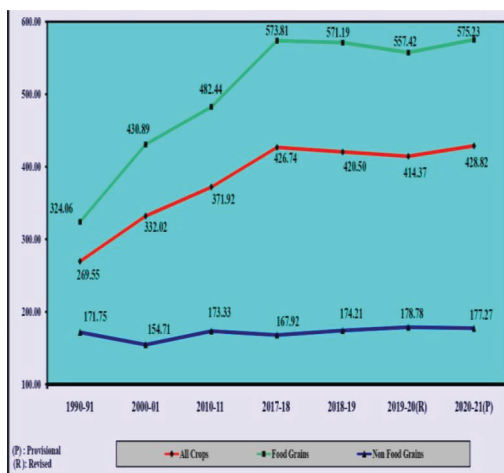
क्षेत्रफल : 000' हेक्टेयर में

उत्पादन : 000' मीट्रिक टन में

स्रोत : पंजाब का सांख्यिकीय सार, 2021

सारणी 9.1 से पता चलता है कि कुल बोया गया क्षेत्र और इसके साथ ही कपास और मक्का का उत्पादन कम हो रहा है। दूसरी ओर गेहूँ, धान और गन्ना, समय के साथ, ऊपर की ओर प्रवृत्ति दिखा रहे हैं। यह इशारा करता है कि पंजाब में गेहूँ-धान फसल पैटर्न अभी भी प्रभावी है, जिसे मोनोकल्चर फसल पैटर्न के रूप में जाना जाता है।

चित्र 9.1 : पंजाब में कृषि उत्पादन का सूचकांक



स्रोत : पंजाब का सांख्यिकीय सार, 2021

गतिविधियाँ

- अपने क्षेत्र में फ़सलों के पैटर्न (प्रतिरूप) विषय में जानकारी एकत्रित करें।
- अपने क्षेत्र में कृषि में कार्यरत लोगों का अनुपात ज्ञात करें। (20 परिवारों का नमूना लिया जा सकता है।)
- चित्र 9.1 का अध्ययन कर उन वर्षों को रेखांकित करें जब खाद्य व गैर खाद्य फ़सलों का उत्पादन अधिकतम था।

9.3 पंजाब की कृषि की मुख्य विशेषताएं (Salient Features of Punjab Agriculture)

पंजाब की कृषि भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक विकसित और उन्नत है। पंजाब की कृषि की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

उच्च उत्पादन और उत्पादकता : 1966-67 में हरित क्रांति के बाद पंजाब में कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ा। वर्ष 2019-20 में पंजाब में फसलों का कुल उत्पादन 308 लाख टन था। परिणामस्वरूप, भारत के कुल कृषि उत्पादन में पंजाब का योगदान 1966 में 4.5% से बढ़कर 2019-20 में 12% हो गया। इसके अतिरिक्त पंजाब में समय के साथ कृषि-उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-20 में पंजाब में गेहूं की उत्पादकता 5004 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और धान की उत्पादकता 4034 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी जो राष्ट्रीय औसत से अधिक थी।

उत्पादन व उत्पादकता में अन्तर

उत्पादन तथा उत्पादकता अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण धारणाएं हैं। उत्पादन से अभिप्राय उत्पादन की कुल मात्रा से है जबकि कृषि में उत्पादकता का अर्थ प्रति हेक्टेयर उत्पादन अर्थात् प्रति हेक्टेयर उत्पादन की मात्रा है। मान लीजिए अमरीक सिंह के पास चार (4) हेक्टेयर भूमि है जबकि जोगिन्द्र के पास पाँच (5) हेक्टेयर भूमि है। दोनों किसान ने 200 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया। अमरिक सिंह ने एक हेक्टेयर में $200/4=50$ क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया। जोगिन्द्र सिंह ने प्रति हेक्टेयर में $200/5 = 40$ क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया। इसके अनुसार अमरीक सिंह के खेत की कृषि उत्पादकता जोगिन्द्र सिंह की तुलना में अधिक है।

$$*1 \text{ हेक्टेयर} = 2.471 \text{ एकड़}$$

रोजगार का साधन : पंजाब में कुल कार्यशील जनसंख्या का 25.8 प्रतिशत कृषि और उसके साथ सम्बंधित गतिविधियों में कार्यरत है। इसके अलावा कई लोग जो कृषि उपकरणों, उर्वरक, कीटनाशक आदि का उत्पादन व व्यापार करते हैं, वे भी कृषि और उसके साथ सम्बंधित गतिविधियों में शामिल हैं। पंजाब में रोजगार में कृषि का हिस्सा समय के साथ घट रहा है। लेकिन बुआई और कटाई के दौरान खेती में मजदूरों की भारी मांग होती है इसके कारण अन्य राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से मजदूर कृषि-क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए पंजाब में आते हैं।

आधुनिक प्रकृति : पंजाब के किसान, खेती के आधुनिक तरीके अपनाते हैं। वे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, कंबाइन, पंप-सेट, मोटर, नलकूप, अधिक उपज देने वाली किस्म (एचवाईवी) के बीज, रासायनिक उर्वरक आदि का उपयोग करते हैं।

मोनोकल्चर फसल पैटर्न : पंजाब में किसान मुख्य रूप से दो फसलों की खेती करते हैं। रबी मौसम में गेहूं और खरीफ मौसम में चावल। वर्ष 2019-20 में पंजाब के कुल फसल-क्षेत्र के 45 प्रतिशत क्षेत्र में गेहूं और 40 प्रतिशत क्षेत्र में धान की खेती की गई थी। हालाँकि, विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे : दालें, गन्ना, तिलहन, कपास आदि का भी उत्पादन किया जाता है।

आर्थिक विकास में योगदान : कृषि किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। कृषि गतिविधियाँ गैर-कृषि गतिविधियों के विकास में भी योगदान देती हैं। कृषि क्षेत्रक औद्योगिक क्षेत्रक को कच्चा-माल प्रदान करता है और बदले में इस क्षेत्रक से आवश्यक मशीनरी और साधन प्राप्त करता है।

व्यापारीकरण : पंजाब में कृषि अत्यधिक-व्यवसायिक

प्रकृति की है क्योंकि किसान अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए बाज़ार के लिए उत्पादन करते हैं। कृषि-उपज विभिन्न एजेंसियों, सहकारी समितियों और निजी बाज़ार को बेची जाती है।

मोनोक्लचर फसली पैटर्न

इसका अभिप्राय है कि किसान स्वयं को एक या दो फसल उगाने तक सीमित रखते हैं जिसमें किसान तरह-तरह की फसलें उगाने के लिए तैयार नहीं होते।

गतिविधि करें						
किन्हीं पाँच किसानों का एक नमूना लेकर निम्नलिखित सारणी को पूरा करें।						
किसान	रबी के मौसम में गेहूँ			खरीफ के मौसम में धान		
	कुल उत्पादन	बाज़ार में बिक्री	स्व-उपभोग	कुल उत्पादन	बाज़ार में बिक्री	स्व-उपभोग
1						
2						
3						
4						
5						
कुल						

खेतों का आकार : खेत के आकार का अर्थ है- किसानों को खेती के लिए उपलब्ध भूमि का क्षेत्र या आकार। सरकार किसानों को उनके पास कृषि-योग्य भूमि के आधार पर सीमांत, लघु, अर्ध-माध्यमिक, माध्यमिक, बड़ा आदि वर्गों में वर्गीकृत करती है। इस संबंध में जानकारी निम्न तालिका से प्राप्त की जा सकती है।

सारणी 9.2 पंजाब में खेतों का आकार

खेत की किस्म	वर्ष 2010-11	वर्ष 2015-16
सीमांत (1 हैक्टेयर से कम)	1,64,431 (15.62%)	1,54,412 (14.13%)
छोटे (1-2 हैक्टेयर तक)	1,95,439 (18.57%)	2,07,436 (18.98%)
अर्द्ध मध्यम (2-4 हैक्टेयर तक)	324515 (30.83%)	367938 (33.67%)
मध्यम आकार (4-10 हैक्टेयर)	298451 (28.36%)	305220 (27.93%)
बड़े (10 हैक्टेयर से अधिक)	69718 (6.62%)	57707 (5.29%)
कुल	1052554 (100%)	1092713 (100%)

स्रोत : कृषि निदेशालय/कृषि जनगणना, पंजाब (पंजाब का सांख्यिकीय सार, 2021)

सारणी 9.2 से पता चलता है कि पंजाब में सीमांत-खेतों की संख्या कम हो रही है। सीमांत खेतों की गिनती में गिरावट का कारण उच्च-खेती लागत, गैर-कृषि गतिविधियों में वृद्धि और ऋण आदि हैं। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार पंजाब में खेतों का औसत आकार 1.08 हैक्टेयर था जो कि राष्ट्रीय औसत 3.62 हैक्टेयर की तुलना में कम था।

क्षेत्रीय विषमताएँ : पंजाब के जिलों में कृषि उत्पादन और उत्पादकता में एकरूपता नहीं है। कुछ जिलों में कृषि-उत्पादन पंजाब के अन्य जिलों की तुलना में अधिक है। उदाहरण के लिए वर्ष 2020-21 में धान की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता संगरूर जिले में सबसे अधिक (5264 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) और फ़ाज़िल्का जिले में सबसे कम (3276 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) थी और गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता संगरूर जिले में सबसे अधिक (5265 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) थी और होशियारपुर जिले में सबसे कम (4145 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) थी।

इसलिए पंजाब में कृषि की प्रकृति अत्यधिक व्यावसायिक, उन्नत, मोनोकल्चर फसल-पैटर्न और घटे सीमांत किसानों की संख्या वाली है।

9.4 पंजाब की प्रमुख फ़सलें (Major Crops of Punjab)

पंजाब में उत्पादित सभी फ़सलों को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। इनका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है:-

9.4.1 मौसम के आधार पर वर्गीकरण (Classification based on season)

मौसम के आधार पर फसलों की बुवाई और कटाई के अनुसार पंजाब की फसलों को दो श्रेणियों में बांटा गया है : रबी और खरीफ की फसलें। इनका वर्णन इस प्रकार है :

रबी की फसलें : ये आम तौर पर अक्टूबर और नवंबर के महीनों के दौरान बोई जाती हैं और मार्च से मई के महीनों के दौरान काटी जाती हैं। उदाहरण के लिए गेहूं, तिलहन, चना, जौ आदि।

खरीफ फसलें : फसलें ये आमतौर पर मई से अगस्त के महीनों के दौरान बोई जाती हैं और सितंबर से दिसंबर के महीनों के दौरान काटी जाती हैं। उदाहरण के लिए धान, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का, गन्ना, मूंगफली आदि।

9.4.2 फ़सलों के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण (Classification on the basis of type of crops)

फ़सलों के प्रकार का अर्थ है कि फ़सल का उत्पादन सीधा उपभोग के लिए किया जा रहा है या उद्योगों में कच्चे माल के रूप उपयोग के लिए और बाजार में बेची जा रही है। इस आधार पर पंजाब से फसलों को दो भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार हैं:-

खाद्य-फसलें : ये वे फ़सलें हैं जिनका उत्पादन सीधे उपभोग के लिए किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से गेहूं, धान, मक्की, जौ, चना, बाजरा, दालें आदि शामिल हैं।

व्यापारिक फसलें : ये ऐसी फ़सलें हैं जिनका उपयोग सीधे उपयोग में नहीं किया जाता है। इसलिए किसान उन्हें बाजार में ले जाकर बेचते हैं, ताकि उद्योग उन्हें कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल कर सके और सामान तैयार सकें। इनमें मुख्य रूप से गन्ना, कपास, तिलहन आदि शामिल हैं।

9.5 पंजाब में कृषि विपणन (Agricultural Marketing in Punjab)

प्रत्येक किसान अपने कुल उत्पादन का एक निश्चित भाग अपने उपभोग के लिए रखता है और शेष को बाजार में बेच देता है। बाजार में फसलों को बेचने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को कृषि-विपणन के रूप में जाना जाता है।

कृषि विपणन के बढ़ते महत्व का कारण

हरित क्रांति से पहले पंजाब में फसलों का उत्पादन बहुत कम था और ये फसलें किसानों की स्वै-उपभोग की जरूरतों को मुश्किल से पूरा कर पाती थीं। किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए उत्पाद बहुत कम था। लेकिन हरित क्रांति के बाद पंजाब में कृषि उत्पादन की मात्रा में जबरदस्त वृद्धि हुई और अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद किसानों के पास बड़ी मात्रा में फसल बच जाती है। किसानों ने ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए इन फसलों को बाजार में बेचना शुरू कर दिया। इस प्रकार किसानों की आर्थिक-स्थिति में सुधार के लिए कृषि-विपणन प्रमुख प्रक्रियाओं में से एक है।

सारणी 9.3 पंजाब में कृषि विपणन की व्यवस्था (आंकड़े मार्च 31, 2021 तक)

बाजार की किस्म	गिनती
नियमित मंडीयां	154
उप मंडीयां	284
औसत गाँव की गिनती प्रति नियमित मंडी	80
क्षेत्रफल प्रति नियमित मंडी (वर्ग किलोमीटर में)	331

स्रोत : पंजाब का सांख्यिकीय सार, 2021

पंजाब में कृषि विपणन में कई संस्थाएं जैसे कि पनग्रेन, भारतीय खाद्य-निगम, मार्कफेड, पंजाब स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन, पंजाब एग्रो हाउस कॉरपोरेशन योगदान देती हैं।

9.5.1 पंजाब में कृषि विपणन में कठिनाइयाँ (Difficulties in Agricultural Marketing in Punjab)

किसान जब भी अपनी फसल को बाजार में बेचने की कोशिश करता है तो उसे तरह-तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयाँ इस प्रकार हैं:-

- पंजाब में नियमित मंडीयां जरूरत से कम हैं जिससे किसानों को इनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।
- पंजाब के अधिकांश बाजार शहरी क्षेत्र में उपलब्ध है और किसानों के पास परिवहन के साधनों की कमी है इसलिए वे अपनी फसलों को इन शहरी बाजारों तक नहीं पहुंचा सकते हैं।

- इन बाजारों में बिचौलिए बड़ी संख्या में मौजूद हैं।
- बहुत कम फसलों के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। जो कई बार उत्पादन लागत को भी पूरा नहीं करता।
- किसान बाजारों में अपनी फसलों की सही ग्रेडिंग नहीं कर पाते हैं जिससे उनकी अच्छी किस्म की फसलें भी कम दामों में बिक जाती हैं।
- इन बाजारों में कई तरह की गड़बड़ी भी देखने को मिलती है जिससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है।
- इन बाजारों में किसानों को पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा, शेड की सुविधा, तिरपाल की सुविधा आदि जैसी आवश्यक सुविधाएं की उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य

इससे अभिप्राय वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से निश्चित फसल खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि किसी किसान को बाजार में इससे कम मूल्य मिलता है तो किसान इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को अपनी फसल बेच सकता है।

गतिविधियां

- पंजाब में विभिन्न महीनों में बोई और काटी जाने वाली फसलों पर चार्ट बनाइए।
- पंजाब की कृषि में मोनोकल्चर क्यों पाया जाता है ? अपने शिक्षक से चर्चा करें।
- कृषि विपणन में सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए? इस पर कक्षा में भाषण प्रतियोगिता आयोजित करें।

9.6 पंजाब में हरित क्रांति (Green Revolution in Punjab)

पंजाब में हरित क्रांति राज्य के कृषि विकास में एक मील का पत्थर है। इसके कारण कृषि उत्पादन और उत्पादकता में काफी हद तक वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन जो वर्ष 1965-66 में 34 लाख टन था, वर्ष 2020-21 में 305.44 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि पंजाब की कृषि पर हरित क्रांति की नीतियों के प्रभाव को स्पष्ट रूप में दिखाता है।

हरित-क्रांति

सामान्य तौर पर कृषि उत्पादन में हर साल लगभग 3 से 4 प्रतिशत की वृद्धि होती है। लेकिन 1966-67 में कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों और आधुनिक उपकरणों के प्रयोग से केवल एक वर्ष में कृषि उत्पादन में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो किसी क्रांति से कम नहीं थी। इसी विकास को 'हरित क्रांति' का नाम दिया गया।

9.6.1 पंजाब में हरित क्रांति के कारण (Causes of Green Revolution in Punjab)

हरित क्रांति में सफल होने और कृषि पद्धतियों की प्रकृति में पर्याप्त परिवर्तन के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। उनका वर्णन इस प्रकार है :

- **नवीन-पद्धतियों का प्रयोग :** पंजाब में खेती के लिए नवीन एवं वैज्ञानिक पद्धतियों, आधुनिक यंत्रों आदि को अपनाया गया। इसमें ट्रैक्टर, कंबाइन, नलकूप, रासायनिक उर्वरक आदि का उपयोग शामिल था। इनके उपयोग से पंजाब में कृषि उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि हुई।
- **सिंचाई प्रणाली का विस्तार :** 1965-66 में पंजाब में कुल 22 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा थी। इसके बाद हरित-क्रांति का लाभ उठाने के लिए पंजाब में सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया। 2019-20 में पंजाब में सिंचाई-सुविधाओं के तहत कुल 40.74 लाख हेक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र था जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 98.9 प्रतिशत था। (निदेशक, भूमि रिकॉर्ड कार्यालय, पंजाब)।
- **बहुफसली प्रणाली को अपनाना :** हरित-क्रांति से पहले पंजाब में एकल-फसल प्रणाली प्रचलित थी। लेकिन, हरित क्रांति के लागू होने के बाद पंजाब ने बहुफसली-प्रणाली को अपनाया जिसके परिणामस्वरूप, राज्य में फसलों का अधिक उत्पादन हुआ।
- **ऋण सुविधाओं का विस्तार :** आधुनिक खेती के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें महंगी थीं अतः, उन्हें प्रत्येक किसान की पहुंच में लाने के लिए किसानों को ऋण देने की सुविधा प्रदान की गई जिसमें किसानों को बैंकों तथा अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा अल्प, मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया गया।
- **नियमित मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य:** हरित क्रांति से पहले, पंजाब में बहुत कम नियमित मंडियां थीं और किसानों को अपनी उपज, साहूकारों और ग्रामीण व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। जो उन्हें उनकी उपज का सही मूल्य नहीं देते थे। हरित-क्रांति की नीतियों को लागू करने के लिए तथा किसानों को प्रेरित करने के लिए सरकार द्वारा नियमित बाजारों की स्थापना की गई और फसल को बेचने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी गई। भारतीय खाद्य-निगम, मार्कफेड आदि, न्यूनतम-समर्थन मूल्य, सुनिश्चित कर, खाद्यान्न एवं अन्य फसलों की खरीद करते हैं।
- **अन्य सुधार :** उपरोक्त के अलावा, कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई अन्य संस्थागत सुधार किए गए। जैसे खेतों के आकार की ऊपरी सीमा तय करना, चकबंदी की नीति अपनाना, सहकारी-खेती को प्रोत्साहित करना, भूमि से संबंधित सभी रिकॉर्ड का कम्प्यूटरीकरण आदि। इसने हरित-क्रांति को पंजाब में सफल बनाने में भी मदद की।

सारणी 9.4 पंजाब में हरित क्रांति की उपलब्धियाँ और सीमाएं

उपलब्धियाँ	सीमाएं
<ul style="list-style-type: none"> • कृषि उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। • ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुई। • किसानों की आय में वृद्धि हुई और जीवन स्तर में सुधार हुआ। • पंजाब द्वारा केंद्रीय खाद भण्डार में दिए गए योगदान में वृद्धि हुई। • कृषि उत्पादनों में वृद्धि के कारण उद्योगों को कच्चा माला सही मात्रा में प्राप्त हुआ। • लोगों की तरह-तरह की कृषि वस्तुएँ प्राप्त हुई। • व्यापारक कृषि को बढ़ावा मिला। 	<ul style="list-style-type: none"> • इससे कृषि में मोनोकल्चर खेती प्रबंध अर्थात गेहूँ और धान के फ़सली कुचक्कर आदि की शुरूआत हुई। • इसमें क्योंकि खेती आधुनिक तकनीकों से भी जानी थी जो केवल अमीरों के लिए उपलब्ध थी। • इससे आय असमानताओं में वृद्धि हुई। • इससे भूमि की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ा जिससे मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ा। • इस ने कृषि क्षेत्र में श्रम के उपयोग को कम – कम दिया जिससे ग्रामीण बेरोजगारी में वृद्धि हुई।

उपरोक्त व्याख्या से यह स्पष्ट है कि पंजाब को हरित क्रांति से जहाँ अनेक लाभ हुए वहीं यह क्रांति कई पहलुओं में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल भी रही। इसलिए वर्तमान में पंजाब में कृषि क्षेत्र में उत्पादन की विकास दर स्थिर प्रकृति की है।

गतिविधि

- पंजाब में हरित क्रांति की उपलब्धियों तथा कमियों के संबंध में कक्षा में वाद – विवाद प्रतियोगिता करवाएँ।
- क्या हमारे कृषि वैज्ञानिकों हरित क्रांति के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की अवहेलना कर गए ? इस पर आप के क्या विचार हैं।
- क्या वर्तमान में पंजाब को एक और हरित क्रांति की आवश्यकता है ? इसके संबंध में रिपोर्ट तैयार करें।

9.7 पंजाब का औद्योगिक विकास (Industrial Development of Punjab)

देश के विभाजन और बाद में राज्य के पुनर्गठन का पंजाब के औद्योगिक विकास पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। लेकिन, उसके बाद पंजाब में उद्योगों को विकसित करने के लिए सरकारों द्वारा कई प्रयास किए गए। परिणाम स्वरूप, आजकल बहुत सारे उद्योग काफी विकसित हुए हैं परन्तु फिर भी उनको और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है।

वर्ष 2020-21 (आधार वर्ष, 2011-12) के दौरान, औद्योगिक उत्पादन का सचूकांक 112 था अर्थात्, 2011-12 की तुलना में 2020-21 में औद्योगिक उत्पादन में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 में पंजाब में संचालित पंजीकृत कंपनियों की संख्या 19814 थी और उनमें लगभग 746731 श्रमिक कार्यरत थे।

सारणी 9.5

पंजाब के लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों के बारे में बुनियादी जानकारी (वर्ष 2019-20)

उद्योगों के प्रकार	कुल इकाइयां	पूँजीगत निवेश (करोड़ रूपए में)	रोज़गार	उत्पादन शक्ति (करोड़ रूपए में)
लघु उद्योग	337 955	36821.29	2146649	150458.97
मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योग	590	83085.93	291816	165684.79

स्त्रोत : पंजाब का सांख्यिकीय सार, 2021

9.8 पंजाब के उद्योग (Industries of Punjab)

पंजाब के उद्योगों को दो श्रेणियों में विभाजित करके वर्णित किया जा सकता है (क) लघु उद्योग (ख) मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योग। इनका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है।

सारणी 9.6 पंजाब के प्रमुख लघु उद्योग और उनका स्थापना स्थान

उद्योग	स्थापित केंद्र
हौज़री उद्योग	लुधियाना
मोटर गाड़ी उद्योग	लुधियाना, पटियाला
कलपुर्जों का उद्योग	जालंधर, कपूरथला
साइकिल व इसके कल पुर्जों का उद्योग	लुधियाना
सिलाई मशीन और इसके कलपुर्जों का उद्योग	लुधियाना, अमृतसर, बटाला
खेलों के समान का उद्योग	जालंधर, बटाला
चमड़ा उद्योग	जालंधर
फर्नीचर उद्योग	करतारपुर
डेयरी उत्पाद उद्योग	अमृतसर, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, पटियाला

स्त्रोत : पंजाब राज्य उद्योगिक विकास निगम

सारणी 9.7 पंजाब के प्रमुख मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योग उनके स्थापना केन्द्र

उद्योग	स्थापना केन्द्र
चीनी उद्योग	कपूरथला, जालंधर, संगरूर, गुरदासपुर, रूपनगर, होशियारपुर
वस्त्र उद्योग	अमृतसर, धारीवाल, फगवाड़ा
ट्रैक्टर उद्योग	अमृतसर, होशियारपुर
कागज उद्योग	अमृतसर, होशियारपुर
उर्वरक उद्योग	बठिंडा, नंगल
लोहा उद्योग	मंडी गोबिन्दगढ़

स्रोत : पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम

उपरोक्त सारणियों 9.6 एवं 9.7 से मालूम होता है कि पंजाब में औद्योगिक विकास के विषय में क्षेत्रीय असमानता पायी जाती है अर्थात् समस्त पंजाब में उद्योगों का विकास समान रूप से नहीं हुआ है तथा अधिकांश उद्योग लुधियाना, जालंधर, अमृतसर आदि नगरों में ही स्थित है, जबकि शेष जिलों में औद्योगिक विकास अत्यंत कम दर से हुआ है।

9.9 पंजाब में औद्योगीकरण की आवश्यकता (Need for Industrialization in Punjab)

औद्योगिक विकास की दृष्टि से पंजाब अभी तक विकसित राज्य नहीं बना है। इसका मुख्य कारण समय के साथ राज्य द्वारा अपनाए गए असंतुलित दृष्टिकोण को माना जा सकता है। इसके अलावा खनिज और प्राकृतिक संसाधनों की कमी ने भी इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास की गति धीमी करने में योगदान दिया है। पंजाब में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास की काफी संभावनाएं हैं। पंजाब में औद्योगीकरण की आवश्यकता निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होती है।

अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास : विकास प्रक्रिया के दौरान अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। जिससे कृषि के विकास में औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया में उद्योग, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक मशीनरी, उर्वरक इत्यादि आदान-प्रदान करते हैं। इससे अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास किया जा सकता है।

रोज़गार का सृजन : पंजाब वर्तमान समय में रोज़गार के मौकों की भारी कमी का सामना कर रहा है। जिसके कारण राज्य के युवाओं का एक बड़ा वर्ग बेहतर रोज़गारों की तलाश में देश से बाहर जा रहा है। पंजाब में उद्योगों का विकास करके रोज़गार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं और 'प्रतिभा पलायन' की समस्या से

गतिविधि

- क्या पंजाब में बड़े स्तर के उद्योगों के विकास की संभावनाएं कम हैं या न के समान हैं ? अपने अध्यापक महोदय के साथ इस विषय पर चर्चा करें।
- अपने क्षेत्र के किसी उद्योग इकाई में जाएं तथा एक अनुरूप रिपोर्ट तैयार करें।

निपटा जा सकता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र के विकास से भी कृषि क्षेत्र में फैली बेरोज़गारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

सरकारी राजस्व में वृद्धि : राज्य में औद्योगिक विकास सरकार के लिए राजस्व सृजन में मदद कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उद्योगों की स्थापना से सरकार विभिन्न प्रकार के कर, शुल्क इत्यादि प्राप्त कर सकती है। सरकार के इस बड़े हुए राजस्व का उपयोग, विकासात्मक गतिविधियों के लिये किया जा सकता है।

जीवन स्तर में सुधार : पंजाब में औद्योगिक-विकास के कारण लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी।

व्यापार में वृद्धि : पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है। पंजाब में लघु और मध्यम-उद्योगों के विकास से औद्योगिक-उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी। यह तैयार वस्तुओं के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय-व्यापार को बढ़ाएगा।

9.10 पंजाब में औद्योगीकरण की राह में कठिनाईयाँ (Difficulties in the way of Industrialization in Punjab)

पंजाब में औद्योगिक विकास की दर संतोषजनक नहीं है। इसलिए इसके पीछे के कारणों को जानना बेहद जरूरी है। इनका वर्णन इस प्रकार है -

बिजली के संसाधनों की कमी : पंजाब में बिजली के संसाधनों, जैसे :- बिजली, पेट्रोलियम और कोयला आदि की भारी कमी है। लंबे समय तक बिजली कटौती की जाती है। इसलिए औद्योगिक विकास कोई आसान काम नहीं है।

खनिजों की कमी : पंजाब में खनिजों की पूरी तरह से कमी है। यहां खनिजों के नाम पर बजरी ही पाई जाती है। खनिजों के अभाव में औद्योगिक विकास सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

सरकार के पास वित्त की कमी : उद्योगों की स्थापना के लिए, भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। लेकिन, पंजाब सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की कमी है। इससे सरकार प्रदेश में और उद्योग नहीं लगा पा रही है।

एक सीमावर्ती राज्य : पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है। इसलिए हमेशा युद्ध का भय बना रहता है और उद्यमी पंजाब में उद्योग लगाने में विशेष रुचि नहीं दिखाते।

उच्च कराधान : अन्य राज्यों की तुलना में पंजाब में कर की दर अधिक है। जिससे उद्यमी उद्योग लगाने के लिए आगे आने से कतरा रहे हैं। एक ओर नए उद्यमी राज्य में अपना उद्योग स्थापित करने के लिए तैयार नहीं है और दूसरी ओर जो उद्यमी हैं वो भी अपने उद्योग राज्य से बाहर लेकर जा रहे हैं।

क्षेत्रीय असमानता : पंजाब में अधिकांश-उद्योग, कुछ जिलों, जैसे : लुधियाना, अमृतसर, जालंधर आदि में स्थित हैं। लेकिन, इसके अन्य जिलों में, विनिर्माण ईकाइयों का अभाव है। परिणामस्वरूप, पंजाब को औद्योगिक-विकास में क्षेत्रीय विषमता की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

कुशल श्रमिकों की कमी : पंजाब में उद्योगों में कार्यरत अधिकांश श्रमिक कृषि क्षेत्र से आते हैं। उनके पास उद्योगों में काम करने के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताओं की कमी है। इस प्रकार वे राज्य के औद्योगिक विकास में योगदान करने में सक्षम नहीं हैं।

2.11 पंजाब में उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

(Steps taken by Government to Develop Industries in Punjab)

हाल के ही वर्षों में पंजाब में विभिन्न छोटे, अर्ध – मध्यम, मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योग विकसित हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा, समय – समय पर औद्योगिक नीतियां बनाई गई हैं। पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन इस प्रकार है :-

1. राज्य वित्तीय निगम : इसकी स्थापना पंजाब सरकार द्वारा 1953 में की गई थी। इसका उद्देश्य नए उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों के विकास, दोनों के लिए काम करना है। इसका मुख्य उद्देश्य पंजाब में निर्माण क्षेत्र का विकास करना, उन्हें आधुनिक बनाना और उनमें विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसलिए यह औद्योगिक इकाइयों को मध्यम और दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है।

2. पंजाब राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम : इसकी स्थापना पंजाब सरकार द्वारा 1962 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य पंजाब में लघु उद्योगों की स्थापना करना, उनकी समस्याओं को हल करना और उनको उनके उत्पादों के निर्यात में मदद करना है। यह निगम लघु उद्योगों को बचे माल की सुविधा, विपणन की सुविधा, तकनीकी सलाह और प्रशिक्षण प्रदान करता है और उनके उत्पादन के निर्यात में मदद करता है।

3. पंजाब राज्य औद्योगिकविकास निगम : इसकी स्थापना पंजाब सरकार द्वारा 1966 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के उद्योगों अर्थात् छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों का विकास करना है। इन उद्योगों की स्थापना के लिए यह निगम ऋण प्रदान करता है तथा अन्य संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में भी सहायता करता है।

4. पंजाब सूचना और प्रौद्योगिकी विकास निगम : इसकी स्थापना पंजाब सरकार द्वारा 1976 में की गई थी और पहले इसे पंजाब राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास और उत्पाद निगम लिमिटेड कहा जाता था। वर्ष 2002 में इसका नाम बदल कर पंजाब सूचना और प्रौद्योगिकी विकास निगम रखा गया। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसका उद्देश्य पंजाब को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। यह इसलिए है क्योंकि वर्तमान समय को सूचना व तकनीक के समय के तौर पर जाना जाता है और कोई भी राज्य सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के बिना अपने निर्माण क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता।

5. फोकल प्वाइंट्स की स्थापना : इन्हें 1977 में पंजाब सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इनका उद्देश्य औद्योगिक विकास के मामले में पंजाब में पाई जाने वाली क्षेत्रीय असमानता को दूर करना, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करना, छोटे और मध्यम उद्योगों की स्थापना और विकास में मदद करना है।

गतिविधि

- क्या पंजाब सरकार द्वारा उद्योगों के विकास के लिये स्थापित भिन्न-भिन्न संस्थाएं अपना कार्य समुचित रूप से कर रही हैं ? इस विषय पर कक्षा में भाषण-प्रतियोगिता करवाएं।
- क्या पंजाब सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयासों के कारण पंजाब में उद्योग सम्बन्धी समस्याओं का निदान हो रहा है ? इस विषय पर अपनी कक्षा में एक वाद-विवाद प्रतियोगिता करवाएं।
- पंजाब में उद्योगों के विकास के लिए और क्या उपाय किये जा सकते हैं ? इस विषय पर एक 'परियोजना' तैयार कीजिए।

6. पंजाब कृषि-औद्योगिक निगम : इसकी स्थापना 1966 में पंजाब सरकार द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पंजाब में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना करना है जो कृषि उत्पादों को कच्चे – माल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यह निगम विभिन्न उद्योगों जैसे कि मेगा फूड पार्क, कृषि आधारित उद्योगों, प्रोसेसिंग इकाइयों, डेयरी उद्योग, पोलट्री उद्योग आदि की स्थापना में मदद करता है।

7. औद्योगिक सहायक एक खिड़की व्यवस्था : यह पंजाब में औद्योगिक – विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। यह उद्यमियों को उनकी सभी समस्याओं को एक ही स्थान पर हल करने में मदद करता है। इसमें उद्यमियों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे लाइसेंस प्रदान करना, बिजली की व्यवस्था करना, तकनीकी सहायता प्रदान करना आदि।

8. अन्य उपाय : इसके अलावा कई अन्य औद्योगिक विकास संगठन जैसे पंजाब स्टेट हैंडमूल एंड टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, पंजाब स्टेट हौजरी एंड निटवेअर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, पंजाब स्टेट लेदर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आदि को शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही, बिजली और परिवहन सुविधाओं के विकास कराधान प्रणाली में सुधार, निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने आदि की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि पंजाब सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों से किए जा रहे प्रयासों के कारण औद्योगिक क्षेत्र में निवेश की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इसलिए उम्मीद की जाती है कि निकट भविष्य में पंजाब में उद्योगों का तेज दर से विकास होगा।

पुनरावृत्ति (RECAP)

- AGRICULTURE शब्द दो लातीनी शब्दों AGRI और CULTURE से मिलकर बना है यहां AGRI का अर्थ है 'भूमि' और CULTURE का अर्थ है 'खेती'। इसलिए कृषि का अर्थ फसल उगाने के लिए भूमि पर जुताई करना और अन्य संबंधित गतिविधियों में संलग्न होना है।
- वर्ष 2019 – 20 में पंजाब ने भारत के कुल अनाज भंडार में 37.8 प्रतिशत गेहूं और 20.9 प्रतिशत धान का योगदान दिया।
- वर्ष 2019-20 में पंजाब ने कुल 308 लाख टन फसलों का उत्पादन किया और भारत के कुल कृषि उत्पादन में पंजाब का योगदान 12 प्रतिशत था।
- वर्ष 2020-21 में पंजाब के कुल घरेलू उत्पाद (जी. डी. पी) (स्थिर मूल्यों पर) में कृषि का योगदान 14.66 प्रतिशत रहा है।
- पनग्रेन, भारतीय खाद्य निगम, मार्कफेड, पंजाब स्टेट वेयरहाउस, कॉर्पोरेशन, पंजाब एग्रो हाउस कॉर्पोरेशन आदि पंजाब में कृषि विपणन में शामिल हैं।
- वर्ष 2019-20 में पंजाब में सिंचाई सुविधाओं के तहत, कुल 40.74 लाख हेक्टेयर बोया गया क्षेत्र था जो शुद्ध बुवाई क्षेत्र का 98.9 प्रतिशत था।
- वर्ष 2020-21 (आधार वर्ष 2011-12) के दौरान, औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक 112 था।
- वर्ष 2019 में पंजाब में संचालित पंजीकृत कंपनियों की संख्या 19814 थी और उन्होंने औसतन 746731 श्रमिकों को रोजगार दिया।
- पंजाब में औद्योगिक विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय असमानताएँ पायी जाती हैं।

- (v) गेहूँ एक फसल है। (रबी/खरीफ)
- (vi) लुधियाना वस्तुएं बनाने के लिए सबसे लोकप्रिय है। (कपड़ा/हौज़री)
- (vii) कपड़ा उद्योग जिले में सर्वाधिक लोकप्रिय है। (अमृतसर /बटाला)
- (viii) पंजाब सरकार उद्योगों का विकास करने के लिए है। (उदासीन /प्रयत्नशील)
- (ix) पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना में हुई थी। (1953/1966)

3. सही / गलत उत्तर वाले प्रश्न (True or False)

- (i) पंजाब को भारत का चीनी का भंडार कहा जाता है।
- (ii) पंजाब में कृषि क्षेत्र में कुल कार्यकारी जनसंख्या का भाग पहले से कम हो रहा है।
- (iii) पंजाब के सकल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है ?
- (iv) सीमांत खेतों पर काम करने से लागत कम आती है।
- (v) चावल खरीफ की फसल है।
- (vi) पंजाब में नंगल में उर्वरक इकाइयां पाई जाती हैं।
- (vii) डेयरी उत्पादों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योगों में शामिल किया जाता है।
- (viii) उद्योगों के विकास से कृषि क्षेत्र के विकास में सहायता मिलती है।
- (ix) पंजाब में कुशल श्रमिकों की कमी पाई जाती है।
- (x) पंजाब में फोकल पॉइंट 1975 में स्थापित किए गए थे।

4. अति लघु उत्तर वाले प्रश्न (एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर) (Very Short Answer Type Questions)

- (i) कृषि उत्पादन और कृषि उत्पादकता में क्या अंतर है?
- (ii) खाद्य फसले और व्यापारिक फसले क्या है ?
- (iii) रबी और खरीफ की फसलों की उदाहरण प्रदान करें।
- (iv) पंजाब की कृषि को आधुनिक कृषि क्यों कहा जाता है?
- (v) कृषि विपणन से क्या अभिप्राय है ?
- (vi) हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है ?
- (vii) मोनोकल्चर कृषि प्रबंध से क्या अभिप्राय है ?

- (viii) छुपी हुई बेरोज़गारी से क्या भाव है ? यह कौन से क्षेत्र में मिलती है ?
- (ix) क्षेत्रीय असमानता से क्या अभिप्राय है ?
- (x) पंजाब के लघु मध्यम और बड़े उद्योगों की उदाहरण दें ।
- (xi) कौन से उद्योगों को हौज़री उद्योग कहा जाता है ?
- (xii) शक्ति के संसाधनों से क्या भाव है ?
- (xiii) एक खिड़की व्यवस्था से क्या भाव है ?
- (xiv) फोकल प्वाइंट से क्या भाव है ?
- (xv) पंजाब के औद्योगिक विकास द्वारा लोगों का जीव स्तर कैसे ऊँचा किया जा सकता है ?
- (xvi) पंजाब में उद्योगों में काम करने के लिए कुशल श्रमिकों की कमी क्यों है ?

5. मिलान करें (Match the Following)

(i) दोनों कॉलम में दिए गए तथ्यों का मिलान कीजिए ।

जोतों की प्रकार

क्षेत्रफल

सीमांत

10 हेक्टेयर से अधिक

अर्ध-मध्यम

1 हेक्टेयर से कम

मध्यम

2-4 हेक्टेयर

बड़ा

4-10 हेक्टेयर

(ii) दोनों कॉलम में दिए गए तथ्यों का मिलान कीजिए

उद्योग

स्थान

साइकिल

करतारपुर

चमड़ा

लुधियाना

फर्नीचर

जालंधर

(iii) दोनों कॉलम में दिए गए तथ्यों का मिलान कीजिए ।

निगम

स्थापना का वर्ष

पंजाब वित्तीय निगम

1996

पंजाब कृषि औद्योगिक निगम

1953

पंजाब राज्य लघु उद्योग और निर्यात

1962

6. मध्य उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा 60-70 शब्द) (Short Answer Type Questions)

- (i) जलवायु के आधार पर पंजाब की प्रमुख फसलों का वर्णन करें।
- (ii) फसलों के प्रकार के आधार पर पंजाब की प्रमुख फसलों का वर्णन करें।
- (iii) पंजाब में कृषि विपणन के महत्व में वृद्धि के क्या कारण हैं ?
- (iv) पंजाब में कृषि विपणन संबंधी कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ?
- (v) पंजाब में औद्योगिक विकास पर निबंध लिखें
- (vi) पंजाब के औद्योगिक विकास में कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ?
- (vii) पंजाब में बड़े उद्योगों के विकास के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए ?

7. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (150-200 शब्द) (Long Answer Type Questions)

- (i) पंजाब की कृषि प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें।
- (ii) पंजाब में हरित क्रांति के प्रमुख कारणों की व्याख्या करें।
- (iii) पंजाब में हरित क्रांति की सफलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
- (iv) पंजाब में औद्योगीकरण की आवश्यकता का वर्णन करें।
- (v) पंजाब सरकार द्वारा उद्योगों के विकास के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या करें।

References

- Abellanosa, A.L., and H.M. Pava (1987). "Introduction to Crop Science", Central Mindanao University, Musuan, Bukidnon: Publications Office. p. 238
- Handbook of Statistics on Indian Economy (2020). "Reserve Bank of India Publication", Available at <https://www.rbi.org.in/scripts/AnnualPublications.aspx?head=Handbook of Statistics on Indian Economy>.
- Handbook of Statistics on Indian Economy (2021). "Reserve Bank of India Publication", Available at <https://www.rbi.org.in/scripts/AnnualPublications.aspx?head=Handbook 20 of 20 Statistics 20 on 20 Indian 20Economy>
- GoP (2020). Statistical Abstract of Punjab. "Economic and Statistical Organization", Department of Planning, Government of Punjab, Publication No. 962

- GoP (2021). Statistical Abstract of Punjab. “Economic and Statistical Organization”, Department of Planning, Government of Punjab, Publication No. 964



10

पंजाब की वित्तीय स्थिति

इस अध्याय को पढ़ने का बाद आप

- पंजाब सरकार के राजस्व और व्यय के विभिन्न स्रोतों को समझने में सक्षम होंगे;
- राज्य की आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका को पहचानेंगे;
- राज्य से संबंधित वित्तीय मुद्दों के प्रबंधन से अवगत होंगे।

अध्याय – 10

पंजाब की वित्तीय स्थिति

10.1 परिचय (Introduction)

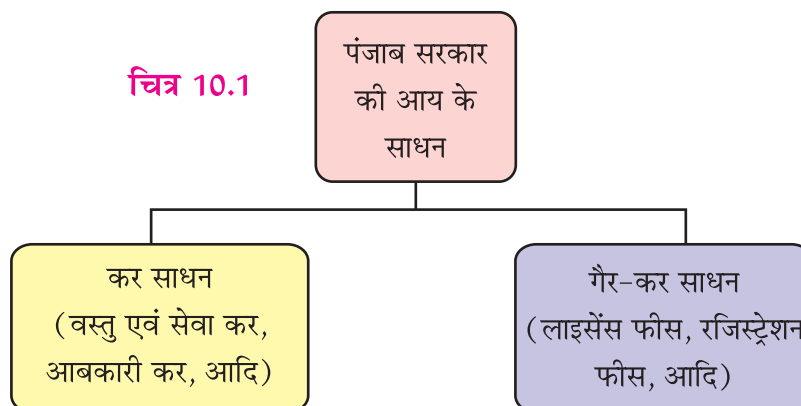
सरकार की वित्तीय प्रणाली का अर्थ उस प्रणाली से होता है जिसके द्वारा सरकार अपना राजस्व पैदा करती है और अपना व्यय करती है। सामान्यतः इसका अर्थ सरकार के बजट से है। किसी सरकार का बजट सरकार के सभी अपेक्षित आर्थिक लेनदेन का वार्षिक विवरण है, यानि इसके अपेक्षित राजस्व और इसके अपेक्षित व्यय। वर्तमान संदर्भ में 'अपेक्षित' शब्द का उपयोग किया जाता है क्योंकि बजट आने वाले वर्ष के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा तैयार किया जाता है। सरकार आने वाले साल में अपने राजस्व और व्यय को लेकर आश्वस्त नहीं होती हैं और वह इन दोनों के बारे में केवल अनुमान ही लगाती है। सरकारी बजट में पिछले साल के सरकार के राजस्व और व्यय का ब्यौरा भी होता है, लेकिन इस हिस्से को बहुत कम महत्व दिया जाता है।

सरकार के लिए बजट तैयार करना आवश्यक है, ताकि उसे इस बात का अंदाजा हो कि आने वाले वर्ष में उसका राजस्व और व्यय क्या होना चाहिए ताकि वह उसके अनुसार कल्याण और विकास-कार्यक्रमों की योजना बना सके।

इस अध्याय में हम पंजाब सरकार के राजस्व के विभिन्न स्रोतों और व्यय की मदों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें यह भी पता चलेगा कि सरकार अपनी राजकोशी नीति के साथ आर्थिक विकास में सुधार करके अपने लोगों के कल्याण का ध्यान कैसे रखती है ?

10.2 पंजाब सरकार के राजस्व के स्रोत (Sources of Revenue of Punjab Government)

किसी भी देश या राज्य की सरकार दो स्रोतों से अपना राजस्व प्राप्त करती है जैसे, कर-स्रोत और गैर-कर स्रोत। इन्हें निम्ननुसार समझाया गया है :



10.2.1 कर साधन (Tax Sources)

सरकार अपने लोगों पर वस्तु एवं सेवा कर, आयकर, उत्पाद-शुल्क, मनोरंजन कर आदि विभिन्न प्रकार के कर लगाती है, जिनका भुगतान जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करना पड़ता है। कर सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत हैं। वर्ष 2020-21 में पंजाब सरकार का कुल कर राजस्व 72042.42 करोड़ रुपये था जो बजट 2021-22 (पंजाब का सांख्यिकीय सार, 2021) के दौरान बढ़कर 95257.60 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पंजाब सरकार जिन करों से अपना राजस्व प्राप्त करती है उन्हें निम्नानुसार वर्णित किया गया है :

केंद्र सरकार के करों से हिस्सा : पंजाब सरकार केंद्र सरकार से विभिन्न करों का अपना हिस्सा प्राप्त करती है। ये कर केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त किए जाते हैं लेकिन, इनमें से एक हिस्सा पंजाब सरकार को प्रदान करवाया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार से पंजाब सरकार को प्राप्त करों में प्राप्त हिस्सा 9833.61 करोड़ रुपये रहा, जो उसके कुल राजस्व का 13.65 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 के दौरान पंजाब सरकार को केन्द्र से करों के हिस्से के रूप में 12026.71 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर : यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो किसी भी वस्तु या सेवा की खरीद पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा देय है। वर्तमान में, यह पंजाब सरकार के लिए राजस्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्ष 2020-21 के दौरान पंजाब सरकार को राज्य वस्तु एवं सेवा कर से 11522.30 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ जो उसके कुल राजस्व का 15.99 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 के दौरान पंजाब सरकार को इस कर से 16,000 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है।

मूल्य वृद्धि कर : यह भी एक अप्रत्यक्ष कर है जो पंजाब सरकार द्वारा वस्तुओं की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान पंजाब सरकार को मूल्य वृद्धि कर से 5470.73 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ जो उसके कुल राजस्व का 7.97 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 के दौरान पंजाब सरकार को इस कर से 6027.76 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।

राज्य उत्पाद शुल्क : राज्य उत्पाद शुल्क पंजाब सरकार द्वारा शराब, पेट्रोलियम, तंबाकू आदि पर लगाया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान पंजाब सरकार को उत्पाद कर से 5794.93 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ जो उसके कुल राजस्व का 8.04 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 के दौरान पंजाब सरकार को इस कर से 7002.53 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

वस्तु एवं सेवा कर को वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यह कर वास्तव में मूल्य-वृद्धि-कर (VAT) की तरह है लेकिन, यह मूल्य वृद्धि कर की तुलना में अधिक व्यापक है। मूल्य वृद्धि कर केवल वस्तुओं पर लागू था। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह कर वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं पर भी लागू होता है। सरकार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के स्वभाव अनुसार, इस कर को अलग-अलग वस्तुओं पर अलग-अलग दर जैसे कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28% निर्धारित करती है।

वाहनों पर टैक्स : जब भी लोगों द्वारा कोई दोपहिया या चार पहिया वाहन खरीदा जाता है तो यह कर पंजाब सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान पंजाब सरकार को इस कर से 1567.94 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ जो उसके कुल राजस्व का 2.18 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 के दौरान पंजाब सरकार को इस कर से 2200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।

बिजली कर : जैसा कि हम जानते हैं कि पंजाब में बिजली, पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) द्वारा प्रदान की जाती है। अतः जब पंजाब सरकार लोगों को घरेलू अथवा व्यापारिक उद्देश्यों के लिए बिजली प्रदान करती है तो उसके द्वारा यह कर वसूला जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान पंजाब सरकार को इस कर से 2894.51 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ जो उसके कुल राजस्व का 4.02 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 के दौरान पंजाब सरकार को इस दर से 3026.01 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

भूमि कर : जैसा कि नाम से पता चलता है यह कर किसानों पर उनकी भूमि के आकार के अनुसार लगाया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान पंजाब सरकार को इस कर से 65.09 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ जो उसके कुल राजस्व का 0.09 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 के दौरान पंजाब सरकार को इस कर से 87.43 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।

अन्य कर : वर्ष 2019-20 के दौरान पंजाब सरकार को अन्य करों जैसे कि मनोरंजन कर, विलासिता कर आदि से 9.01 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। जो उसके कुल राजस्व का 0.01 प्रतिशत था।

यह गतिविधि करें

- पंजाब सरकार को वर्ष 2017-18 से लेकर, वर्ष 2020-21 तक वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य वृद्धि कर से प्राप्त राजस्व की जानकारी एकत्र करें।
- वस्तु और सेवा कर तथा मूल्य वृद्धि करके बीच क्या अंतर है? अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें।

10.2.2 गैर-कर साधन (Non-Tax Sources)

सरकार न केवल कर स्रोतों से बल्कि विभिन्न प्रकार के गैर-कर स्रोतों से भी अपना राजस्व प्राप्त करती है। इनमें मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शुल्क, जुर्माना, आदि शामिल हैं। इन गैर-कर स्रोतों से पंजाब सरकार को प्राप्त कुल राजस्व वर्ष 2020-21 में 4632.88 करोड़ रुपये था जो 2021-22 के बजट (पंजाब का सांख्यिकीय सार, 2021) के दौरान बढ़कर 7758.48 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पंजाब सरकार की इन गैर-कर प्राप्तियों को निम्नानुसार वर्णित किया गया है।

पंजाब रोडवेज : पंजाब रोडवेज, पंजाब के लोगों को परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्रमुख संस्था है। वर्ष 2020-21 के दौरान पंजाब सरकार को इससे 114.23 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो उसके कुल राजस्व का 0.16 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 के दौरान पंजाब सरकार को इस स्रोत से 250 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।

विविध सामान्य सेवाएं : पंजाब सरकार अपने लोगों को विभिन्न सामान्य सेवाएं प्रदान करती है। जैसे : पुलिस, मुद्रण, स्टेशनरी, लॉटरी, आदि। वर्ष 2020-21 के दौरान पंजाब सरकार को इससे 2850.25 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ जो उसके कुल राजस्व का 3.95 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 के दौरान पंजाब सरकार को इस स्रोत से 5533.58 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।

ब्याज प्राप्तियां : पंजाब सरकार द्वारा विभिन्न संस्थानों को ऋण दिए जाते हैं जिन पर वह ब्याज के रूप में राजस्व प्राप्त करती है। वर्ष 2020-21 के दौरान पंजाब सरकार को इससे 121.64 करोड़ रुपये का राजस्व का 0.17 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 के दौरान पंजाब सरकार को इस स्रोत से 250.03 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।

अन्य गैर-कर प्राप्तियां : उपरोक्त करों के अलावा, पंजाब सरकार के पास गैर-कर राजस्व के कई अन्य स्रोत हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के लाभ, लाभांश, आर्थिक सेवाओं से आय आदि शामिल हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान पंजाब सरकार को इनसे 1546.76 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ जो इसके राजस्व का 2.15 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 के दौरान पंजाब सरकार को इस स्रोत से 1724.87 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।

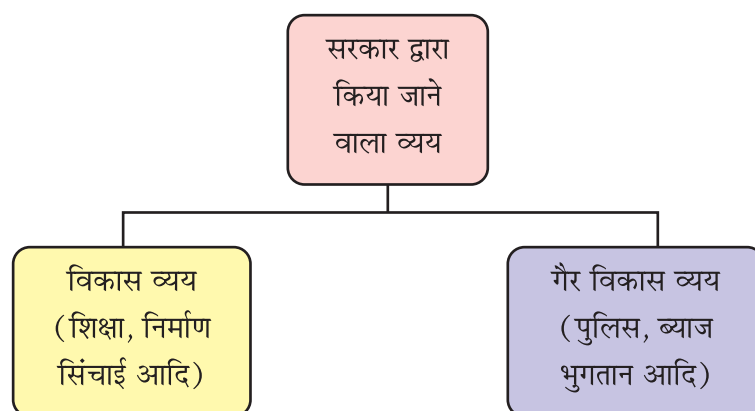
चलो यह करते हैं

- आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे कर हैं, जिनका अधिक हिस्सा है और कुछ अन्य करों का सरकार के राजस्व में एक छोटा सा हिस्सा है। उदाहरण के लिए, शराब की बिक्री, राज्य के राजस्व का है। क्या राजस्व प्राप्त करने के अन्य तरीके हैं? चर्चा करें।
- पंजाब रोजवेज पिछले कई सालों से घाटे में चल रहा है। क्या आपको लगता है कि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली हर सेवा को लाभ अर्जित करना चाहिए? अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें।

10.3 सरकार के खर्च की मदें (Items of Expenditure of the Government)

जिस तरह सरकार को अलग-अलग स्रोतों से अपना राजस्व प्राप्त होता है उसी तरह वह अलग-अलग मदों पर भी अपना पैसा खर्च करती है। पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल 92772.30 करोड़ रुपये खर्च

चित्र 10.2



किए गए जो वर्ष 2021-22 के दौरान 103979.91 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पंजाब सरकार द्वारा किए गए खर्च को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिन्हें चित्र 10.2 में दिखाया गया है।

10.3.1 पंजाब सरकार का विकासात्मक व्यय (Developmental Expenditure of Punjab Government)

एक राज्य द्वारा किए गए विकासात्मक व्यय उसके विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जब भी यह व्यय सरकार द्वारा किया जाता है आर्थिक और सामाजिक विकास में सुधार होता है। पंजाब सरकार द्वारा किए गए विकासात्मक व्यय को निम्नानुसार वर्णित किया गया है :

ऊर्जा पर व्यय : पंजाब सरकार विभिन्न क्षेत्रों जैसे : कृषि, उद्योग और सेवा के विकास के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए व्यय करती है। वर्ष 2020-21 में पंजाब सरकार ने ऊर्जा पर 2202.94 करोड़ रुपये खर्च किए, जो उसके कुल खर्च का 2.38 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 के दौरान पंजाब सरकार इस पर 1512.88 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है।

लोक निर्माण : पंजाब सरकार द्वारा विभिन्न सार्वजनिक कार्य किए जाते हैं। इनका उद्देश्य लोगों के कल्याण को बढ़ाने और उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करवाना होता है। इसमें सड़कों, पार्कों, स्कूलों, अस्पतालों आदि के निर्माण कर किया गया खर्च शामिल हैं। वर्ष 2020-21 में पंजाब सरकार ने इस पर 586.50 करोड़ रुपये खर्च किए जो उसके कुल खर्च का 0.63 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 के दौरान पंजाब सरकार द्वारा इस पर 422.23 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है।

शिक्षा : पंजाब सरकार सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के कर्मचारियों के वेतन के रूप में इन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति आदि पर खर्च करती है। वर्ष 2020-21 में पंजाब सरकार ने इस पर 12133.23 करोड़ रुपये खर्च किए, जो उसके कुल खर्च का 13.08 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 के दौरान पंजाब सरकार द्वारा इस व्यय-मद में 12636.20 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है।

चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य : पंजाब सरकार लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों आदि पर खर्च करती है। वर्ष 2020-21 में पंजाब सरकार ने इस पर 3686.29 करोड़ रुपये खर्च किए जो उसके कुल खर्च का 3.97 प्रतिशत था। वर्ष 2021-23 के दौरान पंजाब सरकार द्वारा इस पर 3821.22 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है।

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण : पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और इसके कृषि विकास के लिए किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करना और खराब मौसम की स्थिति में बाढ़ को नियंत्रित करना आवश्यक है। वर्ष 2020-21 में पंजाब सरकार ने इस पर 1063.33 करोड़ रुपये खर्च किए जो उसके कुल खर्च का 1.15 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 के दौरान पंजाब सरकार द्वारा इस पर 1114.96 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है।

कृषि और उससे संबंधित गतिविधियाँ : पंजाब सरकार, राज्य में कृषि को विकसित करने के लिए किसानों को बीज, उर्वरक (खाद), कीटनाशक, उपकरण आदि प्रदान करती है और पशु अस्पताल आदि चलाती है। वर्ष 2020-21 में पंजाब सरकार ने इस पर 9879.20 करोड़ रुपये खर्च किए जो उसके कुल खर्च का 10.65 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 के दौरान पंजाब सरकार द्वारा इस पर 12465.19 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है।

सड़क परिवहन : पंजाब सरकार सड़क निर्माण पर खर्च करती है। इसके अलावा, सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए भी पैसा खर्च किया जाता है। वर्ष 2020-21 में पंजाब सरकार ने इस पर 568.78 करोड़ रुपये खर्च किए जो उसके कुल खर्च का 0.61 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 के दौरान पंजाब सरकार द्वारा इस पर 323.72 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है।

औद्योगिक और खनिज संसाधन : पंजाब सरकार राज्य में उद्योगों के विकास और खनिजों के खनन पर खर्च करती है। वर्ष 2020-21 में पंजाब सरकार ने इस पर 2132.74 करोड़ खर्च किए जो उसके कुल खर्च का 2.30 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 के दौरान पंजाब सरकार द्वारा इस पर 2115.65 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है।

10.3.2 पंजाब सरकार का गैर-विकासात्मक व्यय (Non-Developmental Expenditure of Punjab Government)

गैर विकासात्मक व्यय का अर्थ है, वह खर्च जिसका किसी राज्य या देश के विकास पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो। फिर भी अपने नागरिकों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है और उसे ये खर्च उठाने पड़ते हैं और कोई भी सरकार इन्हें नजर अंदाज नहीं कर सकती। पंजाब सरकार द्वारा किए गए प्रमुख गैर-विकासात्मक व्यय को निम्नानुसार वर्णित किया गया है :

ब्याज भुगतान : पंजाब सरकार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों से उधार लेती है, जिसके लिए, उसे हर साल, ब्याज भुगतान करना पड़ता है। वर्ष 2020-21 में पंजाब सरकार ने इस पर 19,513.81 करोड़ रुपये खर्च किए जो उसके कुल खर्च का 21.03 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 के दौरान पंजाब सरकार द्वारा इस पर 21240.52 करोड़ रुपये खर्च करने की उम्मीद है।

पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति सम्बन्धी लाभ : पंजाब सरकार के कर्मचारियों को उनकी सेवा और सेवानिवृत्ति के बाद, सरकार द्वारा विभिन्न लाभों का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2020-21 में पंजाब सरकार ने इस पर 13000 करोड़ रुपये व्यय किए जो उसके कुल व्यय का 14.01 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 के दौरान पंजाब सरकार द्वारा 11767 करोड़ रुपये व्यय करने का अनुमान है।

सुरक्षा : पंजाब सरकार प्रांत में प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। उदाहरण स्वरूप सरकार द्वारा लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स तैनात की जाती है। साल 2020-21 में सरकार ने इस पर 6208.01 करोड़ रूपए खर्च किए जो इसके कुल व्यय का 6.69 प्रतिशत था। साल 2021 - 22 के दौरान पंजाब सरकार द्वारा इस पर 6735.78 करोड़ रूपए खर्च किए जाने का अनुमान है।

अनुदान आदि का भुगतान : पंजाब सरकार द्वारा विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अनुदान

आओ, यह गतिविधि करें

- विद्यार्थियों को दिए जाने वाले वजीफे क्या विकासात्मक खर्च है।
- अपनी कक्षा में विचार चर्चा करें। अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस अति महत्वपूर्ण है। लेकिन पंजाब पुलिस पर किए जाने वाले खर्च को गैर-विकासात्मक खर्च को श्रेणी में क्यों रखा जाता है ? अपनी कक्षा में चर्चा कीजिये।

दिए जाते हैं। वर्ष 2020-21 में पंजाब सरकार ने इस पर 6717.06 करोड़ रुपये व्यय किए जो उसके कुल व्यय का 7.24 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 के दौरान, पंजाब सरकार द्वारा 4058.54 करोड़ रुपये व्यय करने का अनुमान है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अपनी बजट निर्माण-प्रक्रिया के दौरान पंजाब सरकार अपनी राजस्व मदों और इसकी व्यय-मदों का विस्तृत लेखा-जोखा तैयार करती है जो अपनी आर्थिक नीतियों और प्राथमिकताओं का प्रकट करता है।

10.4 पंजाब सरकार की समग्र बजट स्थिति (Overall Budgetary Position of Punjab Government)

पंजाब सरकार की समग्र बजट स्थिति से भाव इसकी सम्पूर्ण प्राप्तियों एवं सम्पूर्ण व्यय के इक्वेटे लेखे से है।

सारणी 10.1 पंजाब सरकार के बजट की समग्र स्थिति (रकम करोड़ में)

मद	वर्ष			
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (P)
1. राजस्व लेखा				
(i) प्राप्तियां	62269.08	61574.75	72042.41	95257.60
(ii) व्यय	75403.71	75859.64	92772.30	103879.91
शेष (i-ii)	(-) 13134.63	(-) 14284.89	(-) 20729.88	(-) 8622.30
2. पूंजीगत लेखा				
(i) प्राप्तियां	54775.70	72790.67	71377.08	69341.09
(ii) व्यय	41544.22	58185.51	47227.39	64135.28
शेष (i-ii)	13231.48	14605.16	24149.69	5205.81
समग्र बकाया (1+2)	54678.85	72470.4	67957.27	72757.58
वृद्धि (+) / घाटा (-)	(-) 96.88	320.57	3419.80	(-)3416.49

स्रोत : पंजाब का सांख्यिकीय सार, 2021

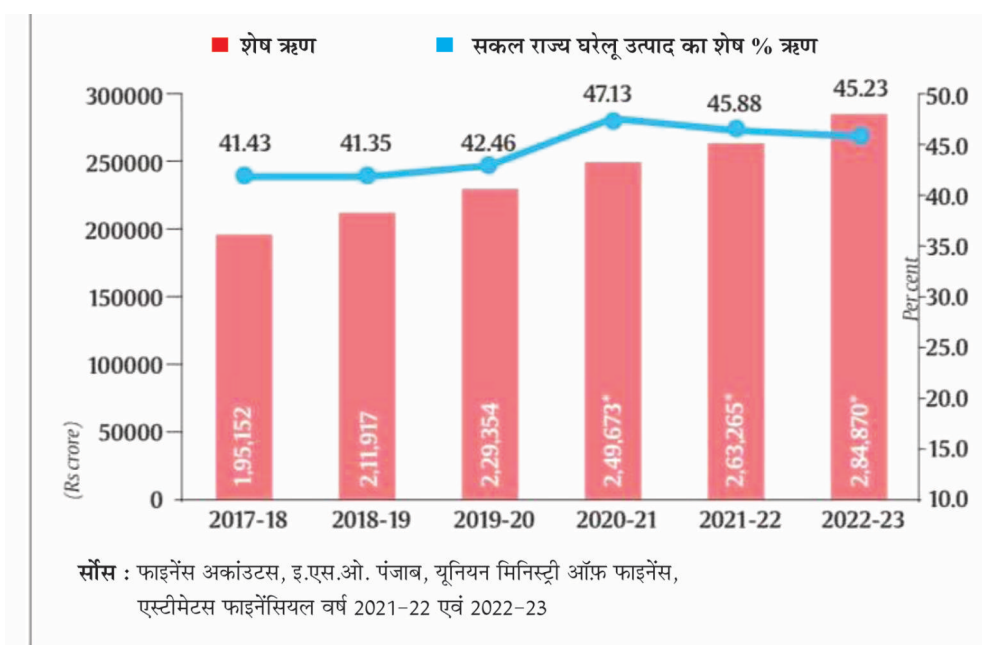
पंजाब सरकार का बजट वास्तव में घाटे का बजट है क्योंकि इस पर किया गया व्यय उसके राजस्व में अधिक रहा है। आर्थिक सिद्धांत में कहा गया है कि यदि कोई सरकार लोगों के हित में घाटे के बजट को अपनाती है तो इसका एक निश्चित स्तर स्वीकारयोग्य है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार को अपने बजट घाटे के एक निश्चित स्तर को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए या अपने राजस्व स्रोतों में बढ़ोत्तरी करके और अपने गैर-विकासात्मक व्यय को कम करके इसे और कम करने की कोशिश करनी चाहिए।

10.5 सार्वजनिक ऋण (Public Debt)

पंजाब सरकार अपने बजट घाटे को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से उधार लेती है और बाद में उस पर भारी ब्याज का भुगतान करती है। पिछले कुछ वर्षों में घाटे के बजट में वृद्धि के कारण सरकार द्वारा लिए गए ऋण की राशि और उस पर भुगतान किए गए ब्याज की राशि समय के साथ साथ बढ़ रही है। यह निम्न सारणी द्वारा दिखाया गया है :

सारणी 10.2 पंजाब सरकार के कर्ज रुझान

चार्ट 10.2 में दिए गए आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लगातार घाटे के बजट के कारण पंजाब सरकार द्वारा लिए गए कर्ज की राशि काफी बढ़ रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए यह सुझाव दिया



स्त्रोत : पंजाब का आर्थिक सार, 2021

जा सकता है कि पंजाब सरकार को अपने गैर-विकासात्मक व्यय को कम करना चाहिए और राज्य में विकास-गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

10.6 निष्कर्ष (Conclusion)

अंत में, यह कहा जा सकता है कि पंजाब सरकार का व्यय, अपने राजस्व के स्रोतों की तुलना में तेजी से बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि पंजाब सरकार का बजटीय घाटा, लगातार बढ़ता जा रहा है। यह सरकार के लिए एक खतरनाक संकेत है कि वह अपने गैर विकासात्मक खर्च कम करके अपने राजस्व के स्रोतों को बढ़ाने की कोशिश करे ताकि पंजाब को फिर से 'रंगला पंजाब' बनाया जा सके।

आओ यह गतिविधियां करें

- पंजाब सरकार का घाटे वाला बजट लगातार बढ़ रहा है। इस के कारण सम्बन्धी चर्चा करो।
- पंजाब राज्य के बजट-घाटे को कम करने सम्बन्धी उठाये जाने वाले जरूरी कदमों सम्बन्धी सुझाव दीजिये।

पुनरावृत्ति (RECAP)

- पंजाब सरकार के बजट में दो भाग होते हैं, जो कि सार्वजनिक राजस्व व सार्वजनिक व्यय हैं।
- पंजाब सरकार को दो तरीकों से राजस्व प्राप्त होता है जोकि कर और गैर-कर स्रोत हैं।
- पंजाब सरकार के कर स्रोतों में मुख्य रूप से वस्तु और सेवा कर, मूल्य वृद्धि, राज्य उत्पाद शुल्क आदि हैं।
- पंजाब सरकार गैर-कर स्रोतों में मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियां, विविध प्राप्तियां, पंजाब रोडवेज आदि से प्राप्त राजस्व शामिल है।
- पंजाब सरकार द्वारा दो प्रकार के खर्च किए जाते हैं, जो विकासात्मक और गैर-विकासात्मक खर्च है।
- विकासात्मक व्यय में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा आदि पर किए जाने वाले व्यय को शामिल किया जाता है।
- गैर-विकासात्मक व्यय में मुख्य रूप से पुलिस, कानून, ब्याज भुगतान आदि पर किया गया व्यय शामिल किया जाता है।
- वर्तमान में पंजाब सरकार का बजट घाटे का बजट है।
- पिछले कुछ सालों से लगातार घाटे के बजट के कारण पंजाब सरकार द्वारा लिए गए कर्ज की राशि बढ़ रही है।

●●● अभ्यास ●●●

1. बहुवैकल्पिक प्रश्न (Multiple Choice Questions)

1. किसी भी सरकार के राजस्व स्रोतों को कितने भागों में बांटा जा सकता है?
(क) 2 (ख) 3
(ग) 4 (घ) 5
2. निम्नलिखित में से कौन सा, एक सरकार के लिए राजस्व का स्रोत है?
(क) कर स्रोत (ख) गैर-कर स्रोत
(ग) क और ख दोनों (घ) अवैध गतिविधियों से होने वाली आय
3. निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब सरकार के राजस्व का कर स्रोत नहीं है?
(क) वस्तु एवं सेवा कर (ख) मूल्य वृद्धि कर
(ग) राज्य उत्पाद शुल्क (घ) ब्याज प्राप्तियां
4. निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब सरकार के लिए राजस्व का गैर-कर स्रोत है?
(क) बिजली कर (ख) पंजाब रोडवेज
(ग) भूमि कर (घ) मनोरंजन कर

5. निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब सरकार द्वारा किया गया व्यय है?
 (क) विकासात्मक व्यय (ख) गैर-विकासात्मक व्यय
 (ग) क और ख दोनों (घ) ब्याज प्राप्तियां
6. निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब सरकार द्वारा किया गया विकास व्यय है?
 (क) शिक्षा पर व्यय (ख) सड़क निर्माण पर व्यय
 (ग) स्वास्थ्य पर व्यय (घ) उपरोक्त सभी
7. निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब सरकार द्वारा किया गया गैर-विकास व्यय है?
 (क) पुलिस पर व्यय (ख) ऊर्जा पर व्यय
 (ग) चिकित्सा-शिक्षा पर व्यय (घ) छात्रवृत्तियों पर व्यय

2. रिक्त स्थान भरें (Fill in the Blanks)

1. वर्तमान में लगभग हर केन्द्र या राज्य सरकार एक सरकार है।
 (कल्याणकारी/तानाशाही)
2. पंजाब सरकार के आमदन के साधनों को भागों में बांटा गया है। (2/3)
3. वस्तु और सेवा कर एक कर है। (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष)
4. पंजाब सरकार द्वारा अपने ब्याज भुगतान पर किया गया व्यय व्यय है।
 (विकासात्मक/गैर-विकासात्मक)
5. पंजाब सरकार द्वारा तैयार किया गया बजट एक बजट है। (घाटे वाला/अतिरिक्त)

3. सही या गलत लिखें (True / False)

1. पंजाब सरकार को केन्द्र सरकार से करों के रूप में कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।
2. मूल्य वृद्धि कर एक अप्रत्यक्ष कर है।
3. पंजाब सरकार द्वारा दोपहिया वाहनों पर कोई कर नहीं लगाया जाता है।
4. स्वास्थ्य पर व्यय को विकास व्यय के रूप में लिया जाता है।
5. पंजाब सरकार द्वारा पेंशन पर किया जाने वाला व्यय गैर-विकास व्यय की श्रेणी में आता है।
6. पंजाब सरकार द्वारा लिए गए सार्वजनिक ऋण में लगातार कमी आ रही है।

4. अति लघु उत्तरीय प्रश्न (Very Short Answer Questions)

1. वस्तु एवं सेवा कर का क्या अर्थ है? इसे कौन लगाता है ?
2. मूल्य वृद्धि कर से क्या तात्पर्य है?

3. मूल्य वृद्धि कर वस्तु एवं सेवा कर से कैसे भिन्न है?
4. राज्य उत्पाद शुल्क से क्या तात्पर्य है?
5. भूमि कर एवं मनोरंजन कर पर नोट लिखें।
6. पंजाब सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विविध सेवाएं कौन सी हैं?
7. पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ पर व्यय को गैर-विकासात्मक व्यय क्यों कहा जाता है?
8. पंजाब सरकार द्वारा सार्वजनिक ऋण लेने का क्या कारण है?
9. सरकार उत्पाद शुल्क से काफी राजस्व अर्जित करती है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इसका औचित्य साबित करें।
10. सार्वजनिक ऋण से क्या भाव है ? सरकार को इसे कम क्यों करना चाहिए?

5. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (60-70 शब्दों में उत्तर दें)

1. पंजाब सरकार के राजस्व के विभिन्न कर स्रोतों का वर्णन कीजिए।
2. पंजाब सरकार के राजस्व के विभिन्न गैर-कर स्रोतों का वर्णन कीजिए।
3. पंजाब सरकार के विभिन्न विकास सम्बन्धी व्यय का वर्णन कीजिए।
4. पंजाब सरकार के विभिन्न गैर-विकास सम्बन्धी व्यय का वर्णन कीजिए।
5. पंजाब सरकार के बजट के प्रारूप पर एक टिप्पणी लिखिए।
6. पंजाब सरकार द्वारा लिए गए सार्वजनिक ऋण पर एक नोट लिखिए।

6. अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (150-200 शब्दों में उत्तर दें) (Long Answer Questions)

1. पंजाब सरकार की आय के विभिन्न कर और गैर-कर स्रोतों का वर्णन कीजिए।
2. पंजाब सरकार के विभिन्न विकास और गैर-विकास सम्बन्धी व्यय का वर्णन कीजिए।

References

- Handbook of Statistics on Indian Economy (2020). "Reserve Bank of India Publication", Available at <https://www.rbi.org.in/scripts/AnnualPublications.aspx?head=Handbook of Statistics on Indian Economy>
- Handbook of Statistics on Indian Economy (2021). "Reserve Bank of India Publication", Available at <https://www.rbi.org.in/scripts/AnnualPublications.aspx?head=Handbook 20of 20Statistics 20on 20Indian 20Economy>

- GoP (2020). Statistical Abstract of Punjab. “Economic and Statistical Organization”, Department of Planning, Government of Punjab, Publication No. 962
- GoP (2021). Statistical Abstract of Punjab. “Economic and Statistical Organization”, Department of Planning, Government of Punjab, Publication No. 964



पारिभाषिक शब्दालवी

1. **बेहतर अनुपालन (Better Compliance)** : सामान्य रूप से कर भुगतान आदि के संदर्भ में प्रयुक्त सरकारी अनुदेशों का पालन।
2. **द्वि-पक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement)** : दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आयात – निर्यात से संबंधित समझौते।
3. **ब्रुंटलैंड कमीशन (Brundtland Commission)**: संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1983 में विश्व की पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन के लिए नियुक्त आयोग। इसने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें धारणीय विकास की परिभाषा के बड़े व्यापक रूप से उदाहरण दिए गए।
4. **बजट घाटा (Budgetary Deficit)** : सरकार की आय और कर राजस्व द्वारा उसके व्यय का पूरा न हो पाना।
5. **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency)** : यह एक सरकारी संस्था है जिसका उद्देश्य ऐसी नीतियों और रण नीतियों का विकास करना है, जिनमें स्व-नियमन तथा बाज़ार-सिद्धांतों पर बल होता है। यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देता है और विद्युत के अपव्यय को रोकने के उपाय करता है।
6. **कर प्रति कर (Cascading Effect)** : करों के कारण वस्तु की कीमतों में अनुपात से अधिक वृद्धि। ये प्रायः अनेक चरणों में लगने वाले करों का परिणाम होता है। उदाहरणार्थ : उत्पादन शुल्क की राशि को वस्तु की उत्पादन लागत में जोड़ कर उस पर विक्रय कर लगाना। इस प्रकार उत्पाद शुल्क पर भी विक्रय कर लग जात है।
7. **उपनिवेशवाद (Colonism)** : युद्ध या अन्य विधियों का प्रयोग कर किसी दूसरे देश को अपने अधीन करना। इस प्रकार, अपने देश की सीमा से बाहर भी अन्य राष्ट्रों के राजनीतिक आर्थिक जीवन पर नियंत्रण कर लिया जाता था। उपनिवेशवाद की सबसे बड़ी विशेषता अधीनस्थ देशों का शोषण रही है।
8. **कृषि का व्यावसायीकरण (Commercialisation of Agriculture)** : स्व-उपभोग या पारिवारिक उपभोग नहीं, बल्कि मुख्यतः बाज़ार में बिक्री। अंग्रेजों के समय कृषि के व्यावसायीकरण ने कुछ अलग ही रूप धारण कर लिया था। अंग्रेजों ने खाद्य फसलों के स्थान पर नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए उनकी उँची कीमतें देनी प्रारंभ कर दी। उन्हें नकदी फसलें अपने देश के उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में चाहिए थीं।

9. **उपभोग समुच्चय (Consumption Basket) :** किसी परिवार द्वारा उपयुक्त वस्तुओं-सेवाओं का समूह जिसका प्रयोग जनता के उपभोग के स्वरूप का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। सांख्यिकीय संस्थान इसका निर्धारण करते हैं। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन उपभोग समुच्चय में 19 वस्तुओं को सम्मिलित करता है। वे हैं: (अ) अनाज (ब) दालें और दूध से बनी चीजें (स) खाद्य तेल (द) सब्जियाँ (ध) वस्त्र, आदि।
10. **घाटे की वित्त व्यवस्था (Deficit Financing):** सरकार के व्यय का राजस्व से अधिक होना।
11. **विमूदरीकरण (Devaluation) :** विदेशी मुद्रा की तुलना में देश की मुद्रा के मूल्य का हास होना।
12. **विनिवेश (Disinvestment) :** किसी कंपनी की पूँजी के एक अंश को जान बूझ कर बेचना। इस प्रकार धन जुटाने के साथ-साथ उस कंपनी की हिस्सेदारी, रचना या प्रबंधन या दोनों, में बदलाव भी किये जा सकते हैं।
13. **नियोजक/रोजगारदाता (Employer) :** वे स्वनियोजक जो अपना काम स्वयं या कुछ भागीदारों की सहायता से चलाते हैं और प्रायः श्रमिकों को उस उद्यम के संचालन के लिए काम पर रखते हैं।
14. **उद्यम (Enterprise) :** किसी व्यक्ति या समूह के स्वामित्व वाला उपक्रम, जो मुख्यतः बिक्री के ध्येय से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण आदि करता है।
15. **निर्यात शुल्क (Export Duties) :** किसी देश से वस्तुओं के निर्यात पर लगाया गया कर।
16. **निर्यात संवर्धन (Export Promotion) :** राजकीय और व्यापारिक समर्थन सहित वे सभी नीतियाँ जिन्हें सरकार उच्च आर्थिक संवृद्धि प्राप्त करने और अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के ध्येय से अपनाती है। इन नीतियों से निर्यात बाधाओं को दूर किया जाता है।
17. **निर्यात-आयात नीति/व्यापार नीति (Export - Import Policy) :** सरकार की वे आर्थिक नीतियाँ जो आयात और निर्यात/व्यापार को प्रभावित करती हैं।
18. **पारिवारिक श्रम/श्रमिक (Family Labour/Worker) :** उद्योग या उद्यम आदि में नकद या वस्तु स्वरूप मजदूरी पाने की इच्छा के बिना काम करने वाला व्यक्ति।
19. **वित्तीय संस्थान (Financial Institution) :** बचतों के संग्रह और प्रयोजन या आबंटन से जुड़े संस्थान। इनमें व्यावसायिक, सहकारी और विकास बैंक तथा निवेश संस्थान शामिल हैं।
20. **औपचारिक/संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठान (Formal Sector Establishments) :** सभी सार्वजनिक तथा निजी प्रतिष्ठान जिनमें दस या अधिक व्यक्ति मजदूरी पर काम कर रहे हों।
21. **जी (G-8) :** आठ देशों का गुट : इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड, सं. रा. अमेरिका और रूस सम्मिलित है। यह राज्याध्यक्षों और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों का वार्षिक आर्थिक-राजनीतिक शिखर सम्मेलन होता है। यहाँ अनेक बैठकें तथा नीतिगत अनुसंधान होते रहते हैं। गुट की अध्यक्षता की अवधि एक वर्ष है जो बारी बारी से सदस्यों को प्रदान की जाती है। वर्ष 2006 का अध्यक्ष रूस था।

22. **जी - 20 (G - 20) :** विश्व आर्थिक स्थायित्व और धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए देशों का एक समूह है। इसमें 19 देशों के वित्त मंत्री तथा केन्द्रीय बैंक गवर्नर सम्मिलित हैं: अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया रिपब्लिक, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूरोपीय संघ भी जी - 20 का सदस्य है जो कि यूरोपीय संघ के अध्यक्ष एवं केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करता है।
23. **मुद्रास्फीति (Inflation) :** सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि।
24. **आंतरिक अर्थव्यवस्था का एकीकरण (Integration of Domestic Economy) :** सरकारी नीतियों द्वारा अन्य देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार और निवेश में वृद्धि, जिससे कि आंतरिक अर्थव्यवस्था अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कुशलता एवं पारस्परिक निर्भरता सहित जुड़ सके।
25. **प्रसव/मातृत्व मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate) :** यह प्रसव काल में माताओं की मृत्यु और सजीव जन्मों का अनुपात है। कई बार सजीव जन्मों के साथ गर्भपात का भी योग बन जाता है। अनुपात की गणना एक वर्ष की अवधि के लिए की जाती है।
26. **मृत्यु दर (Mortality Rate) :** इसे वर्ष भर में प्रति हजार जनसंख्या में हुई मृत्यु की संख्याओं द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। यह मृत्यु सामान्य हो या रोग आदि के कारण, दोनों ही प्रकारों को गणना में सम्मिलित किया जाता है। यह रूग्णता दर से भिन्न है। रूग्णता दर तो बीमारी के कारण काम न कर पाना दर्शाती है।
27. **बहुपक्षीय व्यापार संधियाँ (Multilateral Trade Agreements) :** किसी देश द्वारा दो या अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान - प्रदान संबंधी व्यापार समझौते।
28. **राष्ट्रीय उत्पाद/आय (National Product/Income) :** किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों और विदेशों से प्राप्त आय का योगफल।
29. **नई आर्थिक नीति (New Economic Policy) :** भारत में वर्ष 1991 से अपनाई जा रही नीतियों का नाम।
30. **गैर-नवीकरणीय संसाधन (Non-Renewable Resources) :** वे प्राकृतिक संसाधन जिनका नवीकरण संभव नहीं। उनका भंडार वृहद होता हुआ भी सीमित है। उदाहरण: जीवाश्म उर्जा संसाधन (तेल, कोयला) और लोहा, सीसा, एल्युमीनियम, यूरेनियम खनिज, आदि।
31. **पेंशन (Pension) :** सेवा निवृत्त श्रमिक को मिलने वाली मासिक निर्वाह राशि।
32. **प्रति व्यक्ति आमदन/आय (Per Capita Income) :** किसी अवधि विशेष में राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय जनसंख्या का अनुपात।
33. **निजी क्षेत्रक के प्रतिष्ठान (Private Sector Establishment) :** निजी व्यक्तियों/समूहों के स्वामित्व और नियंत्रण वाले प्रतिष्ठान।

- 34. नवीकरणीय संसाधन (Renewable Resources):** वे संसाधन जो विवेकपूर्वक प्रयुक्त होने पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से नवीनीकृत होते रहते हैं। जल, वन, पशुधन, मत्स्य, आदि ऐसे संसाधन हैं कि यदि इनका अत्यधिक विदोहन नहीं हो तो ये निरंतर बने रह सकते हैं।
- 35. उत्पादकता (Productivity) :** श्रम या पूँजी की दक्षता में वृद्धि से उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। यह शब्द प्रायः श्रम के आगत की उत्पादकता के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
- 36. भविष्य निधि (Provident Fund) :** कर्मचारियों के हितार्थ संचालित कोष। इसमें कर्मचारी और रोज़गारदाता दोनों ही अंशदान जमा करते हैं। इसका संचालन सरकार करती है तथा इसकी संचित राशि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को दे दी जाती है।
- 37. राज्य विद्युत बोर्ड (State Electricity Boards) :** ये राज्य प्रशासन के ऐसे अंग हैं जो विद्युत उत्पादन, संवहन और वितरण के कार्य करते हैं।
- 38. श्रमिक संघ (Trade Union) :** मज़दूरी की दरों, लाभों और कार्य करने की दशाओं को लेकर अपने सदस्यों के हितों के रक्षार्थ मज़दूरों द्वारा बनाई संस्था।
- 39. बेरोज़गार (Unemployment) :** वे सभी व्यक्ति जो काम के अभाव के कारण बेकार बैठे हैं पर रोज़गार कार्यालयों, मध्यस्थों, मित्रों-संबंधियों के माध्यम से अथवा संभावित रोज़गार दाताओं को आवेदन दे कर रोज़गार के लिए अपनी उपलब्धता सूचित कर रहे हों। इन्हें कार्य की वर्तमान दशाओं और प्रचलित पारिश्रमिक दरों पर काम करने के लिए तत्पर होना चाहिए।
- 40. श्रमिक जनसंख्या अनुपात (Worker Population Ratio) :** श्रमिकों की कुल संख्या का देश की जनसंख्या से अनुपात। इसे प्रतिशत में अभिव्यक्ति किया जाता है।



APPENDIX

227

LOGARITHMS

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Mean Difference								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	0000	0043	0086	0128	0170	0212	0253	0294	0334	0374	4	8	12	17	21	25	29	33	37
11	0414	0453	0492	0531	0569	0607	0645	0682	0719	0755	4	8	11	15	19	23	26	30	34
12	0792	0828	0864	0899	0934	0969	1004	1038	1072	1106	3	7	10	14	17	21	24	28	31
13	1139	1173	1206	1239	1271	1303	1335	1367	1399	1430	3	6	10	13	16	19	23	26	29
14	1461	1492	1523	1553	1584	1614	1644	1673	1703	1732	3	6	9	12	15	18	21	24	27
15	1761	1790	1818	1847	1875	1903	1931	1959	1987	2014	3	6	8	11	14	17	20	22	25
16	2041	2068	2095	2122	2148	2175	2201	2227	2253	2279	3	5	8	11	13	16	18	21	24
17	2304	2330	2355	2380	2405	2430	2455	2480	2504	2529	2	5	7	10	12	15	17	20	22
18	2553	2577	2601	2625	2648	2672	2695	2718	2742	2765	2	5	7	9	12	14	16	19	21
19	2788	2810	2833	2856	2878	2900	2923	2945	2967	2989	2	4	7	9	11	13	16	18	20
20	3010	3032	3054	3075	3096	3118	3139	3160	3181	3201	2	4	6	8	11	13	15	17	19
21	3222	3243	3263	3284	3304	3324	3345	3365	3385	3404	2	4	6	8	10	12	14	16	18
22	3424	3444	3464	3483	3502	3522	3541	3560	3579	3598	2	4	6	8	10	12	14	15	17
23	3617	3636	3655	3674	3692	3711	3729	3747	3766	3784	2	4	6	7	9	11	13	15	17
24	3802	3820	3838	3856	3874	3892	3909	3927	3945	3962	2	4	5	7	9	11	12	14	16
25	3979	3997	4014	4031	4048	4065	4082	4099	4116	4133	2	3	5	7	9	10	12	14	15
26	4150	4166	4183	4200	4216	4232	4249	4265	4281	4298	2	3	5	7	8	10	11	13	15
27	4314	4330	4346	4362	4378	4393	4409	4425	4440	4456	2	3	5	6	8	9	11	13	14
28	4472	4487	4502	4518	4533	4548	4564	4579	4594	4609	2	3	5	6	8	9	11	12	14
29	4624	4639	4654	4669	4683	4698	4713	4728	4742	4757	1	3	4	6	7	9	10	12	13
30	4771	4786	4800	4814	4829	4843	4857	4871	4886	4900	1	3	4	6	7	9	10	11	13
31	4914	4928	4942	4955	4969	4983	4997	5011	5024	5038	1	3	4	6	7	8	10	11	12
32	5051	5065	5079	5092	5105	5119	5132	5145	5159	5172	1	3	4	5	7	8	9	11	12
33	5185	5198	5211	5224	5237	5250	5263	5276	5289	5302	1	3	4	5	6	8	9	10	12
34	5315	5328	5340	5353	5366	5378	5391	5403	5416	5428	1	3	4	5	6	8	9	10	11
35	5441	5453	5465	5478	5490	5502	5514	5527	5539	5551	1	2	4	5	6	7	9	10	11
36	5563	5575	5587	5599	5611	5623	5635	5647	5658	5670	1	2	4	5	6	7	8	10	11
37	5682	5694	5705	5717	5729	5740	5752	5763	5775	5786	1	2	3	5	6	7	8	9	10
38	5798	5809	5821	5832	5843	5855	5866	5877	5888	5899	1	2	3	5	6	7	8	9	10
39	5911	5922	5933	5944	5955	5966	5977	5988	5999	6010	1	2	3	4	5	7	8	9	10
40	6021	6031	6042	6053	6064	6075	6085	6096	6107	6117	1	2	3	4	5	6	8	9	10
41	6128	6138	6149	6160	6170	6180	6191	6201	6212	6222	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	6232	6243	6253	6263	6274	6284	6294	6304	6314	6325	1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	6335	6345	6355	6365	6375	6385	6395	6405	6415	6425	1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	6435	6445	6454	6464	6474	6484	6493	6503	6513	6522	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	6532	6542	6551	6561	6571	6580	6590	6599	6609	6618	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	6628	6637	6646	6656	6665	6675	6684	6693	6702	6712	1	2	3	4	5	6	7	7	8
47	6721	6730	6739	6749	6758	6767	6776	6785	6794	6803	1	2	3	4	5	5	6	7	8
48	6812	6821	6830	6839	6848	6857	6866	6875	6884	6893	1	2	3	4	4	5	6	7	8
49	6902	6911	6920	6928	6937	6946	6955	6964	6972	6981	1	2	3	4	4	5	6	7	8
50	6990	6998	7007	7016	7024	7033	7042	7050	7059	7067	1	2	3	3	4	5	6	7	8
51	7076	7084	7093	7101	7110	7118	7126	7135	7143	7152	1	2	3	3	4	5	6	7	8
52	7160	7168	7177	7185	7193	7202	7210	7218	7226	7235	1	2	2	3	4	5	6	7	7
53	7243	7251	7259	7267	7275	7284	7292	7300	7308	7316	1	2	2	3	4	5	6	6	7
54	7324	7332	7340	7348	7356	7364	7372	7380	7388	7396	1	2	2	3	4	5	6	6	7
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9

LOGARITHMS

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Mean Difference								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	7404	7412	7419	7427	7435	7443	7451	7459	7466	7474	1	2	2	3	4	5	5	6	7
56	7482	7490	7497	7505	7513	7520	7528	7536	7543	7551	1	2	2	3	4	5	5	6	7
57	7559	7566	7574	7582	7589	7597	7604	7612	7619	7627	1	2	2	3	4	5	5	6	7
58	7634	7642	7649	7657	7664	7672	7679	7686	7694	7701	1	1	2	3	4	4	5	6	7
59	7709	7716	7723	7731	7738	7745	7752	7760	7767	7774	1	1	2	3	4	4	5	6	7
60	7782	7789	7769	7803	7810	7818	7825	7832	7839	7846	1	1	2	3	4	4	5	6	6
61	7853	7860	7868	7875	7882	7889	7896	7903	7910	7917	1	1	2	3	4	4	5	6	6
62	7924	7931	7938	7945	7952	7959	7966	7973	7980	7987	1	1	2	3	3	4	5	6	6
63	7993	8000	8007	8014	8021	8028	8035	8041	8048	8055	1	1	2	3	3	4	5	5	6
64	8062	8069	8075	8082	8089	8096	8102	8109	8116	8122	1	1	2	3	3	4	5	5	6
65	8129	8136	8142	8149	8156	8162	8169	8176	8182	8189	1	1	2	3	3	4	5	5	6
66	8195	8202	8209	8215	8222	8228	8235	8241	8248	8254	1	1	2	3	3	4	5	5	6
67	8261	8267	8274	8280	8287	8293	8299	8306	8312	8319	1	1	2	3	3	4	5	5	6
68	8325	8331	8338	8344	8351	8357	8363	8370	8376	8382	1	1	2	3	3	4	4	5	6
69	8388	8395	8401	8407	8414	8420	8426	8432	8439	8445	1	1	2	2	3	4	4	5	6
70	8451	8457	8463	8470	8476	8482	8488	8494	8500	8506	1	1	2	2	3	4	4	5	6
71	8513	8519	8525	8531	8537	8543	8549	8555	8561	8567	1	1	2	2	3	4	4	5	5
72	8573	8579	8585	8591	8597	8603	8609	8615	8621	8627	1	1	2	2	3	4	4	5	5
73	8633	8639	8645	8651	8657	8663	8669	8675	8681	8686	1	1	2	2	3	4	4	5	5
74	8692	8698	8704	8710	8716	8722	8727	8733	8739	8745	1	1	2	2	3	4	4	5	5
75	8751	8756	8762	8768	8774	8779	8785	8791	8797	8802	1	1	2	2	3	3	4	5	5
76	8808	8814	8820	8825	8831	8837	8842	8848	8854	8859	1	1	2	2	3	3	4	5	5
77	8865	8871	8876	8882	8887	8893	8899	8904	8910	8915	1	1	2	2	3	3	4	4	5
78	8921	8927	8932	8938	8943	8949	8954	8960	8965	8971	1	1	2	2	3	3	4	4	5
79	8976	8982	8987	8993	8998	9004	9009	9015	9020	9025	1	1	2	2	3	3	4	4	5
80	9031	9036	9042	9047	9053	9058	9063	9069	9074	9079	1	1	2	2	3	3	4	4	5
81	9085	9090	9096	9101	9106	9112	9117	9122	9128	9133	1	1	2	2	3	3	4	4	5
82	9138	9143	9149	9154	9159	9165	9170	9175	9180	9186	1	1	2	2	3	3	4	4	5
83	9191	9196	9201	9206	9212	9217	9222	9227	9232	9238	1	1	2	2	3	3	4	4	5
84	9243	9248	9253	9258	9263	9269	9274	9279	9284	9289	1	1	2	2	3	3	4	4	5
85	9294	9299	9304	9309	9315	9320	9325	9330	9335	9340	1	1	2	2	3	3	4	4	5
86	9345	9350	9355	9360	9365	9370	9375	9380	9385	9390	1	1	2	2	3	3	4	4	5
87	9395	9400	9405	9410	9415	9420	9425	9430	9435	9440	0	1	1	2	2	3	3	4	4
88	9445	9450	9455	9460	9465	9469	9474	9479	9484	9489	0	1	1	2	2	3	3	4	4
89	9494	9499	9504	9509	9513	9518	9523	9528	9533	9538	0	1	1	2	2	3	3	4	4
90	9542	9547	9552	9557	9562	9566	9571	9576	9581	9586	0	1	1	2	2	3	3	4	4
91	9590	9595	9600	9605	9609	9614	9619	9624	9628	9633	0	1	1	2	2	3	3	4	4
92	9638	9643	9647	9652	9657	9661	9666	9671	9675	9680	0	1	1	2	2	3	3	4	4
93	9685	9689	9694	9699	9703	9708	9713	9717	9722	9727	0	1	1	2	2	3	3	4	4
94	9731	9736	9741	9745	9750	9754	9759	9763	9768	9773	0	1	1	2	2	3	3	4	4
95	9777	9782	9786	9791	9795	9800	9805	9809	9814	9818	0	1	1	2	2	3	3	4	4
96	9823	9827	9832	9836	9841	9845	9850	9854	9859	9863	0	1	1	2	2	3	3	4	4
97	9868	9872	9877	9881	9886	9890	9894	9899	9903	9908	0	1	1	2	2	3	3	4	4
98	9912	9917	9921	9926	9930	9934	9939	9943	9948	9952	0	1	1	2	2	3	3	4	4
99	9956	9961	9965	9969	9974	9978	9983	9987	9991	9996	0	1	1	2	2	3	3	3	4
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9

LOGARITHMS

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Mean Difference								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
.00	1000	1002	1005	1007	1009	1012	1014	1016	1019	1021	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.01	1023	1026	1028	1030	1033	1035	1038	1040	1042	1045	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.02	1047	1050	1052	1054	1057	1059	1062	1064	1067	1069	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.03	1072	1074	1076	1079	1081	1084	1086	1089	1091	1094	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.04	1096	1099	1102	1104	1107	1109	1112	1114	1117	1119	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.05	1122	1125	1127	1130	1132	1135	1138	1140	1143	1146	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.06	1148	1151	1153	1156	1159	1161	1164	1167	1169	1172	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.07	1175	1178	1180	1183	1186	1189	1191	1194	1197	1199	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.08	1202	1205	1208	1211	1213	1216	1219	1222	1225	1227	0	1	1	1	1	2	2	2	3
.09	1230	1233	1236	1239	1242	1245	1247	1250	1253	1256	0	1	1	1	1	2	2	2	3
.10	1259	1262	1265	1268	1271	1274	1276	1279	1282	1285	0	1	1	1	1	2	2	2	3
.11	1288	1291	1294	1297	1300	1303	1306	1309	1312	1315	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.12	1318	1321	1324	1327	1330	1334	1337	1340	1343	1346	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.13	1349	1352	1355	1358	1361	1365	1368	1371	1374	1377	0	1	1	1	2	2	2	3	3
.14	1380	1384	1387	1390	1393	1396	1400	1403	1406	1409	0	1	1	1	2	2	2	3	3
.15	1413	1416	1419	1422	1426	1429	1432	1435	1439	1442	0	1	1	1	2	2	2	3	3
.16	1445	1449	1452	1455	1459	1462	1466	1469	1472	1476	0	1	1	1	2	2	2	3	3
.17	1479	1483	1486	1489	1493	1496	1500	1503	1507	1510	0	1	1	1	2	2	2	3	3
.18	1514	1517	1521	1524	1528	1531	1535	1538	1542	1545	0	1	1	1	2	2	2	3	3
.19	1549	1552	1556	1560	1563	1567	1570	1574	1578	1581	0	1	1	1	2	2	3	3	3
.20	1585	1589	1592	1596	1600	1603	1607	1611	1614	1618	0	1	1	1	2	2	3	3	3
.21	1622	1626	1629	1633	1637	1641	1644	1648	1652	1656	0	1	1	2	2	2	3	3	3
.22	1660	1663	1667	1671	1675	1679	1683	1687	1690	1694	0	1	1	2	2	2	3	3	3
.23	1698	1702	1706	1710	1714	1718	1722	1726	1730	1734	0	1	1	2	2	2	3	3	4
.24	1738	1742	1746	1750	1754	1758	1762	1766	1770	1774	0	1	1	2	2	2	3	3	4
.25	1778	1782	1786	1791	1795	1799	1803	1807	1811	1816	0	1	1	2	2	2	3	3	4
.26	1820	1824	1828	1832	1837	1841	1845	1849	1854	1858	0	1	1	2	2	3	3	3	4
.27	1862	1866	1871	1875	1879	1884	1888	1892	1897	1901	0	1	1	2	2	3	3	3	4
.28	1905	1910	1914	1919	1923	1928	1932	1936	1941	1945	0	1	1	2	2	3	3	4	4
.29	1950	1954	1959	1963	1968	1972	1977	1982	1986	1991	0	1	1	2	2	3	3	4	4
.30	1995	2000	2004	2009	2014	2018	2023	2028	2032	2037	0	1	1	2	2	3	3	4	4
.31	2042	2046	2051	2056	2061	2065	2070	2075	2080	2084	0	1	1	2	2	3	3	4	4
.32	2089	2094	2099	2104	2109	2113	2118	2123	2128	2133	0	1	1	2	2	3	3	4	4
.33	2138	2143	2148	2153	2158	2163	2168	2173	2178	2183	0	1	1	2	2	3	3	4	4
.34	2188	2193	2198	2203	2208	2213	2218	2223	2228	2234	1	1	2	2	3	3	4	4	5
.35	2239	2244	2249	2254	2259	2265	2270	2275	2280	2286	1	1	2	2	3	3	4	4	5
.36	2291	2296	2301	2307	2312	2317	2323	2328	2333	2339	1	1	2	2	3	3	4	4	5
.37	2344	2350	2355	2360	2366	2371	2377	2382	2388	2393	1	1	2	2	3	3	4	4	5
.38	2399	2404	2410	2415	2421	2427	2432	2438	2443	2449	1	1	2	2	3	3	4	4	5
.39	2455	2460	2466	2472	2477	2483	2489	2495	2500	2506	1	1	2	2	3	3	4	5	5
.40	2512	2518	2523	2529	2535	2541	2547	2553	2559	2564	1	1	2	2	3	4	4	5	5
.41	2570	2576	2582	2588	2594	2600	2606	2612	2618	2624	1	1	2	2	3	4	4	5	5
.42	2630	2636	2642	2649	2655	2661	2667	2673	2679	2685	1	1	2	2	3	4	4	5	6
.43	2692	2698	2704	2710	2716	2723	2729	2735	2742	2748	1	1	2	3	3	4	4	5	6
.44	2754	2761	2767	2773	2780	2786	2793	2799	2805	2812	1	1	2	3	3	4	4	5	6
.45	2818	2825	2831	2838	2844	2851	2858	2864	2871	2877	1	1	2	3	3	4	5	5	6
.46	2884	2891	2897	2904	2911	2917	2924	2931	2938	2944	1	1	2	3	3	4	5	5	6
.47	2951	2958	2965	2972	2979	2985	2992	2999	3006	3013	1	1	2	3	3	4	5	5	6
.48	3020	3027	3034	3041	3048	3055	3062	3069	3076	3083	1	1	2	3	4	4	5	6	6
.49	3090	3097	3105	3112	3119	3126	3133	3141	3148	3155	1	1	2	3	4	4	5	6	6
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9

“ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ” ਪੰਜਾਬ।

LOGARITHMS

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Mean Difference								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
.50	3162	3170	3177	3184	3192	3199	3206	3214	3221	3228	1	1	2	3	4	4	5	6	7
.51	3236	3243	3251	3258	3266	3273	3281	3289	3296	3304	1	2	2	3	4	5	5	6	7
.52	3311	3319	3327	3334	3342	3350	3357	3365	3373	3381	1	2	2	3	4	5	5	6	7
.53	3388	3396	3404	3412	3420	3428	3436	3443	3451	3459	1	2	2	3	4	5	6	6	7
.54	3467	3475	3483	3491	3499	3508	3516	3524	3532	3540	1	2	2	3	4	5	6	6	7
.55	3548	3556	3565	3573	3581	3589	3597	3606	3614	3622	1	2	2	3	4	5	6	7	7
.56	3631	3639	3648	3656	3664	3673	3681	3690	3698	3707	1	2	3	3	4	5	6	7	8
.57	3715	3724	3733	3741	3750	3758	3767	3776	3784	3793	1	2	3	3	4	5	6	7	8
.58	3802	3811	3819	3828	3837	3846	3855	3864	3873	3882	1	2	3	4	4	5	6	7	8
.59	3890	3899	3908	3917	3926	3936	3945	3954	3963	3972	1	2	3	4	5	5	6	7	8
.60	3981	3990	3999	4009	4018	4027	4036	4046	4055	4064	1	2	3	4	5	6	6	7	8
.61	4074	4083	4093	4102	4111	4121	4130	4140	4150	4159	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.62	4169	4178	4188	4198	4207	4217	4227	4236	4246	4256	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.63	4266	4276	4285	4295	4305	4315	4325	4335	4345	4355	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.64	4365	4375	4385	4395	4406	4416	4426	4436	4446	4457	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.65	4467	4477	4487	4498	4508	4519	4529	4539	4550	4560	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.66	4571	4581	4592	4603	4613	4624	4634	4645	4656	4667	1	2	3	4	5	6	7	9	10
.67	4677	4688	4699	4710	4721	4732	4742	4753	4764	4775	1	2	3	4	5	7	8	9	10
.68	4786	4797	4808	4819	4831	4842	4853	4864	4875	4887	1	2	3	4	6	7	8	9	10
.69	4898	4909	4920	4932	4943	4955	4966	4977	4989	5000	1	2	3	5	6	7	8	9	10
.70	5012	5023	5035	5047	5058	5070	5082	5093	5105	5117	1	2	4	5	6	7	8	9	11
.71	5129	5140	5152	5164	5176	5188	5200	5212	5224	5236	1	2	4	5	6	7	8	10	11
.72	5248	5260	5272	5284	5297	5309	5321	5333	5346	5358	1	2	4	5	6	7	9	10	11
.73	5370	5383	5395	5408	5420	5433	5445	5458	5470	5483	1	3	4	5	6	8	9	10	11
.74	5495	5508	5521	5534	5546	5559	5572	5585	5598	5610	1	3	4	5	6	8	9	10	12
.75	5623	5636	5649	5662	5675	5689	5702	5715	5728	5741	1	3	4	5	7	8	9	10	12
.76	5754	5768	5781	5794	5808	5821	5834	5848	5861	5875	1	3	4	5	7	8	9	11	12
.77	5888	5902	5916	5929	5943	5957	5970	5984	5998	6012	1	3	4	5	7	8	10	11	12
.78	6026	6039	6053	6067	6081	6095	6109	6124	6138	6152	1	3	4	6	7	8	10	11	13
.79	6166	6180	6194	6209	6223	6237	6252	6266	6281	6295	1	3	4	6	7	9	10	11	13
.80	6310	6324	6339	6353	6368	6383	6397	6412	6427	6442	1	3	4	6	7	9	10	12	13
.81	6457	6471	6486	6501	6516	6531	6546	6561	6577	6592	2	3	5	6	8	9	11	12	14
.82	6607	6622	6637	6653	6668	6683	6699	6715	6730	6745	2	3	5	6	8	9	11	12	14
.83	6761	6776	6792	6808	6823	6839	6855	6871	6887	6902	2	3	5	6	8	9	11	13	14
.84	6918	6934	6950	6966	6982	6998	7015	7031	7047	7063	2	3	5	6	8	10	11	13	15
.85	7079	7096	7112	7129	7145	7161	7178	7194	7211	7228	2	3	5	7	8	10	12	13	15
.86	7244	7261	7278	7295	7311	7328	7345	7362	7379	7396	2	3	5	7	8	10	12	13	15
.87	7413	7430	7447	7464	7482	7499	7516	7534	7551	7568	2	3	5	7	9	10	12	14	16
.88	7586	7603	7621	7638	7656	7674	7691	7709	7727	7745	2	4	5	7	9	11	12	14	16
.89	7762	7780	7798	7816	7834	7852	7870	7889	7907	7925	2	4	5	7	9	11	12	14	16
.90	7943	7962	7980	7998	8017	8035	8054	8072	8091	8110	2	4	6	7	9	11	13	15	17
.91	8128	8147	8166	8185	8204	8222	8241	8260	8279	8299	2	4	6	8	9	11	13	15	17
.92	8318	8337	8356	8375	8395	8414	8433	8453	8472	8492	2	4	6	8	10	12	14	15	17
.93	8511	8531	8551	8570	8590	8610	8630	8650	8670	8690	2	4	6	8	10	12	14	16	18
.94	8710	8730	8750	8770	8790	8810	8831	8851	8872	8892	2	4	6	8	10	12	14	16	18
.95	8913	8933	8954	8974	8995	9016	9036	9057	9078	9099	2	4	6	8	10	12	15	17	19
.96	9120	9141	9162	9183	9204	9226	9247	9268	9290	9311	2	4	6	8	11	13	15	17	19
.97	9333	9354	9376	9397	9419	9441	9462	9484	9506	9528	2	4	7	9	11	13	15	17	20
.98	9550	9572	9594	9616	9638	9661	9683	9705	9727	9750	2	4	7	9	11	13	16	18	20
.99	9772	9795	9817	9840	9863	9886	9908	9931	9954	9977	2	5	7	9	11	14	16	18	20
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9